राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 172

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शनिवार, 30 नवंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

रोहित शर्मा की ब्रांड वैल्यू में जबरदस्त उछाल

>>14

सरोकार

बंगाल में मुफलिसों के मसीहा बन गए हैं अनंत नेवटिया

कोलकाता : स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में जीवन का संवैधानिक अधिकार अधूरा है। बंगाल के गरीब ग्रामीण परिवारों को इलाज और रोजगार मुहैया कराने में जुटे हैं अनंत नेवटिया। उनके संगठन रूरल हेल्थ केयर फाउंडेशन के कार्यों को संरा तक ने स्वीकारा है। (पेज-10)

जागरण विशेष

छोटे शहरों को नई राह दिखाता गोरखपुर का को-वर्किंग कैफे

गोरखपुर : गोरखपुर जैसे शहर में को वर्किंग स्पेस यानी साझे ऑफिस की कल्पना मुश्किल काम था। लेकिन आज यहां यह फार्मूला हिट हो चुका है। संसाधनों की कमी के कारण दूसरे शहरों में जाकर नौकरी करने वालों को अपने शहर में कारोबार सुलभ हो गया है। (पेज-10)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

फास्टैग की तिथि 15 दिसंबर तक बढ़ी

नई दिल्ली : घोषणा के बावजूद एनएचएआइ के विफल रहने के कारण सरकार ने फास्टैग की अनिवार्यता की तारीख को 15 दिनों तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब बिना फास्टैग वाहनों के फास्टैग लेन में प्रवेश पर 15 दिसंबर तक कोई जुर्माना नहीं वसूला जाएगा। साथ ही एनएचएआइ के बूथ पर फास्टैग मुफ्त मिलेगा।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

झारखंड में पहले चरण की 13 सीटों पर आज होगा मतदान

रांची : झारखंड विधानसभा चुनाव के तहत पहले चरण के 13 विधानसभा क्षेत्रों में शनिवार को मतदान होगा। ये सभी सीटें सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हैं। कुल 4,892 मतदान केंद्रों पर होने वाले मतदान में करीब 37 लाख मतदाता 189 उम्मीदवारों का भाग्य तय करेंगे। मतदान सुबह सात बजे से अपराह्न तीन बजे तक होगा।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

निर्यातकों के लिए टैक्स रिफंड स्कीम लाने की तैयारी

नई दिल्ली : निर्यातकों के लिए सरकार टैक्स रिफंड स्कीम लाने की तैयारी कर रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा, प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। साथ ही कहा, सरकार श्रम कानूनों में सुधार के लिए भी प्रयासरत है। इस संबंध में प्रस्ताव भी संसद की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

अमेरिका और तालिबान के बीच शांति वार्ता बहाल

वाशिंगटन : अफगानिस्तान के पहले और आकस्मिक दौरे पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलान किया कि उनके प्रशासन ने तालिबान से शांति वार्ता बहाल कर दी है। ट्रंप ने गत सितंबर में इस आतंकी संगठन के साथ वार्ता अचानक रद कर दी थी। तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने कहा, वार्ता बहाल होने के बारे में कुछ कहना अभी जल्दबाजी है।

दूसरी तिमाही में विकास दर 4.5 फीसद

आंकड़े जारी ▶ जुलाई-सितंबर में भी ग्रोथ रेट छह वर्षों के निचले स्तर तक गिरा

कृषि और मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र ने बिगाड़ी आर्थिक विकास की तस्वीर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भी आर्थिक विकास दर में गिरावट का क्रम बना रहा। जुलाई-सितंबर, 2019 की अवधि में जीडीपी की वृद्धि दर 4.5 प्रतिशत रह गई है। यह बीते छह साल का निचला स्तर है। इससे पहले जनवरी-मार्च 2012-13 की तिमाही में 4.3 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर दर्ज की गई थी।

नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस (एनएसओ) ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े जारी किये। बीते वित्त वर्ष की इसी तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर सात प्रतिशत रही थी। जबकि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की आर्थिक विकास दर पांच प्रतिशत रही थी। एनएसओ के मुताबिक दूसरी तिमाही में जीडीपी का आकार 35.99 लाख करोड़ रुपये रहा है, जो बीते वित्त वर्ष की इसी अवधि में 34.43 लाख करोड़ रुपये था। वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के. सुब्रमणियन ने जीडीपी के आंकड़ों पर टिप्पणी करते हुए कहा, 'इकोनॉमी के फंडामेंटल मजबूत हैं और तीसरी तिमाही से अर्थव्यवस्था मंदी से बाहर निकलना शुरू होगी।'

प्रतीकात्मक फोटो

आंकड़ों के मुताबिक, आर्थिक विकास दर को कृषि और मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर के प्रदर्शन ने सर्वाधिक प्रभावित किया है। मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर के उत्पादन में इस तिमाही एक प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। जुलाई-सितंबर की अवधि में यह -1.0 प्रतिशत रही है। बीते वित्त वर्ष की इसी तिमाही में यह 6.9 प्रतिशत रही थी।

बीते वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 4.9 प्रतिशत की रफ्तार से ग्रोथ करने वाले कृषि क्षेत्र की रफ्तार इस अवधि में आधी से भी कम रह गई है। एनएसओ के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 की जुलाई-सितंबर की तिमाही में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 2.1 प्रतिशत रही है। लगभग यही स्थिति कंस्ट्रक्शन सेक्टर की भी रही है। दूसरी तिमाही में इस क्षेत्र की वृद्धि दर बीते साल के 8.5 प्रतिशत से घटकर 3.3 प्रतिशत रह गई है। जबकि खनन क्षेत्र की विकास दर बीते वर्ष की दूसरी तिमाही के 2.2 प्रतिशत से घटकर 0.1 प्रतिशत पर आ गई है। ये सभी सेक्टर रोजगार देने वाले क्षेत्रों की गिनती में आते हैं।

दूसरी तिमाही की विकास दर (प्रतिशत में)

क्षेत्र	2018-19	2019-20
कृषि, वानिकी	4.9	2.1
खनन	-2.2	0.1
मैन्यूफैक्चरिंग	6.9	-1.0
बिजली पानी सेवाएं	8.7	3.6
कंस्ट्रक्शन	8.5	3.3
व्यापार, होटल परिवहन		
कम्यूनिकेशन सेवाएं	6.9	4.8
वित्त, रियल एस्टेट		
प्रोफेशनल सेवाएं	7.0	5.8
लोक प्रशासन, रक्षा		
व अन्य सेवाएं	8.6	11.6

नोट : आंकड़े वित्त वर्ष 2011-12 की कीमतों पर

दूसरी तरफ सेवाओं के क्षेत्र में भी प्रदर्शन में गिरावट का क्रम बना हुआ है। बिजली, गैस, पानी और अन्य सामाजिक सेवाओं की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 3.6 प्रतिशत रही है। जबकि बीते साल की इसी अवधि में इस क्षेत्र ने 8.7 प्रतिशत की दर से वृद्धि हासिल की थी। इसी तरह ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्यूनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग से जुड़ी अन्य सेवाओं की वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत से घटकर दूसरी तिमाही में 4.8 प्रतिशत पर आ गई है। वित्तीय सेवाओं की वृद्धि दर में भी इस अवधि में गिरावट दर्ज की गई है और यह सात प्रतिशत के मुकाबले चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 5.8 प्रतिशत रही है। लेकिन लोक सेवा, रक्षा और अन्य सेवाओं की वृद्धि दर बीते साल की दूसरी तिमाही के 8.6 प्रतिशत से बढ़कर 11.6 प्रतिशत हो गई है। अर्थव्यवस्था में निवेश का बैरोमीटर माने जाने वाले ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉरमेशन 2011-12 के मूल्यों पर दूसरी तिमाही में 10.83 लाख करोड़ रुपये आंका गया है। यह बीते साल इसी अवधि में 11.16 लाख करोड़ रुपये रहा था। यह जीडीपी का 30.1 प्रतिशत है जो बीते साल 32.4 प्रतिशत था। हालांकि सरकार के व्यय के आंकड़े में दूसरी तिमाही में वृद्धि दर्ज की गई है। यह बीते साल की दूसरी तिमाही के 11.9 प्रतिशत से बढ़कर इस वर्ष 13.1 प्रतिशत पर आ गया है।

जहां तक छमाही आधार पर देश की अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का सवाल है उसमें जीडीपी विकास दर अप्रैल-सितंबर की अवधि में 4.8 प्रतिशत रही है। यह बीते साल 7.5 प्रतिशत थी। ज्ञात हो, अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार को लेकर घरेलू व अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने अपने अनुमान घटा दिए थे। रिजर्व बैंक भी वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीडीपी के अपने पूर्व के 6.9 के अनुमान को घटाकर 6.1 प्रतिशत कर चुका है। (पेज-12 भी देखें)

स्विस कंपनी करेगी जेवर एयरपोर्ट का निर्माण

- फाइनेंशियल बिड में अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड दूसरे नंबर पर रही
- बोली जीतने वाली ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल ने लगाई प्रति यात्री 400.97 रुपये की बोली

जेवर एयरपोर्ट के निकट चल रहा काम फाइल फोटो

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

दिल्ली-एनसीआर के तीसरे और देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित होने वाले जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण एवं संचालन का जिम्मा स्विट्जरलैंड की कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी को मिला है। जेवर एयरपोर्ट के लिए शुक्रवार को खोली गई वित्तीय बोली में ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी ने प्रति यात्री सबसे अधिक 400.97 रुपये की बोली लगाई। अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड 360 रुपये की बोली के साथ दूसरे नंबर पर रही। जेवर एयरपोर्ट चार चरणों में विकसित होगा। एयरपोर्ट से 2023-24 में व्यावसायिक उड़ान शुरू करने का लक्ष्य है।

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए चार कंपनियां- ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी, अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआइएएल) व एंकरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट होल्डिंग्स लिमिटेड मैदान में थीं। ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी ने प्रदेश सरकार को प्रति यात्री 400.97 रुपये के राजस्व की बोली लगाई। अडानी इंटरप्राइजेज ने 360 रुपये, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने 352 रुपये व एंकरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स लिमिटेड ने सबसे कम 205 रुपये की बोली लगाई। पीपीपी मॉडल पर बनने वाले जेवर एयरपोर्ट का संचालन 40 साल के लिए कंपनी को मिलेगा।

सोमवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश की परियोजना निगरानी एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक होगी। प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में फाइनेंशियल बिड में सफल कंपनी के नाम पर मुहर लगाकर इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। प्रदेश सरकार जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण एवं संचालन के लिए चयनित ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी के नाम की अधिसूचना जारी करेगी।

जनवरी में हो सकता है शिलान्यास : जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी में कर सकते हैं। हालांकि एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू होने में अभी वक्त लगेगा। पहले सरकार जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए चयनित कंपनी की अपनी एजेंसियों के माध्यम से जांच कराएगी। जांच एजेंसियों की क्लीन चिट के बाद ही जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य धरातल पर शुरू होगा।

बिडिंग में ज्यूरिख से काफी पीछे रह गईं घरेलू कंपनियां पेज>>12

योगी ने दी बधाई

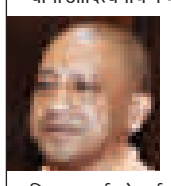

बिड प्रक्रिया सफल होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि एयरपोर्ट का विकास कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा होगा। उन्होंने भरोसा दिया कि प्रदेश सरकार विकासकर्ता को पूर्ण सहयोग देगी। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने कहा, राज्य व केंद्र सरकार के अच्छे तालमेल से बीस वर्ष पुरानी परियोजना जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दो वर्षों में धरातल पर उतारने में सफलता मिली है। केंद्र ने परियोजना के लिए त्वरित फैसले किए। तेजी से भूमि का अधिग्रहण किया गया। बिड प्रक्रिया समय के साथ पूरी की गई।

विकास क्रम : अब तक

- 2017 में नागरिक विमानन मंत्रालय द्वारा साइट क्लियरेंस, गृह मंत्रालय से अनापत्ति
- 2018 में रक्षा मंत्रालय से अनापत्ति, नागरिक विमानन मंत्रालय से सैद्धांतिक मंजूरी
- मई, 2019 में एयरपोर्ट की वैश्विक निविदा जारी
- नवंबर, 2019 में जेवर एयरपोर्ट की तकनीकी बिड खुली
- 29 नवंबर, 2019 को फाइनेंशियल बिड खोली गई

गोडसे को देशभक्त बताने पर प्रज्ञा ठाकुर ने लोकसभा में दो बार मांगी माफी

- गोडसे को देशभक्त नहीं बताने के अपने दावे पर अड़ी रहीं भाजपा सांसद
- आतंकी कहे जाने पर राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान शुक्रवार को लोस में प्रज्ञा सिंह ठाकुर नाथूराम गोडसे के मामले पर लिखित बयान पढ़ती हुईं। एएनआइ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने के बयान पर भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लोकसभा में दो बार माफी मांगनी पड़ी। वैसे माफी मांगने के दौरान भी प्रज्ञा इस बात पर अड़ी रहीं कि उन्होंने गोडसे को कभी देशभक्त नहीं कहा। पहली बार माफी मांगते समय प्रज्ञा ने राहुल गांधी पर उन्हें आतंकी कहने पर निशाना साधा था, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में पूरा विपक्ष प्रज्ञा के बिना शर्त माफी पर अड़ गया। बाद में प्रज्ञा ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया। दूसरी बार बिना शर्त माफी मांगते हुए उन्होंने कहा, 27 नवंबर को एसपीजी संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान मैंने गोडसे को देशभक्त नहीं कहा था। मैंने उसका नाम भी नहीं लिया था। फिर भी यदि किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो मैं माफी मांगती हूं।

लोकसभा में शून्यकाल के बाद विपक्ष ने प्रज्ञा ठाकुर का मामला उठाना शुरू कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निर्देश पर अपने कथन के लिए माफी मांगते हुए प्रज्ञा ने शुक्रवार को राहुल गांधी का नाम लिए बिना उनके द्वारा आतंकी कहे जाने का मुद्दा उठा दिया। उनका कहना था कि उन्हें अभी तक अदालत से दोषी नहीं ठहराया गया है। इसके बावजूद उन्हें आतंकी कहा जा रहा है। यह साध्वी व महिला का अपमान है। प्रज्ञा के इस तरह की माफी को अस्वीकार करते हुए विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। सत्तापक्ष की ओर से यह समझाने की कोशिश की गई कि प्रज्ञा ने माफी मांग ली है, पर विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। इस दौरान भाजपा के निशिकांत दुबे ने लोस अध्यक्ष से एक मौजूदा सांसद को आतंकी बताए जाने को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाए जाने की मांग की। प्रस्ताव स्वीकार होगा या नहीं, इस पर लोस अध्यक्ष फैसला करेंगे।

सत्ता पक्ष की ओर से कुछ सांसदों ने शिवसेना के मुखपत्र में छपे संपादकीय में गोडसे को देशभक्त बताने का मुद्दा उठाया। वहीं, विपक्षी नेताओं का कहना था कि सदन के बाहर किसी ने क्या कहा, इसे मुद्दा बनाना ठीक नहीं है। प्रज्ञा ने सदन के भीतर महात्मा गांधी के हत्यारे को देशभक्त कहा है। बाद में लोस अध्यक्ष ने अपने कमरे में सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई, जिसमें प्रज्ञा के बिना शर्त माफी मांगने पर सहमति बनी।

राहुल बोले-मैंने ट्विटर पर जो कुछ लिखा था, उस पर कायम हूं : प्रज्ञा ठाकुर द्वारा विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने से बेपरवाह पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि वे अपने पुराने बयान पर कायम हैं। कांग्रेस नेता ने शुक्रवार को कहा कि मैंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। मैंने ट्विटर पर जो कुछ लिखा था, उस पर कायम हूं। यह पूछे जाने पर कि भाजपा ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, राहुल ने कहा कि ठीक है। इससे कोई समस्या नहीं है। उनको जो करना है करने दीजिए। मैं स्वागत करूंगा। राहुल ने ट्विटर पर लिखा था कि आतंकी प्रज्ञा ने आतंकी गोडसे को देशभक्त कहा है।

लंदन ब्रिज के निकट आतंकी हमले में कई घायल, हमलावर मारा गया

लंदन, एजेंसियां : ब्रिटेन के मशहूर लंदन ब्रिज के निकट शुक्रवार को चाकूबाजी की घटना में कई लोग घायल हो गए। पुलिस इसे आतंकी हमला मान रही है। पुलिस ने हमलावर को मार गिराने का दावा किया है। ब्रिज की घेराबंदी कर दी गई है और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। आपातकालीन सेवाओं को भी बहाल कर दिया गया है।

स्कॉटलैंड यार्ड ने कहा कि हमने लंदन ब्रिज पर हुई घटना की जांच अभी शुरू की है। उसने बताया कि एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और इसमें कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। स्कॉटलैंड यार्ड ने एक बयान में कहा कि अगर आप घटनास्थल के आस-पास हैं, तो वहां मौजूद अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें।

लंदन एंबुलेंस सेवा ने इसे बड़ी घटना बताया है। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में लोगों को लंदन ब्रिज पर अफरा-तफरी में इधर से उधर भागते देखा जा सकता है। इस इलाके में परिवहन सेवा थमी हुई है और दफ्तरों को बंद कर दिया गया है। लंदन ब्रिज उन इलाकों में से एक है, जहां जून 2017 में आइएस के आतंकी हमले में 11 लोगों की मौत हो गई थी।

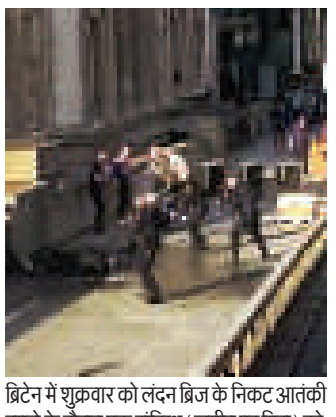

ब्रिटेन में शुक्रवार को लंदन ब्रिज के निकट आतंकी हमले के दौरान एक संदिग्ध (जमीन पर गिरा) को घेरे पुलिसकर्मी। एपी

उद्धव ने आरे कालोनी मेट्रो शेड के निर्माण पर लगाई रोक

- दोपहर में मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही लिया फैसला
- फड़नवीस बोले, हतोत्साहित होंगे निवेशक, रुक जाएंगी परियोजनाएं

मुंबई में शुक्रवार को उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाल लिया। एएनआइ

मुंबई, प्रेट्र : शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार दोपहर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पदभार संभाल लिया। बाद में प्रेस से बातचीत में उन्होंने मुंबई की आरे कालोनी में मेट्रो कारशेड के निर्माण पर रोक लगाने की घोषणा की। इसी शेड के निर्माण के लिए पेड़ काटे जाने का पिछले महीने काफी विरोध हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि इससे निवेशक हतोत्साहित होंगे और शहर की ढांचागत परियोजनाएं रुक जाएंगी।

मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश सचिवालय में आयोजित पहली प्रेस वार्ता में अपने विधायक बेटे आदित्य के साथ मौजूद उद्धव ने कहा, 'मैंने आरे कारशेड के काम पर रोक लगा दी है। मैं सभी चीजों की समीक्षा करूंगा... मैं ऐसी संस्कृति की अनुमति नहीं दूंगा जिसमें रात में पेड़ काटे जाएं। अगले आदेश तक एक पत्ती भी नहीं काटी जाएगी।' बता दें कि आरे कालोनी में पेड़ काटे जाने को लेकर काफी विरोध हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद रात में पेड़ काटे गए थे। उस समय फड़नवीस सरकार में शामिल रही शिवसेना ने इसका विरोध भी किया था।

उद्धव की घोषणा पर ट्वीट कर फड़नवीस ने कहा, 'यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद आरे मेट्रो कारशेड के कार्य पर रोक लगा दी है। इससे साफ है कि राज्य सरकार मुंबई की ढांचागत परियोजनाओं के प्रति गंभीर नहीं है। आखिरकार इससे सिर्फ सामान्य मुंबईवासी ही प्रभावित होंगे।' उन्होंने आगे कहा कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने मेट्रो परियोजना के लिए मामूली ब्याज दर पर 15 हजार करोड़ रुपये दिए थे। इस फैसले से निवेशक हतोत्साहित होंगे। भाजपा विधायक आशीष शेल्कर ने भी फैसले आलोचना करते हुए कहा, 'विकास के हाथों का पीछे की दिशा में जाना तय है जब आप तीर-कमान लिए हाथ में घड़ी बांधते हैं।' मालूम हो कि तीर-कमान शिवसेना, घड़ी राकांपा और हाथ कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है।

मैं अप्रत्याशित सीएम, जिम्मेदारियों से नहीं भागूंगा : प्रेस कांफ्रेंस के दौरान उद्धव ने अपने पूर्ववर्ती देवेंद्र फड़नवीस पर तंज करते हुए कहा, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान यह घोषणा नहीं की थी कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मैं भले ही अप्रत्याशित मुख्यमंत्री हूं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागूंगा। फड़नवीस ने कहा था कि वह लौटकर (मुख्यमंत्री के तौर पर) आएंगे। उद्धव ने इस बात का खासतौर पर जिक्र किया कि वह राज्य के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका जन्म मुंबई में हुआ है। उन्होंने कहा कि वह शहर के विकास की योजनाओं पर काम कर रहे हैं। उनकी सरकार करदाताओं के एक-एक पैसे के प्रति जवाबदेह रहेगी।

किसी लांड्री में नहीं धुल सकता भगवा रंग पेज>>4

रचा कीर्तिमान

भारत की ओर से चार टेस्ट मैच खेल चुके मिथुन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में रचा इतिहास, डेढ़ माह के अंदर ली दूसरी हैट्रिक

अभिमन्यु मिथुन ने छह गेंद पर झटके पांच विकेट

सूरत, प्रेट्र : भारत के लिए चार टेस्ट व पांच वनडे खेल चुके तेज गेंदबाज अभिमन्यु मिथुन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में शुक्रवार को हरियाणा के खिलाफ एक ही ओवर में पांच विकेट लेने का कारनामा किया। इसमें हैट्रिक सहित चार गेंदों में लगातार चार विकेट भी शामिल रहे। उनके इस करिश्माई प्रदर्शन की बदौलत कर्नाटक ने यह मैच आठ विकेट से अपने नाम किया। यह इस साल दूसरा मौका है जब मिथुन ने हैट्रिक ली। इससे पहले उन्होंने अक्टूबर में विजय हजारे ट्रॉफी में हैट्रिक ली थी।

ऐसे लिए पांच विकेट : मैच में मिथुन ने तीन ओवर में 37 रन दिए थे, लेकिन कोई विकेट नहीं लिया था। जब वह पारी का आखिरी ओवर करने आए तो उन्होंने पहली ही गेंद पर हिमांशु राणा (61 रन, 34 गेंद) को मयंक अग्रवाल के हाथों कैच कराया। दूसरी गेंद पर राहुल तेवतिया (32 रन, 20 गेंद) को पवेलियन भेजा। उनका कैच करुण नायर ने लपका। तीसरी गेंद पर सुमित कुमार (00) को रोहन कदम के हाथों कैच कराकर मिथुन ने हैट्रिक पूरी की। चौथी गेंद पर कप्तान अमित मिश्रा (00) के गौतम के हाथों लपके गए। पांचवीं गेंद पर वाइड का एक रन मिला। पांचवीं गेंद दोबारा फेंकी गई तो उस पर जीतेश सरोहा ने एक रन लिया। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने जयंत यादव (00) को केएल राहुल के हाथों कैच कराया।

अभिमन्यु मिथुन फाइल फोटो

फाइनल में पहुंचा कर्नाटक : हरियाणा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में आठ विकेट पर 194 रन बनाए थे, जवाब में कर्नाटक ने महज 15 ओवरों में दो विकेट पर 195 रन बनाते हुए जीत दर्ज की। कर्नाटक के लिए केएल राहुल ने 31 गेंदों में चार चौके और छह छक्के की मदद से 66 रन बनाए, जबकि देवदत्त पडिक्कल ने 42 गेंदों में 87 रनों की पारी खेली। उन्होंने 11 चौके और चार छक्के जड़े। मयंक अग्रवाल 14 गेंदों में 30 रन बनाकर नाबाद रहे।

जन्मदिन पर भी ली थी हैट्रिक : मिथुन ने अपने 30वें जन्मदिन को यादगार बनाते हुए इसी वर्ष 25 अक्टूबर को विजय हजारे वनडे ट्रॉफी के फाइनल में तमिलनाडु के खिलाफ हैट्रिक सहित पांच विकेट चटकाए थे, जिससे कर्नाटक चौथी बार चैंपियन बना था।

तीनों प्रारूपों में हैट्रिक : मिथुन प्रथम श्रेणी क्रिकेट में भी हैट्रिक ले चुके हैं। उन्होंने अपने पहले प्रथम श्रेणी मुकाबले में उत्तर प्रदेश के खिलाफ 2009 में मेरठ में हैट्रिक ली थी। इस तरह वह घरेलू क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं।

फिक्सिंग में आ रहा नाम : मिथुन का नाम कर्नाटक प्रीमियर लीग (केपीएल) में सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग से भी जोड़ा जा रहा है। इस मामले में मिथुन पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर हैं जिससे केंद्रीय अपराध शाखा के अधिकारी सवाल जवाब करेंगे। मिथुन केपीएल में शिवमोगा लायंस के कप्तान हैं।

तेलंगाना में सामूहिक दुष्कर्म के बाद महिला डॉक्टर की हत्या, शव जलाया, चार गिरफ्तार

- बहन को फोनकर बताया था, टोल प्लाजा पर कुछ लोगों से उसे लग रहा डर
- परिजनों का आरोप, कार्रवाई के बजाय अनर्गल बातों में उलझाती रही पुलिस

चटनपल्ली पुल के पास छानबीन करते पुलिसकर्मी, यहीं महिला चिकित्सक का जला शव मिला था। एपी

हैदराबाद, एजेंसियां : तेलंगाना में 27 वर्षीय महिला पशु चिकित्सक की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या की गई थी। तेलंगाना की साइबराबाद पुलिस ने इस मामले में चार आरोपितों मोहम्मद आरिफ, जे. शिवा, जे. नवीन और चेन्ना केशवुलु को गिरफ्तार किया है। 26 वर्षीय आरिफ ट्रक चालक है जबकि बाकी तीन क्लीनर हैं।

पुलिस ने बताया कि गुरुवार रात सामूहिक दुष्कर्म के दौरान आरोपित महिला का मुंह दबाए रहे जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई। इसके बाद वे लोग शव को 28 किलोमीटर दूर शादनगर में चटनपल्ली पुल के पास ले गए और जला दिया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई के बजाय सीमा क्षेत्र में उलझी रही। सही समय पर कार्रवाई होती तो बेटी आज जिंदा होती। मृतका के पिता के मुताबिक वो लोग बुधवार रात ग्यारह बजे पुलिस के पास पहुंचे थे। रात के तीन बजे कुछ सिपाही महिला की तलाश में निकले थे।

साइबराबाद के पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनर ने शुक्रवार को बताया कि टोंडुपल्ली टोल प्लाजा के पास आरोपितों ने महिला चिकित्सक की स्कूटी के टायर से हवा निकाल दी थी। फिर उसे बनवाने के बहाने झांसे में ले लिया और वारदात को अंजाम दे डाला। बाद में परिजनों ने सैंडिल व कपड़ों से महिला चिकित्सक की पहचान की थी। मृतका के पिता ने कहा, दरिंदों को फांसी पर लटकाना चाहिए, ताकि किसी को इस तरह का अपराध करने की हिम्मत ना हो। उन्होंने कहा, महिला चिकित्सक ने टोल प्लाजा से अपनी बहन को फोन कर बताया था कि उसकी स्कूटी पंचर हो गई है और कोई उसे बनवाने ले गया है। उसने यह भी बताया था कि वहां अंधेरा और एक ट्रक के पास कुछ लोग खड़े हैं, जिनसे उसे डर लग रहा है। बाद में उसका मोबाइल बंद हो गया था। टोल प्लाजा पर उसकी स्कूटी मिली थी। उसके पास ही शराब की खाली बोतल भी पुलिस ने बरामद की थी।

तेलंगाना के गृह मंत्री ने दी सफाई पेज>>5

250 करोड़ रुपये सालाना की बचत करेगा उत्तर रेलवे सीधे बिजली उत्पादन कंपनियों से खरीदारी करके। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद अब पंजाब में भी बिजली उत्पादन कंपनियों से सीधे बिजली खरीदी जा रही है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 30 नवंबर 2019

जनता को कानून नहीं, रजिस्ट्री चाहिए : केजरीवाल

दो टूक ▸ मुख्यमंत्री ने अनधिकृत कॉलोनियों के नियमन को लेकर केंद्र सरकार की नीयत पर जताया संदेह

कहा, लोगों के हाथ में जब तक रजिस्ट्री नहीं आ जाए भरोसा करना मुश्किल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अनधिकृत कॉलोनियों के नियमन को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर फिर से हमला बोला है। उन्होंने भाजपा की नीयत पर संदेह जताते हुए कहा कि लोगों को कानून नहीं, बल्कि रजिस्ट्री चाहिए। लोगों के हाथ में जब तक रजिस्ट्री नहीं आ जाती, किसी पर भरोसा करना मुश्किल है।

शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें सुनने में आ रहा है कि नेताओं की रामलीला मैदान में रैली होगी, जहां सौ लोगों को रजिस्ट्री देकर फोटो खिंचवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आखिर सौ लोगों को ही रजिस्ट्री क्यों, पूरी दिल्ली को क्यों नहीं। बाकी लोगों को कहा जा रहा है कि चुनाव बाद रजिस्ट्री देंगे। यह तो पहले भी होता रहा है। चुनाव से पहले लोगों को रजिस्ट्री का वादा किया जाता था, फिर चुनाव बाद अगले चुनाव में आने को कह दिया जाता था। अब इस प्रक्रिया से दिल्ली की जनता ऊब गई है।

केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार की सारी प्रक्रिया पूरी है, केंद्र सरकार से आदेश मिले तो पंद्रह दिनों में सबके हाथ में रजिस्ट्री दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नवंबर 2015 में ही अनधिकृत कॉलोनियों को पक्का करने की सारी प्रक्रिया पूरी कर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया था। लेकिन, केंद्र सरकार चार साल तक उसे दबाए बैठी रही। अब चुनाव नजदीक आता देख प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। यह काम तो छह माह पहले भी प्रारंभ हो सकता था। इससे साफ है कि अनधिकृत कॉलोनियों के मसले पर नियत साफ नहीं थी।

केंद्र सरकार को सेटलाइट मैप 2015 में भेजा गया था लेकिन, उसे मानने से मना कर दिया गया। रजिस्ट्री न करानी पड़े, इसके लिए फिजिकल पैमाइश मांगी। अब केंद्र सरकार सेटलाइट पर ही रजिस्ट्री की बात कर रही है। कांग्रेस ने 2008 के चुनाव से ठीक पहले इसी तरह से प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटे थे। भाजपा सौ लोगों की रजिस्ट्री कराकर जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करने जा रही है। भाजपा लोगों की रजिस्ट्री कराना नहीं चाहती, बल्कि उन्हें सिर्फ बेवकूफ बनाने में लगी है।

दिल्ली सचिवालय में पत्रकार वार्ता करते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व मंत्री कैलाश गहलोत। संजय

मनोज तिवारी बोले, नियमितीकरण पर आप का झूठ आया सामने

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) का झूठ सामने आ गया है। इसे लेकर आप नेता लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वह प्रदेश भाजपा कार्यालय में अन्य सांसदों के साथ प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।

तिवारी ने कहा कि राज्यसभा सदस्य संजय सिंह व अन्य आप नेता पहले लोगों को गुमराह कर रहे थे कि नियमितीकरण का बिल संसद में नहीं लाया जा रहा है। लोकसभा में बिल पास होने से अब उनकी पोल खुल गई है। यही नहीं सदन में बिल पर चर्चा में आप सांसद भगवंत मान ने हिस्सा लिया, लेकिन जब वोट देने की बारी आई तो सदन छोड़कर चले गए। केजरीवाल को जवाब देना चाहिए कि उनकी पार्टी के सांसद ने दिल्ली के 40 लाख लोगों के जीवन से जुड़े बिल को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? राज्यसभा सदस्य विजय गोयल ने कहा कि केजरीवाल पांच सालों से लगातार दिल्ली का नुकसान कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि दिल्ली की स्थिति नरक से भी खराब हो गई है। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद उन्हें अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि केंद्र सरकार बार-बार नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए दिल्ली सरकार को पत्र लिखती रही, लेकिन सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि आप और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अनधिकृत कॉलोनियों को पास करने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने इस दिशा में कोई काम नहीं किया?

प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी। जागरण

लवली ने 180 दिन में नियमन की घोषणा को धोखा बताया

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा के साथ में कांग्रेसी नेता मुकेश शर्मा, अरविंदर सिंह लवली, जेपी अग्रवाल, कीर्ति आजाद, रमेश कुमार। जागरण

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

शीला दीक्षित सरकार में दिल्ली के शहरी विकास मंत्री रहे अरविंदर सिंह लवली ने 180 दिन (छह माह) में अनधिकृत कॉलोनियों के नियमन की घोषणा को सीधे तौर पर एक धोखा बताया है। उन्होंने कहा कि गुरुवार को लोकसभा में इस आशय का जो बिल पास किया गया है, वह ठीक उसी तरह है जिस तरह जमीनी आधार के आकलन के बिना भाजपा महाराष्ट्र में सरकार बना रही थी। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर तय समयावधि में 1731 अनधिकृत कॉलोनियों के लेआउट प्लान भी बन जाएं तो वह सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेंगे।

शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने केंद्र व दिल्ली सरकार पर आधी से ज्यादा अनधिकृत कालोनियों को उजाड़ने की साजिश करने का आरोप लगाया। कहा कि, 19 नवंबर 2019 की अधिसूचना की धारा 7 के भाग ए में मौजूद प्रावधान अनधिकृत कालोनियों के निवासियों के खिलाफ एक बड़ी साजिश का हिस्सा हैं। कांग्रेस पार्टी की अधिसूचना को रद करके नई अधिसूचना जारी करना यही साबित करता है कि दोनों सरकारों की नीयत में खोट है।

चोपड़ा ने कहा कि कांग्रेस को इंदिरा गांधी की नीति के अलावा कोई नीति मंजूर नहीं है। उन्होंने केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है, जिसने हमेशा अनधिकृत कॉलोनियों का भला किया है। जब भी कॉलोनियां नियमित हुई हैं, वो कांग्रेस के समय में ही हुई हैं। लवली ने कहा कि कांग्रेस ने न केवल इन कॉलोनियों को नियमित करने संबधी अधिसूचना जारी की थी बल्कि मास्टर प्लान में भी इसका प्रावधान किया था। नई अधिसूचना मास्टर प्लान की भी अवहेलना है। ओखला, बुलंद मस्जिद, पूर्वी दिल्ली व दक्षिणी दिल्ली की अधिकांश कॉलोनियों को नई नीति के अनुसार नियमित नही किया जा सकेगा।

कीर्ति आजाद ने कहा कि भाजपा की नीति और नीयत दोनों में खोट है, जो लोग दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं। उन्हें आज अपने मकान का दोबारा मालिक बनने के लिए भाजपा सरकार ने स्मार्ट फोन व कंप्यूटर का सहारा लेने के लिए मजबूर कर दिया है।

कई अभिभावकों ने दस से ज्यादा स्कूलों में किए आवेदन

राजधानी में शुक्रवार से स्कूलों में नर्सरी दाखिला प्रक्रिया शुरु हो गई। इस दौरान मॉडर्न स्कूल में इसके लिए जारी निर्देश पढ़ते अभिभावक। ध्रुव कुमार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली में शुक्रवार से नर्सरी, केजी एवं पहली कक्षा के लिए निजी स्कूलों में दाखिले की दौड़ शुरू हो चुकी है। दिल्ली के कुल 1750 स्कूलों में से ज्यादातर स्कूलों में ऑनलाइन ही आवेदन करने की व्यवस्था है। इसमें अभिभावकों को अपने दस्तावेजों क स्कैन करके ऑनलाइन ही जमा कराने के स्कूलों ने निर्देश दिए हैं।

शुक्रवार को ऑफिस का दिन होने के कारण कई अभिभावक ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने दफ्तर में अपने बच्चों के ऑनलाइन फॉर्म भरे तो कुछ अभिभावकों का मानना है कि अभी काफी दिन हैं, तो वह कई स्कूलों के फॉर्म को अच्छी तरह से पढ़कर फिर उसे भरेंगे। हालांकि पहले ही दिन कुछ ऐसे भी अभिभावक रहे जिन्होंने दस से ज्यादा स्कूलों में आवेदन किया। अभिभावक जितने भी स्कूलों में चाहें आवेदन कर सकते हैं। नर्सरी दाखिले में उनके बच्चों का दाखिला स्कूलों की अंक प्रणाली के आधार पर होगा।

दरियागंज के स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला कराने के लिए आए सुमित कुमार ने कहा कि उन्होंने काफी पहले से ही तैयारी करके रखी थी कि नर्सरी दाखिला शुरू होते ही आवेदन कर देंगे। उन्हें अपने बेटे को नर्सरी में दाखिला दिलवाना है। इसके लिए उन्होंने अपने घर से नजदीक पांच किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी स्कूलों की एक सूची तैयार कर ली थी। इसमें यह भी देखा कि कितने स्कूलों में फॉर्म भरने की ऑनलाइन प्रक्रिया मौजूद है और कितने स्कूलों में खुद जाकर फॉर्म भरना होगा।

थोड़ी दिक्कतें भी आईं : अभिभावकों की कुछ शिकायतें भी सामने आ रही हैं कि कुछ स्कूलों की वेबसाइट में ऑनलाइन आवेदन करते समय दिक्कतें आईं। राजेंद्र नगर निवासी दीपक सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने घर के नजदीक स्थित कुछ स्कूलों में ऑनलाइन फॉर्म भरा तो उनके सर्वर में काम नहीं कर रहे थे।

स्कूल से जितना नजदीक होगा घर, उतने ज्यादा मिलेंगे अंक

रीतिका मिश्रा, नई दिल्ली : राजधानी में सत्र 2020-2021 के लिए नर्सरी दाखिले की दौड़ कल (शुक्रवार) से शुरु हो गई है। इस बार करीब 1750 स्कूलों के लिए करीब डेढ़ लाख छात्र आवेदन करेंगे। स्कूलों ने एडमिशन के सभी पैमानों की जानकारी शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट के अलावा स्कूलों की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी है। ज्यादातर स्कूलों ने नेबरहुड, सिबलिंग, अलुमनाई, गर्ल चाइल्ड, सिंगल चाइल्ड को प्राथमिकता दी है, यानी अगर बच्चा इन बिंदुओं पर फिट बैठेगा तो उसके प्रवेश की संभावना ज्यादा होगी। ज्यादातर स्कूलों ने नेबरहुड को भी तीन भागों मे बांटा है। इसमें 0-3, 3-6 व 6 से ऊपर किलोमीटर के हिसाब से बांटा गया है और तीनों के अलग-अलग अंक रखे हैं। अजमेरी गेट स्थित एंग्लो अरेबिक स्कूल की प्रधानाचार्या फराह शाजी ने बताया कि स्कूल में एडमिशन को ऑफलाइन रखा गया है। अब तक 6 फॉर्म बंटे हैं। स्कूल ने सबसे ज्यादा अंक नेबरहुड के लिए निर्धारित किए हैं। इसमें 70 अंक शामिल हैं। इसके अलावा सिबलिंग के लिए 25 अंक व सिंगल चाइल्ड के लिए 5 अंक निर्धारित किए है। वहीं, रोहिणी स्थित माउंट आबू स्कूल की प्रिंसिपल ज्योति अरोड़ा ने बताया कि अभिभावक जितना हो सके पास के स्कूल में ही आवेदन करें। इससे ज्यादा अंक भी मिलेंगे और बच्चे के लिए भी आसानी होगी।

केंद्र के काम व उपल्ब्धियों का झूठा श्रेय लेने में लगी है आप सरकार : जावडेकर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

केंद्रीय मंत्री और दिल्ली चुनाव प्रभारी प्रकाश जावडेकर ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर केंद्र सरकार के काम व उपलब्धियों का झूठा श्रेय लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि यह सरकार सभी मोर्चों पर विफल साबित हुई है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार झूठ का सहारा ले रही है। वह लोक नीति शोध केंद्र (पीपीआरसी) में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दिल्ली सरकार के कामकाज पर पीपीआरसी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट भी जारी की है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी है। सूचना के अधिकार (आरटीआइ) के तहत लोगों को जानकारी नहीं दी जा रही है। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जनलोकपाल बनाने का वादा भी पूरा नहीं किया गया। दिल्ली में नशे की समस्या भी बढ़ रही है। भाजपा के उपाध्यक्ष व दिल्ली के प्रभारी श्याम जाजू ने कहा कि दिल्ली सरकार के पास विकास के लिए दृष्टि, अनुशासन और योजना नहीं है। यही कारण है कि दिल्लीवासियों की समस्या हल नहीं हो रही है। यहां के लोगों को आयुष्मान भारत योजना के लाभ से वंचित किया गया है।

भाजपा के उपाध्यक्ष और पीपीआरसी के निदेशक विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि आरटीआइ और अन्य साधनों से जानकारी हासिल करके रिपोर्ट तैयार की गई है। आरटीआइ के तहत जानकारी के लिए दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के पास 12 सौ प्रश्न भेजे गए थे, जिसमें से सिर्फ तीन सौ के ही जवाब दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब विधानसभा चुनाव में आप ने नशा को बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन दिल्ली में इस समस्या को हल करने में सरकार विफल रही है। युवा इसके शिकार हो रहे हैं। सड़कों पर रहने वाले लगभग 80 फीसद बच्चे नशे के शिकार हैं। पांच वर्षों में सरकार अनधिकृत कॉलोनियों के सीमांकन का काम नहीं कर सकी। पिछले दो वर्षों में दिल्ली का राजकोषीय घाटा तेजी से बढ़ा है। इस मौके पर पीपीआरसी के निदेशक डॉ. सुमित भसीन, भाजपा नेता वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद थे। भाजपा नेताओं ने बताया कि जल्द ही शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली सरकार के कामकाज की रिपोर्ट जारी की जाएगी।

लोक नीति शोध केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम में रिपोर्ट जारी करते केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर और अन्य। सौ : शोध केंद्र

मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के लिए बनाई 13 सदस्यीय टीम

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली सरकार अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए 50 करोड़ खर्च करेगी। इस रकम को किस मद में खर्च किया जाएगा, इसका निर्णय करने के लिए 13 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। इसमें राजधानी के सभी बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। इसके संयोजक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश खन्ना होंगे। कमेटी को दस दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी, ताकि जल्द ही योजना पर कार्य शुरू किया जा सके।

शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत 50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस बजट में क्या कार्य किया जाना है, इसका निर्णय कमेटी करेगी। कमेटी की सिफारिश आते ही योजना पर काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनावी घोषणापत्र में आप ने वकील कल्याण की बात की थी, आज उसे पूरा कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि 12 फरवरी को देशभर के वकीलों ने चिकित्सा सुविधा व पेंशन योजना को लेकर अदालतों में हड़ताल रखी थी। उसी दिन वकीलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात कर अपनी मांगे रखी थीं। इसके बाद सरकार के बजट में वकील वेलफेयर के लिए इस बजट का प्रावधान किया गया।

कमेटी में शामिल हैं ये सदस्य

- राकेश खन्ना (कमेटी संयोजक) अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन
- केसी मित्तल, चेयरमैन बार काउंसिल दिल्ली
- राहुल मेहरा, स्टैंडिंग काउंसल (क्रिमिनल) दिल्ली सरकार, हाई कोर्ट
- रमेश सिंह, स्टैंडिंग काउंसल (सिविल), दिल्ली सरकार, हाई कोर्ट
- मोहित माथुर, अध्यक्ष, दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन
- राजेश कौशिक, उपाध्यक्ष, द्वारका बार एसोसिएशन
- आरके बाधवा, अध्यक्ष नई दिल्ली बार एसोसिएशन, पटियाला हाउस कोर्ट
- एनसी गुप्ता, अध्यक्ष, दिल्ली बार एसोसिएशन, तीस हजारी कोर्ट
- हेमंत महला, उपाध्यक्ष साकेत बार एसोसिएशन
- प्रमोद नागर, अध्यक्ष शाहदरा बार एसोसिएशन कड़कड़डूमा कोर्ट
- राकेश चाहर, सचिव, रोहिणी बार एसोसिएशन
- कमल मेहता, वकील दिल्ली हाई कोर्ट
- अमिताभ चतुर्वेदी, अधिवक्ता दिल्ली हाई कोर्ट

मुख्य सचिव बताएं निर्भया फंड का महिला सुरक्षा के लिए कैसे हो इस्तेमाल : कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

हाई कोर्ट ने राजधानी में महिला एवं बाल सुरक्षा पर चिंता जताते शुक्रवार को मुख्य सचिव को यह जांचने का निर्देश दिया है कि निर्भया फंड का महिला सुरक्षा के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। 16 दिसंबर, 2012 को दिल्ली में एक छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के बाद 2013 में निर्भया फंड बनाया गया था। इसमें बहुत बड़ी रकम बेकार हो रही है और उसके सही इस्तेमाल का हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है।

हाई कोर्ट ने एक रिपोर्ट में पाया कि दिल्ली पुलिस में कर्मचारियों की कमी है। इस पर पीठ ने कहा कि दिल्ली के मुख्य सचिव स्थानीय पुलिस महानिदेशक पुनर्वास (डीजीआर) से सशस्त्र बलों और अन्य एजेंसियों के पूर्व सैनिकों को बल में शामिल कर स्थानीय पुलिस की सहायता करने के लिए मैनपावर पर विचार कर सकते हैं। न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी और अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने यह निर्देश मुख्य सचिव को दिए हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से पीठ को बताया गया कि निर्भया फंड में 2017 में 3200 करोड़ रुपये से अधिक रकम थी, जिसमें से करीब एक हजार करोड़ रुपये कुछ परियोजनाओं के लिए रखे गए थे।

इस दलील पर पीठ ने कहा, 'चूंकि फंड में बड़ी राशि उपलब्ध है, इसलिए हम यह निर्देश देते हैं कि मुख्य सचिव इस बात की जांच करेंगे कि शहर में महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस फंड का उपयोग कैसे किया जा सकता है। यह कवायद फंड के इस्तेमाल को भी सुनिश्चित करेगी, जो फिलहाल बेकार पड़ा हुआ है। इससे अनियंत्रित महिला और बाल विरुद्ध अपराध को रोकने में मदद मिलेगी। वहीं, दिल्ली सरकार के वकील ने पुलिस की तरफ से पीठ को बताया कि चार साल पहले विभाग में 61 हजार कर्मियों की कमी थी, जो फिलहाल 52 हजार के आस-पास है। पुलिस कर्मियों की ड्यूटी के घंटे अमानवीय हैं और वे बोझ से दबे हुए हैं। इस पर पीठ ने कहा कि दिल्ली पुलिस में कमी की फिर से जांच करें।

भारत-चीनी के बीच मालवाहक विमान सेवा शुरू

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

भारत-चीन के बीच कारोबारी संबंधों को बेहतर करने और कारोबार को बढ़ाने की कड़ी में आइजीआइ एयरपोर्ट से चीन के लिए मालवाहक विमान सेवा की शुरुआत की गई है। इसका संचालन हफ्ते में दो दिन किया जाएगा। एयरपोर्ट संचालक कंपनी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) ने इसे भारत-चीन कारोबार में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। अधिकारियों का कहना है कि पहले तक भारत से चीन के बीच कोई सीधी मालवाहक विमान सेवा नहीं थी। लिहाजा मालवाहक विमान अन्य देश से होते हुए चीन जाते और भारत आते थे। इसमें सामान भेजने में कई दिन लग जाते थे। लेकिन अब चंद घंटों में भारत-चीन के कारोबारी परस्पर सामान भेज व मंगा सकेंगे।

सिचुआन चीन की प्रमुख मालवाहक एयरलाइंस है। यह एयरलाइंस विश्व के 130 गंतव्यों के लिए उड़ान संचालित करती है। इस कंपनी ने पहली बार चीन से आइजीआइ की सीधी उड़ान सेवा शुरू की है। चीन के शांशी प्रांत से मालवाहक विमान एयरबस 330-200 का संचालन हफ्ते में दो बार किया जाएगा। इससे उत्तर भारत के उत्पाद चीन के बाजारों में तेजी से पहुंच सकेंगे व चीन से आयात होने वाली वस्तुएं भी जल्द मिल सकेंगी।

इस मौके पर डायल के सीइओ विदेह कुमार जयपुरिया ने कहा कि आइजीआइ एयरपोर्ट उत्तर भारत सहित अन्य पड़ोसी देशों से व्यवसाय के लिए कार्गो हब के रूप में उभरा है। उन्होंने बताया कि आइजीआइ एयरपोर्ट देश का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट है। यहां तीन रनवे और नौ फ्रेटर पार्किंग बे हैं। वहीं एयर कार्गो को संभालने के लिए दो अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल भी बनाए गए हैं। एयरसाइड में एयरपोर्ट कार्गो लॉजिस्टिक्स सेंटर का विकास भी कराया गया है। वहां सभी प्रकार के कार्गो जैसे कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, खराब होने वाले सामान, फार्मा व अन्य चीजों के रखे जाने की सुविधा है। इन सुविधाओं की वजह से एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन कम से कम समय में किया जा सकता है। सिचुआन एयरलाइंस सेल्स विभाग के प्रमुख एडवर्ड झोउ ने कहा कि कंपनी पहली बार भारत के लिए मालवाहक सेवा का संचालन शुरू कर रही है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और विकास में तेजी आएगी।

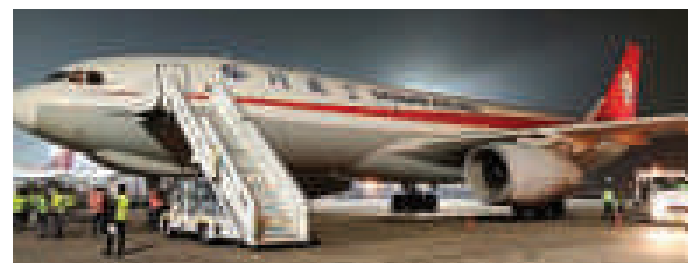

आइजीआइ एयरपोर्ट पर चीन से आया पहला मालवाहक विमान। सौ : डायल

बड़ा कदम

इन सीटू डेवलपमेंट के तहत केंद्र सरकार जल्द ही दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में 'जहां झुग्गी, वहां मकान' की नीति पर काम तेज करने जा रही है

अब भाजपा ने झुग्गियों पर खेला दांव

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

1731 अनधिकृत कॉलोनियों के नियमन और करीब दस लाख दुकानों को फ्री होल्ड करने की घोषणा के बाद अब केंद्र की भाजपा सरकार ने दिल्ली की झुग्गी बस्तियों पर दांव खेला है। इन सीटू डेवलपमेंट के तहत केंद्र सरकार जल्द ही दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में 'जहां झुग्गी वहां मकान' की नीति पर काम तेज करने जा रही है। शुक्रवार को ही दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने एक निजी एजेंसी सोसायटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस (एसपीवाइएम) को 160 झुग्गी बस्तियों के सर्वे का आदेश दिया है। इन झुग्गी बस्तियों में तकरीबन 85 हजार लोग रहते हैं। जल्द ही इसे लेकर केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं।

दिल्ली में केंद्र सरकार और डीडीए की जमीन पर लगभग 376 झुग्गी बस्तियां हैं, जिनमें 1.73 लाख लोग रहते हैं। यह झुग्गी बस्तियां करीब 40 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र को कवर किए हुए है। वर्ष 2022 तक राजधानी को झुग्गी मुक्त करने और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी को आवास देने के केंद्र सरकार के निर्देश के मद्देनजर डीडीए ने अपना काम तेज कर दिया है। डीडीए दिल्ली की इन कॉलोनियों में रहने वालों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए इन सीटू प्रोजेक्ट के तहत पुनर्विकास योजना शुरू करेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत योजना में डेवलपर ही झुग्गियों की जगह फ्लैट बनाने पर पूरा पैसा खर्च करेगा। इसके बदले वह खाली जमीन का उपयोग कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए करेगा।

अधिकारियों के मुताबिक 32 झुग्गी बस्तियों का सर्वे पहले ही पूरा हो चुका है और इनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दिलशाद गार्डन स्थित कलंदर कॉलोनी के लिए जल्द ही टेंडर निकाल दिए जाने की योजना है। इसके बाद उत्तरी बाहरी दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 18 और दक्षिणी दिल्ली में कुसुम पहाड़ी के पास बची झुग्गी बस्ती का टेंडर निकाला जाएगा। बाकी बची 184 झुग्गी बस्तियों के लिए भी जल्द ही किसी एजेंसी की नियुक्ति कर सर्वे शुरू कराया जाएगा। बताया जाता है कि इन सीटू प्रोजेक्ट के तहत बिल्डर खुली बोली लगा सकेंगे। प्रोजेक्ट की पात्रता दिल्ली शहरी आश्रय विकास बोर्ड (डूसिब) की दिसंबर 2017 पॉलिसी के अनुसार ही मान्य होगी। इसके लिए कटऑफ डेट एक जनवरी 2015 तय की गई है। इसके बाद सरकारी जमीन पर कोई झुग्गी न बने, यह डीडीए को सुनिश्चित करना होगा।

इस योजना के तहत जो फ्लैट दिया जाएगा। उसमें 30 वर्ग मीटर के मकान में दो कमरे, रसोईघर, स्नानघर और बालकनी होगी। इसमें दस साल का लॉकिंग पीरियड भी रहेगा। इससे पहले इन्हें बेचा नहीं जा सकेगा। बिल्डर को झुग्गीवासियों के लिए उसी जमीन पर या फिर 5 किमी के दायरे में रहने की वैकल्पिक व्यवस्था भी करानी होगी।

> इन सीटू डेवलपमेंट के तहत कोशिश यही की जा रही है कि 2022 तक सभी झुग्गियों की जगह पर पक्के मकान बना दिए जाएं। इससे यहां रहने वालों का जीवन स्तर भी बेहतर होगा और राजधानी के विकास को नया आयाम दिया जा सकेगा।
>
> -तरुण कपूर, उपाध्यक्ष, डीडीए

जेएनयू के छात्रों ने शास्त्री भवन के बाहर किया प्रदर्शन

जासं, नई दिल्ली : जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ की तरफ से शुक्रवार को जेएनयू के छात्रावास की फीस बढ़ोतरी के मामले में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के कार्यालय शास्त्री भवन पर प्रदर्शन किया गया। छात्र संघ के साथ संस्थान के कई छात्र भी मौजूद थे। इनकी मांग थी कि छात्रावास की फीस वृद्धि के मामले में जेएनयू में अकादमिक गतिविधि को बहाल करने के लिए एमएचआरडी द्वारा गठित की गई उच्चस्तरीय समिति ने मंत्रालय को जो अपनी रिपोर्ट जमा कराई है, उसे सार्वजनिक किया जाए। अपनी मांगों के लिए छात्र संघ अध्यक्ष आईशी घोष, उपाध्यक्ष साकेत मून, महासचिव सतीश चंद्र यादव एवं संयुक्त सचिव एम.दानिश ने एमएचआरडी के सचिव आर सुब्रमण्यम से भेंट की और अपनी मांगों के जुड़ा ज्ञापन सौंपा। छात्र संघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि उन्हें सचिव ने जानकारी दी है कि छात्रों की मांगों पर मंत्रालय की नजर है, लेकिन रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। इस मामले में एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक छात्रों से आने वाले समय में मुलाकात करेंगे।

पराली संकट के स्थायी समाधान के लिए सरकार बना रही नीति

- आइसीएआर के विशेषज्ञों की एक समिति का किया गया गठन
- सरकार ने 1,151 करोड़ की मशीनें किसानों को पराली प्रबंधन के लिए दी हैं

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में पराली जलाने की समस्या के स्थायी समाधान के लिए नीति बना रही है। इस सिलसिले में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर) के विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने शुक्रवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि आइसीएआर के सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है। नई नीति के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया है। यह समिति एक-दो महीने में अपनी रिपोर्ट दे देगी।

रुपाला ने कहा कि पराली जलाने से रोकने के एवज में नुकसान की भरपायी के लिए मुआवजा देने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान किसान अगले फसल की बुआई से पहले खेत खाली करने के लिए पराली जलाते हैं। सरकार उन्हें फसलों की विविधता के बारे में प्रशिक्षित करने की योजना बना रही है।

रुपाला ने कहा कि सरकार ने 1,151 करोड़ रुपये की मशीनें किसानों को पराली प्रबंधन के लिए दी हैं। 55,000 मशीनें तीन राज्यों के किसानों को दी गई हैं। इसके अलावा उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है।

पराली जलाने से मिट्टी की उत्पादन क्षमता कम होने की जानकारी देते हुए रुपाला ने बताया, 'यह अनुमान लगाया गया है कि एक टन धान की पराली में लगभग 5.5 किग्रा नाइट्रोजन, 2.3 किग्रा फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, 25 किग्रा पोटेशियम ऑक्साइड, 1.2 किग्रा सल्फर, 50 से 70 फीसद सूक्ष्म पोषक तत्व और 400 किग्रा कार्बन होता है। ये तत्व पराली जलाने के कारण नष्ट हो जाते हैं। साथ ही मिट्टी के तापमान, पीएच, नमी आदि के कारण मिट्टी की उत्पादन क्षमता भी प्रभावित होती है।

4852 बंकर हैं जम्मू कश्मीर के सीमांत जिलों में, इनमें 4,478 निजी और 374 सामुदायिक बंकर हैं। ग्रामीणों को सीमा पार से होने वाली गोलाबारी से बचाने के लिए ये बंकर बनाए गए हैं।

सिद्दरमैया, कुमारस्वामी समेत कई के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज

बेंगलुरु, प्रेट्र : कर्नाटक पुलिस ने राज्य के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों सिद्दरमैया और एचडी कुमारस्वामी, बेंगलुरु के तत्कालीन पुलिस आयुक्त टी. सुनील कुमार, उनके अधीनस्थ पुलिसकर्मियों और कांग्रेस व जद (एस) के कुछ नेताओं के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया है। यह मामला लोकसभा चुनावों के दौरान की गई आयकर छापेमारी का विरोध करने के लिए दर्ज किया गया है। कांग्रेस ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया है।

सामाजिक कार्यकर्ता मल्लिकार्जुन ए. की शिकायत पर बेंगलुरु की एक अदालत ने हाल ही में कमर्शियल स्ट्रीट पुलिस को आपराधिक साजिश रचने और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के प्रयास करने सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था।

यह मामला कांग्रेस और जद (एस) नेताओं के आवास पर मारे गए आयकर छापे के विरोध में यहां आयकर कार्यालय के पास तत्कालीन मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी सहित अन्य नेताओं की ओर से किए गए विरोध प्रदर्शनों से संबंधित है। आरोप है कि कुमारस्वामी ने छापेमारी की जानकारी होने के बाद लोगों को संभावित कार्रवाई की सूचना दी थी। कुमारस्वामी ने 27 मार्च को मीडिया से कहा था कि छापे मारे जा सकते हैं क्योंकि बड़ी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बल केंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (केआइए) पर पहुंच चुका है। उनका संदेह अगले ही दिन सही साबित हुआ जब सुरक्षा बल राज्य के विभिन्न हिस्सों में फैल गए। बाद में आयकर कार्यालय में व्यापक प्रदर्शन किया गया।

जिन अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उनमें तत्कालीन उपमुख्यमंत्री जी परमेश्वर, डीके शिवकुमार, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश गुंडु राव, तत्कालीन पुलिस उपायुक्त राहुल कुमार और डी देवराजू के अलावा सभी निर्वाचन अधिकारी भी शामिल हैं।

दोनों नेताओं ने कर्नाटक में आयकर छापेमारी का किया था विरोध

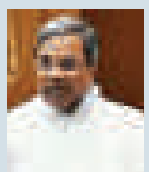

सिद्दरमैया कुमारस्वामी (फाइल)

शिवकुमार ने कहा-हम जेल जाने को तैयार

राजद्रोह के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए

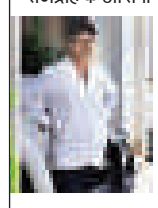

कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने कहा कि वह जेल जाने के लिए तैयार हैं। सभी मामले राजनीति से प्रेरित हैं और वह राजनीतिक तरीके से ही इनका जवाब देंगे। शिवकुमार ने कहा, 'हम आयकर कार्यालय के भीतर नहीं गए थे। हम 150 मीटर दूर खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे।'

जाति के नाम पर वोट मांगने पर मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के खिलाफ एफआइआर

बेंगलुरु, आइएएनएस : कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ जाति के नाम पर वोट मांगने के आरोप में दो एफआइआर दर्ज कराई गई है। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी (व्यय पर्यवेक्षक) प्रियंका मैरी फ्रांसिस ने एक बयान में कहा है, 'कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने 23 नवंबर को कागवाड विधानसभा क्षेत्र के गोकाक और शिरुप्पी गांव में अपने भाषण में कथित रूप से जाति के नाम पर वोट मांगे थे। इस मामले की जांच की गई है।' उन्होंने कहा कि दोनों जगह दिए गए भाषणों को लेकर एफआइआर दर्ज करा दी गई है। चुनाव आयोग ने छह चेक पोस्ट कर्मचारियों पर 20 नवंबर को गृह मंत्री बासवराज बोम्मई के वाहन की जांच नहीं करने का आरोप लगाया है। आयोग ने चेक पोस्ट के दो कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। गृह मंत्री के वाहन चालक के खिलाफ मद्दुर थाने में एफआइआर दर्ज करा दी गई है। चालक पर चेक पोस्ट कर्मियों का सहयोग नहीं करने का आरोप है। मुख्यमंत्री के सांसद बेटे बीवाई राघवेंद्र के वाहन की जांच नहीं करने के आरोप में चुनाव आयोग ने अपने चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। राज्य में 15 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए पांच दिसंबर को मतदान कराए जाएंगे।

देश में डॉक्टरों की कोई कमी नहीं : हर्षवर्धन

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश में डॉक्टरों की कमी नहीं है। उन्हें विदेश जाने से रोकने के लिए समुचित कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि, सरकार के पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है, जिसके जरिये डॉक्टरों को विदेश जाने से बलपूर्वक रोका जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लोकसभा में गुरुवार को यह जानकारी दी।

प्रश्नकाल के दौरान हर्षवर्धन ने कहा कि डॉक्टरों व नर्सों को आजीविका के लिए विदेश जाने से रोकने की दिशा में सरकार समुचित कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में स्थित केंद्र सरकार के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को लेकर सरकार ने कोई विशेष अध्ययन नहीं कराया है। हालांकि, डॉक्टरों व नर्सों के खाली पदों की समय-समय पर समीक्षा और जरूरत के अनुसार भर्ती भी की जाती है। मंत्री ने कहा कि सरकार ने इन अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं।

हर्षवर्धन ने बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की संस्तुति के आधार पर रिक्त पदों के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करता है। कंबाइंड मेडिकल ऑफिसर सर्विस एक्जामिनेशन नामक इस परीक्षा का आयोजन केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के जीडीएमओ सब कैडर में मेडिकल ऑफिसर की तैनाती के लिए किया जाता है।

शिक्षक के पद पर विशेष डॉक्टरों, गैर शैक्षणिक और केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के पब्लिक हेल्थ सब कैडर के पदों पर नियुक्ति के लिए यूपीएससी साक्षात्कार का भी आयोजन करता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई बार संबंधित इकाई यूपीएससी की संस्तुति के अनुरूप अनुबंध के आधार पर भी डॉक्टरों की तैनाती करते हैं।

- केंद्रीय मंत्री ने कहा, डॉक्टरों व नर्सों को विदेश जाने से रोकने के लिए उठाए जा रहे समुचित कदम

लोकसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान जवाब देते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन। प्रेट्र

पोर्नोग्राफी रोकने के लिए समूह बनाकर चर्चा करें सांसद : वेंकैया नायडू

नई दिल्ली, प्रेट्र : राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को कहा कि सांसदों को एक समूह बनाकर सोशल मीडिया और अन्य इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर पोर्नोग्राफी रोकने के लिए ठोस सुझाव देना चाहिए। गुरुवार को अन्नाद्रमुक सांसद विजिला सत्यानंद द्वारा राज्यसभा में उठाए गए मुद्दे का जिक्र करते हुए नायडू ने कहा कि कुछ वरिष्ठ सांसद जैसे- जयराम रमेश (कांग्रेस), विनय सहस्रबुद्धे (भाजपा), सुखेंदु शेखर रॉय (तृणमूल कांग्रेस), तिरुचि शिवा (द्रमुक) और कुछ अन्य लोग अपनी ओर से पहल कर सकते हैं। ये लोग एक समूह बनाकर पोर्नोग्राफी, सोशल मीडिया और बच्चों पर उसके प्रभाव पर चर्चा कर सकते हैं।

नायडू ने कहा कि यह बहुत गंभीर मसला है। सदस्यों को कुछ ठोस सुझावों के साथ आना होगा, ताकि मैं संचार मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री को सलाह दे सकूं।

शून्यकाल के दौरान सत्यानंद ने कहा था कि मोबाइल फोन और इंटरनेट पर बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री तक आसानी से पहुंच होने की वजह से बाल उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं। इस पर महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा था कि 377 वेबसाइटों को बंद कर दिया गया है और 50 प्राथमिकी दर्ज की गई है।

भारत के खिलाफ कोई काम नहीं : राजपक्षे

मजबूत हुए रिश्ते ▸ भारत का श्रीलंका को 45 करोड़ डॉलर की मदद का एलान

पीएम मोदी व श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे के बीच वार्ता

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

गोतबाया राजपक्षे के राष्ट्रपति बनने के साथ भारत में पड़ोसी देश श्रीलंका की नई सरकार को लेकर जो चिंता बनी थी वह शुक्रवार को काफी हद तक समाप्त हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नई दिल्ली में एक घंटे तक अकेले में हुई मुलाकात और उसके बाद दोनों नेताओं की अध्यक्षता में हुई प्रतिनिधि स्तर की वार्ता के दौरान राष्ट्रपति गोतबाया ने यह आश्वासन देने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि किसी भी तीसरे देश को श्रीलंका-भारत के रिश्तों के बीच में नहीं आने दिया जाएगा।

भारत ने भी इस बेहद महत्वपूर्ण पड़ोसी देश की नई सरकार का दिल जीतने में कोई कमी नहीं की। पीएम मोदी ने श्रीलंका को 45 करोड़ डॉलर (तकरीबन 3225 करोड़ रुपये) के बराबर मदद देने का एलान किया।

- इसमें पांच करोड़ डॉलर की रकम आतंकवाद से लड़ने के लिए
- भारतीय मछुआरों की पकड़ी गई सारी नौकाएं लौटाएगा श्रीलंका
- मोदी ने पड़ोसी देश में तेज विकास के लिए दिया हरसंभव भरोसा

नई दिल्ली में शुक्रवार को हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे के साथ बैठक की। एएनआइ

राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे गुरुवार को देर शाम नई दिल्ली पहुंचे। शुक्रवार को उनका राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया गया। उसके बाद हैदराबाद हाउस में उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत हुई। बातचीत का मुद्दा मुख्य तौर पर आर्थिक, सामरिक व सामाजिक द्विपक्षीय सहयोग पर केंद्रित रहे। श्रीलंका को लेकर भारत की सोच पीएम मोदी ने इन शब्दों में साफ कर दी, 'एक मजबूत व स्थाई श्रीलंका सिर्फ भारत के हित में ही नहीं बल्कि समूचे हिंद महासागर क्षेत्र के हित में जरूरी है।' लेकिन पीएम मोदी ने तमिल लोगों की स्थिति का भी जिक्र किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि राजपक्षे की नई सरकार तमिल लोगों की उम्मीदों को भी पूरा करेगी। इस पर राजपक्षे ने आश्वस्त किया कि वह श्रीलंका के हर नागरिक के राष्ट्रपति हैं चाहे वह किसी भी धर्म का हो या चाहे वह किसी को भी वोट देता हो। उन्होंने उत्तरी व पूर्वी श्रीलंका के विकास में खास तौर पर भारत की मदद मांगी। राजपक्षे ने पूर्व में भारतीय मछुआरों की पकड़ी गई सभी नौकाओं को लौटाने का भी एलान किया। यह बहुत दिनों से लंबित मामला था जिस पर पूर्ववर्ती भारत समर्थक सिरीसेना सरकार भी फैसला नहीं कर पा रही थी। इस मौके पर राजपक्षे ने प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका आने का निमंत्रण दिया। उनके श्रीलंका का राष्ट्रपति बनने के बाद से उन्होंने पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है।

राजपक्षे ने दृढ़ता से कहा कि भारत उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी और किसी भी तीसरी ताकत को भारत के साथ सहयोग में आड़े नहीं आने दिया जाएगा। अभी तक चीन का समर्थक माने जाने वाले राजपक्षे से मिले इस आश्वासन से भारतीय रणनीतिकारों को निश्चित तौर पर काफी राहत मिलेगी। भारत ने कुल 45 करोड़ डॉलर की मदद देने का एलान किया है। इसमें से 40 करोड़ डॉलर बतौर ढांचागत व विकास परियोजनाओं व सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए और पांच करोड़ डॉलर आतंकवाद से लड़ने में मदद के तौर पर दिए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता में आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा रहा। सनद रहे कि अप्रैल, 2019 में श्रीलंका में कई स्थानों पर विस्फोट हुआ था जिसमें 250 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें जिस आतंकी संगठन को जिम्मेदार ठहराया गया था उसके तार भारत से जुड़े थे। यही वजह है कि भारत अपने इस पड़ोसी देश को आतंक के खिलाफ लड़ाई में भरपूर मदद दे रहा है।

एसआइटी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की सिख विरोधी दंगों की रिपोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

1984 के सिख विरोधी दंगों के बंद किए जा चुके 186 मामलों की पुनः जांच करके एसआइटी ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल कर दी है। शुक्रवार को केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद ने सील बंद लिफाफे में एसआइटी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी। इसके साथ ही आनंद ने कोर्ट से इन मामलों की जांच कर रही एसआइटी को भी भंग करने की इजाजत मांगी। कोर्ट मामले पर दो सप्ताह बाद विचार करेगा।

केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में 1984 दंगों की समीक्षा के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआइटी) ने कुल 293 मामलों की जांच की थी, जिसमें से 186 को बंद कर दिया था। एसआइटी द्वारा मामले बंद किए जाने की सिफारिश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश एसएन धींगरा की अध्यक्षता में एसआइटी का गठन किया था, जिसे इन 186 मामलों की पुनः जांच सौंपी गई थी। कोर्ट ने तीन सदस्यीय एसआइटी का गठन किया था, जिसमें जस्टिस धींगरा के अलावा सेवानिवृत आइपीएस अधिकारी राजदीप सिंह और वर्तमान आइपीएस अभिषेक दुलार शामिल थे। राजदीप सिंह ने निजी कारणों से एसआइटी में शामिल होने से मना कर दिया था। इसके बाद दो सदस्यीय एसआइटी ने मामलों की जांच कर रिपोर्ट दी है।

शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, बीआर गवई और सूर्यकांत की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश एएसजी पिंकी आनंद ने कोर्ट द्वारा गठित एसआइटी की रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में सौंपते हुए कहा कि इसे फिलहाल याचिकाकर्ताओं के साथ साझा न किया जाए। इसके साथ ही पिंकी आनंद ने कहा कि एसआइटी का काम खत्म हो गया है और अब इसे भंग कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने आइपीएस अभिषेक दुलार को मूल कैडर में भेजे जाने की इजाजत मांगी। लेकिन याचिकाकर्ता पीड़ितों की ओर से पेश वकील एचएस फूलका ने कोर्ट से कहा कि कोर्ट को पहले दाखिल की गई एसआइटी रिपोर्ट देखनी चाहिए कि टीम को कुछ और तो नहीं करना है। इसके बाद ही कोर्ट को एसआइटी भंग करने पर फैसला करना चाहिए। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद एसआइटी रिपोर्ट को रिकार्ड पर लेते हुए मामले को दो सप्ताह बाद फिर सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया।

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिख विरोधी दंगा भड़का था, जिसमें लगभग तीन हजार लोगों की जान गई थी। मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद एसआइटी गठित कर दंगों के मामलों की समीक्षा कराई थी।

- बंद किए जा चुके 186 मामलों की फिर से की गई जांच
- सरकार ने एसआइटी को भंग करने की मांगी इजाजत

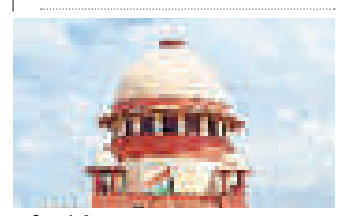

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

सुप्रीम कोर्ट का नया रोस्टर, सीजेआइ व तीन जज करेंगे पीआइएल पर सुनवाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों के कामकाज का नया रोस्टर जारी किया है। इसके मुताबिक जनहित याचिकाओं पर प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे और तीन अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश सुनवाई करेंगे। यह रोस्टर 26 नवंबर से प्रभावी हो गया है। जनहित याचिकाओं (पीआइएल) पर प्रधान न्यायाधीश के अलावा जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस अरुण मिश्र और जस्टिस आरएफ नरीमन सुनवाई करेंगे। नया रोस्टर पुराने से कुछ अलग है। पुराने रोस्टर के मुताबिक जनहित याचिकाओं पर तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई समेत पांच जज सुनवाई करते थे।

सीजेआइ बोबडे ने पीआइएल के अलावा मानहानि, चुनाव, बंदी प्रत्यक्षीकरण, सामाजिक न्याय, प्रत्यक्ष और परोक्ष कर मामलों को अपने पास रखा है। इसके अलावा आपराधिक मामलों और जांच आयोग, कंपनी कानून, सेबी, रिजर्व बैंक से जुड़े मामलों पर भी सुनवाई करेंगे।

जस्टिस रमना की अगुआई वाली पीठ सशस्त्र और अर्धसैनिक बलों, मुआवजा, आपराधिक व सामान्य नागरिकों मामलों और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला जजों के न्यायिक अधिकारियों से जुड़े मामलों इत्यादि पर सुनवाई करेंगे। जस्टिस अरुण मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ भूमि अधिग्रहण, मेडिकल कॉलेजों में दाखिले में आरक्षण संबंधी मामलों इत्यादि को देखेगी। जबकि, जस्टिस नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ सशस्त्र और अर्धसैनिक बलों से जुड़े पारिवारिक कानून, सरकार व स्थानीय निकायों से जुड़े लीज और कांट्रैक्ट के मामलों पर सुनवाई करेगी। इसी तरह, जस्टिस आर भानुमति की अगुआई वाली पीठ श्रम, किराया कानून, भू कानून और कृषि संबंधी मामलों पर सुनवाई करेगी।

बता दें कि प्रधान न्यायाधीश बोबडे के अलावा जस्टिस रमना, जस्टिस मिश्र, जस्टिस नरीमन और जस्टिस भानुमति सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम का हिस्सा हैं। उल्लेखनीय है कि रोस्टर प्रणाली को लेकर ही जस्टिस रंजन गोगोई समेत चार वरिष्ठ न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। रंजन गोगोई बाद में देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआइ) बने। वह 17 नवंबर को ही सेवानिवृत्त हुए हैं।

- पुराने रोस्टर में सीजेआइ समेत पांच जज करते थे पीआइएल पर सुनवाई

एसए बोबडे फाइल फोटो

भारत, जापान के बीच टू-प्लस-टू वार्ता का फोकस समुद्री संबंध बढ़ाना होगा

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत और जापान के बीच यहां शनिवार को होने वाली पहली टू-प्लस-टू वार्ता का मुख्य फोकस हिंद-प्रशांत क्षेत्र समेत सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जलक्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना होगा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे, जबकि जापान की ओर से विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और रक्षा मंत्री तारो कोनो प्रतिनिधित्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और जापान के बीच होने वाली टू-प्लस-टू बैठक से दोनों पक्ष रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की समीक्षा और विचारों का आदान-प्रदान कर सकेंगे। भारत एवं जापान के बीच पिछले साल हुए 13वें वार्षिक शिखर बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष एबी शिंजो के फैसले के बाद नए ढांचे के तहत वार्ता हो रही है। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग को और मजबूती देने तथा विशेष सामरिक एवं वैश्विक भागीदारी में प्रगाढ़ता लाने के उद्देश्य से नई व्यवस्था शुरू करने का फैसला किया।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष क्षेत्र में शांति, समृद्धि एवं प्रगति के लिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिति तथा भारत की 'एक्ट ईस्ट नीति' एवं जापान की 'फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक विजन' के तहत अपने प्रयासों पर चर्चा करेंगे।

फास्टैग की तिथि 15 दिसंबर तक बढ़ी, फिलहाल नहीं लगेगा जुर्माना

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

घोषणा के बावजूद एनएचएआइ के विफल रहने के कारण सरकार ने फास्टैग की अनिवार्यता की तारीख को 15 दिनों तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब बिना फास्टैग वाहनों के फास्टैग लेन में प्रवेश पर 15 दिसंबर तक कोई जुर्माना नहीं वसूला जाएगा। इसके साथ ही एनएचएआइ के बूथ पर फास्टैग मुफ्त मिलेगा। पहले एक दिसंबर के बाद फास्टैग लेन में प्रवेश करने वाले बिना फास्टैग लगे वाहनों से दोगुना टोल वसूलने का प्रावधान किया गया था। यह फैसला सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की एनएचएआइ के अफसरों के साथ हुई समीक्षा बैठक के बाद लिया गया है। बैठक में गडकरी ने वादे के अनुसार, लोगों को समय पर फास्टैग मुहैया न करा पाने के लिए एनएचएआइ अफसरों की जमकर क्लास लगाई।

आधी-अधूरी तैयारी : सूत्रों के अनुसार एनएचएआइ अफसर पिछले कई महीनों से फास्टैग की तैयारियों के बारे में सड़क मंत्रालय को गलत जानकारियां दे रहे थे। वे लगातार सब कुछ दुरुस्त होने का भरोसा दे रहे थे। और इसी आधार पर गडकरी ने 22 नवंबर की प्रेस कांफ्रेंस में फास्टैग को एक दिसंबर तक मुफ्त उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। लेकिन मंत्री की घोषणा के अनुरूप एनएचएआइ वादा निभाने में विफल रही। एनएचएआइ के भरोसे पर ही गडकरी ने एक दिसंबर तक एनएचएआइ के तमाम पीओएस पर मुफ्त फास्टैग मिलने की घोषणा कर दी थी, पर एनएचएआइ एक भी पीओएस पर मुफ्त फास्टैग उपलब्ध नहीं करा सकी। जिन स्थानों पर मुफ्त फास्टैग के कियॉस्क लगाए गए थे वे भी उठा लिए गए।

बैंकों में भी दिक्कत : यही नहीं, जिन बैंकों और पेटीएम के साथ एनएचएआइ की सब्सिडियरी इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने करार किया है, वे भी फास्टैग की अचानक पैदा हुई मांग से निपटने में खुद को असमर्थ पा रहे थे। नतीजतन, टोल प्लाजा से लेकर बैंक शाखाओं तक कतारें लगी हुई थीं और लोग एनएचएआइ को कोस रहे थे।

लोगों की शिकायत : कई लोगों की शिकायत है कि बैंक वाले फास्टैग लेने के लिए खाता खुलवाने पर जोर डाल रहे हैं। यह दिक्कत उन ग्राहकों के साथ है जो नजदीक होने के कारण दूसरे बैंकों की शाखाओं में फास्टैग लेने जा रहे हैं या जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया है। दूसरी दिक्कत कागजी कार्यवाही की है जिसमें समय लगता है। ऑनलाइन आवेदकों को भी एक हफ्ते बाद ही फास्टैग मिलने की उम्मीद है।

कीमत को लेकर भ्रम : ज्यादातर ग्राहकों को भ्रम है कि उन्हें हर जगह मुफ्त में फास्टैग मिलेगा। इसलिए जिन पीओएस पर उनसे पैसे लिए जा रहे हैं वे उसकी शिकायत कर रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिये गुस्से का इजहार कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो 22 नवंबर से पहले मुफ्त फास्टैग न मिलने की शिकायत भी की है, जबकि एनएचएआइ को छोड़ बाकी सभी पीओएस फास्टैग की पूरी कीमत लेने को स्वतंत्र हैं। जब तक प्रबंधन इसे मुफ्त उपलब्ध कराने का निर्णय न ले ले तब तक वे ऐसा कर सकते हैं। कुछ बैंक टैग का पैसा नहीं ले रहे मगर अलग-अलग सिक्यूरिटी डिपाजिट और रिचार्ज रकम वसूल रहे हैं। लोगों की मांग है कि एनएचएआइ को डिलीवरी चार्ज छोड़ फास्टैग को पूरी तरह मुफ्त में उपलब्ध कराना चाहिए।

तकनीकी झमेले : लोगों की शिकायत है कि एनएचएआइ और बैंकों के पीओएस पर फास्टैग मिलने में तकनीकी अड़चनों के कारण भी विलंब होता है। यहां तक कि खुद एनएचएआइ और सड़क मंत्रालय के अफसरों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। एनएचएआइ ने आम लोगों को फास्टैग इश्यू करने के लिए ट्रांसपोर्ट भवन के प्रवेश द्वार पर दो कर्मचारियों के साथ अपना पीओएस स्थापित किया था।

- फास्टैग पर बैठक में गडकरी ने एनएचएआइ अफसरों की क्लास ली
- फास्टैग से जुड़ी तकनीकी अड़चनों से जूझ रहा है एनएचएआइ

सरकार से जुड़ी 'फेक न्यूज' पर अंकुश लगाएगा पीआइबी

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार के मंत्रालयों, विभागों व योजनाओं से संबंधित फेक न्यूज (फर्जी खबर) पर अंकुश लगाने के लिए प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (पीआइबी) ने विशेष इकाई का गठन किया है, जो तथ्यों की जांच करेगी। मंत्रालय ने लोगों से आग्रह किया कि वे किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध संदिग्ध सामग्री की तस्वीर ईमेल करें। तथ्यों की जांच होगी।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, 'खबरें जो सच नहीं हैं... खबरें जो भ्रामक हो सकती हैं... इन खबरों को आगे भेजने से पहले इनसे जुड़े सच को जानिए। आप इन्हें हमारे पास भेजें। हम आपके लिए इसकी जांच करेंगे और आपसे कोई सवाल भी नहीं पूछेंगे।' पीआइबी फैक्ट चेक हैशटैग के साथ मंत्रालय ने ट्वीट किया, 'सभी को संदेह होता है कि वाट्सएप पर आगे बढ़ाया गया संदेश सच है या सिर्फ फेक न्यूज? ट्वीट या फेसबुक पोस्ट वास्तविक हैं? अब इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है।' स्पष्ट किया गया है कि केवल सरकार के मंत्रालय, विभाग और योजनाओं से संबंधित सूचना सामग्री की ही जांच की जाएगी।

ज्ञात हो, सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर फेक न्यूज पर रोक लगाने की बात करते रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ये पेड न्यूज से ज्यादा खतरनाक हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया व न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन से इस पर अंकुश के लिए तंत्र विकसित करने को कह चुके हैं।

सारधा घोटाला

सारधा चिटफंड कंपनी ने लाखों लोगों को ज्यादा लाभ का भरोसा लेकर करोड़ों रुपये निवेश कराए, कंपनी पर आरोप है कि उसने ग्राहकों के करीब ढाई हजार करोड़ रुपये डकार लिए

सीबीआइ की याचिका पर राजीव कुमार को नोटिस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने सारधा चिटफंड घोटाले में साक्ष्यों से छेड़छाड़ के आरोपित कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार की अग्रिम जमानत रद करने की सीबीआइ की मांग पर उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने सीबीआइ से भी कहा कि उसे कोर्ट को संतुष्ट करना पड़ेगा कि हिरासत क्यों जरूरी है।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायाधीश बीआर गवई और सूर्यकांत की पीठ ने सीबीआइ की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, उन्हें कोर्ट को समझाना पड़ेगा कि राजीव कुमार की हिरासत क्यों जरूरी है। कोर्ट के सामने विचार का यही एक मुद्दा है क्योंकि वह एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। मेहता ने कहा कि राजीव कुमार काफी समय तक भागते रहे। जब वह मामले की जांच कर रहे थे, उस दौरान एकत्र की गई कुछ सामग्री उन्होंने सीबीआइ को नहीं उपलब्ध कराई है। सारधा कंपनी ने लाखों लोगों को ज्यादा लाभ का भरोसा लेकर करोड़ों रुपये निवेश कराए थे। इसमें करीब ढाई हजार करोड़ के घोटाले का आरोप है। इस घोटाले की जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरुआत में एक एसआइटी बनाई थी जिसमें राजीव कुमार भी शामिल थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सारधा घोटाले से जुड़े सारे मामलों की जांच सीबीआइ को सौंप दी थी। सीबीआइ का आरोप है कि राजीव कुमार ने एसआइटी टीम के तौर पर की गई जांच में एकत्रित पूरे साक्ष्य सीबीआइ को मुहैया नहीं कराए हैं। सीबीआइ ने उन पर साक्ष्यों को नष्ट करने का आरोप लगाया है।

सीबीआइ राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है। इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने गत एक अक्टूबर को राजीव कुमार को अग्रिम जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने राजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करते हुए अपने आदेश में कहा था कि कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है वह जांच में सहयोग कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर इस केस के सिलसिले में राजीव कुमार को गिरफ्तार किया जाता है तो संबंधित अदालत पचास-पचास हजार के दो जमानती बांड पेश करने पर तत्काल प्रभाव से उन्हें रिहा करेगी। हाईकोर्ट ने आदेश में यह भी कहा था कि सीबीआइ के 48 घंटे पहले दिए गए नोटिस पर राजीव कुमार पूछताछ के लिए जांच अधिकारी के सामने पेश होंगे और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। सीबीआइ ने हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सीबीआइ का कहना है कि राजीव कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं इसलिए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है। राजीव कुमार इस समय पश्चिम बंगाल में क्रिमिनल इंवेस्टीगेशन डिपार्टमेंटस में एडीशनल डीजी हैं।

- जांच एजेंसी की कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त की अग्रिम जमानत रद करने की मांग
- जांच के दस्तावेज न देने वाले राजीव कुमार काफी समय तक भागते रहे

राजीव कुमार फाइल फोटो

बदलेगा साठ साल पुराना आर्म्स एक्ट, लोकसभा में बिल पेश

नई दिल्ली, प्रेट्र : साठ साल पुराने आर्म्स एक्ट में संशोधन के लिए लोकसभा में विधेयक पेश किया गया है। इसमें अवैध तरीके से प्रतिबंधित हथियार रखने और बनाने के लिए सजा बढ़ाने का प्रस्ताव है। साथ ही आर्म्स (संशोधन) विधेयक में किए गए प्रावधान के अनुसार एक व्यक्ति अधिकतम दो

288 सदस्यीय महाराष्ट्र की विधानसभा में शिवसेना के 56, राकांपा के 54 और कांग्रेस के 44 विधायक हैं। इसके अलावा गठबंधन को कुछ छोटे दलों और निर्दलियों का समर्थन भी हासिल है। इसलिए सरकार के आसानी से बहुमत साबित करने की संभावना है। भाजपा के 105 विधायक हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 30 नवंबर 2019

मुंबई में शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभालने के मौके पर छत्रपति शिवाजी की तस्वीर को नमन करते उद्धव ठाकरे। प्रेट्र

शिवसेना के लिए नया नहीं है 'सेक्युलरिज्म'

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई

- मंदिर आंदोलन की शुरुआत पर धारण किया था कट्टर हिंदुत्व का भगवा चोला
- कांग्रेस और राकांपा के साथ गठबंधन के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सेक्युलर मूल्यों को स्वीकारा

महाराष्ट्र में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के साथ साझा सरकार बनाने के लिए 'सेक्युलरिज्म' (धर्मनिरपेक्षता) को स्वीकार करने वाली उद्धव ठाकरे की शिवसेना को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, सच्चाई यह है कि उद्धव की शिवसेना ही सेक्युलर नहीं हुई है। उनके पिता बालासाहब ठाकरे की शिवसेना भी सेक्युलर रह चुकी है। देश में रामजन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत होने के बाद भाजपा के साथ उसने हिंदुत्व का भगवा चोला धारण किया। अब अयोध्या पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ जैसे ही हिंदुत्व की राजनीति के पटाक्षेप का संकेत मिला, वह अपने उसी पुराने ढर्रे पर आ गई जिस पर कभी उद्धव के पिता बाल ठाकरे भी चल चुके थे।

शिवसेना की इस पुरानी पहचान की पुष्टि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नवाब मलिक के इस बयान से भी होती है कि शिवसेना का जन्म सांप्रदायिक राजनीति के लिए नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की जनता की सेवा के लिए हुआ था।

पिछली सदी के सातवें दशक में संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में सक्रिय रहे उद्धव ठाकरे के दादा प्रबोधनकार ठाकरे समाजवादी विचारधारा के पोषक माने जाते थे। इस आंदोलन में लगभग सभी विचारों के लोग एक साथ थे और कोई किसी के लिए अस्पृश्य नहीं था। 1966 में जब शिवसेना का गठन क्षेत्रीय लोगों को नौकरियों में न्याय दिलाने के लिए हुआ, उस समय न तो हिंदुत्व कोई मुद्दा था और न तत्कालीन हिंदुत्ववादी पार्टियों जनसंघ व हिंदू महासभा से शिवसेना का कोई नाता था। बल्कि तत्कालीन कांग्रेसी मुख्यमंत्री वसंतराव नाइक ने जब मुंबई की कम्युनिस्ट यूनियनों को कमजोर करने के लिए शिवसेना को समर्थन देना शुरू किया तो लोग व्यंग्यबोध में शिवसेना को 'वसंतसेना' भी कहने लग गए थे। आपातकाल के दौरान भी जब देशभर के नेता जेलों में इंदिरा गांधी को परास्त करने की रणनीति बना रहे थे, तब शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे ने आपातकाल की तारीफ की थी।

हिंदुत्व पर जोर तो उन्होंने 1985 में अयोध्या आंदोलन के उभार के साथ देना शुरू किया। जनमानस के रुझान को देखते हुए उन्होंने राजनीति में अपने उभार के लिए न सिर्फ भाजपा से हाथ मिलाना बेहतर समझा, बल्कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा दिया गया नारा 'गर्व से कहो हम हिंदू हैं' भी भाजपा से पहले अपना लिया। उसके बाद ही ठाकरे ने भगवा कुर्ता, भगवा शॉल और हाथ में रुद्राक्ष की माला भी धारण करनी शुरू कर दी थी। इसका सुफल भी खूब मिला। 10 वर्ष के अंदर ही भाजपा का बड़ा भाई बनकर शिवसेना 1995 में महाराष्ट्र में अपना मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब हुई। यह सच है कि अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने के बाद उसका श्रेय लेने और उसके बाद अलग-अलग मसलों पर शिवसैनिकों की भूमिका ने मुंबई सहित देश के हिंदुओं का दिल जीतने में बड़ी भूमिका निभाई। उसके बाद तो बाल ठाकरे हिंदुत्व की राजनीति के हिमालय बन चुके थे। यहां तक कि 2011 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब तीन दिन का सद्भावना उपवास रखा तो ठाकरे उन्हें कट्टर हिंदुत्व की राह से नहीं डिगने की सीख देते हुए भी नजर आए थे, लेकिन उन्हीं ठाकरे की शिवसेना का वह रूप भी सामने आ चुका है जिसमें कांग्रेस-राकांपा के साथ बनी उसकी सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सेक्युलर मूल्यों से नहीं डिगने की बात कही जा रही है। नए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे संविधान के नाम पर इन मूल्यों पर अडिग रहने की प्रतिबद्धता भी दिखा रहे हैं। 24 नवंबर को अयोध्या जाने का उनका कार्यक्रम रद किया जा चुका है। माना जा रहा है कि उनके शपथ ग्रहण से ठीक दो घंटे पहले हुई महाविकास अघाड़ी की प्रेस कांफ्रेंस में न्यूनतम साझा कार्यक्रमों की घोषणा के समय यदि सिर्फ जनहित के मुद्दों को ही शामिल किया जाता तो भी काम चल सकता था। लेकिन कांग्रेस-राकांपा के दबाव में न सिर्फ सेक्युलर मूल्यों पर दृढ़ रहने की बात जोड़ी गई, बल्कि शिवसेना द्वारा इसे स्वीकार भी किया गया।

शपथ में नहीं गईं, मगर दस जनपथ में उद्धव से मिलेंगी सोनिया गांधी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- पीएम मोदी से किसानों के लिए विशेष सहायता मांगने जल्द दिल्ली आएंगे उद्धव

सोनिया गांधी फाइल

शिवसेना के साथ सत्ता का साझीदार बनने के बाद भी उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण कार्यक्रम से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने दूरी जरूर बनाई, मगर संकेत हैं कि जल्द ही उद्धव की सोनिया गांधी से मुलाकात होगी। उद्धव की मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली की पहली यात्रा के दौरान ही उनकी कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात की पूरी संभावना है। महाराष्ट्र में बारिश की वजह से फसल बर्बादी के संकट को देखते हुए उद्धव केंद्र से विशेष सहायता मांगने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जल्द मुलाकात की तैयारी कर रहे हैं।

कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व के उद्धव के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाने को गठबंधन को लेकर अंदरूनी असहजता का रंग देना सही नहीं है। शिवसेना से गठबंधन पर पार्टी में कोई दुविधा नहीं है क्योंकि कांग्रेस की शीर्ष नीति नियामक इकाई कार्यसमिति ने बकायदा मंथन कर इस पर मुहर लगाई है। हालांकि, पार्टी रणनीतिकारों ने यह जरूर स्वीकार किया कि शिवसेना से गठबंधन चुनाव बाद विशेष हालात में हुआ है और इसलिए भविष्य की चुनौतियों और सवालों को साधने की रणनीति के तहत कुछ सियासी रास्ते बचाकर भी रखने होते हैं। शायद इसी गुंजाइश को बचाए रखने की रणनीति के तहत सोनिया गांधी, डॉ. मनमोहन सिंह और राहुल गांधी तीनों शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए, जबकि उद्धव ने कांग्रेस से अपनी सियासी दोस्ती को बेहतर शुरुआत देने के लिए खुद अपने बेटे आदित्य ठाकरे को इन तीनों को आमंत्रित करने के लिए भेजा था। सूत्रों के अनुसार, शीर्ष नेतृत्व के नहीं जाने का मतलब यह नहीं है कि उद्धव को पार्टी नेतृत्व कोई नकारात्मक संकेत देना चाहता था। इसके विपरीत महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री का उनकी जल्द होने वाली दिल्ली यात्रा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष दस जनपथ में स्वागत करेंगी। पार्टी रणनीतिकारों के अनुसार, महाराष्ट्र में किसानों की कर्ज माफी के बड़े फैसले की तैयारी चल रही है और कांग्रेस नेतृत्व जाहिर तौर पर चाहेगा कि इसका श्रेय गठबंधन के तीनों दलों को जाए न कि अकेले उद्धव को। इसीलिए कर्ज माफी के फैसले के एलान के साथ ही केंद्र से अधिक सहायता हासिल करने के प्रस्ताव पर उद्धव की कांग्रेस और राकांपा के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत चल रही है। इसी प्रस्ताव के साथ उद्धव प्रधानमंत्री मोदी से मिलने दिल्ली आएंगे। इसी दौरान उनकी सोनिया से मुलाकात तय की जा रही है।

शिवसेना की गोवा में भी महाराष्ट्र जैसा 'चमत्कार' करने की मंशा

नया दांव ▸ संजय राउत ने जीएफपी नेता विजय सरदेसाई से मुलाकात के बाद किया दावा

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई

पणजी में शुक्रवार को विधायकों के साथ प्रेसवार्ता करते गोवा फॉरवर्ड पार्टी (जीएफपी) के प्रमुख और पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय सरदेसाई (बीच में)। एएनआइ

शिवसेना गोवा में भी अब महाराष्ट्र जैसा ही चमत्कार करने का दावा करने लगी है। उसके नेता संजय राउत का कहना है कि शिवसेना जल्द ही गोवा में भी महाराष्ट्र की तर्ज पर विपक्षी दलों का एक फ्रंट बनाकर बड़े उलटफेर को अंजाम देगी।

राउत ने यह दावा गोवा के पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय सरदेसाई से मुलाकात के बाद किया। उनका कहना है कि गोवा फॉरवर्ड पार्टी (जीएफपी) के प्रमुख विजय सरदेसाई का शिवसेना के साथ गठबंधन हो रहा है। सभी विरोधी दलों को मिलाकर शिवसेना वहां एक फ्रंट बनाएगी। इसके बाद गोवा में भी एक नई राजनीति जल्द देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार बनने पर संजय राउत को शुभकामनाएं देने आए विजय सरदेसाई का कहना है कि वह गोवा में सभी विपक्षी दलों को जोड़कर एक ऐसा फ्रंट बनाना चाहते हैं जो वहां की भाजपा सरकार को चुनौती दे सके। बता दें कि गोवा में शिवसेना का एक भी विधायक नहीं है, जबकि विजय सरदेसाई डॉ. प्रमोद सावंत की सरकार में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं।

40 सदस्यों वाली गोवा विधानसभा में फिलहाल भाजपा के 27 सदस्य हैं। इसलिए भाजपा की सरकार वहां मजबूत मानी जा रही है। भाजपा के ये 27 सदस्य शुरुआत से भाजपा के टिकट पर चुनकर नहीं आए थे। फरवरी 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में तो भाजपा की सीटें आठ कम होकर 13 पर पहुंच गई थीं। इसके विपरीत कांग्रेस को 17 सीटें मिली थीं, लेकिन कांग्रेस तब सरकार नहीं बना पाई थी, जबकि भाजपा ने तीन सीटों वाली महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (एमजीपी), तीन ही सीटों वाली गोवा फॉरवर्ड पार्टी (जीएफपी) और तीन निर्दलियों को लेकर बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर लिया था। बाद में गोवा कांग्रेस के दो विधायकों के पार्टी छोड़ देने से उसके विधायकों की संख्या 15 रह गई थी।

इसी वर्ष 17 मार्च को मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर के निधन के बाद मुख्यमंत्री पद संभालने वाले डॉ. प्रमोद सावंत ने शुरू में बहुमत पाने के लिए एमजीपी और जीएफपी का समर्थन लिया। बदले में एमजीपी के नेता सुदिन रामकृष्ण धवलीकर और जीएफपी के नेता विजय सरदेसाई को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी देनी पड़ी थी। लोकसभा चुनाव के साथ ही गोवा विधानसभा की चार सीटों के लिए हुए उप चुनाव में तीन सीटें जीतने और एमजीपी के तीन में से दो विधायकों के भाजपा में आ जाने से भाजपा सदस्यों की संख्या कांग्रेस से दो ज्यादा, यानी 17 हो गई थी। फिर 10 जुलाई को कांग्रेस के दो तिहाई विधायकों ने नेता विरोधी दल चंद्रकांत बाबू कवलेकर के नेतृत्व में अलग गुट बनाकर भाजपा में शामिल होने का फैसला कर लिया। तब से 40 सदस्यों वाली गोवा विधानसभा में भाजपा सदस्यों की संख्या 27 हो गई है। कांग्रेस विधायकों के एक बड़े गुट के सीधे भाजपा में शामिल हो जाने के बाद मुख्यमंत्री सामंत ने जीएफपी के तीन और एक निर्दलीय विधायक को सरकार से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तब विजय सरदेसाई को भी उप मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। वह तभी से गोवा में एक मजबूत विपक्ष खड़ा करने का मौका तलाश रहे हैं। अब महाराष्ट्र में हुए उलटफेर से उन्हें उम्मीदें बंधती दिखीं और वह शिवसेना से मदद मांगने मुंबई पहुंच गए।

शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस सरकार को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : महाराष्ट्र में शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस के चुनाव बाद गठबंधन करके सरकार बनाने को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। जस्टिस एनवी रमना, अशोक भूषण और संजीव खन्ना की पीठ ने ठाणे के रहने वाले अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रमोद पंडित जोशी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि संवैधानिक नैतिकता राजनीतिक नैतिकता से भिन्न है। कोर्ट लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के दूसरे दलों से गठबंधन के अधिकार में कटौती नहीं कर सकता। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील बरुण कुमार सिन्हा से सवाल किया कि कोर्ट को चुनाव पूर्व और चुनाव बाद गठबंधन के मुद्दे पर क्यों विचार करना चाहिए और यह मुद्दा न्यायिक समीक्षा के दायरे में कैसे आता है। सिन्हा ने कहा कि शिवसेना और भाजपा ने राजग के रूप में मिलकर चुनाव लड़ा था, उनका घोषणापत्र था जिस पर मतदाताओं ने उन्हें वोट दिए थे। अब चुनाव बाद शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस का गठबंधन करके सरकार बनाना मतदाताओं के साथ धोखा है। कोर्ट ने ये दलीलें ठुकराते हुए कहा कि लोकतंत्र में आप चुनाव बाद गठबंधन के मामले में दखल देने की कोर्ट से उम्मीद न करें जहां उसका क्षेत्राधिकार नहीं है। यह जनता तय करेगी, न कि कोर्ट। पीठ ने कहा कि आपकी दलीलें स्वीकार की जाएं तो लोकतंत्र नहीं हो सकता। पहले चुनाव पूर्व गठबंधन था जो खत्म हो गया और अब चुनाव बाद गठबंधन बना है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कि अगर कोई दल सत्ता में आने के बाद अपने चुनावी घोषणापत्र को लागू नहीं करता तो कोर्ट उसे लागू करने का निर्देश नहीं दे सकता।

सरकार बचाने के लिए उद्धव को 10 जनपथ में करना होगा आत्मसमर्पण : भाजपा

- कहा, सिर्फ इसी तरीके से चल सकती है तथाकथित नई सेक्युलर सरकार

नई दिल्ली, एएनआइ: भाजपा नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सरकार बचाने के लिए अपनी पार्टी की विचारधारा पूरी तरह छोड़नी पड़ेगी और 10 जनपथ (कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का आधिकारिक निवास) में आत्मसमर्पण करना होगा। सिर्फ इसी तरीके से उनकी सरकार चल सकती है।

उन्होंने कहा, 'महाराष्ट्र में तथाकथित नई सेक्युलर सरकार कुछ और नहीं बल्कि अलग-अलग पार्टियों का अवसरवादी गठबंधन है जो एक दूसरे के साथ खड़ी भी नहीं होना चाहतीं। गांधी परिवार उद्धव को अस्पृश्य के तौर पर देखता है जो उनके साथ मंच भी साझा नहीं करना चाहता।' उद्धव को 'गोडसे भक्त' बताते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी और साथ ही कहा, 'आप और आपके विधायकों ने सल्तनत की निष्ठा की कसम खाई है। इसलिए सामना का नामकरण सोनिया नामा करके इस आत्मसमर्पण को पूरा कीजिए। वे आपके घटिया दर्जे के इस अखबार में बेतुके संपादकीय को बर्दाश्त नहीं करेंगे।'

वहीं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, 'देश में ऐसे दो लोग हैं, जो सेक्युलरिज्म का प्रमाणपत्र देते हैं। एक कांग्रेस और दूसरा वह जो हिंदुओं को गाली दे सकता है। इसलिए जो प्रमाणपत्र लेना चाहते हैं उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए।' उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता के लालच में शिवसेना कांग्रेस से प्रमाणपत्र पाने के लिए बेकरार है। गिरिराज ने दावा किया कि उन्होंने अपने ट्वीट में किसी पार्टी की तुलना मुगलों से नहीं की थी। उन्होंने स्पष्ट किया, 'मैंने सिर्फ इतना कहा था कि सत्ता के लालच में देसी रियासतों और राजाओं ने मुगलों से हाथ मिला लिया था। मुगलों ने इन्हीं कुछ देसी रियासतों की मदद से भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसी तरह कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र सरकार का गठन किया गया।' शिवसेना पर निशाना साधते हुए गिरिराज ने कहा, 'सेक्युलरिज्म के बारे में पूछने पर वह (उद्धव) नाराज कैसे हो सकते हैं? यह सभी टीवी चैनलों पर चल रहा है। सेकुलर की परिभाषा यहां 1976 में आई, लेकिन सनातन धर्म में यह सदियों से है। इसलिए सेक्युलरिज्म हमारे डीएनए में है।'

'छोटे भाई' उद्धव के साथ सहयोग करना पीएम की जिम्मेदारी : सामना

मुंबई, प्रेट्र : शिवसेना ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा-शिवसेना के बीच संबंध भले ही तनावपूर्ण हों, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम उद्धव ठाकरे के बीच बड़े और छोटे भाई का संबंध है। अब यह पीएम की जिम्मेदारी है कि वह अपने 'छोटे भाई' के साथ सहयोग करें। शिवसेना ने अपने मुखपत्र 'सामना' के संपादकीय में केंद्र सरकार का जिक्र करते हुए लिखा कि दिल्ली को महाराष्ट्र के लोगों के फैसले का सम्मान करना चाहिए। शिवसेना ने पीएम को 'हमारा प्रधानमंत्री' कहकर संबोधित किया। लिखा पीएम किसी एक पार्टी के नहीं, पूरे देश के होते हैं। लिहाजा, केंद्र को राज्य के त्वरित विकास में सहयोग करना होगा और राज्य के किसानों को मुश्किलों से उबारने में मदद करनी होगी। संपादकीय आगे कहता है कि छत्रपति शिवाजी से प्रेरित महाराष्ट्र की मिट्टी वीरता से परिपूर्ण है और राज्य के सृजन के लिए यहां के लोगों ने दिल्ली से लड़ाई भी लड़ी है। दिल्ली निश्चित रूप से देश की राजधानी है, लेकिन महाराष्ट्र के सीएम बन चुके उद्धव उन बालासाहब ठाकरे के पुत्र हैं जिनका हमेशा यह दृढ़ विचार रहा कि महाराष्ट्र दिल्ली का गुलाम नहीं है। इसलिए यह बात निश्चित है कि इस सरकार की रीढ़ सीधी ही रहेगी।

किसी लांड्री में नहीं धुल सकता भगवा रंग

▸ प्रथम पृष्ठ से आगे

भगवा कुर्ते के बारे में पूछे जाने पर उद्धव ने रहस्यमय अंदाज में कहा कि यह उनका पसंदीदा रंग है जो किसी भी लांड्री में धोया नहीं जा सकता। राकांपा-कांग्रेस से हाथ मिलाने के बाद से ही भाजपा शिवसेना पर उसके हिंदुत्व को लेकर ही सवाल उठा रही है। उद्धव ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि वह अब 'मातोश्री' छोड़कर मुख्यमंत्री के सरकारी आवास 'वर्षा' में रहने जाएंगे या नहीं।

विधानसभा में बहुमत परीक्षण आज: उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस के गठबंधन 'महाविकास अघाड़ी' की सरकार शनिवार को विधानसभा में बहुमत साबित करेगी। विधानसभा सूत्रों ने बताया कि बहुमत परीक्षण शनिवार दोपहर में होगा। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव सरकार को बहुमत साबित करने के लिए तीन दिसंबर तक का समय दिया है। इसके लिए शुक्रवार को राकांपा विधायक दिलीप वालसे पाटिल को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। वह पहले विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं।

उद्धव ने पूछा, 'सेक्युलर का मतलब क्या है': महाविकास अघाड़ी के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में भले ही सेक्युलर मूल्यों पर दृढ़ रहने की बात कही गई है, लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इसे लेकर सहज नजर नहीं आते। यही वजह रही कि गुरुवार शाम जब पहली कैबिनेट बैठक के बाद उनसे पूछा गया कि क्या शिवसेना सेक्युलर हो गई है? तो वह सवाल पूछने वाले पत्रकार पर ही भड़ककर पूछ बैठे कि सेक्युलर का मतलब क्या है? फिर खुद ही जवाब भी दिया, जो संविधान में लिखा है, वही सेक्युलर है।

राजनीतिक नक्शे पर सिमटती भाजपा

मार्च, 2018 में देश के 76 फीसद (69 फीसद आबादी) हिस्से पर भाजपा और उसके सहयोगी दलों की सरकार थी। लेकिन डेढ़ सालों में राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अब महाराष्ट्र छिन जाने के बाद भाजपा का अब केवल 37.4 (45.6 फीसद आबादी) फीसद हिस्से पर नियंत्रण रह गया है।

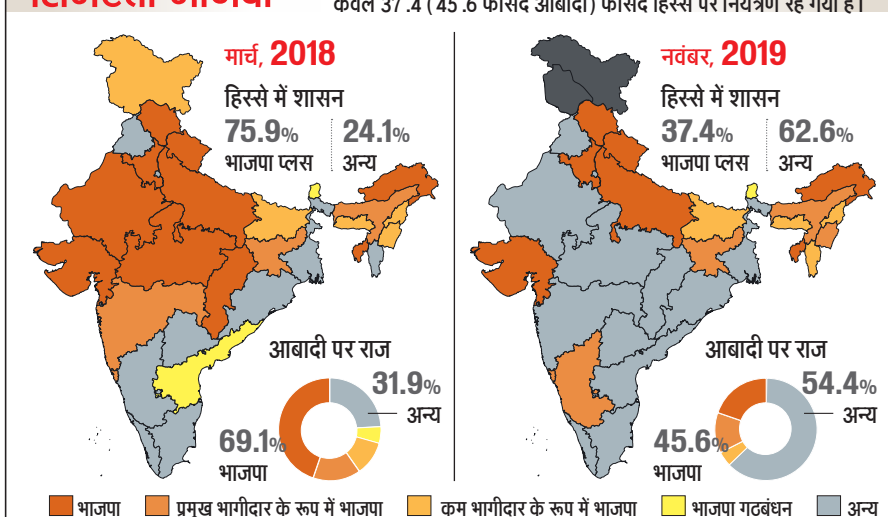

ऐसे बढ़ा भाजपा की सत्ता का ग्राफ

- **7** 2014 में राज्यों में सरकार
- **13** 2015 में राज्यों में सरकार
- **15** 2016 में राज्यों में सरकार
- **21** मार्च 2018 में राज्यों में सरकार
- **17** राज्य भाजपा और उसके सहयोगी दलों की सरकार

विजय रथ रुकने की शुरुआत

भाजपा का विजय रथ 2018 से रुकना शुरू हुआ, जब कर्नाटक में कांग्रेस गठबंधन ने सरकार बना ली। हालांकि, यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चली और कुछ वक्त के बाद भाजपा ने फिर से राज्य में सरकार बना ली।

तल्खी

कहा, उनका आचरण उनके कद व पद को शोभा नहीं देता, सीएम ने संविधान की शपथ ली है, मैंने उसे बचाने की

ममता ने हर मौके पर मुझे अपमानित किया : राज्यपाल धनखड़

जागरण संवाददाता, कोलकाता

जगदीप धनखड़ फाइल

ममता बनर्जी फाइल

बंगाल में राज्यपाल का पद संभालने के बाद से लगातार तृणमूल सरकार से जगदीप धनखड़ के रिश्ते तल्ख बने हुए हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को समाचार एजेंसी पीटीआइ को दिए साक्षात्कार में उन्होंने एक बार फिर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निशाने पर लिया। उन्होंने ममता पर उन्हें लगातार अंधेरे में रखने और हर मौके पर उनका अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसा कर वह खुद अपना कद घटा रही हैं, जबकि मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष विमान बंद्योपाध्याय को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर जानबूझकर विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में प्रोटोकाल का उल्लंघन करते हुए अतिथियों के बाद उन्हें बोलने के लिए बुलाया गया।

उन्होंने कहा कि क्या आपने देश के किसी हिस्से में ऐसा देखा है कि राज्य विधानसभा में वर्तमान राज्यपाल को सदन को संबोधित करने के लिए पांचवें नंबर पर बुलाया जाए। इतना ही नहीं उनकी मौजूदगी में कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व राज्यपाल (एमके नारायणन), पूर्व लोकसभा अध्यक्ष (मीरा कुमार) और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त (एसवाई कुरैशी) करें। मामले पर दुख जताते हुए उन्होंने कहा कि प्रोटोकाल के गंभीर उल्लंघन के बावजूद कार्यक्रम की महत्ता को देखते हुए मैं वहां गया, लेकिन उनका यह कदम अवांछनीय था।

खुद पर समानांतर सरकार चलाने के आरोपों का खंडन करते हुए उन्होंने राज्य सरकार को इसे साबित करने की चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि मैं संविधान के अनुरूप काम कर रहा हूं। सरकार चलाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन सरकार संविधान संगत कार्य कर रही है, यह सुनिश्चित करना मेरा काम है। जहां भी संविधान का उल्लंघन होगा, मैं आऊंगा। मुख्यमंत्री ने संविधान की शपथ ली है और मैंने संविधान बचाने की।

दुर्गापूजा कार्निवल और संविधान दिवस कार्यक्रम में हुए कथित अपमान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कद और पद को ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। भले ही ऐसे व्यवहार से मेरा अपमान हुआ है, लेकिन नतीजे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कद भी बहुत नीचे आ गया है। हालांकि, उन्होंने उम्मीद जताई की तृणमूल प्रमुख के पास जो राजनीतिक अनुभव है, उसके अनुरूप वह जरूर इन मुद्दों पर विचार करेंगी और आगे का कोई सार्थक रास्ता अवश्य निकालेंगी। लगे हाथ राज्य के मंत्रियों को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि राज्य मंत्री बड़े ही असहनीय और नपेतुले अंदाज में उनका अपमान कर रहे हैं। हालांकि, ममता की जैसी पकड़ पार्टी व सरकार पर है, उनकी सहमति के बिना ऐसा करना संभव नहीं लगता है। एनआरसी पर जारी विवाद पर कोई टिप्पणी करने से मना करते हुए उन्होंने इतना भर कहा कि किसी को भी संसद द्वारा पारित किसी भी कानून के विरोध में किसी भी संवैधानिक संस्था को सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आना चाहिए। राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सार्वजनिक रूप से कुछ बोलने से इन्कार करते हुए उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर वह सिर्फ राज्य सरकार से बात करेंगे। भविष्य में राज्यपाल व राज्य सरकार के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध की संभावना पर उन्होंने कहा कि इसके लिए पहले राज्य सरकार को राज्यपाल के लिए खोदी गई खाई को पाटना होगा।

चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामले छिपाने पर फड़नवीस तलब

देवेंद्र फड़नवीस फाइल

नागपुर, प्रेट्र : महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस को नागपुर की एक अदालत ने चुनावी हलफनामे में अपने खिलाफ दो आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने को लेकर दाखिल अर्जी पर समन जारी किया है। नागपुर सदर थाना के एक अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को ही पूर्व मुख्यमंत्री के यहां स्थित आवास पर कोर्ट का समन सौंप दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री नागपुर से विधानसभा सदस्य चुने गए हैं।

फड़नवीस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह प्रक्रिया शुरू की गई है। नागपुर के एक वकील सतीश उके ने 2014 में ही अदालत में अर्जी दाखिल कर उनके खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया शुरू करने की मांग की थी, जिसे मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 2015 में खारिज कर दिया था। बाद में बांबे हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री को राहत देते हुए निचली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक अक्टूबर को मजिस्ट्रेट कोर्ट को वकील उके की अर्जी पर सुनवाई की दिशा में आगे बढ़ने का निर्देश दिया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक नवंबर को भाजपा नेता के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया शुरू करने की अर्जी स्वीकार कर ली।

फड़नवीस के खिलाफ 1996 और 1998 में जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए थे। दोनों मामलों में उनके खिलाफ आरोप नहीं तय किए गए थे। उके ने आरोप लगाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने 2014 के अपने चुनावी हलफनामे में इस संबंध में जानकारी नहीं दी थी। पूर्व मुख्यमंत्री से संबंधित यह प्रक्रिया ऐसे समय में शुरू हुई है जब महाराष्ट्र में एक दिन पहले शिवसेना की अगुआई वाली गठबंधन सरकार ने शपथ ली है।

2014 में झारखंड विधानसभा चुनाव में कुल 947 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी। राज्य के आंकड़े बताते हैं कि हर चुनाव में औसत 900 प्रत्याशियों की जमानत जब्त होती है।

झारखंड की पहले चरण की 13 सीटों पर आज मतदान

तैयारी ▸ नक्सलियों के गढ़ में किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम

महासमर झारखंड विधानसभा चुनाव 2019

हेलीकॉप्टर से होगी निगहबानी, एयर एंबुलेंस भी रहेगी तैनात

राज्य ब्यूरो, रांची

झारखंड विधानसभा चुनाव के तहत पहले चरण के 13 विधानसभा क्षेत्रों में शनिवार को मतदान होगा। ये सभी सीटें सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हैं। कुल 4,892 मतदान केंद्रों पर होने वाले मतदान में लगभग 37 लाख मतदाता 189 उम्मीदवारों का भाग्य तय करेंगे। पहले चरण की सीटों में चार को छोड़कर सभी पलामू प्रमंडल की सीटें हैं। मतदान सुबह सात बजे से अपराह्न तीन बजे तक होगा।

घोर नक्सल प्रभावित इन विधानसभा क्षेत्रों में कड़ी और चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान होगा। साथ ही बूथों की हेलीकॉप्टर से निगहबानी की जाएगी। आपात स्थिति से निपटने के लिए रांची एयरपोर्ट पर एक एयर एंबुलेंस भी तैनात रहेगी। हाल ही में हुई नक्सली घटनाओं के बाद यहां की सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है। आयोग ने कुल 4,892 मतदान केंद्रों में 1,343 मतदान केंद्रों को नक्सलियों के लिहाज से अति संवेदनशील और 588 को संवेदनशील श्रेणी में रखा है। गैर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी 417 मतदान केंद्र अति संवेदनशील तथा 1,814 संवेदनशील हैं।

कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर : पहले चरण के चुनाव में एक पूर्व केंद्रीय मंत्री, एक वर्तमान मंत्री, नौ पूर्व मंत्री, दस वर्तमान विधायक, एक पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की प्रतिष्ठा दांव पर लगी होगी। इनमें स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी (विश्रामपुर), पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव (लोहरदगा), पूर्व मंत्री बैद्यनाथ राम (लातेहार), केएन त्रिपाठी (डालटनगंज) शामिल हैं।

लातेहार में शुक्रवार को झारखंड विधानसभा चुनावों से पहले सर्च ऑपरेशन चलाते सुरक्षा बल। प्रेट्र

इन क्षेत्रों में होगा मतदान

जिला	सीट
चतरा	चतरा
गुमला	गुमला, बिशुनपुर
लोहरदगा	लोहरदगा
लातेहार	मनिका, लातेहार
पलामू	पांकी, डालटनगंज, विश्रामपुर, छत्तरपुर, हुसैनाबाद
गढ़वा	गढ़वा तथा भवनाथपुर।

नक्सल प्रभावित मतदान केंद्र

1,343 अति संवेदनशील

588 संवेदनशील

417 गैर नक्सल प्रभावित मतदान केंद्र अति संवेदनशील

1,814 संवेदनशील

झारखंड में चुनाव तय करेंगे राजनीतिक विमर्श की दिशा

आशुतोष झा, जमशेदपुर

स्थायित्व बनाम अस्थिरता के नारों के बीच झारखंड में शनिवार को पहले चरण का मतदान है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री रघुवर दास की परीक्षा भी होनी है। दरअसल, रघुवर को जनता के दरबार में खुद को भी साबित करना है और भाजपा नेतृत्व के भरोसे पर भी खरा उतरना है। पांच साल पहले 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद तीन राज्यों के चुनाव हुए थे और केंद्र के साथ साथ तीनों राज्यों महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में भाजपा ने इतिहास रच दिया था। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की रणनीति का करिश्मा था। 2019 में दो राज्य हरियाणा और महाराष्ट्र ने संबंधित मुख्यमंत्रियों को कठघरे में खड़ा कर दिया। अब झारखंड के मुख्यमंत्री की बारी है। दरअसल झारखंड सबसे अहम होने वाला है, क्योंकि इसी के नतीजे आने वाले चुनावों में भाजपा की धार और विमर्श की दिशा तय करेंगे। इसमें शक नहीं कि रघुवर ने पांच साल के शासनकाल में दम दिखाया है। विकास के कई कार्यों के साथ-साथ नक्सलवाद पर प्रभावी अंकुश लगाया है। लेकिन, चुनावी राजनीति में जिस तरह एकबारगी चौतरफा घेरेबंदी की कोशिशें शुरू हुई हैं, उसे अलग-अलग नजरिए से देखा जा रहा है। एक वर्ग जहां इसे भाजपा के लिए खतरनाक मान रहा है, वहीं दूसरे वर्ग का मानना है कि बहुकोणीय लड़ाई भाजपा के लिए फायदेमंद ही साबित होगी। ऐसा मानने वालों में भाजपा ही नहीं, ऐसे दलों के उम्मीदवार भी हैं जो भाजपा को चुनौती दे रहे हैं। इसमें शक नहीं कि अगर यह फायदेमंद होता है तो रघुवर को इसका श्रेय मिलेगा, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें टिकट बंटवारे से लेकर रणनीति तय करने तक में छूट दी थी। उन्हें बेरोकटोक पांच साल का शासन करने का मौका मिला। केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा मिला है। दरअसल, राजनीतिक रूप से झारखंड की अहमियत हरियाणा और महाराष्ट्र से अधिक हो गई है, क्योंकि झारखंड का नतीजा आने वाले चुनावों में राजनीतिक परिदृश्य और बहस को रुख देगा। दो-तीन महीने में दिल्ली में मतदान है और उसके बाद 2020 के अंत तक बिहार में, जहां जदयू के साथ भाजपा गठबंधन की सरकार है। बिहार में लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जदयू के साथ बराबरी की भागीदारी की थी, लेकिन स्ट्राइक रेट भाजपा की सौ फीसद रही थी। रघुवर का प्रदर्शन पूरे देश में भाजपा के मनोबल के लिए अहम है।

हरियाणा में भाजपा ने पिछली बार से कम सीटें जीतीं और गठबंधन पर निर्भर होना पड़ा, जबकि महाराष्ट्र में अच्छे प्रदर्शन के बावजूद बड़ा झटका लगा है। माना तो यह जा रहा है कि इन दोनों राज्यों के कारण ही झारखंड में चुनौती और प्रबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ी हैं।

राजाओं का रसूख बरकरार जनता लुटाती है प्यार...

आदिवासी और लोकतंत्र

संजय कृष्ण, रांची

झारखंड में राजाओं की रियासतें भले ही खत्म हो गई हों, लेकिन उनका रसूख आज भी कायम है। राजनीति में भी यह दबदबा साफ दिखता है। कुछ सीधे-सीधे चुनाव मैदान में उतरते हैं और जनता की आवाज बनते हैं तो कुछ चुनाव से दूर अपने अतीत की यादों के साथ वर्तमान के तंत्र के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। कहा जा सकता है, लोकतंत्र ने राजा और रंक को एक ही कतार में खड़ा कर दिया है। राजा अब भी अपने गढ़ और सम्मान के लिए इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बने रहना चाहते हैं, लेकिन जनता कहती है कि अब राजाओं का प्रभाव उतना नहीं रह गया है।

बात राज्य की राजधानी रांची से सटे तमाड़ से शुरू करते हैं। यहां के राजा कुमार महेंद्रनाथ शाहदेव मानते हैं कि तमाड़ देवोत्तर इस्टेट है। यहां जनता में इस गढ़ का प्रभाव कायम है। आज भी जनता इस गढ़ पर प्यार लुटाती है। उन्हें इस बात का मलाल जरूर है कि सीट आरक्षित होने से वह चुनाव नहीं लड़ सकते। कहते हैं पिता स्व अमरेंद्रनाथ शाहदेव जनसंघ से जुड़े थे। यहां से उन्होंने अपने मैनेजर अनिरुद्ध पातर को दो बार विधायक बनाया। वह खुद 1974 से 1980 तक एमएलसी रहे और 1980 में ही उनका निधन हो गया। आज इस क्षेत्र से रीता मुंडा भाजपा की प्रत्याशी हैं। वह मुंडा राजा से आशीर्वाद लेना नहीं भूलतीं। राजा भी इनकी जीत के लिए मेहनत कर रहे हैं।

होता रहा राजघरानों का विस्तार

पलामू, चैनपुर के राजा टिकैत विश्वदेव नारायण सिंह के पुत्र कुमार विवेक भवानी सिंह कहते हैं कि हमारा प्रभाव आज भी है। हम अपने गढ़ी में ही रहते हैं। भाजपा से जुड़ाव 2005 से है, लेकिन कभी चुनाव नहीं लड़े। विवेक कहते हैं कि झारखंड में प्रमुख राजघराने छह ही हैं। इसके ही विस्तार होते-होते दो दर्जन हो गए हैं। बड़ा घराना रांची का रातू गढ़ है। रातू गढ़ के राजकुमार गोपालनाथ शाहदेव हटिया से कांग्रेस से दो बार विधायक रहे। वह अपनी पिता लाल चिंतामणि शरण नाथ शाहदेव के एकलौते पुत्र थे। 2010 में उनका निधन हो गया। इनकी कोई संतान नहीं है। फिलहाल बहू और बहनें विरासत संभाल रही हैं।

भाजपा प्रत्याशी का समर्थन : सिमडेगा जिले के बीरू गढ़ के राजा दुर्गविजय सिंहदेव भी मानते हैं कि उनका प्रभाव कम नहीं हुआ है। वह भाजपा प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं। अपने क्षेत्र में राजा के प्रभाव पर वह जरूर कहते हैं कि राजतंत्र जरूर खत्म हो गया, लेकिन प्रभाव अभी भी कायम है। अपने विशाल बैठक के अंदर से 16वीं शताब्दी के मिट्टी के विशाल खंडहर दिखाते हैं। ओडिया शैली के इस खंडहर को देखकर सिर्फ आप अतीत की बुलंदी का अंदाजा लगा सकते हैं। भाजपा से अपने जुड़ाव के बारे में कहते हैं कि 1988 में कड़िया मुंडा उन्हें भाजपा में लेकर आए, तब से यहीं हैं। भाजपा ने बस इन्हें जिला स्तर पर 20 सूत्रीय उपाध्यक्ष बनाया है।

बायोमीट्रिक सिस्टम से लैस 'निशंक' बाजार के लिए तैयार

जागरण संवाददाता, कानपुर : सबसे अधिक मारक क्षमता और सुरक्षित रिवॉल्वर 'निशंक' की लांचिंग शुक्रवार को हो गई। फील्ड गन फैक्ट्री में मुख्य अतिथि अपर महानिदेशक पुलिस प्रेम प्रकाश ने रिवॉल्वर की प्रशंसा की। कानपुर की फील्ड गन फैक्ट्री में तैयार निशंक रिवॉल्वर 50 मीटर तक घातक मारक क्षमता रखती है। इसके अलावा रिवॉल्वर का होलस्टर भी बायोमीट्रिक सिस्टम पर आधारित है। ऐसे में किसी दूसरे के हाथों में चले जाने पर दुरुपयोग नहीं हो सकेगा।

समारोह की अध्यक्षता कर रहे फैक्ट्री के वरिष्ठ महाप्रबंधक अनिल कुमार ने उपस्थित जनों को रिवॉल्वर की विशेषता बताई। उम्मीद जताई कि इस रिवाल्वर की बेहद मांग होगी। इसके ट्रिगर पुल को कम किया गया है तथा सेफ्टी मैकेनिज्म में परिवर्तन कर यह सुनिश्चित किया गया है कि मिस फायर न हो। उन्होंने कहा कि गन फैक्ट्री आगे भी इस तरह के प्रयोग जारी रखेगी।

अदालत ने निर्भया के दोषियों से फांसी की सजा पर मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▸ पीड़िता के परिजनों ने पटियाला हाउस अदालत में दायर की थी अर्जी

वसंत विहार सामूहिक दुष्कर्म (निर्भया) मामले में दोषियों को जल्द फांसी दिए जाने की मांग पर पटियाला हाउस अदालत ने नोटिस जारी कर दोषियों से जवाब मांगा है। पूछा है कि उन्होंने दया याचिका दायर की है या नहीं? अगर नहीं की है, तो ऐसा करने को लेकर उनका पक्ष क्या है?

पीड़िता की मां की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि फिलहाल दोषियों को फांसी देने के लिए नोटिस जारी नहीं कर सकते, जब तक कि उनका पक्ष पता नहीं चलता। वहीं, सुनवाई के बाद पीड़िता की मां अदालत के बाहर भावुक हो गईं और कहा कि वह लंबे समय से इंतजार कर रही हैं। वह ऐसा नहीं कह रही हैं कि दोषियों को सुने बिना फांसी दे दी जाए, लेकिन कम से कम दोषी अपना पक्ष तो बताएं। इस संबंध में दायर अर्जी में कहा था कि दोषियों को फांसी की सजा हो चुकी है, लेकिन सजा की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा रहा है। 16 दिसंबर 2012 की रात में फिजियोथेरेपिस्ट की पढ़ाई कर रही छात्रा के साथ चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। इसके कुछ दिनों बाद पीड़िता ने इलाज के दौरान सिंगापुर में दम तोड़ दिया था। इस मामले के एक दोषी ने जेल में आत्महत्या कर ली थी। एक नाबालिग को कोर्ट ने तीन साल के लिए बाल सुधार गृह में भेजने की सजा सुनाई थी। वहीं चार अन्य दोषियों मुकेश, पवन, विनय और अक्षय को निचली अदालत से फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद दोषियों ने फांसी की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दया याचिका दायर की थी। हालांकि, सभी दोषियों की दया याचिका को खारिज कर फांसी की सजा बरकरार रखने का आदेश दिया गया था।

नेताजी के प्रपौत्र बोले-बंगाल में काम नहीं आएगी भाजपा की राष्ट्रीय रणनीति

जागरण संवाददाता, कोलकाता

बंगाल में विधानसभा उपचुनाव में तीनों सीटों खड़गपुर सदर, कालियागंज व करीमपुर पर भाजपा को मिली हार के बाद पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्र कुमार बोस ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी को अब राज्य विशेष के लिए योजना बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि 'स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरती पर पार्टी की राष्ट्रीय रणनीति कारगर नहीं होगी'। गौरतलब है कि उक्त तीनों सीटों पर तृणमूल ने कब्जा जमाया है।

नेताजी के प्रपौत्र बोस ने इस हार के बाद आत्मविश्लेषण का आह्वान करते हुए कहा कि पार्टी को उपचुनाव के दौरान एनआरसी को अपना मुख्य चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए था। यह बंगाल के लिए कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन सभाओं में पार्टी नेताओं ने इसे मुद्दा बनाकर बयानबाजी की। इस पर शोर मचाने की जरूरत नहीं थी। एनआरसी पहले असम में लागू होने की बात है। बंगाल के दौरे पर आए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि पहले नागरिक संशोधन बिल पारित होगा उसके बाद ही बंगाल में एनआरसी लागू होगा। यह घुसपैठियों को पहचानने की प्रक्रिया है। यह भारत के नागरिकों के लिए चिंता का कोई विषय नहीं है। बोस ने कहा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एनआरसी के बारे में लोगों को भ्रमित कर राजनीतिक फायदा उठाया है।

चंद्र कुमार बोस। फाइल

बंगाल में भाजपा का शुद्धिकरण जरूरी: बोस ने कहा कि बंगाल में भाजपा का शुद्धिकरण करना जरूरी है। शुद्धिकरण से उनका तात्पर्य संगठन के चुनाव को सही तरीके से कराना था, जिससे दल में योग्य व्यक्तियों को शामिल किया जाए। पार्टी में पदाधिकारियों का चयन योग्यता के आधार पर हो न कि व्यक्तिपरक। बोस ने कहा कि गुटबाजी पर भी नियंत्रण करने की जरूरत है। ऐसे तो हर दल में गुटबाजी की समस्या होती, लेकिन उस पर पार्टी नेतृत्व का नियंत्रण होना चाहिए। हमें सिर्फ डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बोलने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनके आदर्शों पर चलकर दिखाना होगा। तभी हमारी पार्टी अन्य दलों से अलग कहलाएगी। पार्टी में एकता जरूरी है। बोस ने कहा कि हमें अपने संगठनात्मक लक्ष्य को सुधारना होगा। उन्होंने बूथ स्तर पर संपर्क मजबूत करने पर बल दिया और कहा, हमें अपने मतदाताओं को भी पहचाना होगा।

दूध प्रकरण में शिक्षामित्र बर्खास्त, प्रभारी प्रधानाध्यापक निलंबित

जागरण संवाददाता, सोनभद्र : सोनभद्र (उप्र) में चोपन ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय सलईबनवा में एक लीटर दूध में एक बाल्टी पानी मिलाकर 81 बच्चों को पिलाने के मामले में प्रभारी प्रधानाध्यापक को निलंबित किया गया, जबकि शिक्षामित्र जितेंद्र कुमार की सेवा समाप्त कर चोपन थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। खंड शिक्षा अधिकारी मुकेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई के लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय को पत्र भेजा गया है। गुरुवार को सोनभद्र में मिड डे मील में धांधली का मामला सामने आया था। यहां चोपन ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय सलईबनवा में 81 बच्चों में एक लीटर दूध बांटा गया। प्रभारी प्रधानाध्यापक ने बताया था कि उनके भाई की तेरहवीं थी, जिसकी वजह से वह दूध नहीं खरीद सके थे। सुबह पांच पैकेट लेकर पहुंचे थे। चार पैकेट का दूध बांट दिया। एक डिब्बे का दूध रसोइया को देकर लौट आए। जब वह दोपहर को और दूध लेकर पहुंचे तो दूध में पानी मिला बच्चों को पिला दिया गया था।

गुजरात की भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक : कांग्रेस

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद

▸ सीसीटीवी फुटेज जारीकर किया दावा- परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थी मोबाइल की मदद से कर रहे थे नकल

गुजरात में सचिवालय भर्ती परीक्षा को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। सीसीटीवी फुटेज जारी कर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रश्नपत्र लीक हो गया था और परीक्षार्थी मोबाइल से नकल कर रहे थे। सरकार ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अब तक हुई भर्तियों में पूरी पारदर्शिता बरती गई है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावडा ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि गत दिनों सचिवालय लिपिक व सचिवालय सहायक पदों पर भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी मोबाइल से नकल कर रहे थे। परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्र लीक करा दिया गया, जिसके बाद परीक्षार्थी मोबाइल की मदद से सवालों के जवाब लिख रहे थे। उन्होंने आरोपों की पुष्टि के लिए सुरेंद्रनगर व बनासकांठा के कुछ परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज भी जारी की।

परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था गुजरात गौण सेवा पसंदगी मंडल के अध्यक्ष असित वोरा ने कहा कि कांग्रेस के सभी आरोप बेबुनियाद हैं। वह युवाओं को गुमराह करना बंद करे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से जारी फुटेज सुरेंद्रनगर के वढवाण केंद्र (सीयू शाह कॉलेज) की हैं। उनकी जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक करीब एक लाख 20 हजार युवाओं को सरकारी सेवा का मौका दिया है। गुजरात गौण सेवा पसंदगी मंडल के जरिये भी 25 हजार युवाओं की भर्ती सरकारी सेवाओं के लिए की गई है।

अमित चावडा। फाइल

माधुरी दीक्षित ने भजनलाल सरकार में मिली कोठी सवा तीन करोड़ में बेची

विशाल पाठक, चंडीगढ़

प्रसिद्ध अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने शुक्रवार को पंचकूला के मनसा देवी कांप्लेक्स सेक्टर-4 की स्थित अपनी कोठी (संख्या-310) इंटरनेशनल ब्रांड 'क्लियर ट्रिप डॉट कॉम' के संस्थापक सदस्य और चीफ बिजनेस ऑफिसर अमित तनेजा को बेच दी। तत्कालीन मुख्यमंत्री भजनलाल के कोटे से मिली एक कनाल की इस कोठी के लिए माधुरी ने तब लगभग ढाई लाख रुपये दिए थे। अब इसे सवा तीन करोड़ रुपये में बेचा गया है।

माधुरी दीक्षित के पति डॉ. श्रीराम माधव नैने शुक्रवार को इस सौदे के लिए पंचकूला के सेक्टर-6 स्थित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) ऑफिस पहुंचे। हरियाणा के एडिशनल डायरेक्टर हॉस्पिटेलिटी सतपाल शर्मा की मौजूदगी में डॉ. श्रीराम नैने और अमित तनेजा के बीच डील हुई। इस दौरान कई प्रॉपर्टी डीलर भी मौजूद रहे।

1996 में पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल ने दी थी माधुरी को कोठी : वर्ष 1996 में हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भजनलाल ने अपने मुख्यमंत्री कोटे से माधुरी दीक्षित को यह कोठी (संख्या-310) दी थी। उस समय माधुरी चंडीगढ़ आई थीं। उन दिनों माधुरी ने हम आपके हैं कौन, अंजाम और राजा जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में अहम किरदार निभाया था।

जानिए : कौन हैं अमित तनेजा : क्लियर ट्रिप डॉट कॉम के इंटरनेशनल मार्केट्स के चीफ बिजनेस ऑफिसर से पहले अमित तनेजा भारत के पहले ऑनलाइन होटल कंसोलिडेटर देसिया के संस्थापक और प्रबंध निदेशक रह चुके हैं। तनेजा क्लियर ट्रिप डॉट कॉम के इन दिनों एंकरिंग बिजनेस परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स, चैनल्स और इंटरनेशनल मार्केट का काम संभालते हैं।

पंचकूला के एमडीसी-4 की कोठी नंबर-310। जागरण

माधुरी ने प्रॉपर्टी के लिए दिए थे केवल ढाई लाख रुपये

अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने मनसा देवी कांप्लेक्स सेक्टर-4 की इस कोठी के लिए वर्ष 1996 में विभिन्न औपचारिकताओं के लिए हुडा ऑफिस में पहले 60 हजार रुपये और उसके बाद करीब 1.75 लाख रुपये दिए थे। माधुरी ने कुल ढाई लाख रुपये का भुगतान किया था।

तेलंगाना के गृह मंत्री ने दी सफाई

▸ प्रथम पृष्ठ से आगे

इस बीच, पुलिस की जगह बहन को फोन करने का विवादित बयान देने वाले तेलंगाना के गृह मंत्री मोहम्मद महमूद अली ने अब सफाई दी है और महिला चिकित्सक को अपनी सगी बेटी के समान बताया है। अली ने कहा था कि महिला चिकित्सक अगर अपनी बहन की जगह पुलिस को फोन की होती तो उसकी जान बच सकती थी। मंत्री ने कहा, निजी तौर पर मामले को देखेंगे

मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के पुत्र और राज्य के वरिष्ठ मंत्री केटी रामराव ने कहा कि वह इस मामले को निजी तौर पर देखेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाएगा।

राहुल गांधी ने जताया दुख : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस घटना पर स्तब्धता जताते हुए पीड़िता के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जताई है। तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन. राजकुमार ने घटना पर दुख जताते हुए दरिंदों को फांसी देने की मांग की है।

महिला सुरक्षा पर एडवाइजरी जारी करेगा केंद्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने पीड़ित परिवार को र संभव मदद का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सभी राज्यों को महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने के लिए एडवाइजरी जारी करेगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

रेड्डी ने कहा कि वह कोशिश करेंगे कि हत्यारों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के अपराध में शामिल आरोपितों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए और किसी भी वकील को इनका केस नहीं लड़ना चाहिए।

एनसीडब्ल्यू ने पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने समय पर महिला पशु चिकित्सक के पिता की मदद नहीं वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने ट्वीट कर कहा कि आयोग पीड़ित परिवार की मदद के लिए एक सदस्य को हैदरबाद भेज रहा है। उन्होंने कहा है कि जब तक अपराधियों को उनके किए की सजा नहीं मिल जाती आयोग चैन से नहीं बैठेगा। आयोग ने इस मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई है और साइबराबाद पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनार से इस संबंध में कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है।

आयोजन

नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी भी पहुंचीं, बरातियों और प्रभु श्रीराम का किया स्वागत

जनकपुरधाम में प्रभु श्रीराम का हुआ तिलकोत्सव

निरंजन कुमार साह, नेपाल

विवाह पंचमी के अवसर पर जनकपुरधाम में आयोजित होने वाले राम-जानकी विवाहोत्सव को लेकर हर तरफ उत्साह है। शुक्रवार को प्रभु श्रीराम का तिलकोत्सव हुआ। हजारों लोग इसके गवाह बने। ऐसा लग रहा था स्वागत में पूरा जनकपुर उतर आया है। शनिवार को मां जानकी का मटकोर और रविवार को श्रीराम-जानकी का विवाह होगा।

दोपहर एक बजे अयोध्या से आई बरात जानकी मंदिर पहुंची। मंदिर के महंत रामतपेश्वर दास के नेतृत्व में तिलक के सामान की व्यवस्था की गई। तिलकोत्सव के लिए जानकी मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर स्थित राम मंदिर तक 551 महिलाएं सिर पर विभिन्न प्रकार के फल, मिठाइयां, कपड़े सहित अन्य सामान टोकरी में लेकर चलीं। रास्ते में स्थानीय महिलाओं ने उनका स्वागत किया। हंसी-ठिठोली के बीच मिथिला की परंपरा के अनुसार गालों पर दही लगाने और मजाकिया लहजे वाले स्वागत गीत गाए गए।

तिलक में आए लोगों का राम मंदिर के महंत रामदास ने स्वागत किया। तिलकोत्सव विधि-विधान व मैथिल रस्म के साथ किया गया। स्थानीय कलाकारों ने मिथिला के परिधान में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मिथिला और राम जानकी से जुड़े मैथिली गीतों पर नृत्य भी हुआ।

इस मौके पर नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने भी शिरकत की। वह सेना के हेलीकॉप्टर से जनकपुर पहुंचीं। बरबीघा मैदान में बने भव्य पंडाल में उन्होंने बरातियों के साथ प्रभु श्रीराम और माता जानकी का स्वागत किया। इस मौके पर नेपाल के संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराई, भूमि सुधार व्यवस्था मंत्री पद्मा अर्याल भी रहे।

जनकपुरधाम में तिलकोत्सव के लिए जानकी मंदिर से राम मंदिर 551 भार (फल व मिठाइयों से भरी टोकरी) सिर पर ढोकर ले जाती महिला श्रद्धालु। निरंजन कुमार साह

राम-जानकी विवाहोत्सव के मौके पर आम जनमानस का अभिवादन स्वीकार करतीं नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। जागरण

भारत-नेपाल संबंध को प्रगाढ़ बनाने वाला विवाह पंचमी महोत्सव अब अंतिम चरण में है। जनकपुरधाम स्थित जानकी मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। एक दिसंबर को होने वाले विवाह महोत्सव को यादगार बनाने के लिए जनकपुरवासी भी अपने घरों को सजा रहे हैं।

सेना पर विवादित बयान मामले में आजम पर 18 को तय होंगे आरोप

जागरण संवाददाता, रामपुर

▸ सांसद को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश

सेना पर विवादित बयान देने के मामले में सपा सांसद आजम खां के खिलाफ अदालत में सुनवाई शुरू हो गई है। अदालत 18 दिसंबर को इस मुकदमे में सांसद के खिलाफ आरोप तय करेगी। इसके लिए सांसद को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के आदेश दिए हैं। सेना पर विवादित बयान का यह मामला मई 2017 का है। इस संबंध में 30 जून 2017 को मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट लगा दी थी। शुक्रवार को मुकदमे में सुनवाई हुई।

आचार संहिता के मुकदमे में अब चार को होगी सुनवाई : आचार संहिता के मुकदमे की सुनवाई के लिए सांसद आजम खां कोर्ट नहीं पहुंचे। इस मुकदमे में उनके खिलाफ अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किए थे। अदालत अब चार दिसंबर को सुनवाई करेगी। आचार संहिता उल्लंघन का यह मामला लोकसभा चुनाव के दौरान का है।

आजम खां के मीडिया प्रभारी शानू जिला बदर : आजम खां के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खां शानू को जिला प्रशासन ने गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर कर दिया है। हालांकि वह पिछले चार माह से जिले से बाहर हैं। जिलाधिकारी ने शानू खां पर चार माह पहले गंज थाने की पुलिस ने गुंडा एक्ट की कार्रवाई की थी। 17 जुलाई को पुलिस अधीक्षक ने जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी थी।

आजम खां फाइल

63 हजार इंसास व 23 हजार एसएलआर रायफल मिलीं हैं उत्तर प्रदेश पुलिस को। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि उप्र पुलिस भी अब अत्याधुनिक हथियारों से लैस हो गई है। अब थ्री नॉट थ्री रायफलों का प्रयोग नहीं होगा।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 30 नवंबर 2019

न्यूज गैलरी

बैंक घोटाले में रतुल पुरी ने दायर की जमानत अर्जी

नई दिल्ली : बैंक लोन घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित कारोबारी और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी ने जमानत अर्जी दायर की है। राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने इस पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से 30 नवंबर तक जवाब मांगा है। रतुल पुरी को उनकी कंपनी मोजर बियर से जुड़े करीब 354 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद पुरी को अगस्ता वेस्टलैंड मामले में भी गिरफ्तार किया गया। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। बैंक घोटाले में रतुल के पिता दीपक पुरी, मां नीता सहित कई अन्य भी आरोपित हैं। (जासं)

भूषण स्टील के पूर्व सीएमडी सिंघल फिर से रिमांड पर

नई दिल्ली : भूषण स्टील एंड पावर लिमिटेड के पूर्व सीएमडी संजय सिंघल का सात दिन का रिमांड खत्म होने के बाद ईडी ने शुक्रवार को उन्हें फिर से राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में पेश किया। सिंघल को ईडी ने कई करोड़ रुपये के बैंक घोटाले के आरोप में पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया था। ईडी ने हाल ही में भूषण स्टील एंड पावर लिमिटेड की करीब चार हजार करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। ईडी का आरोप है कि कंपनी ने करीब 695 करोड़ रुपये के बैंक लोन में हेरफेर किया है। (जासं)

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले दोषी को 20 साल कैद

चंडीगढ़ : नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले मूल रूप से नेपाल निवासी दोषी कृष्ण लांबा (54) को जिला अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर दो लाख पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अभियोग के मुताबिक दोषी ने 3 नवंबर 2018 को पीड़िता को बहला-फुसलाकर होटल में ले गया और दुष्कर्म किया। दोनों को उत्तर प्रदेश के शामली शहर से बरामद किया गया था। (जासं)

देशद्रोह की धारा हटवाने हाई कोर्ट पहुंचा रामपाल

चंडीगढ़ : हरियाणा में करौंथा स्थित सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल ने अपने खिलाफ दर्ज एफआइआर में देशद्रोह और गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल होने की धाराओं को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। शुक्रवार को हाई कोर्ट का रोस्टर बदलने के कारण इस मामले पर सुनवाई नहीं हो पाई। वर्तमान में जस्टिस दया चौधरी और जस्टिस मीनाक्षी आई मेहता की डिविजन बेंच है, लेकिन पहले यह मामला जस्टिस दया चौधरी और जस्टिस सुधीर मित्तल की डिविजन बेंच सुनती रही है। यह मामला पार्ट हर्ड मैटर (पूर्व में किसी जज द्वारा सुनवाई जारी रहने) के कारण अन्य बेंच सुनवाई नही कर सकती। इसलिए जस्टिस दया चौधरी ने मामले को 20 दिसंबर तक स्थगित कर दिया। (जासं)

'रेडीमेड' पुलिसकर्मी बनाने को बनेगा रक्षा शक्ति विवि

एलान ▶ लखनऊ में 47वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में अमित शाह की घोषणा

अपराधियों को सजा दिलाने के लिए नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी भी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पेशेवर और प्रशिक्षित पुलिस कार्मिकों की कमी को दूर करने के लिए रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार जल्द विधेयक लाएगी। कहा कि कक्षा दस उत्तीर्ण कर चुके जो बच्चे पुलिसिंग में अपना कॅरियर बनाना चाहते हैं, वे इनमें पढ़ सकते हैं। इस विवि में फोरेंसिक साइंस, कानून, अभियोजन, विवेचना और पुलिस थानों के संचालन की पढ़ाई होगी। जो छात्र यहां से पढ़कर निकलेंगे उन्हें पुलिस भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी, क्योंकि वे 'रेडीमेड पुलिस कार्मिक' होंगे। वह शुक्रवार को लखनऊ में पुलिस मुख्यालय में आयोजित दो दिवसीय 47वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के समापन समारोह में बोल रहे थे।

शाह ने भी कहा कि ब्रिटिश राज में बने भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) जैसे कानून अब अप्रासंगिक हो चुके हैं। सरकार इनमें आमूलचूल परिवर्तन करेगी। ब्रिटिश हुकूमत ने इन कानूनों को भारत पर शासन करने के लिए बनाया था। हमारी प्राथमिकता इस देश के नागरिक और गरीब से गरीब व्यक्ति हैं, जिन्हें सुरक्षा प्रदान करने के साथ उन्हें इसका आभास भी कराना है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने आइपीसी और सीआरपीसी में संशोधन का मसौदा तैयार कर गृह मंत्रालय को भेज दिया है। इसे सरल, सुचारू और लोकाभिमुख बनाया जाएगा। इसके लिए शाह ने प्रत्येक राज्य के पुलिस महानिदेशक से लेकर बीट कांस्टेबल तक से सुझाव मांगा है। इन सुझावों को वेबसाइट पर सार्वजनिक भी किया जाएगा।

अपराधियों को सजा दिलाने में आएगी तेजी : अपराधियों को सजा दिलाने की दर बेहद कम होने से चिंतित शाह ने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है। सात साल से अधिक सजा वाले संगीन आपराधिक मामलों में फोरेंसिक साक्ष्यों को जुटाना अनिवार्य होगा। राज्यों में इस विश्वविद्यालय से संबद्ध फोरेंसिक साइंस कॉलेज स्थापित होंगे। इससे फोरेंसिक साक्ष्य जुटाने के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध होगा। राज्य किसी साइंस कॉलेज को भी फोरेंसिक साइंस कॉलेज में बदल सकते हैं।

निदेशक अभियोजन का पद स्थापित हो : शाह ने कहा कि प्रायः सरकारी वकील मुकदमों की तारीख बढ़वाते रहते हैं। उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। अभियोजन की प्रक्रिया की निगरानी और उसे चुस्त-दुरुस्त करने के लिए उन्होंने पुलिस मुख्यालय में निदेशक अभियोजन का पद स्थापित करने के लिए भी कहा। जेल मैनुअल को अपग्रेड किए जाने पर भी जोर दिया क्योंकि वह भी कानून व्यवस्था का ही अंग है।

लखनऊ में शुक्रवार को गोमती नगर विस्तार में स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस में लगी प्रदर्शनी में एटीएस के स्टॉल पर जानकारी लेते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साथ में उपस्थित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डीजीपी ओपी सिंह, मुख्य सचिव आरके तिवारी। हृदेश चंदेल

▶ ब्रिटिश राज में बने आइपीसी और सीआरपीसी में बदलाव के लिए केंद्र सरकार लाएगी विधेयक

▶ कक्षा दस उत्तीर्ण कर चुके जो बच्चे पुलिसिंग में अपना कॅरियर बनाना चाहते हैं, वे इनमें पढ़ सकते हैं

राज्यों में स्थापित होंगे मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो

राज्यों में मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो स्थापित किया जाएगा। एफआइआर दर्ज होते ही मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो के पास उसका सारांश पहुंचेगा और जिन मामलों में सजा होगी, उसका ब्योरा भी ब्यूरो को भेजा जाएगा। ब्यूरो उसका विश्लेषण करेगा कि एक प्रकार के अपराध करने वालों से कैसे निपटा जाए।

नारकोटिक्स ब्यूरो के ढांचे में होगा बदलाव

यह भी कहा कि नारकोटिक्स (मादक पदार्थों) से जुड़े अपराधों से संबंधित एजेंसियों में अभी कोई समन्वय नही है। इसलिए सरकार नोरकोटिक्स ब्यूरो के ढांचे में भी बदलाव करेगी। इसके एक्ट को भी कठोर बनाया जाएगा। अर्धसैनिक बल भी नारकोटिक्स से जुड़े अपराधों को रोकेंगे। केंद्र सरकार नारकोटिक्स से जुड़े अपराधियों के खिलाफ अभियोजन के लिए राज्यों को प्रशिक्षित मानव संसाधन सुलभ कराएगी। सभी विधि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र लिखकर इसके लिए अलग विभाग खोलने के लिए कहा गया है।

जागरण न्यू मीडिया ने लांच किया 'जागरण टीवी'

▶ प्रेरणादायक विषयों के साथ समाज में वैल्यू विकसित करना मूल मकसद

जेएनएन, नई दिल्ली : लोगों को विश्वसनीय और तथ्यपरक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 'जागरण टीवी' लांच किया गया है। 'हकीकत देखने की आदत डालो' टैगलाइन के साथ जागरण प्रकाशन लिमिटेड (जेपीएल) की ऑनलाइन इकाई जागरण न्यू मीडिया (जेएनएम) द्वारा लांच किए गए इस ऑनलाइन वीडियो प्लेटफार्म का मूल मकसद प्रेरणादायक विषयों के साथ समाज में जागरूकता फैलाना और मूल्य विकसित करना है।

इस मौके पर जागरण न्यू मीडियो के सीईओ भरत गुप्ता ने बताया कि सूचना एवं संपर्क के कारण भारत में तेजी से बड़े बदलाव हो रहे हैं। हम ऐसी कहानियों, जानकारियों और आइडिया को लोगों से शेयर करना चाहते हैं, जो लोगों का सशक्तीकरण करके बेहतर जिंदगी जीने में उनकी मदद करें। वीडियो ऐसा मजबूत माध्यम है जो भाषा की सीमाओं से परे जाकर लोगों की भावनाओं को प्रभावित करता है। इस प्लेटफार्म पर विस्तृत फीचर वीडियो स्टोरी के साथ ही छोटी कहानियों, लव गुरु, ह्यूमर (हास-परिहास) और क्षेत्रीय भाषाओं में रेडियो सिटी के कंटेंट को भी रखा गया है।

'हमारा मिशन नॉलेज, इंफॉर्मेशन और वॉइस के जरिए न्यू इंडिया को मजबूत बनाना है। इससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक विकास के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलेगा।'

-भरत गुप्ता, सीईओ, जागरण न्यू मीडिया

मलयालम कवि अक्कितम को मिलेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार

जेएनएन, नई दिल्ली : साहित्य जगत का प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम भाषा के कवि अक्कितम अच्युतन नंबूदरी को देने की घोषणा की गई है। 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा के पहले मशहूर उड़िया लेखिका प्रतिभा राय की अध्यक्षता में निर्णायक मंडल की बैठक हुई जिसमें शमीम हनफी, सुरंजन दास, माधव कौशिक और डॉ. पुरुषोत्तम बिलिमाले समेत अन्य सदस्य मौजूद थे। बैठक में लंबी चर्चा के बाद अक्कितम का नाम तय किया गया। अक्कितम का जन्म आठ मार्च 1926 को केरल के पलक्कड़ जिले में हुआ था और बचपन से ही उनकी रुचि साहित्य और कला की ओर थी। कविता के अलावा अक्कितम ने नाटक और उपन्यास भी लिखे हैं। उन्होंने अन्य भारतीय भाषाओं की रचनाओं का अनुवाद भी किया है। उनकी 40 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनका खंड काव्य इरुपदाम नूट्टांडिडे इतिहासम काफी चर्चित और लोकप्रिय रहा है।

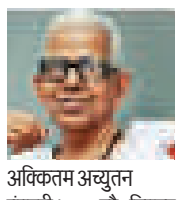

अक्कितम अच्युतन नंबूदरी। सौ. ट्विटर

नीति आयोग की पूर्व सीईओ समेत छह को अंतरिम जमानत

आइएनएक्स मीडिया मामला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▶ विशेष अदालत ने सीबीआइ से जमानत पर मांगा जवाब

▶ सुनवाई के दौरान पूर्व वित्तमंत्री चिदंबरम भी रहे मौजूद

राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने आइएनएक्स मीडिया मामले में नीति आयोग की पूर्व सीईओ सिंधुश्री खुल्लर और पांच अन्य को अंतरिम जमानत दे दी। इन सभी को दो लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक गारंटी पर यह राहत दी गई है। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम भी मौजूद रहे। अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी।

सीबीआइ ने पिछले माह इस मामले में एक आरोपपत्र दायर किया था, जिसमें चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति सहित 12 अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग सहित कई आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में कार्ति चिदंबरम और पीटर मुखर्जी जमानत पर हैं, जबकि कार्ति के सीए एस. भास्करन अग्रिम जमानत पर चल रहे हैं। अदालत ने अन्य को समन जारी किए, जिन्होंने अग्रिम जमानत अर्जी दायर कर दी। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने सभी छह अधिकारियों को अंतरिम जमानत देकर सीबीआइ से जवाब मांगा है।

इन्हें भी मिली राहत : विशेष न्यायाधीश पूर्व ओएसडी प्रदीप कुमार बग्गा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड (एफआइपीबी) के पूर्व निदेशक प्रबोध सक्सेना, वित्त मंत्रालय की एफआइपीबी इकाई के पूर्व सेक्शन अधिकारी अजीत कुमार डुंगडुंग, एफआइपीबी इकाई में तत्कालीन अवर सचिव रबिंद्र प्रसाद और पूर्व संयुक्त सचिव (विदेश व्यापार) अनूप के पुजारी को भी अंतरिम जमानत दी है।

यह है मामला

सीबीआइ ने 15 मई 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोप है कि चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए आइएनएक्स मीडिया समूह को दी गई एफआइपीबी मंजूरी में अनियमितताएं हुई थीं।

साध्वी को जलाने के बयान पर तहसीलदार ने विधायक से कहा-आपकी औकात नहीं

नईदुनिया, राजगढ़

▶ बैकफुट पर आए कांग्रेसी विधायक ने बयान पर फिर जताया खेद

▶ सांसद के पुतला दहन के दौरान दिया था विवादास्पद बयान

भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जिंदा जलाने की धमकी वाले बयान देने वाले ब्यावरा से कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी बैकफुट पर आ गए हैं। शुक्रवार को उन्होंने बयान के लिए फिर खेद जताकर माफी मांगी। वहीं, श्योपुर की तहसीलदार अमिता सिंह ने फेसबुक पर विधायक के लिए लिखा कि आपकी ऐसी औकात नहीं, दोबारा मत बोलना।

उल्लेखनीय है कि गुरुवार को सांसद प्रज्ञा ठाकुर के पुतला दहन के बाद विधायक दांगी ने मीडिया को बयान दिया था कि पूरा पुतला नहीं, प्रज्ञा ठाकुर कभी आएंगी तो साथ-साथ उन्हें भी जला देंगे। विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही उनकी निंदा होने लगी। उन्होंने गुरुवार को भी बयान पर खेद जताया था। शुक्रवार को दांगी ने कहा कि उनके बयान से अगर किसी को तकलीफ हुई तो मैं खेद जताता हूं। गलती होती है तो क्षमा मांगना कोई बुरी बात नहीं है। उधर, विधायक के बयान को लेकर तहसीलदार अमिता सिंह ने फेसबुक पर लिखा कि आपकी ऐसी औकात नहीं, दोबारा मत बोल देना। मीडिया के सवाल पर अमिता सिंह ने टिप्पणी संशोधित कर लिखा कि आप संवैधानिक पद पर हैं, ऐसी भाषा अशोभनीय है। अमिता पूर्व में ब्यावरा में तहसीलदार रह चुकी हैं।

शिवराज सिंह ने की निंदा : मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायक दांगी के बयान पर ट्वीट कर निंदा की। उन्होंने कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी मानसिकता के लोग सभ्य समाज में हमारे बीच रहते हैं। एक जनप्रतिनिधि होकर एक महिला के लिए ऐसी टिप्पणी करने वाले की जितनी निंदा की जाए, कम है। सत्ता के नशे में इतना चूर होना ठीक नही है। तत्काल माफी मांगें।

स्पष्ट करें कि गांधी विचारधारा के साथ हैं या गोडसे की : सांसद प्रज्ञा को लेकर शुक्रवार को लोकसभा में हुए घटनाक्रम पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया कि संसद में दिए गए बयान से ऐसा नहीं लगता है कि उन्हें अपने कथन पर आत्मग्लानि या शर्मिंदगी है। अब भाजपा और सांसद प्रज्ञा सिंह को देश के सामने यह स्पष्ट करना चाहिए कि वे गांधी विचारधारा के साथ हैं या गोडसे की।

गोडसे के पर्चे मामले में नामजद दो आरोपितों ने किया समर्पण : ग्वालियर में महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे की महिमामंडित करने व पर्चे बांटने के मामले में नामजद हिंदू महासभा के पवन व नरेश बाथम ने गुरुवार दोपहर को कोतवाली थाने में समर्पण कर दिया। इस मामले में कोतवाली थाने की पुलिस दो लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

साध्वी प्रज्ञा पर प्रकरण दर्ज करने की मांग

सांसद प्रज्ञा के बयान को लेकर गुरुवार को इंदौर में कांग्रेस के नेता सेंट्रल कोतवाली पहुंचे और शिकायती आवेदन देकर प्रकरण दर्ज करने की मांग की। पुलिस अधिकारियों ने सांसद के विशेषाधिकार का हवाला देकर कांग्रेसियों को रवाना कर दिया।

45 लाख टन प्लास्टिक पचा जाएंगी देश की सड़कें

जागरण संवाददाता, लखनऊ : देश के लिए मुश्किल बनता जा रहे प्लास्टिक कचरे को लेकर बेशक हल्ला मचा है, लेकिन उससे निपटने का आसान तोड़ भी संभव है। देश की सड़कें पर्यावरण की दुश्मन 45 लाख टन प्लास्टिक को खपाने के लिए काफी हैं। यह दावा भारत में प्लास्टिक मिलाकर सड़क बनाने की तकनीक को आगे बढ़ाने वाले पद्मश्री से अलंकृत प्रो. आर. वासुदेवन का है। शुक्रवार को लखनऊ में 'अपशिष्ट प्लास्टिक सड़क निर्माण में प्रयोग किए जाने व व्हाइट सीमेंट टॉपिंग' विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

प्रो. आर. वासुदेवन ने कहा कि प्लास्टिक विभिन्न कारणों से महत्वपूर्ण हैं। इससे सड़क सस्ती बनती हैं। आज सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि प्लास्टिक विलेन नहीं, हीरो है। प्लास्टिक में कुछ भी खराब नहीं है। वासुदेवन ने कहा कि आप मेरे गांव में आएं सब कुछ प्लास्टिक का है। 2003 में मैंने चेन्नई में पहली प्लास्टिक रोड बनाई। देशभर में अब तक लाखों किमी सड़क प्लास्टिक से बनाई जा चुकी है। हकीकत यह है कि सड़क बनाने के लिए जरूरत की केवल 10 फीसद प्लास्टिक ही उपलब्ध है। भारत में प्लास्टिक उपयोग अच्छा है, मगर निस्तारण खराब है। ये बहुत सस्ती तकनीक है।

प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण

प्लास्टिक अपशिष्ट से सड़क निर्माण का यह प्रयोग सफल रहा तो देश में प्लास्टिक कचरे की समस्या से छुटकारा मिलने में मदद मिल सकेगी। भारतीय सेना की सैन्य अभियंता सेवा ने असम के नारंगी मिलिट्री स्टेशन में प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत करीब 1.24 मीट्रिक टन प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग किया गया है। एएनआइ

नए कश्मीर में आतंकियों से भिड़े ग्रामीण, सरपंच को बना रहे थे निशाना

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

आतंक की नर्सरी कहे जाने वाले दक्षिण कश्मीर में भी अब आतंक के पांव उखड़ने लगे हैं। नए कश्मर के ग्रामीण भी अब डरने के बजाय आतंकियों से दो-दो हाथ कर रहे हैं। शोपियां के हीरपोरा में सरपंच को निशाना बनाने आए आतंकियों से ग्रामीण सीधे भिड़ गए। ऐसे में आतंकियों को जान बचाकर भागना पड़ा। फिलहाल, पुलिस ने आतंकियों को दबोचने के लिए अभियान चला रखा है। हीरपोरा के सरपंच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं।

गुरुवार देर रात गए स्वचालित हथियारों से लैस दो-तीन आतंकियों ने हीरपोरा गांव के सरपंच एजाज अहमद के दरवाजे पर दस्तक दी। देर रात दस्तक से एजाज अहमद को संदेह हो गया कि आतंकी हैं। लिहाजा उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। आतंकियों ने धमकी दी कि वह बाहर न आए तो पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। इस बीच, एजाज और उसके परिजनों ने मदद के लिए शोर मचा पड़ोसियों को जमा करने का प्रयास किया।

आवाज सुनकर पड़ोसी घरों से बाहर निकल आए और उन्होंने आतंकियों का प्रतिरोध शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार, आतंकियों ने ग्रामीणों को डराने के लिए हवा में दो राउंड भी फायर किए, लेकिन ग्रामीण न डरे और न झिझके बल्कि उनसे सीधे भिड़ गए। लोगों ने आतंकियों से राइफल छीनने का भी प्रयास किया। लोगों का आक्रोश देख आतंकियों के पांव उखड़ गए और जान बचाने के लिए निकल भागे। ग्रामीणों ने गांव के बाहर तक किया आतंकियों का पीछा।

फिर सरपंच को निशाना बनाने का प्रयास : यहां यह बताना असंगत नहीं होगा कि मंगलवार को आतंकियों ने अनंतनाग के हाकूरा में गांव की ओर कार्यक्रम में हमला किया था। इस हमले में एक सरपंच और कृषि अधिकारी समेत की मौत हो गई थी।

पड़ोसियों के हौसले से बची जान : सरपंच एजाज ने कहा कि अगर उसके पड़ोसी समय रहते मदद नहीं करते तो आतंकी दरवाजा तोड़कर भीतर घुस सकते थे। उनके हौसले से जान बची है। ऐसे में उन्होंने प्रशासन से पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने की भी मांग की है। ग्रामीणों ने भी परिवार को सुरक्षित ठिकाने पर भेजने की मांग की है।

बालाकोट सेक्टर में घुसपैठ नाकाम, पाक को करारा जवाब

जागरण संवाददाता, पुंछ : पाकिस्तानी सेना ने शुक्रवार देर शाम पुंछ के बालाकोट सेक्टर में घुसपैठ करवाने के लिए नियंत्रण रेखा पर भारी गोलाबारी की। भारत ने भी कड़ा जवाब देकर घुसपैठ को नाकाम बना दिया। देर रात तक हुई गोलाबारी में किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। जानकारी के अनुसार, पाकिस्तानी सेना ने देर शाम करीब साढ़े आठ बजे पहले बालाकोट में सेना की अग्रिम चौकियों को निशाना बनाकर गोलाबारी की। इसके कुछ ही समय बाद पाकिस्तान ने भारत के रिहायशी क्षेत्रों पर भी मोर्टार दागने शुरू कर दिए। कई गोले लोगों के घरों के आसपास भी गिरे। इसके बाद भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को कड़ा जवाब देना शुरू कर दिया। बावजूद इसके देर रात तक पाकिस्तानी सेना गोलाबारी करती रही। सूत्रों के अनुसार, पाक सेना गोलाबारी की आड़ में आतंकियों के दल को भारतीय क्षेत्र में दाखिल करवाने का प्रयास कर रही थी, जिसे भारतीय सेना ने विफल कर दिया।

उम्मीद

आइबी व एलओसी पर मंजूर हुए 15 हजार बंकर, अब तक बने सिर्फ पांच हजार, जम्मू संभाग के पुंछ और राजौरी जिले में होती है अधिक गोलाबारी

पाकिस्तानी गोलाबारी के बीच सरहद पर बंकरों की आस

विवेक सिंह, जम्मू

जम्मू-कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान लगातार गोलाबारी कर रहा है। सरहद से सटे गांवों में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। केंद्र सरकार लोगों की सुरक्षा के लिए आइबी और एलओसी पर 15 हजार से अधिक बंकरों का निर्माण करवा रही है, लेकिन तीन साल में सिर्फ पांच हजार बंकर बन पाए हैं। सबसे अधिक गोलाबारी जम्मू संभाग के पुंछ व राजौरी जिले में होती है। यहां के लोग जिंदगी बचाने के लिए बंकरों के जल्द निर्माण की आस लगाए बैठे हैं।

4852 बंकर बनकर तैयार : जम्मू संभाग के पांच सीमांत जिलों में 4,852 बंकर बनकर तैयार हैं। इनमें 4,478 निजी बंकर हैं और 374 सामुदायिक बंकर हैं।

राज्य प्रशासन से खफा : केंद्र सरकार भी बंकर निर्माण में हो रही देरी से राज्य प्रशासन से खफा है। जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर नियमित रूप से बैठकें कर सीमांत क्षेत्रों में बंकर निर्माण के कार्य को तेजी दे रहे हैं। जम्मू संभाग के सीमांत जिलों के डिप्टी कमिश्नरों (डीसी) और निर्माण में जुटी एजेंसियों के अधिकारियों को जवाबदेह बनाया गया है।

क्या है देरी का कारण : बंकर निर्माण प्रोजेक्ट केंद्र का होने के कारण इसे राज्य सरकार की एजेंसी बनाएगी या केंद्र की, देरी का सबसे बड़ा कारण यह भी रहा। इसके बाद जगह चिह्नित करने में दिक्कतें आईं। अब राज्य का लोक निर्माण विभाग बंकर बना रहा है।

बंकरों के जल्द निर्माण का मुद्दा उठा : जम्मू-कश्मीर में वर्ष 2016-17 में पायलट प्रोजेक्ट के तहत तीन करोड़ की लागत से 60 बंकरों का निर्माण किया था। इसके बाद वर्ष 2017 में 415.73 करोड़ से 14,460 बंकर बनाने का काम शुरू हो गया था। 2018 में तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने 400 अतिरिक्त बंकर बनाने को भी मंजूरी दी थी। अब तक इनमें 35 फीसद बंकर लोगों को गोलाबारी से बचाने के लिए उपलब्ध हैं। लगातार तेज हो रही गोलाबारी के बीच बंकरों के जल्द निर्माण का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। तीन माह में पाक ने 2700 से अधिक बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है।

जल्द बंकर बनने के प्रयास जारी : जम्मू-पुंछ के भाजपा सांसद जुगल किशोर शर्मा का कहना है कि पूरी कोशिश है कि लोगों के लिए जल्द बंकर बन पाएं। बंकर बनाते समय यह सुनिश्चित किया है कि वे तय मानकों के आधार पर ही बनें। उनकी गुणवक्ता से किसी प्रकार का समझौता मंजूर नहीं है।

राजौरी-पुंछ में सबसे ज्यादा बंकर : जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर संजीव वर्मा के अनुसार बनकर तैयार हो गए 4852 बंकरों में से सांबा में 1093, जम्मू में 899, कठुआ में 1131, राजौरी में 1473 व पुंछ में 256 बंकर शामिल हैं। काफी बंकरों का निर्माण कार्य इस समय स्लैब स्तर तक पहुंच गया है। पुंछ और राजौरी जिले में एलओसी के करीब 7298 बंकर बनाए जा रहे हैं। जम्मू, कठुआ और सांबा जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास 7162 भूमिगत बंकर बनाए जा रहे हैं। इन बंकरों में 13029 निजी बंकर और 1431 सामुदायिक बंकर हैं। कश्मीर के उड़ी और कुपवाड़ा में भौगोलिक स्थिति के कारण निर्माण में देरी हो रही है।

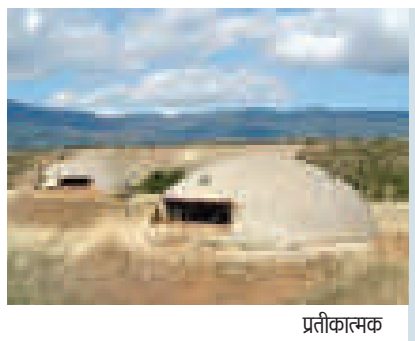

प्रतीकात्मक

निजी और सामुदायिक बंकर

निजी बंकर का आकार 160 वर्ग फीट है। इसमें आठ लोग शरण ले सकते हैं। 800 वर्ग फीट के सामुदायिक बंकर में 40 लोग आ सकते हैं। भूमिगत बंकर बनाने के लिए स्टील और कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है। इनकी दीवारें और छत सामान्य घर के मुकाबले तीन गुना मोटी होती हैं। निजी बंकर घर के पास बनाए जाते हैं या फिर जमीन देने पर घर में भी बंकर का निर्माण

एक महीने में लश्कर और हिजबुल के छह मॉड्यूल नष्ट

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

कश्मीर में लोगों में डर का माहौल पैदा करने की साजिश में जुटे आतंकियों और अलगाववादियों के खिलाफ अभियान तेज करते हुए पुलिस ने विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के सहयोग से बीते एक माह में लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के छह मॉड्यूल नेस्तनाबूद किए हैं। इसके अलावा पुलिस ने आतंकियों के 28 ओवरग्राउंड वर्करों (ओजीडब्ल्यू) को भी हिरासत में लिया है।

पकड़े गए ओजीडब्ल्यू से भारी मात्रा में जिहादी साहित्य, धमकी भरे पोस्टर और विस्फोटकों का जखीरा भी बरामद किया गया है। गुरुवार को पुलिस ने बांडीपोर में मंजूर अहमद वानी नामक एक ओजीडब्ल्यू को पकड़ा है। गांदरबल में नारनाग इलाके से करीब 15 दिन पहले हिजबुल मुजाहिदीन के दो ओजीडब्ल्यू पकड़े गए थे। सोपोर पुलिस ने लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के दो मॉड्यूल नेस्तनाबूद करते हुए 10 ओजीडब्ल्यू को पोस्टरों और जिहादी साहित्य के साथ पकड़े थे। सुरक्षाबलों ने इनसे दो हथगोले और अन्य विस्फोटक भी बरामद किए थे।

दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में गत सप्ताह पुलिस ने चार ओजीडब्ल्यू पकड़े। यह चारों गत जुलाई में अरिहाल पुलवामा में एक सैन्य वाहन को आइईडी धमाके में उड़ाने की साजिश में शामिल थे। 25 नवंबर को बारामुला पुलिस ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर (एसपीओ) भर्ती रैली को निशाना बनाने आए पांच ओजीडब्ल्यू को दबोच लिया था। इनके कब्जे से चार ग्रेनेड व अन्य असलहा मिला था। कुलगाम मे पुलिस ने सीआरपीएफ के जवानों के साथ मिलकर लश्कर व हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े तीन ओजीडब्ल्यू को पकड़ा। गत मंगलवार को श्रीनगर के आंचर में सक्रिय लश्कर के ओजीडब्ल्यू बशीर गनई को पकड़ा गया। पुलवामा में एक आतंकी ने सुरक्षाबलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जबकि श्रीनगर में जैश का एक आतंकी भी पकड़ा गया।

15 दिनों में भीतर रिपोर्ट सौंपनी होगी विदेश प्रशिक्षण लेने गए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को उत्तराखंड में। प्रदेश में इस समय तकरीबन 40 सरकारी महकमे हैं। सभी विभागों में यही कवायद शुरू होने वाली है।

फटकार के बाद अनुसूचित जाति के इंस्पेक्टरों की तैनाती के आदेश

आरोप ▶ हरियाणा पुलिस में अनुसूचित जाति के इंस्पेक्टरों की अनदेखी

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने डीजीपी से कहा, सीपी-एसपी नहीं सुनते तो क्या लिया एक्शन बताओ

दीपक बहल, अंबाला

- दो दिसंबर तक आयोग ने मांगी रिपोर्ट, डीजीपी ने सीपी-एसपी को लिखा पत्र
- प्रदेश में अनुसूचित जाति के इंस्पेक्टरों का किया जाएगा रिव्यू, हो सकती हैं नई तैनाती

हरियाणा पुलिस में अनुसूचित जाति के इंस्पेक्टरों की अनदेखी का मामला तूल पकड़ गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की फटकार के बाद डीजीपी मनोज यादव ने प्रदेश के सभी एसपी और पुलिस कमिश्नर को लिखित आदेश जारी कर अनुसूचित जाति के इंस्पेक्टरों का रिव्यू कर तैनाती करने के आदेश जारी किए।

पुलिस महानिदेशक के जवाब से असंतुष्ट होकर आयोग ने कहा कि इधर-उधर की बात कर गुमराह करने का प्रयास किया गया है। डीजीपी सुनिश्चित करें कि इनकी अनेदखी न हों। यदि, पुलिस कमिश्नर और एसपी जिले में डीजीपी के आदेश नहीं मान रहे तो ऐसे अफसरों के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया, इन आदेशों की प्रतिलिपि भी मांगी गई है। दैनिक जागरण ने भी पर्दाफाश किया था कि प्रदेश में कुछ जिलों में एससी वर्ग के इंस्पेक्टरों की तैनाती थानों में नहीं कर रखी हैं।

बता दें आयोग ने 12 अक्टूबर 2019 को डीजीपी हरियाणा मनोज यादव को पत्र भेजा था। इस पत्र में पूछा गया था कि प्रदेश में एससी वर्ग से संबंधित इंस्पेक्टर रैंक के अफसर, जो एसएचओ तैनात किए गए हैं, का ब्योरा दिया जाए। प्रत्येक जिले के अनुसार विभिन्न बिंदुओं पर जवाब मांग था।

पूछा था प्रदेश स्तर पर इंस्पेक्टर रैंक पर ट्रांसफर करने वाले अधिकारी का रैंक, जो इसके लिए अधिकृत हो, जिला स्तर पर एसएचओ की तैनाती करने वाले अधिकारी का रैंक व पुलिस कमिश्नरी में एसएचओ की पोस्टिंग करने वाले अधिकारी का रैंक पर जानकारी मांगी। इसके लिए बाकायदा फारमेट भी भेजा गया था। डीजीपी ने फारमेट भरकर आयोग को भेजा तो पता चला कि कई जिलों में एससी वर्ग के इंस्पेक्टर थानों में तैनात ही नहीं हैं।

डीजीपी ने 14 नवंबर को आयोग को बताया था प्रदेश में लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लागू थी जिस कारण तबादले नहीं हो सके। अब इस संबंध में ध्यान रखा जाएगा और जल्द ही आदेश जारी होंगे। डीजीपी के इस जवाब से असंतुष्ट आयोग ने 15 नवंबर को फिर से डीजीपी को सख्त रवैया अपनाते हुए आदेश जारी किए।

इन आदेशों में कहा कि 10 नवंबर से 30 नवंबर तक कितने इंस्पेक्टरों के तबादले किए गए, इनकी प्रतिलिपि दी जाए। साथ ही जिलों में एसपी और पुलिस कमिश्नरी में सीपी को एससी वर्ग के इंस्पेक्टरों को लेकर जारी आदेशों की प्रतिलिपि मांगी। इतना ही नहीं, आयोग ने कहा कि फिर रिव्यू किया जाए कि किस जिले या फिर कमिश्नरी में अफसरों ने डीजीपी के आदेश नहीं माने, उनके खिलाफ लिए गए एक्शन से आयोग को अवगत करवाएं।

इन आदेशों के बाद डीजीपी ने आयोग से आइ चिट्ठी भी सभी एसपी, सीपी को 28 नवंबर को भेजकर आदेश जारी कर दिए हैं। माना जा रहा है कि प्रदेश में जल्द इंस्पेक्टरों का तबादला किया जाएगा।

रोजवैली ग्रुप के चेयरमैन गौतम कुंडू की पत्नी के खिलाफ लुकआउट नोटिस

जागरण संवाददाता, कोलकाता : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हजारों करोड़ के चिटफंड घोटाले की जांच के सिलसिले में रोजवैली समूह के चेयरमैन गौतम कुंडू की पत्नी शुभ्रा कुंडू के खिलाफ शुक्रवार को लुकआउट नोटिस जारी किया। गौरतलब है कि ईडी ने 2015 में रोजवैली समूह के चेयरमैन गौतम कुंडू को गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही उनके होटल, रिसॉर्ट, कई प्लॉट समेत उनकी 2300 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी।

सूत्रों ने बताया कि रोजवैली घोटाले में मनी लांड्रिंग को लेकर जांच कर रही ईडी अधिकारियों की एक टीम दक्षिण कोलकाता स्थित उनके फ्लैट पर पहुंची थी, लेकिन उस वक्त वह घर पर नहीं थीं। अधिकारियों के अनुसार, कुंडू ने अपने फ्लैट पर ईडी की टीम के आने की खबर सुनकर जांच एजेंसी को एक पत्र लिखा था। हालांकि, अधिकारी ने पत्र के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी। ईडी अधिकारी ने बताया कि एहतियातन कदम के तहत शुभ्रा कुंडू के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है।

आरोप है कि रोजवैली ग्रुप ने चिटफंड के धंधे के लिए कथित रूप से 27 कंपनियां शुरू की थीं। इसके जरिये कंपनी ने निवेशकों को कम समय में आकर्षक ब्याज दर के साथ मोटी रकम लौटाने का वादा कर बाजार से हजारों करोड़ रुपये जुटाए। सूत्रों का कहना है कि रोजवैली घोटाला में कथित रूप से ब्याज एवं अर्थदंड समेत 15,000 करोड़ रुपये की अनियमितताओं का अनुमान है।

लॉ छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में हाई कोर्ट सख्त, डीजीपी तलब

राज्य ब्यूरो, रांची

- डीजीपी ने मुख्य न्यायाधीश को दी जांच की प्रगति रिपोर्ट

झारखंड हाई कोर्ट। फाइल

झारखंड की राजधानी रांची में दो दिन पूर्व विधि छात्रा से हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन ने शुक्रवार को राज्य के पुलिस महानिदेशक कमल नयन चौबे को तलब कर पूरे मामले में रिपोर्ट ली।

जानकारी के अनुसार मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन को बताया गया कि घटना में शामिल सभी आरोपित दबोचे जा चुके हैं। घटना में प्रयुक्त गाड़ियां पकड़ी जा चुकी हैं। पीड़िता की मेडिकल जांच कराई जा चुकी है। आरोपितों की भी मेडिकल जांच करा दी गई है। अब उनकी पहचान परेड व फोरेंसिक रिपोर्ट कराना बाकी है। फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद पुलिस आरोप पत्र दाखिल करेगी।

डीजीपी ने बताया कि अनुसंधान लगभग 80 फीसद पूरा हो चुका है। फोरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद आरोप पत्र दाखिल कर प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई (स्पीडी ट्रायल) के लिए न्यायालय से आग्रह किया जाएगा। आरोपितों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य के साथ पुलिस न्यायालय जाएगी, ताकि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके।

जेल भेजे गए सभी आरोपित: इस मामले में सभी 12 आरोपितों कुलदीप उरांव, सुनील उरांव, संदीप तिर्की, अजय मुंडा, राजन उरांव, नवीन उरांव, बसंत कच्छप, रवि उरांव, अमन उरांव, रोहित उरांव, सुकरा उरांव, ऋषि उरांव को अपर न्यायायुक्त की स्पेशल अदालत में पेश किया गया। यहां से दो दिसंबर तक के लिए सभी को जेल भेज दिया गया। सुनील मुंडा को दुष्कर्म के साथ आर्म्स एक्ट में भी आरोपी बनाया गया है। उसे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी फहीम किरमानी की अदालत में पेश किया गया। उसे 13 दिसंबर तक के लिए जेल भेजा गया। सुनील के पास से ही पीड़िता का मोबाइल बरामद हुआ था। दो पिस्तौल भी उसी के पास से मिली थी। अगली सुनवाई पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेशी होगी।

यह हुई थी घटना

रांची स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा मंगलवार शाम अपने दोस्त के साथ हॉस्टल लौट रही थी कि संग्रामपुर बस स्टॉप के पास बाइक सवार छह बदमाशों ने पिस्टल के बल पर अगवा कर लिया। बाद में उन्होंने छह अन्य दोस्तों को कार से बुला लिया और पीड़िता को दूर ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया।

रिलीज से पहले ही विवादों में घिरी सलमान खान की 'दबंग 3'

एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई : सलमान खान अभिनीत फिल्म 'दबंग-3' रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है। विवाद के केंद्र में फिल्म के टाइटल सॉन्ग 'हुड़ हुड़ दबंग...' के कुछ दृश्य हैं। हिंदू जनजागृति समिति ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को पत्र लिखकर उन दृश्यों को हटाने की मांग की है, जिनमें 'साधुओं' को हाथ में गिटार लेकर वेस्टर्न स्टाइल में नृत्य करते दिखाया गया है। मांग की गई है कि इन दृश्यों को नहीं हटाने पर फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट न जारी किया जाए। गाने का वीडियो और समिति की तरफ से बोर्ड को लिखे गए पत्र की प्रति सोशल मीडिया पर भी जारी की गई है। 'दबंग-3' 20 दिसंबर को हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होने वाली है। समिति के प्रवक्ता मोहन गौड़ा का कहना है कि साधु-संतों को डांस करते हुए दिखाना हिंदू धर्म का अपमान है। इसकी वजह से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने कहा कि वह सूचना और प्रसारण मंत्रालय व प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर ऐसा कानून बनाने की मांग करेंगे, जिससे फिल्मों में धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले दृश्यों पर लगाम लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि समिति की सलमान खान से अभी इस मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई है। अगर टीम बात करना चाहे तो, उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

सलमान खान। फाइल

हत्या के दोषी को आजीवन कारावास व दस हजार जुर्माना

जागरण संवाददाता, नाहन : नाहन स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार की अदालत ने शुक्रवार को हत्या के दोषी को आजीवन कारावास व दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जिला न्यायवादी मोहिंदर कुमार शर्मा ने बताया कि 20 जनवरी, 2016 को त्रिलोकपुर पंचायत प्रधान विष्णु परमार ने पुलिस स्टेशन कालाअंब को फोन कर सूचना दी थी कि ललिता देवी मंदिर के पास जंगल में युवती का शव पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने पाया कि शव शॉल से ढका था और गले में रस्सी बंधी थी। लड़की के गले पर रस्सी से गला घुटने के निशान पाए गए। पुलिस टीम ने प्रधान को जानकारी देने वाले रिंकू राम से बातचीत की। रिंकू ने बताया कि 26-27 साल का एक युवक और 23-24 साल की एक युवती उसकी दुकान से प्रसाद लेकर मंदिर की तरफ गए थे। इसके बाद जब वह शिव मंदिर के पास जंगल में घास काट रहा था तो उसने देखा कि युवती रो रही थी युवक ने उसको मारने के लिए पत्थर उठाया, मगर रिंकू को देखकर उसने पत्थर फेंक दिया। इस घटना की जानकारी रिंकू राम ने मंदिर के चौकीदार करमचंद व पंचायत प्रधान विष्णु परमार को दी। जब तक रिंकू और करमचंद पहुंचे तब तक लड़की की हत्या हो चुकी थी।

नौसेना में कमीशन हुआ डोर्नियर विमान

- पोरबंदर में हुई तैनाती, पहली खेप में आए चार निगरानी विमान
- युद्धक अभियानों, समुद्री निगरानी, खोज और बचाव कार्यों में होगा उपयोग

पोरबंदर, प्रेट्र : भारतीय नौसेना ने छठे डोर्नियर विमान के स्क्वाड्रन गुजरात के पोरबंदर शहर में तैनात कर दिए गए हैं। इस बंदरगाह शहर में इनकी तैनाती का मकसद पाकिस्तान से लगी समुद्री सीमा पर निगरानी और दुरुस्त करना है। पहली खेप में मिले चार विमानों का इस्तेमाल इलेक्ट्रानिक युद्धक अभियानों, समुद्री निगरानी, खोज और बचाव कार्यों में किया जाना है। इस विमान का विशिष्ट कार्य हथियारों के संचालन स्थल तक भेदे जाने वाले लक्ष्य के समग्र आंकड़े और जानकारियां उपलब्ध कराना है।

नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल एमएस पवार ने शुक्रवार को कमीशन किया है। इस बहुआयामी विमान को भारतीय नौसेना की एयर स्क्वाड्रन 314 ने रैप्टर्स (शिकारी पक्षी) नाम दिया है। जल क्षेत्र में भारतीय नौसेना को निगरानी और सुरक्षा में इससे उत्तरी अरब सागर में काफी बढ़त मिल जाएगी। इस अहम क्षेत्र में तैनाती के चलते किसी भी जरूरत के वक्त सबसे पहले इसी स्क्वाड्रन की भूमिका होगी। उन्होंने बताया कि डोर्नियर विमान पिछले तीन दशकों से उनके साथ सेवारत हैं और किसी भी घातक अभियान का अहम हिस्सा बनते हैं। मुझे खुशी है कि पिछले चार सालों में गुजरात नौसैनिक क्षेत्र बहुत बदल गया है।

नौसेना के वक्तव्य के अनुसार आइएनएएस 314 स्क्वाड्रन के जवान बहुआयामी डोर्नियर एसआरएमआर (शार्ट रेंज मेरीटाइम रीजोनेंस) का संचालन करेंगे। वह चौथी पीढ़ी के इस विमान को उड़ाने वाली पहली स्क्वाड्रन है। इस विमान में लगा ट्विन टर्बोप्रॉप इंजन हिंदुस्तान एयरोनाटिकल्स लिमिटेड (एचएएल) कानपुर ने बनाया है। डोर्नियर ऑपरेटिंग रेंज 1,111 किमी है और इसके संचालन की लागत बेहद कम है। 'मेक इन इंडिया' प्रोजेक्ट के तहत इस विमान को अपग्रेड कर और घातक व आक्रामक बनाया गया है। एचएएल के जरिए नौसेना को कुल 12 नए डोर्नियर विमान हासिल हो रहे हैं। इस विमान में स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर लगे हैं। इसमें कांच का कॉकपिट है और 360 डिग्री वाले एडवांस निगरानी रडार भी लगे हुए हैं। इसमें ऑप्टिकल सेंसर और नेटवर्किंग के फीचर भी हैं। स्क्वाड्रन को पहली बार में अगली पीढ़ी के चार विमान मिल रहे हैं जिसे नई तकनीकों से लैस किया गया है। इन विमानों को इस तरह तैयार किया गया है कि वह एक शिकारी बाज की तरह आसमान से अथाह समुद्र पर पैनी नजर रख सके। विमान के मजबूत डैने और पंजे की मजबूत पकड़ इसे शिकारी पक्षी के गुणों वाला बनाती है। नौसेना को मिलने वाले डोर्नियर विमानों की यह छठी स्क्वाड्रन है।

इस विमान को नौसेना ने रैप्टर्स (शिकारी पक्षी) नाम दिया है। प्रतीकात्मक

राम मंदिर से देश में शांति और भाईचारा कायम होगा : श्री श्री

नागपुर, प्रेट्र : आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने विश्वास जताया है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से देश में शांति आएगी और समुदायों के बीच भाईचारा कायम होगा। श्री श्री अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित मध्यस्थता समिति के सदस्यों में शामिल थे।

यहां हवाईअड्डे पर संवाददाताओं से बातचीत में श्री श्री ने कहा कि देश में लोगों ने अयोध्या में जिस भव्य राम मंदिर की उम्मीद पाल रखी थी, उसके हकीकत में बदलने का काम शुरू हो गया है। यह पूछे जाने पर कि अयोध्या विवाद में मध्यस्थता कमेटी के सदस्य होने नाते वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस रूप में देखते हैं आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री ने कहा, 'काम पूरा हो गया है। हमने जो पहले कहा था वही हुआ है। फैसला भी उसी तरह का है।' एक अन्य सवाल पर उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण का काम जल्द ही शुरू होगा। उन्होंने यह भी कहा कि राम मंदिर के निर्माण कार्यों पर निगरानी रखने के लिए गठित होने वाली कमेटी में वह शामिल नहीं होंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में अयोध्या में विवादित 2.77 एकड़ जमीन भगवान राम लला विराजमान को देने का आदेश दिया था, जो विवाद में एक पक्षकार थे।

बीएचयू कुलपति आवास पर हुआ फिरोज खान का साक्षात्कार

जागरण संवाददाता, वाराणसी

- विवि के आयुर्वेद संकाय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए भी दावेदारी
- विवि प्रशासन ने उन्हें मीडिया से दूर रखने का प्रयास किया

काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के साहित्य विभाग में नियुक्ति प्रकरण पर मचे बवाल के कई दिनों बाद डा. फिरोज खान शुक्रवार को विवि परिसर में दिखाई दिए। वह आयुर्वेद संकाय के संहिता एवं संस्कृत विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के साक्षात्कार के लिए सुबह कुलपति आवास पहुंचे थे। हालांकि विवि प्रशासन ने उन्हें मीडिया से दूर रखने का प्रयास किया। इसी कारण उनका साक्षात्कार वीसी आवास पर रखा गया। सुबह करीब आठ बजे शुरू साक्षात्कार प्रक्रिया में डा. फिरोज को पहले नंबर पर रखा गया।

उनके यहां दिखाई देने के बावजूद विवि प्रशासन उनके बारे में किसी प्रकार की अधिकारिक जानकारी देने से इन्कार करता रहा। मगर साक्षात्कार देने पहुंचे अन्य अभ्यर्थियों के मुताबिक एलडी गेस्ट हाउस से सभी को वीसी गेस्ट हाउस बुलाया गया था, जहां सभी के साक्षात्कार होने थे। अन्य अभ्यर्थी वहीं बैठे ही रह गए और इन लोगों से अलग और पहले डा. फिरोज को विवि के कुछ अधिकारी अपने साथ लेकर आए और साक्षात्कार दिलाकर अपने साथ वापस ले गए। डा. फिरोज खान की नियुक्ति 5 नवंबर को संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में हुई थी। इसके विरोध में संकाय के छात्रों ने वीसी आवास के सामने सात नवंबर से धरना देना शुरू किया, जो लगातार 16 दिनों तक चला। इसके बाद विवि के लिखित आश्वासन पर छात्रों ने धरना जरूर खत्म किया लेकिन, नियुक्ति के खिलाफ उनका आंदोलन अब भी जारी है। इस बीच आयुर्वेद संकाय के संहिता एवं संस्कृत विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों की सूची जारी हुई, जिसमें डा. फिरोज का नाम सबसे ऊपर था। माना जा रहा है कि विवि प्रशासन बीच का रास्ता निकालने पर विचार कर रहा है। सुबह होल्कर भवन में साक्षात्कार प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से इंटरव्यू का स्थान बदल कर वीसी आवास कर दिया गया।

84 वर्ष का जवान हूं, मेरे पुनर्जन्म के बारे में न करें जल्दबाजी : दलाईलामा

जागरण संवाददाता, धर्मशाला

तिब्बती धर्मगुरु दलाईलामा ने कहा है, 'मैं अभी 84 वर्ष का जवान हूं। मेरे पुनर्जन्म के बारे में जल्दी क्यों हैं। मैं काफी अच्छा और स्वस्थ हूं। इसलिए मेरे पुनर्जन्म के बारे में कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए।' दलाईलामा मैक्लोडगंज में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सभागार में तीन दिवसीय 14वें तिब्बती सम्मेलन के समापन अवसर पर उपस्थिति को संबोधित कर रहे थे।

दलाईलामा ने कहा कि तीन दिवसीय सम्मेलन में मेरे पुनर्जन्म को लेकर चर्चा की गई, लेकिन अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम दुनिया की बेहतरी के लिए काम करें, इससे सभी को खुशी मिलेगी। उन्होंने कहा, 'मैंने पहले ही अनुरोध किया है कि हमारे तिब्बती मठों को अध्ययन पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए।' दलाईलामा ने कहा कि चीन में करोड़ों लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं और यह संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। तिब्बत में अधिकारों की बहाली के लिए तिब्बती आत्मदाह कर रहे हैं, उनकी कुर्बानी को नमन है। तिब्बत में लोग चीन सरकार से अधिकारों की मांग कर रहे हैं, तो उसमें क्या गलत है। भारत हमारा गुरु देश है और नालंदा विश्वविद्यालय की परंपराओं को लेकर वह आगे बढ़ रहे हैं। बौद्ध धर्म विश्व के हर कोने में पहुंच चुका है। उन्होंने बौद्ध धर्म की परख करके ही इसका अनुयायी बनने का आग्रह भी किया।

चीन इस बात को लेकर जोर दे रहा है कि अगले दलाईलामा को वही नामित करेगा। इस पर तिब्बती समुदाय में रोष है। दलाईलामा के उत्तराधिकारी के संबंध में चर्चाएं कई वर्षों से हैं। इसी वर्ष हुए तिब्बतियों के विशेष अधिवेशन में यह स्पष्ट संदेश चीन को दिया गया था कि दलाईलामा ही खुद उत्तराधिकारी तय करेंगे। अब हुए तिब्बती धर्म गुरुओं के तीन दिवसीय सम्मेलन में भी यही संदेश चीन को दिया गया है। दलाईलामा ने सम्मेलन से पूर्व केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नए भवन का भी शुभारंभ किया गया। न्होंने कहा कि बहुत कम समय में बहुत कुछ बदलाव भी आया है। जो कि एक खुशी का विषय है।

14वें तिब्बती धर्म सम्मेलन के समापन पर संबोधित करते हुए दलाइलामा। जागरण

अनशन पर बैठे उपेंद्र कुशवाहा की तबीयत बिगड़ी, भर्ती

राज्य ब्यूरो, पटना : बिहार में शिक्षा सुधार को ले 26 नवंबर से मिलर हाईस्कूल के मैदान में आमरण अनशन कर रहे पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री एवं रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की तबीयत शुक्रवार की शाम खराब हो गई। इसके बाद जिला प्रशासन ने उन्हें पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड की आइसीयू में भर्ती कराया। इससे पहले रालोसपा के कार्यकर्ताओं ने उपेंद्र कुशवाहा को ले जा रही एम्बुलेंस को रोकने का प्रयास किया। इसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। वहीं, बाद में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह कांग्रेस सांसद अखिलेख समेत कई नेताओं ने पीएमसीएच जाकर उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली। शुक्रवार दोपहर को वीआइपी अध्यक्ष मुकेश सहनी भी उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में अनशन पर बैठे। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, वरिष्ठ नेता शरद यादव, पूर्व मंत्री वृषिण पटेल, पूर्व सांसद अर्जुन राय और भाकपा के राज्य सचिव सत्यनारायण सिंह समेत महागठबंधन के अन्य नेताओं ने अनशन स्थल पर जाकर उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की और उनके आंदोलन का समर्थन किया।

एक साथ डांस का रिकॉर्ड

अहमदाबाद में 'बालिका बचाओ, बालिका पढ़ाओ' के संदेश के साथ छह हजार छात्र-छात्राओं ने सामूहिक नृत्य कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। एपी

सफलता

बोले आइजी- पोटाली और पालोडी तक पहुंचेंगे, इंद्रावती नेशनल पार्क तक बनाएंगे अपना कैंप

नक्सल मांद अबूझमाड़ में अंदर घुसी फोर्स

अनिल मिश्रा, जगदलपुर

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से निपटने के लिए फोर्स ने अब रणनीति बदली है। बस्तर आइजी सुंदरराज पी ने विशेष बातचीत में कहा कि तीन सालों में फोर्स ने नक्सलियों के गढ़ में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। चिंतलनार, किस्टारम और अबूझमाड़ के सोनपुर तक वर्चस्व के बाद नक्सली अपनी मांद में सिमट गए हैं, लेकिन फोर्स अब उनकी मांद तक पहुंचने की तैयारी में है। सुकमा जिले के पालोडी और दंतेवाड़ा के धुर नक्सल प्रभावित इलाके पोटाली में फोर्स के कैंप खोलने के बाद नक्सलियों को कदम पीछे खींचने पड़े हैं। अब पुलिस की योजना है कि पोटाली के आगे बुरगुम, ककाड़ी, नहाड़ी आदि इलाकों में तलाशी अभियान चलाने के लिए वहां फोर्स की तैनाती की जाए। सुकमा जिले के किस्टारम-चिंतलनार इलाके में नक्सली बहुत सक्रिय रहे। इन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा घटनाएं बीते दस सालों में हुई हैं। अब किस्टारम के आगे पालोडी तक फोर्स पहुंच चुकी है। बीजापुर जिले में इंद्रावती नेशनल पार्क के भीतर कैंप खोला जाएगा। अब इस इलाके सुदूर जंगलों तक पहुंचने की तैयारी की जा रही है। ऐसे ही अबूझमाड़ में भी बासिंग और सोनपुर से आगे जाने की योजना बनाई जा रही है।

आइजी ने कहा कि दो साल पहले जब सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत फोर्स कोलेंग गांव में गई तो महिलाओं ने उन्हें घेर लिया। उनकी मांग थी कि वहां कैंप खोला जाए। लिखित आश्वासन देने के बाद ही वे पीछे हटीं। टीम के साथ आइजी खुद भी थे। दो महीने के बाद कोलेंग में कैंप खोला गया। पोटाली में कैंप खोला गया तो नक्सलियों के इशारे पर विरोध किया गया। अब वहां सड़क सुधर रही है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य का इंतजाम किया जा रहा है।

प्रतीकात्मक

ग्रामीण खुद बताने लगे कहां बिछे हैं बम

आइजी सुंदरराज पी ने कहा कि फोर्स को सबसे ज्यादा नुकसान लैंडमाइन से ही हुआ है। इसकी चपेट में ग्रामीण भी आते रहे हैं। नारायणपुर में तीन महिलाएं और बच्चे प्रेशर बम की चपेट में आए थे। कुछ दिन पहले दो मजदूर बम की चपेट में आ गए। ग्रामीण समझने लगे हैं कि नक्सलियों का साथ देने का खामियाजा उन्हें ही उठाना पड़ता है। यही वजह है कि अब वे खुद सामने आकर बता रहे हैं कि कहां बम बिछे हैं। ऐसे में लगातार बम बरामद हो रहे हैं।

बाहरी घेरा ध्वस्त, जल्द नेताओं तक पहुंचेंगे: आइजी ने कहा कि नक्सली तीन घेरे में रहते हैं। मुठभेड़ में जनमिलिशया सामने होती है, फिर मिलिट्री दलम और आखिरी में कमांडर होते हैं। फोर्स का हमला हाते ही लीडर्स महत्वपूर्ण दस्तावेज आदि लेकर भाग जाते हैं। हमने बाहरी लेयर को निशाने पर लिया। सालभर पहले भेज्जी इलाके में साढ़े चार सौ जनमिलिशिया सदस्यों को पकड़ा तो हल्ला मचा। बाद में ग्रामीण सहमत हो गए। इसके बाद मिलिट्री दलम वाले पकड़ में आने लगे। लीडर भी ज्यादा दिनों तक बच नहीं पाएंगे।

भारत-नेपाल सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास तीन दिसंबर से

जागरण संवाददाता, लखनऊ : भारत और नेपाल की सेनाएं संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास सूर्य किरण 14 में आतंकी ऑपरेशन से निपटने के अपने अनुभव एक दूसरे से साझा करेंगी। नेपाल के रूपदेही जिले के सलझंडी में तीन से 16 दिसंबर तक यह संयुक्त युद्धाभ्यास होगा।

मध्य कमान की ओर से आयोजित होने वाले इस संयुक्त युद्धाभ्यास में दोनों देशों के 300 सैनिक हिस्सा लेंगे। युद्धाभ्यास के दौरान दोनों देशों की सेनाएं आतंकवाद विरोधी अभियानों एवं विद्रोह के खिलाफ कार्यवाही, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान की जाने वाली सहायता के अपने अनुभवों को साझा करेंगी। रक्षा मंत्रालय की जनसंपर्क अधिकारी गार्गी मलिक सिन्हा ने बताया कि सूर्यकिरण युद्धाभ्यास बारी-बारी से भारत और नेपाल में आयोजित किया जाता है। भारतीय सेना इस तरह के सैन्य संयुक्त युद्धाभ्यास विभिन्न देशों में आयोजित करता है। सूर्य किरण सैन्य संयुक्त युद्धाभ्यास दोनों देश आतंकवाद के बदलते तरीकों के खिलाफ सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए किया जाता है।

श्राइन बोर्ड के गठन को तीर्थ पुरोहितों ने बताया काला कानून

जागरण संवाददाता, देहरादून

- तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी महापंचायत ने सीएम से मांगा समय
- तीन दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास कूच करने का एलान

चारधाम श्राइन प्रबंधन बोर्ड विधेयक-2019 के कैबिनेट से मंजूरी के बाद भड़का तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। देवभूमि तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारी महापंचायत आंदोलन का एलान कर चुकी है। उन्होंने इसे काला काननू करार दिया। तीर्थ पुरोहित तीन दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे।

शुक्रवार को आयोजित बैठक में महापंचायत के संयोजक सुरेश सेमवाल ने कहा कि तीर्थ पुराहितों में सरकार के फैसले के खिलाफ खासा आक्रोश है और वे किसी भी सूरत में इस फैसले को स्वीकार नहीं करेंगे। विरोध स्वरूप सभी तीर्थ पुरोहित तीन दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे।

महापंचायत के महामंत्री हरीश डिमरी ने कहा कि उनकी मांग है कि मुख्यमंत्री उन्हें वार्ता के लिए समय दें और उनकी मांग पर विचार करें। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांग न मानी गईं तो वे चार धामों के शीतकालीन पूजा स्थलों में किसी भी जन प्रतिनिधि और अधिकारी को प्रवेश नहीं करने देंगे। गंगोत्री समिति के पूर्व सचिव संजीव सेमवाल ने बताया कि बैठक में विरोध की रणनीति तैयार की गई, जिस पर महापंचायत अडिग है। बताया कि आज महापंचायत पहले शीतकालीन पूजा स्थलों में सरकार की बुद्धि-शुद्धि यज्ञ करेगी। इसके बाद बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और देवप्रयाग के विधायकों का घेराव किया जाएगा।

तीन दिसंबर को सीएम आवास कूच और चार दिसंबर को विधानसभा घेराव किया जाएगा। बैठक में यमुनोत्री मंदिर समिति के उपाध्यक्ष जगमोहन उनियाल और ब्रह्मकपाल तीर्थ पुरोहित संघ के अध्यक्ष उमेश सती समेत बड़ी संख्या में पंडा समाज के लोग उपस्थित थे।

दैनिक जागरण

पराजय से मनुष्य खत्म नहीं होता-मैदान छोड़ने से होता है

गिरावट का सिलसिला

वर्तमान वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के आर्थिक विकास दर के आंकड़े निराश करने वाले तो हैं, लेकिन उनसे हैरानी इसलिए नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा ही होने का अंदेशा था। यह अंदेशा तभी उभर आया था जब पहली तिमाही की आर्थिक विकास दर पांच प्रतिशत पर आ टिकी थी। वास्तव में तभी स्पष्ट हो गया था कि अगली तिमाही में भी आर्थिक विकास दर में गिरावट का सिलसिला कायम रहने वाला है। जुलाई-सितंबर माह की 4.5 प्रतिशत जीडीपी दर बीते छह वर्षों में सबसे कम है। इतनी कम विकास दर इसलिए सरकार की चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि अनुमान यह लगाया था कि विकास दर 4.7 प्रतिशत रह सकती है। अनुमान से भी अधिक गिरावट के बाद सरकार पर ऐसे कदम उठाने का और अधिक दबाव होगा जिनसे विकास दर में गिरावट का सिलसिला थमे। इस दबाव के बावजूद इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि सरकार ने अर्थव्यवस्था की सेहत सुधारने के लिए जो कदम उठाने शुरू किए उनका असर आनन-फानन नहीं हो सकता। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसकी ओर से ये कदम उठाने की शुरुआत ही तब हुई जब दूसरी तिमाही खत्म होने वाली थी। इसकी संभावना है कि सरकार के इन कदमों के साथ त्योहारी खरीद का सकारात्मक असर अगली तिमाही के आंकड़ों में दिखेगा, लेकिन इसके बावजूद अर्थव्यवस्था के फिर से पटरी पर आने में और वक्त लग सकता है। इसकी बड़ी वजह मैन्यूफैक्चरिंग के साथ कृषि क्षेत्र का खराब प्रदर्शन है। यह सामान्य बात नहीं पिछले साल के मुकाबले इस साल कृषि विकास दर लगभग आधी रह गई है।

आर्थिक सुस्ती के कारण किसी से छिपे नहीं। इन कारणों में सबसे चिंताजनक यह तथ्य सामने आना है कि उपभोक्ता खर्च कम हो रहा है। यह कमी शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में हो रही है। इसका मतलब है कि लोग भविष्य को लेकर आशंकित हैं और बचत करना पसंद कर रहे हैं। इससे इन्कार नहीं कि बीते दो-तीन महीनों में सरकार एक के बाद एक करीब दो दर्जन कदम उठा चुकी है और इनमें कुछ कदम ऐसे रहे जिन्हें क्रांतिकारी कहा गया, जैसे कॉरपोरेट दरों में व्यापक कटौती। इस कटौती से कॉरपोरेट जगत को प्रोत्साहन तो मिला है, लेकिन इस तथ्य को ओझल नहीं कर सकते कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं वे आपूर्ति बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में सरकार को कुछ ऐसे भी उपाय करने चाहिए जिससे मांग बढ़े। यह तभी होगा जब उपभोक्ता अपना खर्च बढ़ाएंगे। उचित होगा कि कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के बाद व्यक्तिगत आयकर दरों में कटौती करने के साथ अन्य वे उपाय किए जाएं जिससे लोग अपनी खपत बढ़ाएं।

उचित बदलाव

ग्राम पंचायत के मुख्यालय गांव में ही पंचायत सरकार भवन बनाने की अनिवार्यता समाप्त कर बिहार सरकार ने उचित कदम उठाया है। सुशासन की संकल्पना के एकीकृत केंद्रबिंदु के रूप में कार्य करने वाले इस भवन के निर्माण में जमीन की उपलब्धता बड़ी बाधा बनी हुई थी। पंचायती राज विभाग ने नीतिगत बदलाव करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अगर पंचायत के मुख्यालय गांव में जमीन नहीं मिली तो अधिक जनसंख्या वाले राजस्व ग्राम को प्राथमिकता दी जाएगी। शर्तों में ढील भी दी गई है। जाहिर है सरकार का उद्देश्य साफ है कि राज्य की सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो जाए। सरकार की सोच है कि पंचायत के क्रियाकलापों के सफल कार्यान्वयन के लिए एक भवन का होना जरूरी है जो कार्यालय के रूप में काम करे। पंचायत सरकार भवन में पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत स्तर के सरकारी कर्मियों के लिए स्थान, ग्राम कचहरी के लिए न्यायालय कक्ष, अभिलेखों के संरक्षण के लिए स्थान, स्टोर, बैठकों के लिए हॉल, स्वागत कक्ष, कंप्यूटरीकृत सेवा केंद्र, रसोई एवं शौचालय की व्यवस्था रहेगी। पंचायत के लोग इस दोमंजिले भवन का बहुद्देशीय उपयोग कर सकेंगे। पंचायत में ही सेवा प्रदान करने के अलावा बाढ़ एवं अन्य आपदा में भी इसका उपयोग हो सकेगा। सभी पंचायतों में इस भवन के बनने के बाद सरकार आपके द्वार की सोच साकार हो सकेगी। यहां बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत दी जाने वाली सेवाएं यथा जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र की सेवा सुलभ होगी। आम लोगों को प्रखंड कार्यालय एवं बाबुओं का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। पंचायत स्तर पर ही उन्हें यह सेवा मिल जाएगी। यहां तैनात कार्यपालक सहायक ही आवेदक को बीडीओ या सीओ द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों का प्रिंट उपलब्ध कराएंगे। अगर लोगों को दोबारा इसकी जरूरत होगी तो पहचान पत्र से पुष्टि कर उन्हें मुहैया कराया जाएगा। बहरहाल जरूरत है कि जनप्रतिनिधि एवं सरकारी मुलाजिम पूरे मनोयोग से जनसुविधाएं मुहैया कराएं तभी सरकार आपके द्वार की सोच का सपना साकार हो सकेगा।

पंचायत सरकार भवन के निर्माण से पंचायतों को कार्य संचालन में लोगों के प्रति जवाबदेह बनाने में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही उनके कार्यकलाप भी पारदर्शी हो सकेंगे

संवैधानिक समानता का अधूरा लक्ष्य

शंकर शरण

संविधान दिवस मनाने के साथ ही यह भी समझा जाना चाहिए कि उसके सभी अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हों

कुछ समय से देश में समान नागरिक संहिता की चर्चा बार-बार हो रही है, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसी तरह हिंदू मंदिरों को सरकारी कब्जे से मुक्त कराने की मांग भी अनुसनी बनी हुई है। छोटे-मोटे संगठन और एक्टिविस्ट धर्मांतरण के विरुद्ध कानून बनाने की भी मांग कर रहे हैं। भोजन उद्योग में हलाल मांस का दबाव बढ़ाने की संगठित गतिविधियों के विरुद्ध भी असंतोष बढ़ा है। शिक्षा अधिकार कानून में हिंदू-विरोधी पक्षपात पर भी काफी उद्वेलन है। आखिर इन मांगों पर सत्ताधारियों का क्या रुख है? समान नागरिक संहिता की चाह तो मूल संविधान में ही थी, लेकिन शासकों ने शुरू से इसे उपेक्षित किया। कई बार सुप्रीम कोर्ट के पूछने पर भी कार्रवाई नहीं की। समान संहिता की मांग हिंदू मुद्दा नहीं, बल्कि सेक्युलर मांग है। यह मांग तो सेक्युलरवादियों को करनी चाहिए। धर्मांतरण रोकना भी कानूनी प्रतिबंध का विषय नहीं। धर्मांतरण कराने में मिशनरी रणनीति और कटिबद्धता ऐसी है कि चीन जैसा कठोर शासन भी महज कानून से इसे रोकने में विफल रहा है। धर्मांतरण रोकने के आसान रास्ते की आस छोड़नी चाहिए। इसका उपाय शिक्षा और वैचारिक युद्ध में है। उससे कतरा कर संगठित धर्मांतरणकारियों से पार पाना असंभव है।

कुछ लोग जब-तब हिंदू राष्ट्र की बातें किया करते हैं, जबकि यथार्थवादी मांग यह होती कि हिंदुओं को दूसरे समुदायों जैसे बराबर अधिकार मिलें। दुर्भाग्यवश अधिकांश लोगों को इसकी चेतना नहीं। हालिया समय में संविधान के अनुच्छेद 25 से 31 की हिंदू-विरोधी व्याख्या स्थापित कर दी गई है। कई शैक्षिक, सांस्कृतिक, सामाजिक अधिकारों पर केवल गैर हिंदुओं यानी अल्पसंख्यकों का एकाधिकार बना दिया गया है। सरकार हिंदू शिक्षा संस्थान और मंदिरों पर मनचाहा हस्तक्षेप करती है और अपनी शर्तें लादती है। वह ऐसा गैर-हिंदू संस्थाओं पर नहीं करती। इसी तरह अल्पसंख्यकों को संवैधानिक उपचार पाने का दोहरा अधिकार है, जो हिंदुओं को नहीं है। हिंदू केवल नागरिक रूप में न्यायालय से कुछ मांग सकते हैं, जबकि अन्य नागरिक और अल्पसंख्यक, दोनों रूपों में संवैधानिक अधिकार रखते हैं। ऐसा अंधेर दुनिया के किसी लोकतंत्र में नहीं कि अल्पसंख्यक को ऐसे विशेषाधिकार हों जो अन्य को न मिलें। यह हमारे संविधान निर्माताओं की कल्पना न थी।

1970 के आसपास कांग्रेस-कम्युनिस्ट दुरभिसंधि और हिंदू संगठनों के निद्रामग्न होने से संविधान के अनुच्छेद 25 से 31 को मनमाना अर्थ दिया जाने लगा। संविधान की उद्देशिका में जबरन सेक्युलर शब्द जोड़ने से लेकर दिनों-दिन विविध अल्पसंख्यक संस्थान, आयोग, मंत्रालय आदि बना-बना कर अधिकाधिक सरकारी संसाधन मोड़ने जैसे अन्यायपूर्ण कार्य होते गए। विडंबना यह कि

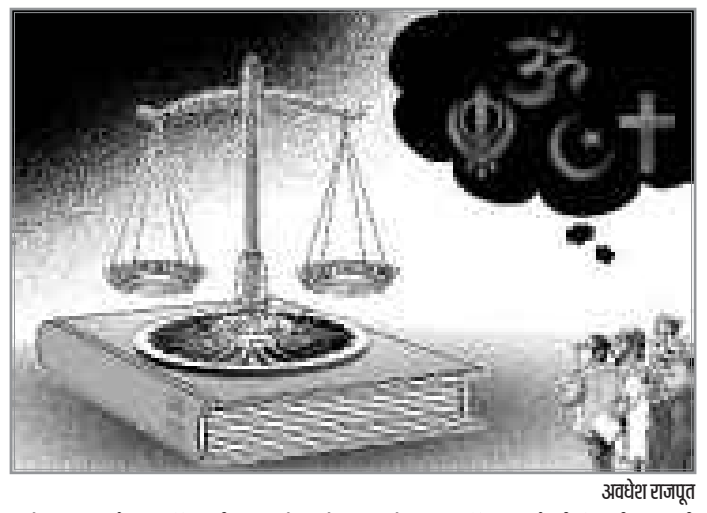

अवधेश राजपूत

इनमें कुछ कार्य स्वयं हिंदूवादी कहलाने वाले नेताओं ने किए। वे केवल सत्ता कार्यालय, भवन, कुर्सी आदि की चाह में रहे। नीतियों में होते परिवर्तनों की दूरगामी मार पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसके विपरीत कम्युनिस्टों ने शिक्षा-संस्कृति की धारा पर कब्जा करने की कोशिश की, क्योंकि सामाजिक बदलाव के मूल स्रोत वही होती है। इसीलिए सत्ता पर काबिज हुए बिना भी कम्युनिस्टों ने देश की शिक्षा-संस्कृति पर वर्चस्व बनाया और हिंदू ज्ञान-परंपरा को बेदखल कर दिया। आज हिंदू धर्म-समाज डूबता जहाज समझा जाने लगा है, जिससे निकल कर ही जान बचाई जा सकती है। इन सच्चाइयों की अनदेखी कर अनेक हिंदुवादी खुद अपनी वाह-वाही करते हैं, किंतु हालिया दशकों में भारत में ही हिंदू धर्म का चित्रण जातिवादी, उत्पीड़क, दकियानूस आदि जैसा प्रचलित हुआ है। यही विदेशों में प्रतिध्वनित हुआ। किसी पार्टी की सत्ता बनने से इसमें अंतर नहीं पड़ा, यह विविध घटनाओं से देख सकते हैं। अयोध्या में राम-जन्मभूमि के लिए सदियों पुराने, सहज हिंदू संघर्ष की जितनी बदनामी पिछले तीन दशकों में हुई, वह पूरे इतिहास में कभी नहीं मिलती। सदैव दूसरों को दोष देना और अपनी भूल न देखना बचकानापन है। यहां ईसाई और इस्लामी दबदबा बढ़ने में उनके नेताओं का समर्पण और दूरदृष्टि भी कारण है। उन्होंने कुर्सी के लिए अपने धर्म-समाज के मूल हितों से कभी समझौता नहीं किया। यह न समझना आत्मप्रवंचना है।

हिंदुओं को दूसरों के समान संवैधानिक अधिकार दिलाने की लड़ाई जरूरी है। इसमें दूसरे का कुछ नहीं छिनेगा। केवल हिंदुओं को भी वह मिलेगा, जो मुसलमानों, ईसाइयों को हासिल है। संविधान दिवस मनाने की अपील तो ठीक है, लेकिन यह समझा जाना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 25-31 को देश के सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू करना आवश्यक। यह न केवल संविधान की मूल भावना के अनुरूप, बल्कि सहज न्याय है। हिंदुओं के हित की कुंजी अन्य धर्मावलंबियों जैसे समान अधिकार में है। स्वतंत्र भारत में हिंदू समाज का मान-सम्मान, क्षेत्र संकुचित होता गया है और यह प्रक्रिया चालू है।

धर्मांतरण रोकना सामाजिक काम है। भारत में यह आसान भी है। धर्मांतरण को समान धरातल पर लाना चाहिए। विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन-परीक्षण का वातावरण बनाना चाहिए। चूंकि ईसाइयत और इस्लाम धर्मांतरणकारी हैं, इसलिए वे विपरीत गमन का विरोध नहीं कर सकते। वस्तुतः पश्चिम में पिछली दो-तीन सदियों में एक विस्तृत श्रेष्ठ साहित्य तैयार हुआ जिसने ईसाइयत की कड़ी समीक्षा कर यूरोप को चर्च अंधविश्वासों से मुक्त कराया। फलतः वहां ईसाइयत में धर्मांतरण शून्यप्राय हो गए। उसी विमर्श को भारत लाकर यहां ईसाई मिशनों को ठंडा करना था, किंतु दुर्भाग्य से गांधीजी ने उस आलोचनात्मक विमर्श के बदले मिशनरी प्रचारों को ही आदर देकर ईसाइयों को 'अच्छा ईसाई' बनने का उपदेश दिया। फलतः यहां मिशनरी और जम गए। जबकि धर्मांतरण रोकने का रामबाण सभी धर्मों के वैचारिक दावों के खुले बौद्धिक परीक्षण में है। इसी से हिंदू, बौद्ध, सिख धर्म सुरक्षित होंगे, कानून बनाकर नहीं। तुलनात्मक धर्म अध्ययन और शोध को विषय के रूप में शिक्षा में स्थापित करना इस में उपयोगी होगा।

यह सब करना कोई हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं, बल्कि हिंदू-विरोधी भेदभाव खत्म कर स्थिति सामान्य बनाना भर है। जैसे जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटाना सामान्यीकरण है, कोई हिंदू राज्य बनाना नहीं। इसी प्रकार अनुच्छेद 25-31 के व्यवहार में की गई विकृति को खत्म कर उसे सबके लिए बराबर घोषित करना एक सामान्यीकरण भर होगा। इसके बिना हिंदुओं के हितों पर दिनों-दिन चोट बढ़ती जाएगी।

(लेखक राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

पारदर्शिता से बचते राजनीतिक दल

जगदीप एस छोकर

देश में लोकतंत्र तभी ठीक से चल सकता है जब देश की राजनीति वास्तव में पारदर्शी बनेगी

चुनावी बांड संबंधी योजना एक बार फिर चर्चा में है। जहां सत्तापक्ष चुनावी बांड स्कीम को एक सही और साहसी कदम बता रहा है वहीं विपक्षी दल और स्वैच्छिक संस्थाएं इस योजना की कमियों और गलतियों की तरफ देश का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। अगर इस सारी बहस को देखा जाए दो बातें तो स्पष्ट होती हैं। पहली यह कि यह योजना पारदर्शिता को आगे बढ़ाने के बजाय गोपनीयता को बढ़ावा देती है और दूसरी यह कि इसे जारी करने का तरीका ठीक नहीं था। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जिस दिन संसद में बजट इस योजना का उल्लेख किया था उसी दिन एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि चुनावी बांड के तहत पैसा देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। उनकी बात सही साबित हो रही है। इस स्कीम से पारदर्शिता नहीं बढ़ रही है। चंदे में पारदर्शिता एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आवश्यक है। यह एक अजीब बात है कि सब राजनीतिक दल पारदर्शिता के बारे में बहुत बड़ी-बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन जब उसे व्यावहारिक रूप से लागू करने का समय आता है तो बिना किसी भेदभाव के सभी दल एकजुट हो जाते हैं। प्रत्येक राजनीतिक पार्टी कहती है कि पहले बाकी दल पारदर्शी हों, तब हम भी पारदर्शी हो जाएंगे।

यह भी कहा जाता है कि चुनाव लड़ने के लिए पैसे सरकार को देने चाहिए, जिसे स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन कहा जाता है। इसमें कई पेचीदगियां हैं। पहली तो यह कि सरकार जो पैसे देगी वे वास्तव में जनता के पैसे ही होंगे। अगर जनता को यह बताया जाए कि उसके पैसे उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के लिए दिए जाएंगे तो बहुत कम लोग इसके लिए तैयार होंगे। दूसरा मुद्दा है कि चुनावी खर्च के लिए कितना पैसा दिया जाए? इसका अनुमान लगाने के लिए यह जानना जरूरी है कि चुनाव पर सब मिलाकर कितनी राशि खर्च होती है ताकि उतनी या उससे कुछ अधिक राशि का बजट में प्रावधान किया जा सके। समस्या यह आती है कि कोई भी उम्मीदवार और राजनीतिक दल यह बताने को राजी नहीं है कि उसने वास्तव में कितने पैसे खर्च किए? तीसरा मुद्दा है कि अगर उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के लिए जनता के पैसे दिए जाएंगे तो फिर उनको कहीं और से पैसे लेने की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए कोई राजनीतिक दल राजी नहीं है। घूम-फिर कर बात वहीं आती है कि दलों को यह सार्वजनिक करना होगा कि उनको कितने पैसे मिले और कहां से? जब तक यह नहीं होता तब तक चुनावी और राजनीतिक चंदों में पारदर्शिता की बात करना सरासर निरर्थक है।

इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के प्रयत्नों का सभी राजनीतिक दलों ने पुरजोर विरोध ही किया है। इसका एक ठोस प्रमाण है तमाम राजनीतिक दलों द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग के वर्ष 2013 के निर्णय की खुलेआम अवहेलना करना। तीन जून 2013 को केंद्रीय सूचना आयोग ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया था कि छह राष्ट्रीय राजनीतिक दल (भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी) सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पब्लिक अथॉरिटी हैं। उन्हें सार्वजनिक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए और सूचना अधिकार के अंतर्गत मांगी गई सूचनाएं जनता को देनी चाहिए, लेकिन इन सभी दलों ने इस निर्णय को मानने से इन्कार कर दिया। अब यह मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

देश में लोकतंत्र तभी ठीक से चल सकता है जब देश की राजनीति स्वच्छ हो। राजनीति स्वच्छ होने के लिए राजनीति में वास्तविक पारदर्शिता अनिवार्य है। इसके लिए राजनीतिक दलों और राजनीतिक नेताओं को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। इसका एक उपाय राजनीतिक दलों पर सूचना अधिकार अधिनियम लागू करना हो सकता है। जब तक यह नहीं होता तब तक आधे मन से किए गए उपाय या फिर गोपनीयता कायम रखने वाले चुनावी बांड योजना से कुछ लाभ नहीं होगा। इससे तो केवल सत्तारूढ़ दल ही मजबूत होंगे।

(लेखक आइआइएम अहमदाबाद में प्रोफेसर, डीन एवं डायरेक्टर इंचार्ज रहे हैं)

response@jagran.com

तथ्य-कथ्य | उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों में सोशल मीडिया के उपयोगकर्ता

स्रोत: विश्व बैंक

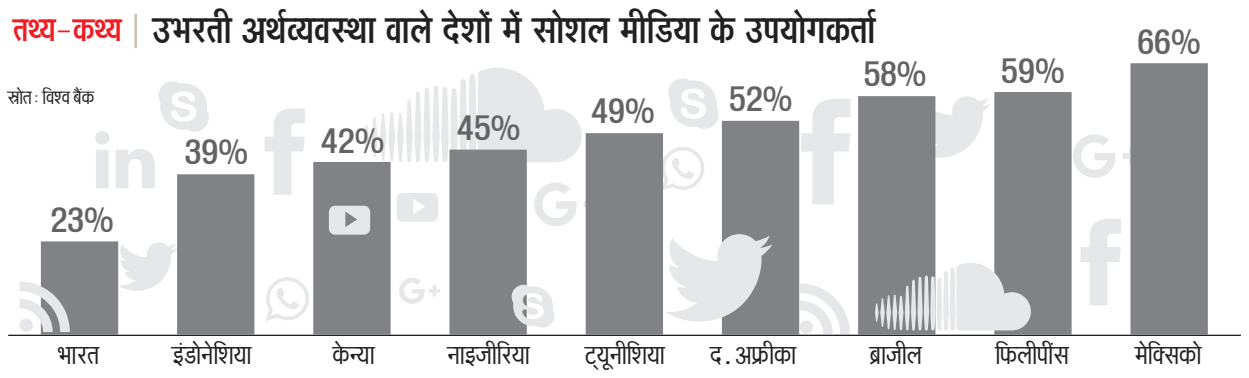

ऊर्जा

आत्मज

आत्मज, पुत्र और संतान एक-दूसरे के पर्यायवाची हैं। संस्कृत भाषा में इन शब्दों की व्याख्या जिस रूप में की गई है, उससे यह इंगित होता है कि किसी भी माता-पिता के द्वारा अपने बेटों के लिए कहे गए ये शब्द अपनी अर्थ सार्थकता से भारतीय संस्कृति के एक बड़े आयाम को प्रकट भी करते हैं। जैसे कि आत्मज शब्द के लिए यह बताया गया है कि पिता स्वयं आत्मरूप में आत्मज में जन्मता है इसीलिए इसे आत्मज कहा जाता है। इसी तरह से पुत्र के लिए यह कहा गया कि जो नरक से पिता को त्राण देता है अर्थात बचाता है वह पुत्र है। संतान से अभिप्राय यह है कि जो वंश को अपनी आगे आने वाली पीढ़ी की संतान देकर निरंतरता देता है वह संतान है।

गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रीरामचरित मानस में दशरथ पुत्र श्रीराम तथा जनकपुत्री के लिए बड़े ही विस्मयकारी विशेषण दिए हैं। मिथिलापुरी में विवाह मंडप के नीचे बैठे हुए श्रीराम तथा मां मैथली के विषय में उन्होंने कहा है कि 'दशरथ सुकृत राम धरि देही।' अर्थात महाराज दशरथ के जीवन के जो सुकृत हैं, वही शरीर धारण करके यहां राम रूप में अवतरित हैं और इसी तरह से महाराज जनक के जीवन के जो सुकृत हैं, उनके वही सुकृत आज मूर्तिमंत होकर मां मैथिली के रूप में यहां उपस्थित हैं। अर्थात पुत्र और पुत्री अन्य कोई न होकर हमारे अपने जीवन के किए गए सुकृत फल ही हैं।

इस समय हम इसलिए प्रसन्नता का अनुभव करते हैं कि आर्थिक दृष्टि से एक बड़ी शक्ति बन गए हैं। किंतु जैसे-जैसे हमारी आर्थिक संपन्नता बढ़ी है, वैसे-वैसे ही हमारी मानवीय संवेदनाएं क्षीण भी हुई हैं। यही कारण है कि आज बहुतायत की संख्या में माता-पिता या तो संकोचवश घर में रहकर अपनी ही संतानों के उत्पीड़न को बर्दाश्त कर रहे हैं अथवा अपने भरण-पोषण के अधिकार की याचना करते हुए न्यायालयों के चक्कर लगा रहे हैं और दोष नई पीढ़ी को दे रहे हैं। किंतु हमारी परंपरा जब यह कह रही है कि आत्मजों के रूप में हमारे सुकृत ही हमारे सामने हैं तो हमें अपने जीवन में सजग होकर सुकृत का आचरण ही करना चाहिए।

डॉ. गदाधर त्रिपाठी

खाद्य पदार्थों की बर्बादी

डॉ. मोनिका शर्मा

अफसोस कि आजादी के बाद से देश में सरकारें आती जाती रहीं, पर अनाज की बर्बादी को नहीं रोका जा सका

हाल में सरकारी गोदाम में रखा 32 हजार टन प्याज सड़ गया। खुद केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री ने बताया है कि 65,000 टन प्याज के बफर स्टॉक में से 50 फीसद प्याज खराब हो गया है। अफसोसनाक है कि एक ओर प्याज सड़ रहा है तो दूसरी ओर बाजार में प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। आम लोगों के लिए प्याज खरीदना बजट बिगाड़ने वाला साबित हो रहा है। यह आमजन को हैरान-परेशान ही नहीं लाचार महसूस करवाने वाली स्थिति है।

यह पहली बार नहीं है जब गोदाम में रखा कोई खाद्य पदार्थ सड़ गया हो। पिछले साल आरटीआइ में सामने आई जानकारी के मुताबिक बीते दस वर्षों में सरकारी गोदामों में 7. 80 लाख क्विंटल अनाज खराब हो गया है। एक सर्वे बताता है कि देश में 10 लाख टन प्याज और 22 लाख टन टमाटर हर साल खेत से बाजार पहुंचते-पहुंचते रास्ते में ही खराब हो जाते हैं। यह असंवेदनशीलता और प्रशासनिक लापरवाही की पराकाष्ठा ही कही जा सकती है कि भुखमरी के आंकड़ों की फेहरिस्त में दिखने वाले देश में सरकारी गोदामों में रखा अनाज बर्बाद हो जाए। हमारे यहां आज भी हर दिन करीब 20 करोड़ लोग भूखे रह जाते हैं। भरपेट भोजन न मिलने से किसी की जान जाने के समाचार आते रहते हैं। इतना ही नहीं देश में ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं जिन्हें जरूरत से कम भोजन में संतोष करना पड़ता है। यही वजह है कि कुछ समय पहले खुली जगहों और गोदामों में भारी मात्रा में अनाज सड़ने की खबरों के बाद उच्चतम न्यायालय कह चुका है कि सरकार को खुले में अनाज को सड़ने के लिए छोड़ने के बजाय इसे गरीबों में बांट देना चाहिए। यकीनन यह एक सख्त आदेशात्मक सुझाव था। बावजूद हालात जस के तस हैं। अफसोस कि आजादी के बाद से सरकारें आती जाती रहीं, पर अनाज की बर्बादी को रोकने के प्रति उदासीन रवैया ही अपनाया गया है।

जीवन के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक भोजन है। बावजूद इसके खाद्य पदार्थों के भंडारण से लेकर उन्हें समय पर बाजार पहुंचाने तक, लचरता ही देखने को मिलती है। हर साल देखने में आता है कि सरकार न तो किसानों को फसल का समुचित मूल्य दे पाती है और न ही उपज का सही ढंग से संरक्षण कर पाती है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के मामले में कुप्रबंधन के हालात ऐसे हैं कि कई बार बंपर उत्पादन के बाद भी बाजार में अनाज, फल या सब्जियां महंगी बिकती हैं। दुखद है कि भंडारण की सही व्यवस्था न होने से किसानों को भी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता। ऐसे में यह बात समझ से परे है कि बरसों तक खाद्यान्नों का घोर अभाव झेलने वाले जिस देश ने कड़ी मेहनत के बाद खाद्यान्न उत्पादन में न केवल आत्मनिर्भरता प्राप्त की, बल्कि खाद्यान्न निर्यातक देश भी बना, उसी देश में आज भी अनाज के संरक्षण की सही व्यवस्था नहीं है। देश के नीति-निर्माताओं के लिए यह बड़ा सवाल है कि भंडारण की सही व्यवस्था को लेकर यह ढुलमुल रवैया क्यों है? भूख और महंगाई से जूझ रहे देश में खाद्य पदार्थों की बर्बादी कब तक होती रहेगी?

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

भाजपा की कोशिश

सत्ता के लिए विचारधारा को तिलांजलि शीर्षक से लिखे अपने लेख में डॉ. एके वर्मा ने महाराष्ट्र में शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस गठबंधन के सैद्धांतिक विरोधाभासों की चर्चा की है। यह सही है कि 1966 में शिवसेना की नींव रखने वाले बालासाहेब ठाकरे ने कभी भी मराठी मानुष, हिंदू अस्मिता और कांग्रेस के विरोध के सवालों पर समझौता नहीं किया। उनकी इसी आक्रामकता और स्पष्टवादी दृष्टिकोण ने शिवसेना के लिए कोर वोटरों का एक ऐसा वर्ग तैयार कर दिया, जो उनकी एक आवाज पर अपनी जान छिड़कता था, लेकिन उन्हीं के पुत्र उद्धव ने आज सत्ता के लिए कांग्रेस और उसकी सहयोगी राकांपा से समझौता करने में गुरेज नहीं किया। जहां तक भाजपा का प्रश्न है तो उसने सत्ता खोई है, अपने वोटरों की सद्भावना नहीं। कहा यह जा रहा है कि उसने भी सत्ता के लिए अधीरता दिखलाई, किंतु यदि वह अपनी इसी मुहिम में सफल रहती तो इसे ही उसका मास्टर स्ट्रोक कहा जाता। वैसे भी भाजपा ने मोदी और शाह के नेतृत्व में सफलता की नई ऊंचाइयों को इसलिए छुआ है, क्योंकि अब उसने अपनी राजनीति में विचारधारा और महत्वाकांक्षा का बेहतर समिश्रण करना सीख लिया है। जहां उसने अनुच्छेद-370, राम मंदिर, तीन तलाक और एनआरसी जैसे मुद्दों पर विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया, वहीं कई राज्यों में सत्ता में आने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार दिखी। काम कितना ही मुश्किल क्यों न हो, कोशिश जरूर करो। इसी लक्ष्य के साथ भाजपा नेतृत्व ने महाराष्ट्र में कोशिश की। यह ठीक है कि वहां बाजी पलट गई, लेकिन इस एक हार से न भाजपा की उम्मीदें खत्म होंगी और न ही कोशिशें। प्रसंगवश मिर्जा अजीम बेग की एक शायरी को यहां उद्धृत कर रहा हूं- 'गिरते हैं शहसवार ही मैदान-ए-जंग में, वो शख्स क्या गिरे जो घुटनों के बल चले।'

चंदन कर्ण, देवघर

आसान भाषा में एफआइआर

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआइआर आसान भाषा में दर्ज होनी चाहिए। यद्यपि उत्तर प्रदेश में यह कार्य बरसों से हो रहा है। वस्तुतः अंग्रेजों के कार्यकाल से पुलिस विभाग में उर्दू एवं फारसी शब्दों की प्रधानता रही। जामातलाशी, मुचलका ,अहकाम, मजरूब, मुजामत, बयान, तहरीर, चस्पा, तरमीम जैसे शब्दों का आज भी बहुतायत से प्रयोग हो रहा है, जिनका भावार्थ ढूंढना आज के नव युवकों के लिए टेढ़ी खीर है। आज समय की यही मांग है कि आसान सर्वस्पर्शी व सर्वग्राही भाषा का प्रयोग हो। वर्ष 2011 में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम की अवधारणा के बाद थानों में कंप्यूटरीकरण बढ़ चुका है। पहले उर्दू अनुवादकों की भर्ती होती थी, जो 1995 में अंतिम बार हुई। आज अच्छे पढ़े-लिखे युवा पुलिस में चयनित होते हैं, जिनके लिए ये शब्द क्लिष्ट एवं गूढ़ ही हैं। रोजमर्रा के ऑफिस कार्यों में ऐसी भाषा ही प्रयोग में लाई जानी चाहिए जो सबको आसानी से समझ आ सके। इसमें उर्दू, अंग्रेजी के भी प्रचलित शब्द लिए जाने चाहिए तथा क्लिष्ट शब्दों से भी दूरी बनाई जानी चाहिए, क्योंकि यह कार्रवाई जनसाधारण के लिए होती है। दरअसल इन गूढ़ उर्दू व फारसी शब्दों का अब तक प्रयोग इसलिए होता रहा, क्योंकि जल्दी कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता है। जैसा चल रहा है, उसी में समय पास कर लेते हैं। अब कोर्ट की टिप्पणी आ गई तो सरकारों को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और बिना देरी के आसान भाषा में लिखा-पढ़ी का कार्य शुरू कराना चाहिए।

डॉ. मनोज कुमार शर्मा, स्याना

भ्रष्ट अफसर

आयकर विभाग से फिर हाल ही में 21 अफसरों को जबरन सेवानिवृत्त कर दिया गया। कारण इन पर भ्रष्टाचार के कई मामले दर्ज हैं। इनको मिलाकर इस साल लगभग 85 अधिकारियों को जबरन सेवानिवृत्त कर दिया गया। सब पर भ्रष्टाचार के कई संगीन मामले दर्ज थे। केंद्र सरकार ने हमेशा भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य किया और प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हें चेतावनी भी दी थी। प्रधानमंत्री ने अपने इस सत्र की शुरुआत में ही कहा था कि सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है जिन्होंने इसे बढ़ावा दिया है। भ्रष्टाचार पर रोक के लिए इससे भी सख्त कार्रवाई की जरूरत है।

raialokk97@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

54 सांसदों वाले पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की समाजवादी जनता पार्टी को वर्ष 1990 में 195 सांसदों वाली कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया था, लेकिन करीब चार माह बाद ही कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया था।

आजकल

आसान नहीं शिवसेना के लिए आगे की राह

उमेश चतुर्वेदी
वरिष्ठ पत्रकार

कांग्रेस और शिवसेना वैचारिक रूप से नदी के दो पाट हैं और दोनों पाटों का मिल पाना संभव नहीं है। इसलिए महाराष्ट्र में विरोधी विचारधाराओं वाले दलों की सरकार भले ही बन गई, लेकिन दिल मिल जाएंगे, यह कहना जल्दबाजी होगी। वैसे भी जिन मंत्रियों ने शपथ ली है, उनमें नितिन राउत और बाला साहेब थोराट कांग्रेस के धाकड़ और दबंग नेता हैं। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के छगन भुजबल भी कुछ कम नहीं हैं। लिहाजा तमाम विसंगतियों को दूर करते हुए राज्य में सरकार चलाना शिवसेना के लिए आसान नहीं होगा

प्रतीकात्मक फोटो
साभार : याहू डॉट कॉम

नवंबर 2019 में मुंबई और मई 1996 में दिल्ली के मौसम की तासीर और वक्त का भले ही फासला हो, लेकिन दोनों में कुछ समानताएं जरूर हैं। तब लोकसभा में 162 सीटें जीतकर सबसे बड़ा दल बनकर उभरी भाजपा के नेता अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार महज 13 दिन ही चल पाई। सबसे बड़ा दल विपक्ष में बैठने को मजबूर हुआ, और एक-एक सांसद वाले दल भी सरकार में शामिल होने में कामयाब रहे। ठीक उसी तरह मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा की 105 सीटें जीत चुकी सबसे बड़े दल के नेता देवेंद्र फड़नवीस की सरकार महज 80 घंटे तक ही रह सकी। अब देवेंद्र फड़नवीस को अपने शीर्ष नेता अटल बिहारी वाजपेयी की तरह नेता विपक्ष की भूमिका निभानी है।

ऐसे में एक सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या महज डेढ़ साल के अंतराल पर हुए चुनावों के बाद जिस तरह केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी और उनकी अगुआई में भारतीय जनता पार्टी उभरी और उसके बाद साढ़े पांच वर्ष सरकार चलाने में सफल रही, क्या महाराष्ट्र में वैसा ही इतिहास दोहराया जाने वाला है? चूंकि राजनीति की दुनिया गणित की तरह सटीक नहीं होती, लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्य और राजनीतिक हालात बता रहे हैं कि शिवसेना के सामने आत्मसमर्पण ना करके भाजपा ने बड़ा संदेश दिया है। उसने साफ कर दिया है कि वह अपने सहयोगी दलों का साथ तो चाहेगी, लेकिन उनकी उल-जलूल मांगों के सामने नहीं झुकेगी। महाराष्ट्र के संदेश बिहार, पंजाब और दूसरे राज्यों में उसके सहयोगी दल स्पष्टता से सुन चुके होंगे। इसके बाद उनका आशंकित होना और नए मिजाज के मुताबिक रणनीति बनाना स्वाभाविक है। तो क्या यह मान लिया जाए कि भाजपा अपने गठबंधन में अब दबंग बड़े भाई की भूमिका निभाने को कमर कस चुकी है? महाराष्ट्र के हालात तो कम से कम यही संकेत देते हैं।

भाजपा और शिवसेना के सूत्रों से कुछ खबरें आई हैं कि भाजपा की करीब तीन दशक पुरानी और सबसे विश्वस्त सहयोगी मानी जाती रही शिवसेना ढाई-ढाई वर्ष के मुख्यमंत्री की अपनी मांग से तब पीछे हटती जा रही थी, जब इस मसले को सुलझाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इशारे पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आगे आए थे। तब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आपसी बातचीत में स्वीकार कर लिया था कि अगर भाजपा गडकरी को मुख्यमंत्री बनाती है तो वे ढाई वर्ष के लिए शिवसेना के मुख्यमंत्री की मांग को वापस ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से आई खबरों के मुताबिक उद्धव ठाकरे इस बात पर भी तैयार थे कि गडकरी की अगुआई में बनने वाली सरकार में आदित्य ठाकरे को उप-मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा तो वे नए हालात को स्वीकार कर लेंगे। लेकिन सूत्रों के हवाले से आई खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवसेना की इस बदली मांग को ठुकरा दिया। दरअसल प्रधानमंत्री खुद महाराष्ट्र की चुनावी सभाओं में दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र का नारा दे आए थे। प्रधानमंत्री का मानना था कि अगर गडकरी को मुख्यमंत्री स्वीकार किया गया तो शिवसेना इसे अपनी जीत के तौर पर प्रचारित करेगी और इसके संकेत ठीक नही जाएंगे। इसलिए भाजपा ने महाराष्ट्र की सरकार को कुर्बान करना ज्यादा उचित समझा।

ढाई-ढाई वर्ष के सत्ता के बंटवारे की शिवसेना की मांग को अगर भाजपा स्वीकार कर लेती तो यह भारतीय राजनीति में एक और गलत परंपरा बनती। करीब दोगुनी ज्यादा सीटें जीतने वाला दल सत्ता में सहयोगी की भूमिका में रहे और छोटा दल सत्ता की अगुआई करे, यह उस जनता का अपमान होता, जिसने सबसे बड़े दल को चुना है। वैसे भी महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है, उसे चाहे जितना भी संविधान की रक्षा के तौर पर प्रचारित किया जाए, यह राज्य की जनता के बड़े हिस्सों के मतों का अपमान ही है, क्योंकि जनता ने चुनाव पूर्व गठबंधन को जीत दी थी। भाजपा को बड़ी जीत देने का संकेत यही था कि राज्य की जनता के लिए नई सरकार के संदर्भ में वही उसकी पसंदीदा पार्टी रही। इन संदर्भों में देखें तो शिवसेना की अगुआई में गठित सरकार को राज्य के मतदाताओं का बड़ा हिस्सा शायद ही स्वीकार करे। यहीं पर एक बार फिर वर्ष 1996 की घटनाएं याद आती हैं। भाजपा को सत्ता से अलग-थलग रखने को देश ने स्वीकार नहीं किया और भारतीय मतदाओं ने अगले चुनाव में और आक्रामक ढंग से उसे समर्थन दिया। अगर दो आम चुनावों से भाजपा केंद्र की सत्ता में अपने दम के बहुमत से काबिज है और जनता का उसे व्यापक समर्थन मिला है तो उसकी एक बड़ी वजह यही है कि राजनीति की दुनिया में सारे दलों का उसे अलग-थलग रखने की रणनीति आम लोगों को पसंद नहीं आई। इसके बाद प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीय मतदाता और आक्रामक ढंग से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गोलबंद हुआ।

छोटे दलों के साथ बड़े दलों की सरकार चलाने का अनुभव भाजपा का भी रहा है और निश्चित तौर पर वह अनुभव खराब ही रहा है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह से अलगाव के बाद 63 विधायकों वाली बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती को 176 विधायकों वाली भाजपा ने सहयोग दिया और तब भी तय हुआ था कि आधे-आधे वक्त के लिए दोनों के मुख्यमंत्री होंगे। मायावती ने अपनी मियाद तो पूरी कर ली और बड़े दल वाली भारतीय जनता पार्टी ने उनका धैर्यपूर्वक साथ दिया। लेकिन जब वायदे के मुताबिक भाजपा के नेता कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो मायावती मुकर गईं, और गठबंधन टूट गया। इसी तरह बीते दिनों कर्नाटक में हुआ था, जब जनता दल सेक्युलर जैसी छोटी पार्टी के नेता एचडी कुमारस्वामी को बड़े दल भाजपा ने समर्थन दिया और जब भाजपा की सरकार बनाने की बारी आई तो कुमारस्वामी की पार्टी मुकर गई। इसके बाद कर्नाटक में चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला। कुछ समीक्षक मानते हैं कि महाराष्ट्र में भी ऐसा ही होने की संभावना ज्यादा है।

दरअसल महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने वाले मंत्रियों का इतिहास देखें तो बहुत कुछ सामने आता है। दिल्ली के महाराष्ट्र सदन घोटाला में जेल की यात्रा कर चुके छगन भुजबल पहले शिवसेना के नेता रहे और बाद में विद्रोह करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। उन्हें शिवसेना का आम कैडर स्वीकार नहीं कर पाता था। एक दौर में उनके खिलाफ शिवसेना ने जगह-जगह आक्रामक प्रदर्शन किए थे। उनकी छवि भी साफ नहीं है। अजीत पवार बेशक अभी सरकार में शामिल नहीं हैं, लेकिन माना जा रहा है कि 70 हजार करोड़ रुपये के सिंचाई घोटाले के आरोपी अजीत पवार राज्य के उप-मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इन पुराने और घाघ राजनेताओं पर उद्धव ठाकरे कैसे काबू कर पाएंगे, इसे देखना दिलचस्प होगा।

शिवसेना के समक्ष हिंदुत्व की चुनौती

वैसे शिवसेना के सामने एक और बड़ी चुनौती सामने आने वाली है। उसके कैडर का विकास उग्र हिंदुत्व के साथ आक्रामक शैली की स्थानीय राजनीति करते हुआ है। अपने गठन से लेकर अब तक कुछ मौकों को छोड़कर उसका कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कैडरों से आक्रामक विरोध का रिश्ता रहा है। लेकिन बदले हालात में उन्हें साथ बैठने में हिचक होगी। कुछ वैसी ही हालत महाराष्ट्र के शिवसैनिकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच होने जा रही है, जैसी एक-दूसरे के व्यापक प्रतिस्पर्धी रहे उत्तर प्रदेश के समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के कैडरों के बीच रही। कांग्रेस के साथ से अगर शिवसेना को लंबी पारी खेलनी है तो उसे उग्र हिंदुत्व की राह को छोड़ना पड़ेगा या उसे थोड़ा नरम बनाना पड़ेगा। पार्टी तो बन भी सकती है, लेकिन तीन दशक से स्थानीय स्तर पर तेवर की राजनीति की रवायत में प्रशिक्षित उसके कार्यकर्ताओं के लिए ऐसा कर पाना आसान नहीं होगा। यही शिवसेना की बड़ी चुनौती होगी। इसी आधार पर सरकार की स्थिरता पर सवाल उठेंगे। वैसे कुछ महीने बाद राज्य में स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं। अब तक शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ती रही है। लेकिन बदले हालात में उसे कई जगह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के लिए त्याग करना पड़ेगा। यह त्याग पार्टी के शीर्ष स्तर पर एक हद तक स्वीकार्य हो भी जाए, लेकिन अपनी विकास की बाट जोह रहे स्थानीय कैडरों को यह शायद ही स्वीकार्य हो। शिवसेना के लिए यह भी चुनौती होगी।

भविष्य में भाजपा को बड़ा फायदा होने की उम्मीद

शरद पवार बेशक इन दिनों बड़े रणनीतिकार माने जा रहे हों, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी छवि ऐसे राजनेता की है, जो अवसरवादी है। सोनिया गांधी के विदेशी मूल के सवाल पर उन्होंने तारिक अनवर और पीए संगमा के साथ कांग्रेस से विद्रोह करके अलग पार्टी बनाई। यह बात और है कि 1999 में उसी कांग्रेस के साथ उन्होंने राज्य में और 2004 से लेकर 2014 तक केंद्र में सरकार चलाई। चूंकि वे महाराष्ट्र में इसी रूप में स्थापित हैं और उनका अपना एक वोट बैंक भी है, लिहाजा उनका इस नए गठबंधन में कोई नुकसान नहीं होने जा रहा। रिमोट कंट्रोल से सरकार वे चलाएंगे और सत्ता की मलाई उनके लोग और उनकी पार्टी चखती रहेगी। कांग्रेस राज्य में इतनी कमजोर हो गई है कि उसके पास खोने को कुछ खास है भी नहीं, इसलिए मौजूदा गठबंधन में उसे सिर्फ पाना ही है। वैसे भी वह सबसे ज्यादा फायदे में है। जिस सोनिया गांधी को बाल ठाकरे स्वीकार तक नहीं कर पाते थे, उनके बेटे और पोते उनके सामने सरकार बनाकर झुक ही गए हैं। कांग्रेस मौजूदा गठबंधन में शिवसेना को उदार हिंदुत्व की तरफ मोड़ने की कोशिश भी करेगी। ऐसा करने के लिए उसने शपथ ग्रहण के दिन संकेत दे भी दिए, जब उसके शीर्ष नेतृत्व ने शपथ ग्रहण से दूरी बनाए रखी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि किसे सबसे ज्यादा नुकसान होना है, जाहिर है कि वह नुकसान शिवसेना को ही उठाने के लिए तैयार रहना होगा। हिंदुत्व के नाम पर बने वोट बैंक को जब निराशा होगी तो वह कांग्रेस या राष्ट्रवादी कांग्रेस की बजाय उदार हिंदुत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की ओर जाएगा।

कांग्रेस पर मुश्किल है भरोसा करना

राजनीति के कई सिद्धांत परंपराओं के आलोक में विकसित होते हैं। भारतीय राजनीति में कई बार ऐसा हुआ है कि बड़े दल ने सत्ता से बाहर रहकर छोटे दल को समर्थन दिया, इसके बावजूद वे सरकारें चल नहीं पाईं। सबसे पहले 1979 में केंद्र में चौधरी चरण सिंह की अल्पमत सरकार को कांग्रेस ने समर्थन दिया और उस सरकार को संसद जाने से पहले ही धराशाई कर दिया। वर्ष 1990 में 54 सांसदों वाले चंद्रशेखर की समाजवादी जनता पार्टी को 195 सांसदों वाली कांग्रेस ने समर्थन दिया। जिस तरह इस बार भी कुछ राजनीतिक समीक्षक कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे सरकार पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी, कुछ वैसा ही 1990 में भी दावा किया गया था। लेकिन चंद्रशेखर की सरकार चार महीने बाद ही कांग्रेस ने गिरा दी थी। सरकार बनवाने और गिराने की परंपरा को कांग्रेस ने जारी रखा। पहले 1997 में राजीव गांधी की हत्या की जांच कर रहे जैन आयोग की रिपोर्ट में तत्कालीन जनता दल के सहयोगी डीएमके का नाम आने के आरोप में तत्कालीन एचडी देवगौड़ा सरकार और 1998 में इंद्रकुमार गुजराल सरकार को गिराने में कांग्रेस ने तत्परता दिखाई। चाहे चरण सिंह रहे हों या देवेगौड़ा या इंद्रकुमार गुजराल, ये सभी नेता कभी न कभी कांग्रेस में रहे थे और उनकी विचारधारा कांग्रेसी सोच से ज्यादा इतर नहीं थी। फिर भी खुद के लायक बेहतर मौका ताड़ते ही उन सरकारों को गिराने में कांग्रेस ने गुरेज नहीं किया तो क्या गारंटी है कि ठीक विपरीत विचारधारा वाली पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे की सरकार को कांग्रेस बहुत देर तक बर्दाश्त कर पाएगी।

खरी-खरी

सालगिरह और वादों का चाबुक

पीयूष पांडे

प्रेम विवाह का एक नकारात्मक पहलू यह है कि प्रेमी-प्रेमिका के बीच विवाह से पहले कथित प्रेम का एक दौर होता है, जिसे अंग्रेजी में 'कोर्टशिप' कहते हैं। माननीय कोर्ट को प्रेम के लफड़े में क्यों घुसेड़ा गया, यह अंग्रेजी के अल्पज्ञान की वजह से अपन नहीं जानते। इतना जानते हैं कि इस कोर्टशिप में मुवक्किल उर्फ प्रेमी उसी तरह झूठे वादे करता है, जैसा पब्लिक की कोर्ट में राजनेता। खासकर वो, जिसे सत्ता में आने की उम्मीद ना हो।

अपन ने भी कोर्टशिप के दौर में मुफ्त का राग जपते हुए प्रेमिका से ऐसे वादे कर दिए, जिसका बजट कभी स्वीकृत होना ही नहीं था। प्रेमिका संयोग से पत्नी बन गई और वादें बेड़ियां। अब हर साल वो पुराने वादे तानों के चाबुक के रूप में मुझ पर बरसते हैं। वैवाहिक वर्षगांठ नजदीक आते ही चाबुक पर नमक भी रगड़ा जाता है। साल-दर-साल वादों के कर्ज में ब्याज के रूप में एक साल और जुड़ जाता है।

शादी से पहले का मेरा मेनिफेस्टो विवाह की वर्षगांठ पर उसी तरह जमकर उछाला जाता है, जैसे आजकल उद्धव का राहुल के बारे में दिया पुराना बयान।

ऐसा नहीं है कि मैंने वादा पूरा करने के बारे में नहीं सोचा। सोचा, तो थर्ड-पार्टी ने मामले को कॉम्पलेक्स बना दिया। थर्ड-पार्टी यानी बच्चे। पत्नी बिना थर्ड-पार्टी के विदेश जाने को तैयार नहीं, और अपना तर्क रहा कि वादों के टाइम थर्ड-पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं था।

अब हाल यह है कि बीवी को ताने मारने की आदत है, और अपन को झेलने की। शादी की सालगिरह पर पुराने वादों को एक-एक कर बाउंसर की तरह हमारी तरफ फेंका जाता है, और अपन मुंडी झुकाए एप में बैंक-बैलेंस देखते हुए उन्हें 'डंप' करते रहते हैं। कभी-कभी मेहमानों के सामने भी गोलीबारी होती है और तब सिवाय जलील होने के कोई चारा नहीं होता, क्योंकि वादे किए तो हमने ही थे।

मगर, कोर्टशिप के वादों को लेकर अब अपनी स्पष्ट सोच है। पहली, यदि खजाने में दम ना हो तो उलजुलूल वादे नहीं करने चाहिए। सरकार को भी, प्रेमी को भी। वादे पूरा ना करो तो बुरा पब्लिक भी मानती है, प्रेमिका उर्फ बीवी भी। मामला हाथ से निकल गया तो ब्याज चढ़ता चला जाता है, जिसे पाटने का एक ही उपाय है कर्ज लेना। इमरान आजकल यही कर रहे हैं। मैं भी विवाह की इस सालगिरह पर यही सोच रहा हूं।

इमरान के साथ चीन है। मेरे साथ कौन-कौन समीचीन है? देखते हैं!

ट्वीट-ट्वीट

बहुत ही दुखद तेलंगाना में पशु चिकित्सक महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या! ऐसे दरिंदों को सिर्फ और सिर्फ फांसी होनी चाहिए।
गीता फोगाट@geeta_phogat

हैदराबाद में डॉक्टर की हत्या की खबर इतनी खतरनाक है कि कोई लड़की इस पर बोलना भी नहीं चाहती। स्कूटी खराब होने पर रुकना इतना खतरनाक है? ऐसी घटना 24 घंटे का डर पैदा करती है। लड़कियों के इस डर को कोई समझ नहीं सकता।
ज्योति यादव@jyotiyadaav

इस घटना पर समझ नहीं आ रहा कि क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करूं। समय आ गया है कि एक राष्ट्र के रूप में हम लोगों में ऐसा भय पैदा करें कि आगे से वे इस तरह की बर्बरता की हिम्मत न जुटा सकें।
रकुल सिंह@Rakulpreet

आज आजादी के दशकों बाद जब ये खबर पढ़ने को मिलती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 63 फीसद गर्भवती महिलाएं प्रसूति के दिन तक काम करती हैं तो चिकित्सा सेवाओं समेत सामाजिक- आर्थिक व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाने का मन करता है। दुखद!
अखिलेश यादव@yadavakhilesh

अंतरराष्ट्रीय स्तर का धार्मिक पर्यटन केंद्र बने अयोध्या

संजय दुबे

किसी भी स्थान विशेष की आर्थिक प्रगति वहां के सामाजिक सौहार्द पर निर्भर होती है। यह बात अयोध्या के विकास पर भी लागू होती है। धार्मिक पर्यटन इसमें मुख्य भूमिका निभा सकता है। हालांकि एक बात इसमें काफी दिलचस्प है कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य भागों से भी लोग अयोध्या को अपने धार्मिक कैलेंडर में शामिल नहीं करते। काशी, प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार जैसे शहर हमेशा से इस सूची में महत्वपूर्ण स्थान पाते रहे हैं, जबकि एक प्रख्यात श्लोक में कहा जाता है :

अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका। पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिकाः।।

अर्थात पुराण में वर्णित ये सभी नगर मोक्षदायी हैं। अयोध्या के इस सूची में शामिल होने और अयोध्या विवाद का हल हो जाने पर यहां के लोगों की आर्थिक स्थिति में बदलाव होना तय है। जैसे काशी और प्रयागराज में धार्मिक पर्यटन से वहां के लोगों को अच्छी खासी आमदनी होती है। हर पितृपक्ष और गंगा स्नान पर्व पर काशी में बाबा विश्वनाथ दर्शन के पूजन अर्चन के चलते साल भर जहां यात्रियों का आना लगा रहता है। वहीं प्रयागराज में हर वर्ष माघ मेले के चलते लाखों लोगों के प्रयाग आने से वहां के निवासियों को आर्थिक रूप से काफी फायदा मिलता है। कुंभ जैसे महापर्व पर देश-दुनिया के लोग इस अस्थायी शहर के बाशिंदे हो जाते हैं। इसका सीधा फायदा मिलता है कुटीर उद्योग से जुड़े लोगों को। दोना, पत्तल, कुल्हड़, प्लास्टिक, रस्सी, किराना, मिठाई आदि सामानों की काफी मांग निकलती है। साथ ही हवन, पूजन सामग्री सहित फूल-माला, रिक्शा आदि अन्य ऐसे और कई छोटे मोटे काम निकलते हैं। खास बात यह है कि इसका संबधित दुकानदार, मजदूर और कारोबारियों को हमेशा शिद्दत से इंतजार रहता है।

काशी, प्रयाग, मथुरा के इतर अयोध्या इस मामलें में उतना संपन्न नहीं है, जितना उसे होना चाहिए। यहां पर रामनवमी के अतिरिक्त पूर्णिमा के स्नान पर मेला, रामायण मेला, पंचकोशी परिक्रमा जैसे कई पर्व हैं जिन्हें हम विश्व व्यापी बनाकर उसे धार्मिक पर्यटन से जोड़ सकते हैं। अयोध्या को जिस तरह का विश्व पटल पर होना चाहिए वैसा अभी यह है नहीं। दुनिया की लगभग हर प्रमुख भाषा में रामायण का होना क्या अयोध्या को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसी तरह का एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का शहर बनाता है? नहीं, तो ऐसा क्यों? शायद इसके पहले की सरकारों ने इस पर समुचित ध्यान नहीं दिया।

कनक भवन, अयोध्या
फोटो साभार : यूपी टूरिज्म डॉट जीओवी इन

हालांकि इस क्षेत्र के समग्र विकास की शुरुआत इसी सरकार ने पिछले वर्ष 2018 में कर दी थी। उस समय केंद्र में पर्यटन व संस्कृति मंत्री महेश चंद शर्मा ने संसद में रामायण सर्किट बनाने की घोषणा की थी। इसे स्वदेश दर्शन योजना के नाम से भी जाना जाता है। यह महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री की महत्वकांक्षी योजना मानी जाती है। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि जब प्रधानमंत्री जनकपुर, नेपाल गए थे तब वहां उन्होंने इसके संदर्भ में काफी कुछ कहा था। माता सीता के धाम में पूजा अर्चन करने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। रामायण सर्किट योजना प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस योजना में राम से जुड़े शहरों को जोड़ा गया है। अयोध्या के सरयू घाट नए कलेवर में रंग गए हैं। दीपावली का रिकार्ड भी अयोध्या ने खुद का ही तोड़ा है। इन सारी व्यवस्थाओं के बीच इस रामनगरी को लेकर धार्मिक पर्यटकों के बीच काफी आकर्षण देखा जा रहा है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने भी आम पर्यटकों के मन में सुरक्षा समेत अन्य मामलों से पैदा होने वाली अनेक आशंकाओं को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इस फैसले के बाद देश के हर हिस्से से लोगों में अयोध्या दर्शन को लेकर काफी उत्सुकता है। धार्मिक पर्यटन से अगर रोजगार पैदा होगा तो जाहिर सी बात है कि इन क्षेत्रों की गरीबी दूर होगी। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों को फायदा होगा। यहां कई ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जो पीढ़ियों से मां जानकी और भगवान राम के वस्त्र बनाते आ रहे हैं। अयोध्या आज भी लाखों देशी-विदेशी पर्यटक और तीर्थयात्री पहुंचते हैं, पर अभी भी देश के प्रमुख तीर्थस्थलों की अपेक्षा यहां उस संख्या में नहीं आते हैं। इसके लिए सरकार को अयोध्या के बारे में रोचक और आधुनिक ढंग से बताने की जरूरत है। आज के आधुनिक परिवेश और डिजिटल हो चले युवा वर्ग के बीच इसका प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए।

यह तथ्य और सर्व विदित है कि अयोध्या में श्रीराम के दर्शन के पूर्व हनुमानजी के दर्शन का विधान है। कहा जाता है कि श्रीराम ने हनुमानजी को यह अधिकार दिया कि जो भी व्यक्ति उनका दर्शन करना चाहेगा उसे पहले उनसे आज्ञा लेनी होगी। सरयू नदी में अपने पाप धोने के लिए स्नान से पूर्व भी अनुमति लेनी होगी। यह परंपरा आज भी जारी है।

आमजन को अयोध्या के इतिहास, उसकी महत्ता से परिचित कराते हुए उसे धार्मिक पर्यटन से जोड़कर इस समूचे इलाके के हिंदू मुसलमानों के आर्थिक स्तर को भी सामाजिक रूप के साथ साथ समृद्ध किया जा सकता है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या आप वित्त मंत्री के इस कथन से सहमत हैं कि देश में मंदी जैसी स्थिति नहीं है?

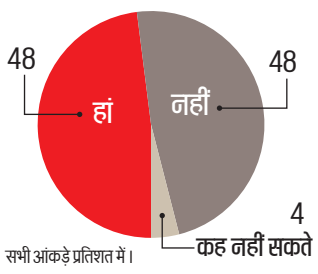

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या गोडसे पर बयान देने के लिए भाजपा को साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को पार्टी से निकाल देना चाहिए?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

सेक्युलर उद्धव के लिए सावरकर हैं गौड़,
नहीं अयोध्या याद अब दिया राम को छोड़।
दिया राम को छोड़ रोम से जोड़ा नाता,
अब तो शरद पवार बन गए नए विधाता।
हैं कंधे पर लाद ढो रहे 'भगवे' का शव,
तज कर सभी विचार पिता के सेक्युलर उद्धव!
- ओमप्रकाश तिवारी

मुद्दा

शिक्षा में न हो धार्मिक भेदभाव

डॉ. रसाल सिंह
प्राध्यापक, किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

सांस्कृतिक विशिष्टताओं का सम्मान होना चाहिए, किंतु विधि के सामने सबकी समानता सुनिश्चित हो। राष्ट्र में किसी भी धार्मिक समूह को वरीयता और अन्य की उपेक्षा अशांति पैदा करती है

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान विभाग में डॉ. फिरोज खान की नियुक्ति का विरोध पिछले दिनों बौद्धिक जगत में चर्चा का विषय रहा है। संबंधित विभाग के छात्रों ने बीएचयू के संविधान और हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का हवाला देते हुए यह विरोध किया। वैसे हमें इस नियुक्ति का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में विश्वविद्यालय की नियमानुसार गठित चयन समिति का निर्णय अंतिम और सर्वोपरि होता है। उच्चतम न्यायालय ने भी विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का सम्मान करते हुए नियमानुसार गठित चयन समिति के निर्णय में कभी हस्तक्षेप नहीं किया है।

हिंदू धर्म अत्यंत उदार और सर्वसमावेशी है। उसमें कभी किसी 'दुराग्रह' को स्वीकृति नहीं मिली। यह नियुक्ति इस उदार दृष्टि का ही प्रतिफलन है। इस नियुक्ति का कुछ छात्रों द्वारा किया गया विरोध संभवतः भाषा और धर्म दोनों को सीमित दृष्टि से देखने का परिणाम है। उल्लेखनीय है कि संस्कृत भाषा ही नहीं, धर्मग्रंथों का भी पठन-पाठन एवं अनुवाद दारा शिकोह से लेकर मैक्समूलर तक ने किया है। रसखान से लेकर नजीर अकबराबादी तक हिंदू देवी-देवताओं पर भक्ति-काव्य लिखने वाले मुस्लिम कवियों की सुदीर्घ परंपरा है।

हालांकि यह भी समझने की आवश्यकता है कि धर्म, महज ज्ञान का ही नहीं, भावना का विषय भी है। धर्मशास्त्र एवं पौरोहित्य के अध्यापन में सैद्धांतिक पक्ष के अलावा व्यावहारिक/ प्रायोगिक पक्ष भी है। इस्लाम धर्म और सनातन धर्म में 'मूर्तिपूजा' जैसे कई विषयों पर गहरी असहमतियां हैं।

यह विरोध न्यायसंगत भले न हो विचारणीय अवश्य है। छात्रों के विरोध ने कुछ आधारभूत प्रश्न खड़े किए हैं जो विचारणीय हैं :

क्या उदारता की अपेक्षा सिर्फ हिंदुओं से ही की जानी चाहिए या सभी धर्मों को उदार और समावेशी होने की आवश्यकता है? अल्पसंख्यक संस्थानों में धर्म विशेष को दिए जाने वाले विशेषाधिकार और वरीयता कितनी न्यायसंगत है? इन संस्थानों में पिछड़ों की हिस्सेदारी नगण्य है। उनके लिए आरक्षण का प्रावधान क्यों नहीं होना चाहिए?

क्या यह विरोध समान नागरिक संहिता की महत्ता, उपयोगिता और आवश्यकता को स्थापित नहीं करता है? क्या धर्म विशेष के आधार पर मिलने वाले विशेषाधिकारों की समीक्षा करते हुए सभी धर्मानुयायियों को सार्वजनिक स्थानों और सरकारी संस्थानों में एक समान अधिकार सुनिश्चित करने की जरूरत नहीं है? धर्मविशेष के विशेषाधिकारों की सार्वजनिक स्वीकार्यता से ही ऐसे विरोध का आधार बनता है। क्या तुष्टिकरण उदार और लोकतांत्रिक समाज की विषबेल नहीं है?

दरअसल 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान का उद्देश्य भारत के नागरिकों के साथ धार्मिक आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म करना है। पर आज तक समान नागरिक संहिता लागू ना हो पाने के कारण भारत में नागरिक समाज का एक बड़ा हिस्सा धार्मिक कारणों से अपने अनेक अधिकारों और अवसरों से वंचित है। वहीं, एक हिस्सा धर्म विशेष की आड़ में बहुत से विशेषाधिकारों का लाभ ले रहा है।

भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों में विधि के शासन की भावना विद्यमान है। लेकिन अभी भी धार्मिक और लैंगिक असमानता व्याप्त है। विधि के शासन की अवधारणा का अर्थ है विधि के सामने सभी नागरिक समान होने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं व रूढ़ियों की वजह से समाज के किसी भी वर्ग के अधिकारों का हनन रोका जाना चाहिए। यह लोकतांत्रिक और प्रगतिशील समाज का आधार है। साथ ही, विधि के समक्ष समता की अवधारणा के तहत सभी के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए।

राजनीतिक लाभ के लिए कई बार सरकारें/ राजनीतिक दल ऐसे धार्मिक मुद्दों पर बहस या बदलाव से बचते हैं। सरकारों को ऐसे मामलों को कानून और न्याय की दृष्टि से देखना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शाहबानो मामले में लिए गए निर्णय को तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने धार्मिक दबाव में आकर संसद के कानून के माध्यम से पलट दिया था। यह एक प्रतिगामी कदम था।

सुप्रीम कोर्ट ने कई न्यायिक निर्णयों के माध्यम से समाज में समानता हेतु उल्लेखनीय प्रयास किया है। लेकिन सरकार व न्यायालय को इस दिशा में और प्रयास करना होगा।

फोटो साभार : बीएचयू डॉट एसी डॉट इन

आज समान नागरिक संहिता का मुद्दा एक संवैधानिक मसला या सामाजिक/ व्यक्तिगत अधिकारों के मुद्दे से हटकर एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। इसलिए जहां एक ओर कुछ राजनीतिक दल इस मामले के माध्यम से राजनीतिक तुष्टिकरण कर रहे हैं, वहीं उसकी प्रतिक्रिया में धार्मिक ध्रुवीकरण भी हो रहा है।

किसी भी धर्म के मामले में बदलाव को सुगम व स्वीकार्य बनाने के लिए उस धर्म के बहुसंख्यक समर्थन की जरूरत होती है। इसलिए राजनीतिक व न्यायिक प्रक्रिया के साथ धार्मिक समूहों से चर्चा कर मानसिक बदलाव का प्रयास किया जाना भी जरूरी है।

समाज का एक बड़ा हिस्सा आज भी अपने मूल अधिकारों से वंचित है। धर्म विशेष के संस्थानों में वंचित वर्गों के लिए आरक्षण का न होना विचारणीय है। धर्मविशेष के अनुयायियों को प्रश्रय और अन

2017 के आंकड़ों के अनुसार देश में जेलों की क्षमता 3,91,574 कैदियों की थी, जबकि इनमें 4,50,696 कैदी बंद थे। इस तरह देश की विभिन्न जेलों में क्षमता से करीब 60 हजार अधिक कैदी बंद थे।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 30 नवंबर 2019

छोटे शहरों को नई राह दिखा रहा गोरखपुर का को-वर्किंग कैफे

जागरण विशेष ▸ संसाधनों की कमी के कारण दूसरे शहरों में जाने वालों का अपने शहर में सुलभ हुआ कारोबार

जीतेन्द्र पांडेय, गोरखपुर

गोरखपुर जैसे शहर में को-वर्किंग स्पेस यानी साझे ऑफिस की कल्पना मुश्किल काम था, लेकिन आज यहां यह फार्मूला हिट हो चुका है। संसाधनों की कमी के कारण दूसरे शहरों में जाकर नौकरी करने वालों को अपने शहर में कारोबार सुलभ हो गया है। बदलाव की इबारत लिखी है शहर के ही एक युवा अरुण गुप्ता ने।

उन्होंने गोरखपुर में स्टार्टअप कैफे के रूप में पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला को-वर्किंग स्पेस मुहैया कराया। स्वरोजगार के इच्छुक लोगों को इस प्रयोग ने नई राह दिखाई है। यह कैफे नित नया प्रतिमान गढ़ रहा है और कभी सुविधाओं के अभाव में दूसरे शहरों को रुख करने वालों को भी वापस बुलाने में भूमिका निभा रहा है। इस समय एक दर्जन से अधिक लोग इस कैफे के जरिये व्यवसाय कर रहे हैं।

शहर के विजय चौक पर बना यह कैफे एक ही छत के नीचे नए प्रोफेशनल्स और स्टार्टअप के लिए वह सारी सुविधाएं मुहैया कराता है, जो उन्हें अनयत्र ज्यादा कीमत देने पर भी नहीं मिलतीं। शहर के लिए यह योजना बिलकुल नई है। इसे साकार करने वाले 30 वर्षीय अरुण गुप्ता का मानना है कि कम पूंजी में अपना काम शुरू करने की हसरत रखने वालों को शहर में अपना ऑफिस शुरू करने के लिए जगह नहीं मिलती। पूंजी की कमी आड़े आती है। इसी अड़चन को दूर करने का प्रयास हमने किया है। महानगरों में रहकर नौकरी करने वाले युवाओं ने शहर वापस आकर इस कैफे से अपने कारोबार की सफल शुरुआत की है।

> यह अवधारणा हर लिहाज से समय की मांग है। एक ही छत के नीचे कई प्रोफेशनल्स के बैठने से बिजनेस ग्रोथ की अच्छी संभावना रहती है। एक अनुमान के अनुसार अगले पांच वर्षों में देश में को-वर्किंग स्पेस की अवधारणा तेजी से विस्तार पाएगी। केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया योजना में भी इस अवधारणा को तवज्जो दी गई है।
>
> **- अरुण गुप्ता, संस्थापक स्टार्टअप कैफे**

गोरखपुर में इस कैफे में आज एप डेवलपमेंट, डेटा रिसर्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंपनी सेक्रेटरी, फोटोग्राफी आदि विभिन्न विधाओं में युवा स्वउद्यम कर रहे हैं। कैफे में लगभग 50 लोगों के बैठने की जगह है। सभी कमरे जरूरी सुविधाओं से युक्त हैं। यहां बिजली, हाई स्पीड इंटरनेट, प्रिंटर, वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा के साथ मीटिंग रूम, पूर्णतया वातानुकूलित ऑफिस की सुविधा है। यही नहीं, यह कैफे उस समय और प्रसिद्ध हो गया जब तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने स्टार्टअप कैफे के बारे में ट्वीट किया।

को-वर्किंग स्पेस स्टार्टअप कैफे के संस्थापक अरुण गुप्ता। जागरण

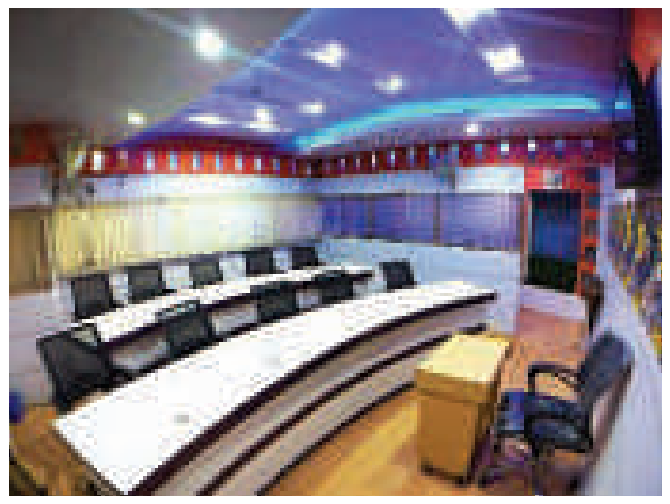

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित स्टार्टअप कैफे में उपलब्ध मीटिंग हाल। जागरण

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

जल्द ही ऑनलाइन पढ़ सकेंगे बापू के पत्र, भाषण और किताबें

▸ आइआइटी खड़गपुर के शोधकर्ता तैयार करेंगे गांधीपीडिया

जागरण संवाददाता, कोलकाता

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दुर्लभ किताबों, पत्रों और भाषणों को आप बहुत जल्द ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी पढ़ सकेंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी), खड़गपुर के शोधकर्ता बापू की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में गांधीपीडिया तैयार करेंगे।

गांधीपीडिया में महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई किताबों, पत्रों और भाषणों का दुर्लभ संग्रह होगा। बापू के इन दुर्लभ संग्रहों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए आइआइटी और नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम (एनसीएसएम) ने हाथ मिलाया है। आइआइटी खड़गपुर की ओर से शुक्रवार को जारी एक बयान में बताया गया कि पूरे प्रोजेक्ट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) की मदद से पूरा किया जाएगा। पहले चरण में बापू द्वारा लिखित करीब 40 से ज्यादा किताबों को डिजिटल फॉर्मेट में बदला जाएगा। उसकी इंडेक्स तैयार की जाएगी और उसके हिस्सों को ट्वीट किया जाएगा। पहले चरण का कार्य अगले साल मार्च तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके अलावा चार और चरणों में इस काम को अंजाम दिया जाएगा। इन सभी चार चरणों का काम मार्च 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। इस परियोजना में आइआइटी खड़गपुर के साथ आइआइटी गांधीनगर भी सहयोग कर रहा है। वहीं, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संस्थान नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम भी इसमें सहयोग कर रहा है। आइआइटी खड़गपुर के प्रोफेसर व इस परियोजना की अगुआई कर रहे अनिमेष मुखर्जी ने बताया कि महात्मा गांधी की किताब 'सच के साथ मेरे प्रयोग' से इसकी शुरुआत की जाएगी। उन्होंने बताया कि बापू के पत्रों और भाषणों समेत उनके कुल 100 कार्यों को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

महात्मा गांधी फाइल

विश्व बैंक को भा गई मथुरा की तुलसी और कंठी माला

मथुरा के जैंत गांव में कंठीमाला बनाने के लिए मनिया काटता किसान। जागरण

125 हेक्टेयर में होता है तुलसी का उत्पादन

जैंत गांव के अलावा सकराया, बाबूगढ़, बिरला और राधाकुंड में करीब सवा सौ हेक्टेयर में तुलसी का उत्पादन किया जाता है। यहां से तैयार कुछ कंठी माला शहर के अलावा बाहर के कुछ व्यापारी ले जाते हैं और फिर उन्हें बेचते हैं। यही नहीं कुछ व्यापारी तुलसी के तने को ले जाते हैं और फिर उसे उबालकर खुद माला बनाकर बेचते हैं। किसानों को तो कम दाम मिलते हैं, लेकिन व्यापारी इससे अच्छी कीमत पाते हैं।

एन आर राजपूत, मथुरा

▸ बैंक ने गांव को गोद लिया, कारोबार की होगी ब्रांडिंग, मिलेगा बाजार

देश-दुनिया धर्म-आध्यात्म के लिए पहचाने जाने वाली कान्हा की नगरी मथुरा की धूम अब कंठी माला के जरिये भी दुनियाभर में होगी। जैंत गांव में तुलसी की खेती और कंठी माला के कारोबार को अब विश्व बैंक नई पहचान दिलाएगा। कंठी माला की ब्रांडिंग के साथ उसे बाजार भी मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए खाका तैयार किया गया है। मथुरा में हाईवे किनारे स्थित करीब 20 हजार की आबादी वाले इस गांव का प्रमुख कारोबार ही तुलसी की खेती और कंठी माला का निर्माण है। करीब 35 फीसद आबादी यही काम करती है, लेकिन ग्रामीणों के सामने समस्या है कि उन्हें कंठी माला की बिक्री के लिए उचित बाजार नहीं मिल पाता। बीते दिनों जैंत गांव को वर्ल्ड बैंक ने गोद लिया। ऐसे में यहां की खेती और कंठी माला के कारोबार को बड़ा बाजार देने की रूपरेखा भी तैयार की गई है।

25 नवंबर को विश्व बैंक आगरा से आई तकनीकी टीम ने गांव का निरीक्षण किया और इसकी रिपोर्ट अमेरिका भेजी। वर्ल्ड बैंक की टीम लीडर स्टेफानिया अल्पाकेरी ने उस पर मुहर लगा दी है। अब वर्ल्ड बैंक ने अनुमति के लिए फाइल शासन को भेज दी है। वर्ल्ड बैंक ने तुलसी व कंठी माला की ब्रांडिंग करने के साथ ही दुनिया भर में बाजार मुहैया कराने की योजना तैयार की है।

> गांव का तकनीकी सर्वे कर लिया गया है। शासन को पत्रावली भेज दी है। वहां से अनुमति मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा।
>
> **- शशिकांत गिरी, सामाजिक पर्यटन विकास विशेषज्ञ, वर्ल्ड बैंक इकाई**

ये भी होगा काम : तुलसी के खेती करने वाले किसानों के खेतों पर सोलर पंप लगेंगे। तुलसी उत्पादन वाले खेतों तक करीब सात किमी इंटरलॉकिंग व आरसीसी रोड बनेगी। कंठी माला को बढ़ाना देने के लिए हाईटेक मशीनें लगेंगी।

दो सौ का माल, पांच हजार कीमत : आसपास के व्यापारी जैंत गांव के किसानों से जो माल सौ या दो सौ रुपये में खरीदते हैं, उसकी विदेश में कीमत करीब पांच हजार रुपये है। किसानों को बड़ा बाजार मिलने पर बिचौलिये तो खत्म होंगे ही सीधे-सीधे माला यहां से उपभोक्ता के हाथ पहुंचेगी।

इसलिए पहनी जाती है कंठी माला : तुलसी को काफी पवित्र माना जाता है। वृंदावन में रह रहे विदेशी के अलावा वैष्णव संप्रदाय के लोग तुलसी की कंठी माला पहनते हैं। ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

बंगाल में मुफलिसों के मसीहा बन गए अनंत नेवटिया

दे रहे जीवनदान ▸ स्वास्थ्य देखभाल के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मुहैया करा रहा रूरल हेल्थ केयर फाउंडेशन

फिक्की ने स्वास्थ्य सेवा पुरस्कार-2019 से नवाजा

प्रकाश पांडेय, कोलकाता

समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में जीवन का संवैधानिक अधिकार अधूरा है। बंगाल के गरीब ग्रामीण परिवारों को इलाज और रोजगार उपलब्ध करा इस अधूरेपन को दूर करने में जुटे हैं अनंत नेवटिया। उनके संगठन रूरल हेल्थ केयर फाउंडेशन के कार्यों को संयुक्त राष्ट्र ने स्वीकारा है। वहीं, फिक्की ने पुरस्कृत किया है। अनंत आज बंगाल में मुफलिसों के मसीहा बन गए हैं।

सुशिक्षित समाज

रूरल हेल्थ केयर फाउंडेशन (आरएचसीएफ) आज लाखों ग्रामीणों को चिकित्सकीय सुविधा मुहैया करा नवजीवन प्रदान करने का काम कर रहा है। कोलकाता की मलिन बस्तियों से लेकर राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में इस गैर सरकारी संगठन ने कुल 17 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की है, जहां वंचित समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। हालांकि, सुचारू व्यवस्था संचालन को मरीजों के स्वजनों से पूरे सप्ताह के लिए महज 80 रुपये लिए जाते हैं, जिसके एवज में उन्हें चिकित्सकीय परामर्श, उपचार व मुफ्त में दवाएं दी जाती हैं। दो भाइयों के प्रयास से शुरू हुई इस परियोजना से प्रति वर्ष लाखों मरीजों की सेवा के साथ ही ग्रामीणों को रोजगार भी मिल रहा है।

जब तक इंसान खुद दर्द महसूस नहीं करता, तब तक उसे दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। इस मुहिम की नींव पड़ने के पीछे भी एक ऐसा ही दर्द छिपा है, जिसे संस्थापक अनंत नेवटिया बखूबी बयां भी करते हैं। अनंत ने बताया कि महज दस साल की उम्र में उनके छोटे भाई अरुण नेवटिया को कैंसर हो गया था और उनके भाई के साथ ही इस दर्द को उनके परिवार ने 38 सालों तक महसूस किया। इसी कड़ी में पिता की मृत्यु के उपरांत दोनों भाइयों ने उनके द्वारा की जाने वाली समाज सेवा को जारी रखने का निर्णय लिया। अनंत ने बताया कि उनके स्वर्गीय पिता श्याम सुंदर नेवटिया अकसर जरूरतमंदों के बीच दवाएं वितरित किया करते थे। दोनों भाई पिता के साथ नदिया जिले के मायापुर स्थित चैतन्य महाप्रभु के मंदिर भी जाया करते थे, जहां उनके पिता के सहयोग से लोगों की सेवा को एक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन हुआ करता था। पिता के निधन के बाद इस सिलसिले को जारी रखने के लिए साल 2007 में भाइयों ने शारदा देवी नेवटिया फाउंडेशन की स्थापना की, जो 2009 में रूरल हेल्थ केयर फाउंडेशन के रूप में आगे बढ़ी।

इस बीच साल 2013 में अरुण नेवटिया का निधन हो गया और इसके बाद से ही उनकी धर्मपत्नी फाल्गुनी नेवटिया, भतीजे श्रेयस और बड़े भाई अनंत साथ मिलकर इस संस्थान के जरिये जरूरतमंदों की सेवा करने में जुटे हुए हैं। बंगीय क्षेत्र में बेमिसाल नजीर बन चुके अनंत नेवटिया कहते हैं, जब हमने अपना रियल एस्टेट व्यवसाय बंद किया, उस समय हमारा काम जोरों पर चल रहा था, लेकिन हमने जनसेवा को ही ध्येय बना लिया था।

फाउंडेशन की कम्युनिकेशन मैनेजर कृष्णा कुंतल बनर्जी ने बताया, इस समय हमारे कुल 17 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। 12 ग्रामीण क्षेत्र में हैं और पांच कोलकाता में। ग्रामीण क्षेत्रों में यह सेवा सप्ताह में छह दिन तो शहर में रोजाना दो घंटे मुहैया कराई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की स्थायी नियुक्ति की जाती है, जो वहीं रहते हैं। जनरल फिजीशियन, नेत्र विशेषज्ञ, दंत विशेषज्ञ, होम्योपैथी आदि विशेषज्ञों की सेवाएं मुहैया कराई गई हैं। वर्तमान तक हमने करीब 23 लाख से अधिक मरीजों को चिकित्सकीय सेवाएं प्रदान की हैं। साल 2016 के बाद एक बार फिर 2019 में भारतीय वाणिज्य व उद्योग महासंघ (फिक्की) ने फाउंडेशन के संस्थापक अनंत नेवटिया को सम्मानित किया है। फाउंडेशन के फील्ड ऑफिसर रणमय साहा ने बताया कि दक्षिण व उत्तर 24 परगना जिले के बुलबुल तूफान प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल चिकित्सकीय सेवा के जरिए जगह-जगह शिविर लगाए गए। इन इलाकों में चार माह तक सेवा जारी रखी जाएगी।

आरएचसीएफ के स्वास्थ्य केंद्र पर ग्रामीण महिला के दांतों का उपचार करती दंत चिकित्सक। जागरण

फाल्गुनी नेवटिया। जागरण

फाउंडेशन के संस्थापक अनंत नेवटिया। जागरण

प्रेरक प्रयास

- बंगाल में कुल 17 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित
- 12 ग्रामीण क्षेत्र में और पांच कोलकाता में
- ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की स्थायी नियुक्ति
- बीते 10 वर्ष में 23 लाख से अधिक गरीब व्यक्तियों का उपचार
- अस्पताल में भर्ती पर 80 रुपये प्रति सप्ताह शुल्क, दवाएं नि:शुल्क दी जाती हैं

www.jagran.com/topics/positive-news

बिजली का झटका खाकर जमीन और भूगर्भ जल से कैंसर निकालेगा पौधा

हिमांशु मिश्र, बरेली

- रुहेलखंड विश्वविद्यालय के प्लांट साइंस विभाग के प्रोफेसरों ने किया शोध
- जमीन में मौजूद कैंसर के कई भारी तत्वों को निकालने में पाई कामयाबी

बिजली के झटकों से मानसिक बीमारी का इलाज तो आपने सुना होगा, लेकिन अब ये झटके कैंसर जैसे रोग को इंसान से दूर रखने में भी मददगार होंगे। कुछ विशेष पौधों को ये झटके दिए जाएंगे, जो जमीन और भूगर्भ जल में मौजूद कैंसर तत्वों को निकालने का काम करेंगे। ऐसा करने में बरेली के रुहेलखंड विश्वविद्यालय के प्लांट साइंस विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर आलोक श्रीवास्तव और उनकी टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। पानी में मौजूद कैंसर के कारक तत्वों को निकालने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्लांट साइंस विभाग को 12 लाख का अनुदान भी दिया है।

पानी के जरिये शरीर में पहुंच रहे लेड व आर्सेनिक : प्रो. आलोक ने बताया कि जमीन और भूगर्भ जल में कैडमियम, लेड, मरकरी और आर्सेनिक जैसे भारी तत्व मौजूद होते हैं। कैंसर के 70 फीसद कारक यही तत्व होते हैं। ये तत्व इंसान के जीन्स या जेनेटिक मेकअप तोड़ते हैं, जिससे इंसान के शरीर में कैंसर जैसी विकृति आ जाती है। खेतों व फैक्ट्रियों में प्रयोग हो रहे तमाम केमिकल से ये तत्व निकलकर जमीन के अंदर जाते हैं और फिर भूगर्भ जल के जरिये लोगों के घरों तक। इसलिए सबसे पहले इन तत्वों को खींचने की क्षमता रखने वाले पौधे ढूंढ़ निकाले। इसमें खस घास, गेंदा, सूरजमुखी और सरसों के पौधे शामिल हैं। हालांकि, सामान्य तौर पर इसकी प्रक्रिया थोड़ी धीमी होती है।

ऐसे दिए जाते हैं झटके : प्रो. आलोक के मुताबिक, पौधों की जड़ों में इलेक्ट्रोड की मदद से झटके दिए जाते हैं। इससे पौधे में मौजूद फाइटो चिलेंटिस तत्व सतर्क हो जाता है और भारी तत्वों को खींचने की उसकी क्षमता 40 गुना हो जाती है।

प्रोफेसर आलोक श्रीवास्तव। सौजन्य : आलोक

क्षमता बढ़ाने के लिए दिए बिजली के झटके

पहले इन पौधों की क्षमता बढ़ाने के लिए केमिकल का प्रयोग किया गया। नतीजा अच्छा था, पर पौधों की जड़ें टूटने लगीं, जो खींचने के बाद भारी तत्वों को वापस मिट्टी में मिला देती थीं। फिर प्राकृतिक साइट्रिक एसिड की मदद ली गई। केमिकल की अपेक्षा इसका असर 15 फीसद कम दिखा। तब इलेक्ट्रिक करंट की मदद लेकर पौधों की क्षमता बढ़ाने का काम किया।

कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में वह स्टॉल लोगों को भा रहा है, जहां कैदियों की बनाई गई पेंटिंग व अन्य चीजें रखी हैं। जागरण

कैदियों ने जेल में सीखा कर्म का फल ही है मीठा

▸ अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव एक स्टाल पर जेल में बंद कैदियों की बनाई गई पेंटिंग भी लुभा रही हैं यहां आने वाले लोगों को

चरखे, जिन्हें कैदियों ने तैयार किया है। जागरण

विनीश गौड़, कुरुक्षेत्र

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में एक स्टाल ऐसा भी है जहां जाते ही लोगों के कदम बरबस ही थम जाते हैं। इस स्टाल पर जिला जेल में बंद कैदियों द्वारा बनाई गई पेंटिंग प्रदर्शित की जा रही हैं। ब्रह्मसरोवर के दूसरे मुख्य द्वार के पास लगी इन पेंटिंग को देख हर किसी के मन में सवाल कौंध उठता है कि इन्हें बनाने वालों के हाथ अपराध के लिए कैसे उठे होंगे। इन्हें जेल में बंद कैदियों और विचाराधीन कैदियों ने बनाया है।

इन पेंटिंगों में प्रकृति के खूबसूरत नजारे, धर्मयुद्ध में गीता का ज्ञान देते श्रीकृष्ण-अर्जुन, कृष्ण भक्त मीरा और वात्सल्य की कल्पना को उकेरा गया है। लोग इन पेंटिंगों को सहेजना तो चाहते हैं, लेकिन अधिकतर सामान को केवल प्रदर्शनी के लिए रखा गया है। यहां आने वाले विदेशी पर्यटक तक इन कल्पनाओं को रूप देने वाले कलाकारों की कहानी तक जानना चाहते हैं।

हिंसा करने वाले बना रहे अहिंसा का चरखा : पॉक्सो में विचाराधीन बंदी की ओर से बनाई पेंटिंग में इतनी कशिश है कि हर किसी को अपनी ओर खींच रही है। लोग इसे बनाने वाले बंदी के बारे में पूछने पर विवश हो रहे हैं। इतना ही नहीं इस स्टॉल पर अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा कातने वाले छोटे-छोटे चरखे भी यहां प्रदर्शित किए गए हैं, जिन्हें विचाराधीन और बंदियों ने बनाया है। लोग इन चरखों को भी खरीदने की इच्छा जाहिर करते हैं।

काफी सामान सिर्फ प्रदर्शनी के लिए : रुपेश कुमार : कुरुक्षेत्र जिला जेल में कांस्टेबल रुपेश कुमार ने बताया कि जेल अधीक्षक डॉ. संजय सिंह के मार्गदर्शन पर यहां पर स्टॉल लगाया गया है, जिसमें प्रदेश भर की जेलों से विचाराधीन कैदियों और कैदियों के बनाए सामान को प्रदर्शित किया गया है। इनमें से कुछ सामान बेचने के लिए है, जबकि कुछ सामान को सिर्फ प्रदर्शित किया जा रहा है, क्योंकि कुछ बंदियों ने इन्हें सिर्फ प्रदर्शित करने की ही स्वीकृति दी है।

उन्होंने बताया कि गुरुग्राम की जेल से महिला बंदियों की ओर से रीबन पेपर से बनाए आभूषणों को प्रदर्शित किया गया है। झज्जर से महिलाओं के बनाए पर्स हैं, भिवानी जेल से छोटे-छोटे चरखे, जबकि कुरुक्षेत्र जेल से पेंटिंग, फैंसी मोमबत्तियां, लकड़ी का सामान भी प्रदर्शित किया गया है।

उठाया कदम

पैराग्लाइडिंग के दौरान हो रहे हादसों को देखते हुए पर्यटन विभाग ने सख्त किए नियम, प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र दिखाने के बाद ही कर पाएंगे पैराग्लाइडिंग

हिमाचल में प्रशिक्षण के बाद ही उड़ान भर पाएंगे मानव परिंदे

दविंद्र ठाकुर, कुल्लू

हिमाचल प्रदेश में नियमों को नजरअंदाज करने वाले मानव परिंदों के पर उड़ान भरने से पहले ही कतर दिए जाएंगे। पैराग्लाइडिंग के दौरान हो रहे हादसों से सबक लेते हुए पर्यटन विभाग ने नियमों को सख्त करते हुए कुछ और औपचारिकताएं भी जरूरी कर दी हैं। पैराग्लाइडिंग साइट्स पर प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र दिखाने के बाद ही पैराग्लाइडर उड़ान भर पाएंगे। पर्यटन विभाग ने प्रशिक्षण का समय निर्धारित कर दिया है। दिसंबर के दूसरे सप्ताह पैराग्लाइडरों को 15 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान पायलटों को सुरक्षा नियमों का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। मानव परिंदे प्रशिक्षण के बाद ही उड़ान भर पाएंगे। पायलट को पर्यटन विभाग की ओर से जारी पहचान पत्र पहनकर ही उड़ान भरनी होगी। विभाग भी इस पर नजर रखेगा। पैराग्लाइडिंग करवाने वाले संचालकों को भी इसका ध्यान रखना होगा अन्यथा उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

पैराग्लाइडिंग की समयसारिणी में होगा बदलाव : पर्यटन विभाग ने पैराग्लाइडिंग की समयसारिणी में बदलाव किया है। पहले समयसारिणी में सनसेट लिखा गया था। इससे पायलट सूरज के ढलने के बाद भी उड़ान भरते रहते थे। नई समयसारिणी के बाद ऐसा नहीं होगा। अब विंटर सीजन में एक अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक पैराग्लाइडिंग होगी। समर सीजन में पहली अप्रैल से 30 सितंबर तक सुबह नौ बजे से शाम सात बजे तक पैराग्लाइडिंग की जा सकेगी।

> लगातार हो रहे हादसों के कारण विभाग ने पैराग्लाइडिंग करने के लिए प्रशिक्षण जरूरी कर दिया है। इसके बाद ही पायलट उड़ान भर पाएंगे। इनके लिए पहचानपत्र अनिवार्य कर दिया गया है।
>
> **- बीसी नेगी, जिला पर्यटन अधिकारी, कुल्लू**
>
> हिमाचल में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से कड़े नियम बनाए जा रहे हैं। हादसे न हों, इसके लिए प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है।
>
> **- गोविंद ठाकुर, वन मंत्री**

अब स्थान में नहीं होगा बदलाव

कुल्लू जिले में सात पैराग्लाइडिंग साइट्स हैं। पहले पर्यटकों की भीड़ बढ़ने पर पैराग्लाइडर संचालक दूसरी जगह पैराग्लाइडिंग करवाते थे। अब निर्धारित साइट पर ही संचालकों को बुकिंग कर पैराग्लाइडर उड़ाना पड़ेगा।

कुल्लू की पहाड़ियों में पैराग्लाइडिंग करते पर्यटक। फाइल फोटो

दैनिक जागरण
सबरंग
शहर को जानने के...
नई दिल्ली, शनिवार, 30 नवंबर, 2019
सुझाव व प्रतिक्रिया के लिए लिखें : sabrang@nda.jagran.com
https://www.facebook.com/jagransabrang/

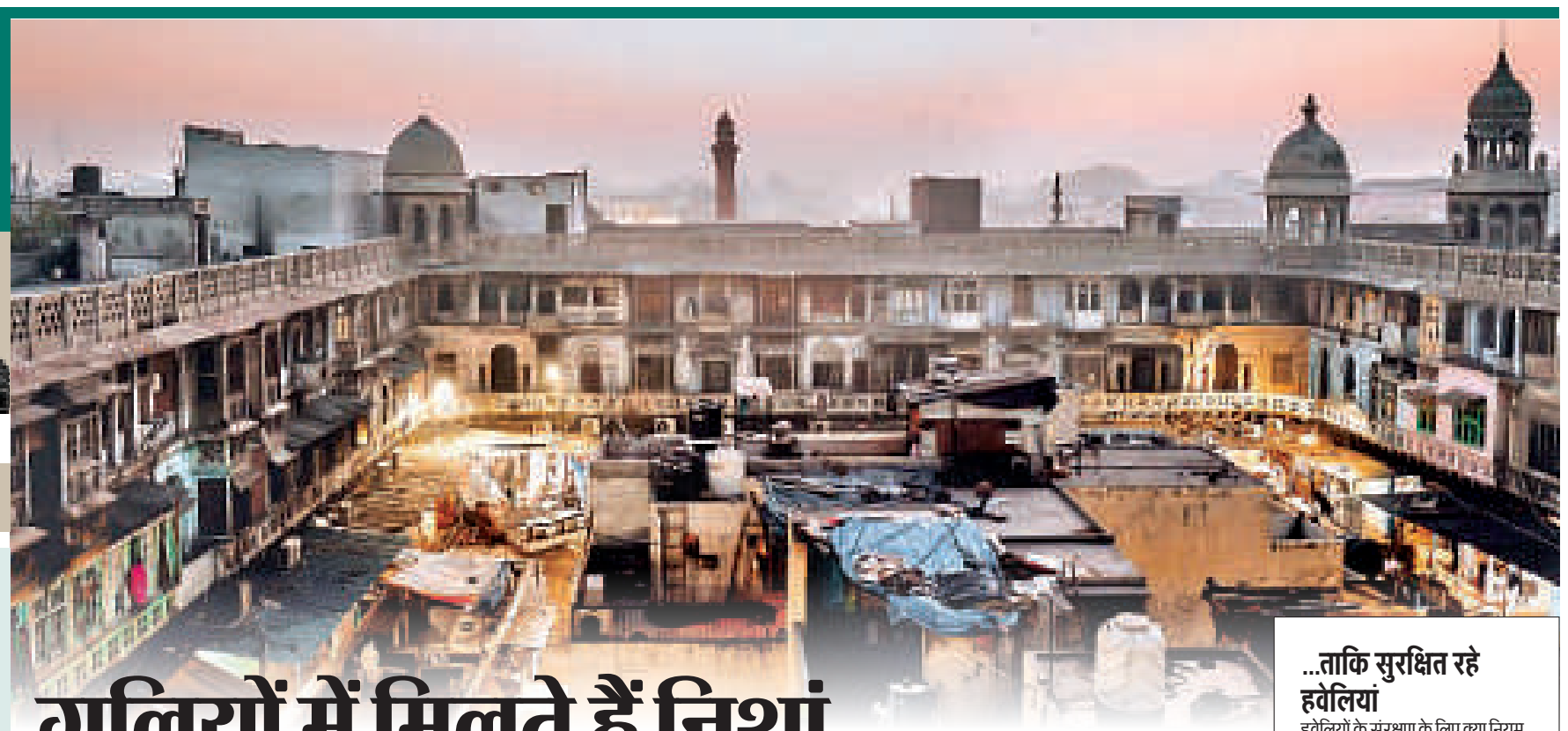

गलियों में मिलते हैं निशां आलीशान इतिहास के

चटक रंगों से सजे होते थे फर्श जहां और ऊंची होती थीं दीवारें...छतें होती थीं फूल-पातियों से सजी। छज्जों पर होती थीं दुर्लभ कलाकारी...पत्थरों पर जिनके गढ़ी रहती थी नक्काशी...। बड़ी भले थीं पुरानी दिल्ली की हवेलियां, रिश्तों पर बनी रही स्नेह भरी छांव हवेलियां। सबरंग के इस अंक में इटैंक की एक रिपोर्ट के माध्यम से शाहजहांनाबाद की हवेलियों की रूपरेखा से रूबरू करा रहे हैं संजीव कुमार मिश्र :

दावे अपने-अपने

सर सैयद अहमद खान ने दिल्ली के स्मारकों समेत हवेलियों का जिक्र करते हुए किताबें लिखी है। अपनी एक किताब में इन्होंने 1847 में पुरानी दिल्ली में मौजूद लगभग हर इमारत का इतिहास लिखा है। इस किताब में उन्होंने अपने नाना नवाब दाबिर उल दौला महरूम की हवेली के बारे में विस्तार से लिखा है। लिखते हैं कि फैज बाजार की तरफ हवेली स्थित थी। सर सैयद अहमद की हवेली जामा मस्जिद के पास थी। इनका जन्म 17 अक्टूबर 1817 में हुआ था। राना सफवी अपनी पुस्तक शाहजहांनाबाद में लिखती हैं कि मैं फैज बाजार गई जो अब दरियागंज के नाम से प्रसिद्ध है। दरियागंज में सड़क का नाम सर सैयद अहमद के नाम पर है। एक समय यह पुरा इलाका मुगलों के लिए गर्व का एहसास कराता था। यहीं अहमद दाबिर उल दौला में भी रहे। कभी हवेली का द्वार बहुत भव्य था। लेकिन अब यह अतिक्रमण की जद में है। राना सफवी कहती हैं कि मैं हवेली में गई थी। वर्तमान मालिक ने मुझे चाय भी ऑफर की। उन्होंने इसका सर सैयद अहमद से किसी तरह से संबंध होने की बात से इन्कार कर दिया। हवेली दो हिस्सों में बटी है। राना की मानें तो स्थानीय लोगों का यह कहना था कि हवेली पहले से मौजूद है। लोगों के इन्कार के बाद मैंने सर सैयद अहमद की ही किताब के पन्ने पलटे। जिसमें उन्होंने अपनी हवेली के बारे में लिखा है। हवेली औलिया मस्जिद के पास तिराहा बैरम खां के पास थी।

यही होती थी सर सैयद की हवेली ▲

रजिया बेगम के मिल गए निशां

चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन के पास एक हवेली रजिया बेगम के नाम से जानी जाती है। यह राजी-उन-निसा बेगम से संबंधित है जो नवाब कमरुद्दीन खान की बेटी थी। ये मुहम्मद शाह के शासनकाल में बड़े रईस थे। इनके नाम पर राजा बेगम नाम से कूचा भी है। नवाब की तीन बेटियां थी। राजी उन निशा, शाह तारा और फत-उन-निशा बेगम। हौजकाजी से अजमेरी गेट तक का बड़ा हिस्सा नवाब साहब का ही था। राना सफवी लिखती हैं कि हवेली वर्तमान में अतिक्रमणकी जद में हैं। यहां रिक्शा खड़े होते हैं। वर्तमान में यह कई भागों में विभाजित हो चुका है। यहां पर उनकी मुलाकात राजा लाल से हुई। 90 वर्षीय राजा लाल ने बताया कि उनका परिवार कई वर्षो से रह रहा है। इनके पिता एवं दादा जी भी यहीं रहे थे। राना कहती हैं कि इस तरह यह तो साफ हो गया कि यह हवेली 19वीं शताब्दी की है। नवाब कमरुद्दीन खान हवेली को मुगल जनरल मिर्जा नजफ खान ने 1779-1782 के बीच अधिकृत किया था। इस समय मिर्जा नजफ वजीर थे। इनकी मौत के बाद इनकी बहन खादिजा बेगम रहने लगी। जबकि इसके एक बड़े हिस्से पर कमरुद्दीन खान की बेटी रहती थीं

चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन के पास स्थित रजिया बेगम की हवेली इलाका

धरोहर

कैसा होता होगा एक हवेली का आकार...स्वरूप...उसकी नक्काशी...दरो-दीवारें...छज्जे... और उसकी वास्तु। गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल, रिश्तों में सुदृढ़ बनातीं इन हवेलियों में रिश्तों की मिठास गूंजती थी। पुरानी दिल्ली की संस्कृति और परंपरा यहीं से बनती और सजती थी। गालिब और जोंक भी इन गलियों में बसी हवेलियों से दिल लगाए रहे। समय की धार में सब दीवारें जरूर जर-जर हुईं पर उन दरारों से इनके इतिहास की खूबसूरती आज भी झलकती है। हवेलियों में बसी तहजीब को आज भी पुरानी दिल्ली जेहन में बसाए रखती है। तभी पुरानी दिल्ली की इसी रिवायत एवं हवेलियों को जिंदा रखने की कोशिश में नगर निगम व इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड क्लचर हेरिटेज (इंटैक) भी लगे हैं। इंटैक दिल्ली चैप्टर ने तो शाहजहांनाबाद में विरासत भवनों का संरक्षण नाम से मकान मालिकों के लिए नियमावली का भी प्रकाशन किया था और हवेलियों के संरक्षण के लिए मकान मालिकों को जागरूक किया जा रहा है।

शाहजहांनाबाद की चारदीवारी से घिरे मुगल शहर के रिहायशी इलाके में 17वीं शताब्दी में मेहराबी प्रवेश द्वार वाली भव्य और शानदार हवेलियां थीं। शहर का 18वीं और 19वीं शताब्दी में विकास हुआ। यहां खूब हवेलियां बनीं। हालांकि ये बहुत छोटी थीं और कूचे, कटरा और मोहल्लों में स्थित थीं। स्वपना लिडले कहती हैं कि जिन मालिकों की दुकानें थीं, उन्होंने इनकी ऊपरी मंजिलों पर अपना ठिकाना बना लिया। आज, अधिकांश ढांचों का वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा है। शाहजहांनाबाद की इन हवेलियों को दिल्ली के उप-उष्णकटिबंधीय जलवायु को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। पुरानी दिल्ली की पारंपरिक हवेलियों का गहन अध्ययन करने पर उन विशेषताओं का पता चलता है जो उन्हें अन्य वास्तुकला शैलियों या इतिहास के काल से अलग बनाती है। मूलरूप से हवेली की योजना में कई घटक शामिल थे, जिनमे पुरुषों व महिलाओं के लिए अलग कमरे, मालिक का कार्यालय, एक पुस्तकालय, एक ड्राइंगरूम, फव्वारा, बैरक, अस्तबल और संभवतः एक कारखाना सहित औपचारिक उद्यान शामिल होते थे। घरों के नक्शे में एक रूपता होती थी। जिसमें एक आंगन और कम से कम दो मंजिल जरूर होती थीं। दीवारों पर फूलों की नक्काशी के पैनल लगे होते थे या उन्हें ज्यामितीय डिजाइन से चित्रित किया गया था। बकौल लिडले यह सौभाग्य ही है कि आज भी कई हवेलियां हैं, जिन्हें अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है, जो हमें उन विशेषताओं और पहलुओं के बारे में बताती हैं जो मुगलों की रिहायशी वास्तुकला में संजोई गई थीं।

बहुत खास होती थीं छतें : शाहजहांनाबाद के प्राचीन शहर का विहंगम दृश्य देखें तो हमें हर कहीं सपाट छत वाली इमारतें और सीढ़ियां दिखाई देंगी। मस्जिद जैसे कुछ प्रमुख स्मारकों में गुंबद वाली छत दिखाई देगी जबकि अधिकांश इमारतों की छतें सपाट हैं। ये सपाट छतें घनी आबादी वाले चारदीवारी से घिरे शहर में बेहद जरूरी खुली जगह प्रदान करती हैं। इनका निर्माण मुख्य रूप से रोड़ी-पत्थर-चूना-गारा, इमारती लकड़ी के स्तंभों या धातु के गार्डरों और वजन उठाने वाली ईंट की दीवारों से किया गया है। पानी के रिसाव से बचने के लिए इन पर चूना, कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया था। सपाट छतों में एक और ढलान बनाया जाता था ताकि बारिश का पानी बहकर पाइपों से नीचे चला जाए या जगह-जगह लगाए गए खुर्रा से बाहर निकल जाए। आज जैसे सभी जगह वाटर हार्वेस्टिंग बनाने के लिए जोर दिया जाता है। इसे बिलकुल उसी तरह देखा जा सकता है।

कई तरह के होते थे फर्श : स्वपना बताती हैं कि 20वीं शताब्दी की शुरुआती वर्षों में इमारतों को ईंटों के जैक वाली मेहराब और धातु के खंडों से सहारा देकर चूना और कंक्रीट से बनाया जाता था। कहीं कहीं ईंटों की मेहराब बनाकर नालियों या सीढ़ियों जैसी खाली जगह का भी इस्तेमाल किया जाता था। वहीं अधिकतर हवेलियों में फर्श को विभिन्न प्रकार से बनाया जाता था। मसलन पत्थर का फर्श, चीनी पच्चीकारी, विशेष सीमेंट की टाइल वाले फर्श जैसे भारत टाइलें से बने फर्श होते थे। अभी जो कुछ हवेलियां संरक्षित की गई हैं उनकी वास्तुकला को देखकर पता चलता है कि पत्थरों को स्लैब के आकार में चूना कंक्रीट की बिछाई गई सतह पर चूने-गारे से जोड़ों को बेहतरीन ढंग से भरकर बिछाया जाता था।

द्वार पर आला जरूर होता था : अधिकांश इमारतें वजन उठाने वाली 00 मीमी मोटी दीवारों से निर्मित हैं। हवेलियों को पतली मुगल ईंटों से बनी हैं जिसे लखोरी ईंटों या नानकशाही ईंटों के नाम से जाना जाता है। पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से प्रवेश द्वार में ब्रैकेट, कॉलम के साथ-साथ आवरण या पट्टी बनाने के लिए किया जाता था। अधिकांश ईंटों से निर्मित इमारतों को पारंपरिक रूप से चूना-गारा से पलस्तर करके फपर सफेदी की जाती थी। पुरानी दिल्ली की इमारतों में बड़े पैमाने पर ईंटों से निर्मित अर्धगोलाकार उभारदार, खंडवार और बेल-बूटों से निर्मित विविध मेहराबों का इस्तेमाल दिखाई पड़ता है। जबकि प्रवेश द्वार मेहराबी होता था। प्रवेश द्वार के दोनों तरफ आला भी जरूर नजर आ जाएंगे।

लकड़ी में होती थी गजब की मजबूती : इंटैक द्वारा हवेलियों पर तैयार रिपोर्ट से पता चलता है कि हवेली के निर्माण में इमारती लकड़ी का अधिक इस्तेमाल किया जाता था। लकड़ी एक कार्बनिक पदार्थ है, जो लिग्नाइट से बनी होती है जिससे इसे मजबूती मिलती है। यह नरम होती है और इसमें पोषक तत्व और नमी होती है। इमारती लकड़ी कुछ अलग नहीं होती बल्कि वृक्षों की लकड़ी को जब निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है उसे ही इमारती लकड़ी कहा जाता है। यदि लकड़ी का उपयोग सही ढंग से हो तो यह एक टिकाऊ सामग्री साबित होती है। जैसा कि शाहजहंनाबाद में निर्मित अधिकांश दरवाजे पैनल दरवाजे हैं, जिनका निर्माण स्थानीय रूप से उपलब्ध लकड़ी से किया गया है। जैसे सागौन या शीशम की लकड़ी। हवेलियों की अधिकांश खिड़कियों में लकड़ी के शटर और जालीदार रोशनदान होते थे। हवेलियों की खिड़कियों में उभारदार मेहराबें, तीन मेहराबों वाले झरोखे और अर्धवृत्ताकार मेहराब ओपनिंग थीं। मुगल काल की इमारतों में बेलबूटेदार मेहराबों को देखा जा सकता है जबकि उभारदार अर्धवृत्ताकार मेहराब औपनिवेशिक स्थापत्य कला की विशेषता होती थी।

छज्जे जो आज भी करते हैं आकर्षित : छज्जे जो आज भी पुरानी दिल्ली की गलियों में घरों में खास आकर्षित करते हैं। छज्जे के बारे में यह जानना दिलचस्प है कि समय के साथ रेलिंग का विकास कैसे हुआ। इसकी शुरुआत लकड़ी के खंभों में लोहे के काम से हुई और फिर बलुआ पत्थर और संगमरमर का जंगला या जालीदार कार्य होने लगा। इसके बाद गच्चकारी कार्य और अब हल्की स्टील रेलिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए छज्जे की रेलिंग शाहजहांनाबाद के इतिहास की खास निशानी है। जबकि अधिकांश जैन परिवारों और मंदिरों में संगमरमर के जंगले बने हैं। जिन पर धार्मिक प्रतीक चिन्हों की महीन कारीगरी की गई है जबकि अन्य अधिकांश इमारतों में लोहे के साथ इमारती लकड़ी के खंभे या गचकारी जालियां लगाई गई हैं। शाहजहांनाबाद की गलियों से हवेलियों की पहली मंजिल के छज्जों पर लगी रेलिंग बेहद आकर्षक दिखाई देती हैं।

...ताकि सुरक्षित रहे हवेलियां

हवेलियों के संरक्षण के लिए क्या नियम रहे होंगे? इनकी बनावट की क्या और कैसी बारीकियां होती थीं। सबसे खास इनकी वास्तुकला कैसी होती थी इन सभी के बारे में इंटैक दिल्ली चैप्टर में बताया जा रहा है। जिसका नेतृत्व इतिहासकार स्वपना लिडले कर रही हैं।

शाहजहां के वजीर की निशानी अब सिर्फ किताबों में

इसी जगह पर होती थी कभी सैदुल्ला खान की हवेली

सैदुल्ला खान बादशाह शाहजहां के वजीर थे। इन्हीं के सुपरविजन में लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था। इनकी हवेली लाल किले के पास दक्षिण की तरफ थी। नजदीक बनाए जाने के पीछे एक कारण इनके नेतृत्व में किले का निर्माण होना भी था। लाल किले के सामने चौक भी कभी सैदुल्ला चौक के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब इनसे जुड़ी बातें सिर्फ किताबों में ही मिलती हैं।

अब सब भूल गए इस हवेली को

जीनत महल ▼

लाल कुआं की पिछली गलियों में फतेहपुरी मस्जिद से निकलकर, एक हवेली दिखती है। यह लंबे अरसे से भुला दी गई हवेली है। राहगीर इस ऐतिहासिक हवेली के सामने से यूं ही गुजरते रहते हैं, सब अनजान हैं इसके इतिहास से। पहली मंजिल पर अग्रभाग का एक भाग ऐसा प्रतीत होता है मानो समय के साथ ठहर गया हो। खूबसूरत जालियां अभी भी बरकरार है। किसी को यकीन नहीं है कि जीनत महल कहां से शुरू और खत्म होता है। स्थानीय निवासियों के अनुसार, महल एक मुगल सम्राट की पत्नियों में से एक जीनत महल के नाम था और बाद में पटियाला के महाराजा द्वारा खरीदा गया था जिन्होंने इसे एक सरकारी स्कूल में विकसित करने की पहल की थी। फाटकों के अंदर, खूबसूरत लखोरी ईंट का बेहतरीन इस्तेमाल आज भी दिखता है।

यहां देखिए राजा नवाब और फिरंगी

दिल्ली की देहरी

नलिन चौहान
दिल्ली के अनजाने इतिहास के खोजी

राष्ट्रीय संग्रहालय में 'राजा, नवाब और फिरंगी' प्रदर्शनी में लगा चित्र जो दिल्ली के इतिहास से जुड़े कई पात्रों की कहानी कहता है। सौजन्य : संग्रहालय

अभी राष्ट्रीय संग्रहालय में 'राजा, नवाब और फिरंगी' शीर्षक से एक प्रदर्शनी लगी हुई है। प्रदर्शनी में फ्रांस के राष्ट्रीय पुस्तकालय के अभिलेखागार में संग्रहित सामग्री सहित भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय की कलाकृतियों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है। सभी चित्रों की विशेषता यह है कि 18 वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर 19 वीं सदी के आरंभ की अवधि में भारत में ही बनाए गए। यह प्रदर्शनी फ्रांसीसी-भारतीय व्यक्तियों के आपसी व्यवहार पर नए सिरे से रोशनी डालती है।

पियरे फ्रांस्वा कुइलियर-पेरोन: फ्रांस में एक कपड़ा व्यापारी के रूप में जन्मा पियरे कुइलियर अपने उपनाम जनरल पेरोन के नाम से अधिक प्रसिद्ध था। उसे अंग्रेज ग्वालियर के मराठा राज्य और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ प्रगाढ़ संबंधों के कारण अपने साम्राज्य विस्तार के लिए खतरा मानते थे। भारत में वर्ष 1780 में पहुंचे पेरोन ने सबसे पहले गोहद के राणा के यहां नौकरी की। उसने वर्ष 1795 में कर्दला की लड़ाई में हैदराबाद राज्य के खिलाफ मराठा विजय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका परिणाम यह हुआ कि महादजी सिंधिया के उत्तराधिकारी दौलत राव शिंदे ने पेरोन को अपनी 24,000 पैदल सेना, 3,000 घुड़सवार सेना और 120 तोपों की लगाम देते हुए अपना सेनापति बना दिया। यह एक दुर्जेय तालमेल था जबकि पेरोन की विस्तारवादी नीति से अंग्रेज चिंता में आ गए। पेरोन ने धीरे-धीरे शिंदे की सेना में अंग्रेज अधिकारियों को हटाकर उनके स्थान पर फ्रांसीसी अधिकारियों को नियुक्त किया। यहां तक कि उसने यमुना नदी के दक्षिण में एक बड़ी समृद्ध जागीर पर शासन करते हुए विभिन्न पक्षों से संधियां कीं। एक ऐसी ही संधि जनरल पेरोन ने दिल्ली में सिंधिया के रेसिडेंट के रूप में पटियाला के महाराजा साहिब सिंह से संधि की थी। जिसमें दोनों पक्षों ने आवश्यकता के समय में आपसी सहायता की सहमति पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के कौलनामे की प्रति भी यहां प्रदर्शित है। अंत में शिंदे को धोखा देने के बाद पेरोन की सेनाओं को अंग्रेजों ने पटपड़गंज की लड़ाई (1803) में पराजित किया। फिर अंग्रेजों ने उसे वर्ष 1806 में फ्रांस लौटने से पहले दो साल बंगाल में नजरबंद रखा।

शाह आलम द्वितीय: अली गौहर के रूप में जन्मा शाह आलम द्वितीय का पालन नजरबंदी में ही हुआ था। वर्ष 1759 में अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और फ्रांसीसी सैनिकों की मदद से वह बच निकला। पानीपत की तीसरी लड़ाई (वर्ष 1761) में अफगानों के विजयी गठबंधन का हिस्सा होने के कारण उसे ईनाम के रूप में सोलहवें मुगल सम्राट के रूप में ताज मिला। फिर उसे इलाहाबाद में 12 साल नजरबंदी के रूप में बिताने पड़े। अपनी राजधानी दिल्ली में आने में नाकाबिल निर्वासित मुगल सम्राट को वर्ष 1772 में मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने इलाहाबाद (अब प्रयागराज) से दिल्ली लाकर दोबारा तख्त पर बिठाया। इस दौरान उसने अपनी सेना को मजबूत करते हुए रोहिल्लों, जाट और सिखों के खिलाफ कई सैनिक सफलताएं हासिल की। वर्ष 1788 में रोहिल्ला नेता गुलाम कादिर ने उसे अंधा करके अपदस्थ कर दिया। फिर दोबारा महादजी ने कादिर को मारकर अंधे शाह आलम को तख्तनशीं किया। शाहआलम ने अपनी सल्तनत को बचाने के लिए अंग्रेजों से मराठों के खिलाफ मदद मांगी। बस यहीं से असली हुकूमत उसके हाथ से सदा के लिए निकल गई। वर्ष 1803 में हुई पटपड़गंज की लड़ाई के साथ ही दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। फिर तो मुगल सत्ता के लिए कहा जाने लगा, सल्तनत-ए-शाह आलम, दिल्ली से पालम (यानी शाह आलम का राज केवल दिल्ली से पालम तक ही है)।

बेगम समरू: बेगम समरू की पैदाइश को लेकर कयास ही अधिक है। दुश्मनों के लिए वह लड़ाई के मैदान में पांच फीट की एक आफत थी, जिसे अक्सर चुड़ैल समझा जाता था। दिल्ली में 14 साल की वह भोली लड़की, तीस साल के वाल्टर रेनहाईट उर्फ सोम्ब्रे की नजर में चढ़ गई। जिसका नतीजा यह हुआ कि बेगम समरू भरतपुर के राजा के कमांडर और एक कैथोलिक ईसाई सोम्ब्रे की दूसरी पत्नी बन गई। बेगम समरू केवल देखने भर की चीज नहीं थी, वह स्थानीय रियासतों की राजनीति और आपसी साजिशों से भली भांति परिचित थी। यही कारण है कि सोम्ब्रे की मौत के बाद समरू ने उसके बेटे को जागीर से बेदखल कर दिया। सोम्ब्रे की जागीर और सेना दोनों पर अधिकार करने के बाद कैथोलिक बनी समरू ने चतुराई से शाह आलम का भी समर्थन हासिल किया। मुगलिया सल्तनत के विद्रोहियों के दिल्ली की घेराबंदी के दौरान से लड़ने में मदद करने के एवज में शाह आलम ने उसे जेब-उन-निसा (स्त्री रत्न) का खिताब दिया। वर्ष 1793 में, बेगम समरू के गुप्त रूप से फ्रांसीसी कप्तान पियरे एंटोइन ले वासल्ट से शादी करने की खबर मिलने पर उसके सैनिकों ने विद्रोह करके उसे बंदी बना लिया। वह आयरिश कमांडर जॉर्ज थॉमस की मदद से रिहा तो हो जाती है पर वासाल्ट आत्महत्या करता है! वर्ष 1803 में दिल्ली पर कब्जा होने के बाद अंग्रेजों ने बेगम समरू को अपनी जागीर रखने की अनुमति दी। इसी का नतीजा था कि उसने कई वर्षों तक दिल्ली में अपना शानदार दरबार लगाया, जिसमें सभी राष्ट्रीयताओं के दरबारी-सैनिक होते थे।

मौज में जीते हैं मौजपुर के लोग

शहर के गांव

खान-पान...रीति-रिवाज...और परंपरओं से संपन्न है मौजपुर गांव। दिल्ली के समृद्ध, सर्वगुण संपन्न गांवों की नजीर है यह गांव। जहां पूरा गांव ही परिवार की मिसाल नजर आता है। मौजपुर गांव में, जहां महिलाएं एक ओर तो बड़ों को सम्मान देने के लिए पर्दा करती हैं वहीं महिलाएं छोटों व बड़ों दोनों के साथ खूब हंसी ठिठोली भी करती हैं। यहां आज भी समाज के लोग मिलजुल की ही हर त्योहार मनाते हैं। इस गांव को गुर्जर व ब्राह्मण समाज के लोगों ने मिलकर बसाया था। वर्तमान में यहां लगभग सभी जाति व धर्म के लोग मिल-जुलकर रह रहे हैं।

यूं बसा गांव : 150 वर्ष पुरानी बात है तब मौजपुर गांव पश्चिमी दिल्ली के रजौकरी इलाके के पास हुआ करता था। इसके बाद गांव के लोग किंग्सवे कैंप के पास आकर रहने लगे थे लेकिन इस क्षेत्र को विकसित करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने इस गांव को वहां विस्थापित कर दिया। गांव के लोगों ने फिर सोनिया विहार नानकसर के पास खजूरी नाम से अपना गांव बसाया। यमुना के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के पास होने के कारण यहां अक्सर बाढ़ आ जाती थी जिस कारण गांव के लोगों ने यहां से भी विस्थापन कर लिया। चौधरी बाबू ने बताया कि सन् 1869 के आसपास गांव के कुछ बुजुर्ग चौधरी मोती, पंडित रामप्रसाद व चौधरी चेतराम, चौधरी छज्जन, पंडित रामचंद्र ने मौजुद्दीन नामक एक व्यक्ति से खेत खरीद लिए और अपने परिवार को इस गांव में बसाया तो उन्होंने इस गांव का नाम मौजुद्दीन के नाम पर मौजपुर गांव रख दिया। तब से इस गांव का नाम मौजपुर गांव है।

कभी होती थी खेती अब चलती है मेट्रो : बुजुर्ग चौधरी अनूप ने बताया कि जाफराबाद का नाला पहले नहर हुआ करता था। यह नहर सहारनपुर से आती थी जिसमें यमुना का पानी बहता था। जब यमुना में बाढ़ आ जाती थी तो सारा पानी नहर से टकरा कर गांव में आ जाता था। उसके बाद क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिए तत्कालीन सरकार द्वारा 1956 में बांध का निर्माण कराया गया जिसे उस्मानपुर पुश्ता रोड का नाम दिया गया। आबादी बढ़ने के साथ-साथ क्षेत्र में गंदगी भी बढ़ने लगी और देखते ही देखते जाफराबाद नहर नाले में तब्दील हो गई। मौजपुर गांव यमुनापार के सबसे पुराने गांव में से एक है, एक समय में यहां खेती हुआ करती थी और आज यहां मेट्रो भी आ गई है।

ऐसे ही बरकरार है मौजपुर गांव के पुरुषों का ठाठ...हर उम्र वर्ग के लोग यूं आज भी ही मेल मिलाप से रहते हैं

इस गांव में चूल्हा कभी अलग नहीं बंटा। घर व पड़ोस की महिलाएं सब मिलजुल कर इसी तरह खाना पकाती हैं।

गांव की ऐतिहासिक धरोहर: मौजपुर गांव स्थित कृष्णा गली में एक बावली है जोकि गांव बसने से पहले ही यहां मौजूद थी। गांव के बुजुर्ग निवासी चौधरी भोला डेढ़ा ने बताया कि इस बावली के पानी से चरम रोग की बीमारी ठीक हो जाती थीं। बावली में अब पानी नाममात्र रह गया है लेकिन जब मैं छोटा था तो इस बावली में नहाया करता था। दूर-दूर से लोग इस बावली के पानी में नहाने आते थे। यह बावली आज भी जीवित है लेकिन अब यहां उतना पानी नहीं है। इस बावली के आसपास अब मंदिर बना दिया गया है। वहीं, बाबू राम चौक के पास एक कुआं है जो अब सूख चुका है। मौजपुर गांव में ही हरिजन बस्ती के पास गांव की कुल देवी का मंदिर भी है।

श्रमदान कर तैयार किया पंचायत घर : 1957 में गांव में एक पंचायत घर का निर्माण किया गया। गांव के बुजुर्ग चौधरी मुरली ने बताया कि इस पंचायत घर के निर्माण में मिट्टी ढोकर उन्होंने भी श्रम दान किया था। पंचायत घर की नींव चौधरी मोती, चौधरी चेतराम, चौधरी रूपचंद व चौधरी रामसरन प्रधान ने रखी थी। इस पूरे गांव ने पंचायत घर को बड़ी मेहनत करके बनवाया है।

गांव के रीति-रिवाज परंपराएं : गांव की महिलाओं का पहनावा ओढ़नी, कमीज व सलवार और पुरुषों का पहनावा धोती, कुर्ता व साफा है। अब महिलाएं सलवार सूट पहनती हैं लेकिन बुजुर्ग लोगों का पहनावा वही पुराना है। गांव में आज भी घूंघट प्रथा जीवित है इसलिए नहीं कि यहां लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, यहां की महिलाएं अपने से बड़े-बुजुर्ग के आगे घूंघट करके उनके प्रति सम्मान व्यक्त करती हैं। आज भी घर की सभी महिलाएं मिल-जुलकर खाना बनाती हैं। गांव में कुछ घरों में मिट्टी के तो कुछ घरों में पक्के सीमेंट के चूल्हे हैं। सभी महिलाएं चूल्हे के आसपास बैठ जाती हैं और तब मेल मिलाप के साथ खाना बनता है। गांव की बुजुर्ग महिला कर्मवती ने बताया कि उनके घर पर दूध उबालने के लिए राहे (मिट्टी का बर्तन) रखा है और हाथ से आटा पीसने वाली चक्की भी उनके पास है। आज भी गांव की महिलाएं अपने पर ही दूध से घी, मक्खन, मट्ठा बनाती हैं। वहीं, तीज-त्योहार, शादी ब्याह में गांव की महिलाएं मिलकर लोकगीत गाती हैं। चौधरी लाखू पहलवान बताते हैं कि हर साल चौमास में भूमिया माता का भव्य मेला लगता है, भूमिया माता के मंदिर में पूजा व हवन करके पानी को शुद्ध किया जाता है। लोगों ने बताया कि चौमास में खूब बरसात होती है जिस कारण भैंस व बैलों के पैर फट जाते हैं वह बीमार होने लगते हैं इस पानी से उनके पैर धोए जाते हैं जिससे उनकी बीमारी दूर हो जाती है।

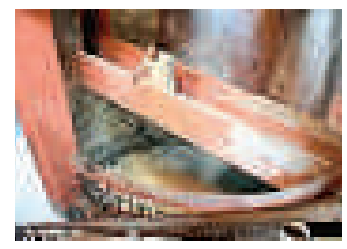

मौजपुर गांव की पुरानी बावली

किसान परिवार के बेटे बॉलीवुड तक पहुंचे :1988 गेंहू, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि की खेती हुआ करती थी। इसके बाद जैसे-जैसे शहरीकरण बढ़ता गया और लोगों की जरूरतें बढ़ने लगी, लोगों ने खेती छोड़ शिक्षा को अपनाया। बावजूद इसके आज भी गांव का हर व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ है। पढ़-लिखने के बाद भी लोग अपनी परंपराओं व संस्कारों को नहीं भूले हैं। गांव का बेटा सुधीर के चौधरी बॉलीवुड फोटोग्राफी निदेशक है जिसने प्यार का पंचनामा,प्यार का पंचनामा 2, सोनू के टीटू की स्वीटी आदि फिल्मों के लिए काम किया है।

रितु राणा
सभी फोटो : हरीश कुमार

कारोबारियों के लिए इन्सॉल्वेंसी प्रावधान में सुधार

नई दिल्ली, आइएएनएस : इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (आइबीबीआइ) ने कारोबारियों के लिए इन्सॉवेंसी प्रक्रिया में सुधार किया है। यह सुधार गुरुवार से प्रभाव में आ गए हैं। आइबीबीआइ की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के नियम 25-ए में सुधार किया गया है। इस नियम में कहा गया है कि अधिकृत प्रतिनिधि कर्जदाताओं के नाम से वोट डाल सकता है।

मौजूदा आर्थिक परिदृश्य ने सरकार को संरचनात्मक सुधार आजमाने और उन पर काम करने के मौके दिए हैं। मैं समझता हूं कि पूर्व में उठाए गए कदम इकोनॉमी को मजबूती देने में पूरी तरह कारगर साबित होंगे।

— कृष्णमूर्ति सुब्रमणियन
मुख्य आर्थिक सलाहकार

सेंसेक्स 40,793.81 ▼ 336.36	निफ्टी 12,056.05 ▼ 95.10	सोना प्रति दस ग्राम ₹38,695 ▲ ₹143	चांदी प्रति किलोग्राम ₹45,375 ▲ ₹108	$ डॉलर ₹71.73 ▲ ₹0.11	क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल $ 63.61

निवेश को बढ़ावा देने के लिए की गई कॉरपोरेट टैक्स में कटौती

नई दिल्ली, प्रेट्र : मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमणियन ने कहा है कि इकोनॉमिक गतिविधियों को गति देने के लिए कॉरपोरेट टैक्स में कटौती जैसा कदम उठाना जरूरी था। उन्होंने कहा कि पिछली कुछ तिमाहियों से इकोनॉमी अपेक्षा के अनुरूप विकास नहीं कर रही है। इसमें जान फूंकने के लिए टैक्स कटौती जैसा फैसला लेना जरूरी हो गया था। सुब्रमणियन ने कहा कि वर्ष 2025 तक पांच लाख करोड़ डॉलर इकोनॉमी का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आर्थिक सुधार के क्षेत्र में कदम बढ़ाने होंगे।

इस वर्ष जुलाई में जारी आर्थिक सर्वे में 2025 तक पांच लाख करोड़ डॉलर इकोनॉमी का लक्ष्य रखा गया और इसे पाने के रणनीतिक उपायों की चर्चा की गई थी। इस दौरान निवेश पर विशेष जोर दिया गया था। सुब्रमणियन ने कहा कि इकोनॉमी में उत्पादन को गति देने के लिए निवेश बहुत जरूरी है। उत्पादन बढ़ेगा तो आय बढ़ेगी, नौकरियां पैदा होंगी। इससे निर्यात भी बढ़ेगा। इन सबकी वजह से लोगों के हाथ में पैसा आएगा, जिससे उनकी खरीद क्षमता बढ़ेगी और मांग में इजाफा होगा।

मुख्य आर्थिक सलाहकार का कहना था कि कॉरपोरेट जगत को दोहरा टैक्स देना पड़ता है। पहले तो उन्हें कंपनी के रूप में टैक्स चुकाना होता है। इसके बाद पूंजी पर हुई बचत या लाभांश पर टैक्स चुकाना होता है। उन्होंने कहा कि इस दोहरे टैक्स के भार को कम करने के लिए कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की गई है। गौरतलब है कि इसी वर्ष सितंबर में सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स को 30 परसेंट से घटाकर 22 परसेंट कर दिया था। इसके अलावा नई मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों के लिए यह 15 परसेंट कर दिया गया था।

प्रतीकात्मक

- मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कॉरपोरेट टैक्स में छूट को बताया जरूरी
- कहा - कॉरपोरेट जगत पर दोहरे टैक्स का भार, इसलिए जरूरी थी कटौती

इकोनॉमी में नई जान फूंकने के लिए करने होंगे गंभीर प्रयास

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- विशेषज्ञों की राय में तीसरी तिमाही से हालात सुधरने के बावजूद धीमी रहेगी विकास दर
- राजकोषीय स्थिति भी बेहद चिंताजनक, खपत बढ़ाना बड़ी चुनौती

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में देश की आर्थिक विकास दर पिछले छह वर्षों के निचले स्तर तक लुढ़क गई है। लेकिन ज्यादा चिंता की बात यह है कि इस हालात में फिलहाल बड़े सुधार की गुंजाइश नहीं है। विशेषज्ञों की राय में लगातार छह तिमाहियों से आर्थिक विकास में आ रही गिरावट और सरकार के राजस्व में भारी कमी मिलकर अर्थव्यवस्था के समक्ष एक बड़ी चुनौती पेश कर रही हैं, जिससे पार पाना आसान नहीं होगा। ऐसे में सरकार के लिए चालू वित्त वर्ष के अगले चार महीनों के दौरान राजकोषीय संतुलन बनाना आसान नहीं होगा। आर्थिक विशेषज्ञ यह भी कह रहे हैं कि अगली तिमाही से देश की आर्थिक विकास दर सुधरेगी। लेकिन यह इसलिए नहीं कि मूलभूत हालात में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, बल्कि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाहियों में विकास दर काफी नीचे रही थी।

दूसरी तरफ, अर्थविदों की इस आशंकाओं के बावजूद वित्त मंत्रालय के अधिकारी मानते हैं कि अगली तिमाही से हालात में सुधार तय है। आर्थिक मामलों के सचिव अतनु चक्रवर्ती का कहना है कि विकास दर के ताजा आंकड़ों के बावजूद भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है। विदेशी संस्थागत व अन्य निजी निवेशकों का भरोसा भारतीय बाजार व यहां की इकोनॉमी पर मजबूत हो रहा है। अप्रैल-अक्टूबर, 2019 में 23.86 अरब डॉलर का निवेश आया है जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह राशि महज 9.04 अरब डॉलर की थी। उन्होंने निजी निवेश की रफ्तार को लेकर चिंता जरूर जताई, लेकिन यह भी कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को अर्थव्यवस्था में ज्यादा भागीदारी देने की कोशिश कर रही है। इस संदर्भ में उन्होंने सरकारी उपक्रमों के विनिवेश को लेकर हाल के फैसलों का जिक्र किया और कहा कि कुछ महत्वपूर्ण उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी 51 फीसद से नीचे लाने का फैसला ऐसा है, जो पहले कभी नहीं हुआ।

दैनिक जागरण ने कई अर्थविदों से इस बारे में बात की। ज्यादातर जानकार इस बात से सहमत हैं कि तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर, 2019) और उसके बाद से आर्थिक विकास दर पहले से बेहतर होगी। लेकिन पहली छमाही में विकास दर के बेहद कम होने का असर कई तरह से आने वाले दिनों में पड़ेगा।

राजकोषीय संतुलन की चुनौती : शुक्रवार को सरकार की तरफ से बताया गया है कि वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में राजकोषीय घाटा लक्ष्य का 102.4 फीसद हो गया है। चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 3.3 फीसद का रखा है। जीएसटी और प्रत्यक्ष कर के जो आंकड़े अभी तक सामने आए हैं, वे बेहद निराशाजनक हैं। जीएसटी संग्रह पिछले सात महीनों में सिर्फ एक बार एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रहा है, जबकि सरकार ने हर महीने 1.14 लाख करोड़ रुपये संग्रह का अनुमान लगाया था। फिच रेटिंग एजेंसी के चीफ इकोनोमिस्ट सुनील सिन्हा का कहना है कि बाकी बचे महीनों में लक्ष्य के मुताबिक राजस्व संग्रह करीब-करीब नामुमकिन है। ऐसे में सरकार को राजकोषीय घाटे का लक्ष्य बढ़ाना होगा, या फिर खर्चे पर लगाम लगाना होगा। हालांकि मौजूदा परिदृश्य में खर्चे में कटौती करने का ज्यादा विपरीत असर होगा।

क्रिसिल के अर्थशास्त्री डीके. जोशी का कहना है कि, 'सरकार के खर्चे में 13.1 फीसद का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से विकास दर की रफ्तार चार फीसद को पार कर सकी है। दूसरी तरफ देखा जाए, तो निजी क्षेत्र के खर्चे में महज 3.1 फीसद की गिरावट है। अब देखना है कि देश में उपभोग बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये जाते हैं।' फिक्की, एसोचैम जैसे उद्योग चैंबर भी जीडीपी की सुस्त रफ्तार के लिए उपभोग में कमी को बड़ी वजह मानते हैं। माना जा रहा है कि आरबीआइ ने इस वर्ष रेपो रेट घटा कर कर्ज को सस्ता कर घरेलू मांग बढ़ाने की जो कोशिश की है, वह भी काम नहीं कर पा रही है।

तिमाही दर तिमाही बदहाली की गवाही

भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भले ही सफाई दें कि यह मंदी नहीं आर्थिक सुस्ती है, लेकिन एक के बाद एक तिमाही में गिरती जीडीपी विकास दर तस्वीर साफ कर देती है। शुक्रवार को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में ये विकास दर गिरकर 4.5 फीसद पर पहुंच चुकी है।

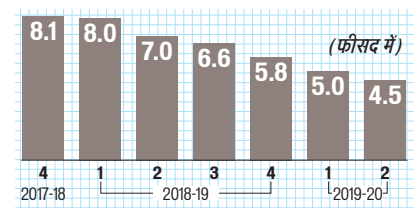

अनुमानों के निकट रही वास्तविक दर

केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कई कदम उठाए। सितंबर में कॉरपोरेट टैक्स में कमी की गई। इसके बावजूद अर्थव्यवस्था में गिरावट लगातार जारी है। कई आर्थिक संस्थाओं ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए पहले ही गिरावट का अनुमान जताया था।

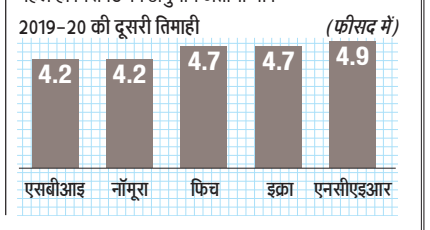

न्यूज गैलरी

ओएफआइ ग्लोबल चाइना फंड ने जी में खरीदी अतिरिक्त हिस्सेदारी

नई दिल्ली : जी एंटरनेटमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड (जेडईईएल) ने गुरुवार को कहा कि ओएफआइ चाइना ग्लोबल फंड एलएलसी ने उसके 1.37 करोड़ अतिरिक्त शेयर खरीदे हैं। यह कंपनी की 1.431 प्रतिशत शेयर हिस्सेदारी के बराबर हैं। इससे पहले जी एंटरटेनमेंट में ओएफआइ ग्लोबल चाइना फंड की 8.7 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। अब कंपनी में चीन के इस फंड की हिस्सेदारी 10.99 प्रतिशत हो गई है। (प्रेट्र)

स्वीडन के कारोबारियों की भारत में बड़ी दिलचस्पी

स्टॉकहोम : स्वीडन के किंग कार्ल-16 गुस्ताफ ने अपनी भारत यात्रा से पहले कहा है कि उनके देश के कारोबारियों की भारत में बड़ी दिलचस्पी है। गुस्ताफ अपनी पत्नी के साथ दिसंबर की शुरुआत में भारत यात्रा पर जाने वाले हैं। यह उनकी तीसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वे वर्ष 1993 और फिर वर्ष 2005 में भारत यात्रा पर गए थे। गुस्ताफ ने कहा कि कारोबार के मामले में भारत में काफी कुछ नया हो रहा है। उनके यहां का कारोबारी समाज भारत के प्रति बेहद सकारात्मक नजरिया रखता है। (प्रेट्र)

आदित्य पुरी के उत्तराधिकारी की तलाश शुरू

नई दिल्ली : निजी क्षेत्र के अग्रणी कर्जदाता एचडीएफसी बैंक ने एमडी आदित्य पुरी के उत्तराधिकारी की तलाश के लिए छह सदस्यीय समिति का गठन किया है। पुरी 70 वर्ष की आयु में अगले वर्ष 26 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। समिति में श्यामला गोपीनाथ, संजीव सच्चर, एमडी रंगनाथ, संदीप पारेख, श्रीकांत नादमुणि और केकी मिस्त्री शामिल हैं। यह समिति बैंक के भीतर और बाहर से संभावित उम्मीदवारों का चयन करेगी। (प्रेट्र)

बिना इजाजत विदेशी आइटी स्क्रूटनी सेवा नहीं लें

नई दिल्ली : साइबर सेक्योरिटी के लिए नोडल एजेंसी सर्ट-इन ने सरकारी कंपनियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि सरकारी कंपनियां अपनी आइटी सेक्योरिटी की ऑडिट संबंधित गतिविधियों के लिए गृह मंत्रालय की इजाजत के बगैर किसी भी विदेशी ऑडिट कंपनी की सेवा नहीं लें। सर्ट-इन ने 21 नवंबर को यह एडवाइजरी जारी की है। एजेंसी के मुताबिक इससे संवेदनशील सूचनाएं विदेशी कंपनियों या व्यक्तियों तक पहुंचने का जोखिम है। (प्रेट्र)

निर्यातकों के लिए टैक्स रिफंड स्कीम लाने की तैयारी

सरकार ने कहा ▶ स्कीम के जरिये निर्यात को दिया जाएगा बढ़ावा

कैबिनेट के सामने जल्द रखी जाएगी योजना

नई दिल्ली, प्रेट्र : निर्यातकों के लिए सरकार टैक्स रिफंड स्कीम लाने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा को बताया कि इसे जल्द ही कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान गोयल ने बताया कि सरकार श्रम कानूनों में सुधार के लिए भी प्रयासरत है। इससे जुड़े प्रस्ताव को संसद की मंजूरी के लिए पेश करने की तैयारी की जा रही है।

ट्रेड-वार और संरक्षणवाद की चर्चा करते हुए वाणिज्य मंत्री ने कहा कि इस समय व्यापार के लिए विपरीत वैश्विक परिस्थितियां हैं। इन सबके बीच सरकार उत्पादन में विस्तार हेतु स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा निर्यात पर शुल्क और टैक्स में छूट देने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। इस छूट को टैक्स रिफंड स्कीम के जरिये लागू किया जाएगा।

इस दौरान गोयल ने तकनीक क्षेत्र के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत टेक्नोलॉजी की दौड़ में पीछे नहीं रह सकता। इसलिए सरकार कौशल-विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस क्षेत्र में 3-डी मैन्यूफैक्चरिंग, एआइ और बेहतर डाटा एनालिटिक्स पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारत इन मामलों में दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कई बार हम प्रतिस्पर्धी मौकों का लाभ उठाने में असफल रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, जिनसे उबरने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की है। नई कंपनियों के मामले में कॉरपोरेट टैक्स घटकर 15 परसेंट रह गया है।

प्रतीकात्मक

आसियान देशों से एफटीए पर बातचीत कर रही सरकार

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार एफटीए पर पुनर्विचार के लिए आसियान देशों से संपर्क कर रही है। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि 10 वर्ष पहले हुए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से भारत को पर्याप्त लाभ नहीं हो रहा है। कई मामलों में एफटीए की वजह से घरेलू उत्पादकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। गोयल के मुताबिक भारत ने घरेलू कॉफी उत्पादकों का हित ध्यान में रखे बिना अपने बाजार को दुनियाभर के लिए खोल दिया। इससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। सरकार इस समझौते में सुधार के लिए प्रयासरत है और आसियान के सदस्य देशों से इस बारे में बातचीत की शुरुआत हो चुकी है।

सोने के गहनों और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग 2021 से होगी अनिवार्य

नई दिल्ली, प्रेट्र : उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने शुक्रवार को एलान किया कि 15 जनवरी, 2021 से देशभर में सोने के गहनों और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी। इसके लिए जौहरियों को एक वर्ष की मोहलत दी जाएगी। हॉलमार्किंग अनिवार्य किए जाने से ग्राहकों को शुद्ध सोना मिलेगा। वर्तमान में सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग ऐच्छिक है।

पासवान ने कहा कि उपभोक्ता मामलों का विभाग 15 जनवरी, 2020 तक गोल्ड हॉलमार्किंग अनिवार्य बनाने से संबंधित अधिसूचना जारी कर देगा। उसके बाद एक वर्ष की मोहलत इसलिए दी गई है, ताकि ज्वैलर्स अपना पुराना स्टॉक निकाल सकें। पासवान ने यह भी स्पष्ट किया कि ग्राहकों के पास जो पुरानी ज्वैलरी पड़ी है, उसकी हॉलमार्किंग अनिवार्य करने की मंत्रालय की कोई योजना नहीं है।

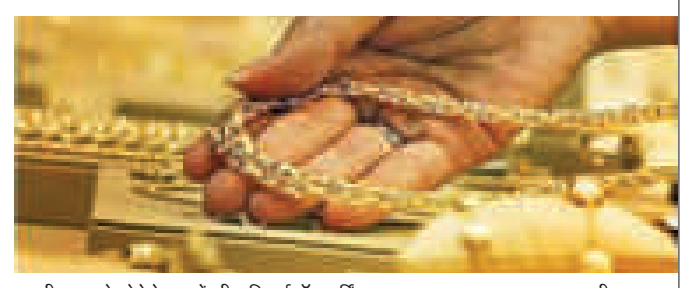

काफी समय से सोने के गहनों की अनिवार्य हॉलमार्किंग पर काम चल रहा था। प्रतीकात्मक

- उपभोक्ता मामलों के मंत्री पासवान ने किया एलान, 15 जनवरी 2020 तक जारी होगी अधिसूचना

क्या होता है हॉलमार्किंग

हॉलमार्किंग सोने की शुद्धता का प्रमाण होता है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग के लिए अधिकृत अथॉरिटी है। बीआईएस उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अधीन है। ब्यूरो ने सोने के गहनों की हॉलमार्किंग के लिए तीन ग्रेड 14 कैरट, 18 कैरट और 22 कैरट में स्टैंडर्ड निर्धारित किए हैं। मंत्रालय के अनुसार ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए सोने के गहनों पर मानक तय करना अनिवार्य है।

सराफा बाजारों में रहा तेजी का रुख

नई दिल्ली, प्रेट्र : शुक्रवार को प्रमुख भारतीय सराफा बाजारों में तेजी का रुख रहा। इस दौरान सोना 143 रुपये सुधार के साथ के 38,695 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिका। वहीं चांदी कीमत में भी इजाफा हुआ। दिन के कारोबार में चांदी 108 रुपये की तेजी के साथ 45,375 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बिकी। जानकारों के मुताबिक रुपये की कीमत में गिरावट और सोने के अंतरराष्ट्रीय भाव में तेजी के चलते घरेलू बाजारों में सोना मजबूत हुआ। इस दौरान ग्लोबल मार्केट में सोना 1,458 डॉलर और चांदी 16.92 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) के भाव पर बिके।

ऑटो क्षेत्र को कुशल संसाधन की कमी नहीं होने देंगे : मेघवाल

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम

- केंद्रीय भारी उद्योग राज्यमंत्री न्यू जेन मोबिलिटी समिट में बतौर मुख्य अतिथि रहे मौजूद
- आइएमटी मानेसर स्थित आइकेट समिट के समापन समारोह को किया संबोधित

केंद्रीय भारी उद्योग राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र को कुशल मानव संसाधनों की कमी नहीं होने देंगे। इसके लिए स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय के साथ तालमेल स्थापित किया जाएगा। उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। आइएमटी मानेसर स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आइकेट) में आयोजित न्यू जेन मोबिलिटी समिट, 2019 में उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र की बेहतरी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक निकाय बनाने का जो सुझाव दिया गया है, उस पर विचार किया जाएगा।

मेघवाल ने यह भी जिक्र किया कि केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए फेम इंडिया के अंतर्गत 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। केंद्रीय राज्यमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के उस सूत्र का भी उल्लेख किया कि हमेशा सपने बड़े देखने चाहिए।

सम्मेलन के दौरान तीनों दिन विशेषज्ञों ने इस क्षेत्र की वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों और संभावनाओं को लेकर मंथन किया। सभी इस बात को लेकर एकमत रहे कि मौजूदा स्थिति में इस क्षेत्र की बेहतरी के लिए काफी कुछ करने की जरूरत है। आरएंडडी की बहुत बहुत जरूरत है। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ने की चुनौती है। ऐसा होगा तो ही संभावनाओं के बड़े द्वारा खुलेंगे। विशेषज्ञों ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर भारत में दबाव बढ़ रहा है। इस दिशा में बिना किसी संकोच के आगे बढ़ने की जरूरत है।

बिडिंग में ज्यूरिख से काफी पीछे रहीं घरेलू कंपनियां

अरविंद मिश्रा, ग्रेटर नोएडा

- दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को अतिरिक्त 10 अंक भी नहीं आए काम

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डेवलपर की दौड़ में भारतीय कंपनियां स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी के सामने बौनी साबित हुईं। ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल ने न सिर्फ प्रति यात्री अधिकतम राजस्व की बोली लगाकर बाजी मार ली, बल्कि तकनीकी बिड में कंपनी की नेटवर्थ के हिसाब से भी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल और भारतीय कंपनियों के बीच बड़ा अंतर था। डेवलपर के तौर पर ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल के चयन के साथ एक रिकॉर्ड भी कायम हो गया है। भारतीय एयरपोर्ट के डेवलपर के रूप में यह पूर्ण विदेश स्वामित्व वाली पहली कंपनी बन गई है।

तकनीकी स्कोर के मामले में भी भारतीय कंपनियां स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख एयरपोर्ट से पिछड़ गईं। ज्यूरिख एयरपोर्ट का तकनीकी स्कोर 91021 रहा, जबकि निकटतम प्रतिद्वंद्वी कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज का 53784, एंकरेज का 16751 रहा। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को इसमें 10 अंक का बोनस भी दिया गया था। लेकिन ज्यूरिख एयरपोर्ट के सामने यह काम नहीं आया।

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बिड के लिए शर्त थी कि कंपनी ने पिछले 10 वर्षों में कम से कम 10 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट डेवलप किया हो और उसकी नेटवर्थ कम से कम 1,250 करोड़ रुपये हो। इस मामले में भी ज्यूरिख एयरपोर्ट सब पर भारी साबित हुई।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के अधिकारियों के अनुसार देश में जितने भी एयरपोर्ट हैं, उसमें किसी का संचालन पूरी तरह से विदेश कंपनी के हाथ में नहीं है। भारतीय कंपनियों के साथ विदेशी कंपनियों की भागीदारी है। जबकि ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी पूरी तरह से विदेशी कंपनी है, जो जेवर एयरपोर्ट का निर्माण एवं संचालन करेगी।

दुनियाभर में चार एयरपोर्ट का संचालन कर रही है ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल : जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए चयनित ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी दुनिया में चार इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन करती है। ब्राजील में बेलो हॉरीजोंटे एयरपोर्ट, चिली में एंटोफोगास्टा एयरपोर्ट, कोलंबिया एयरपोर्ट शामिल हैं।

3,700 परिवारों का होगा विस्थापन

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए दयानतपुर, रोही, पारोही, किशोरपुर, रन्हेरा, बनबारीवास गांव की जमीन का अधिग्रहण किया गया है। एयरपोर्ट से करीब 3,700 परिवारों का विस्थापन होगा। इन परिवारों को जेवर बांगर गांव में बसाया जाएगा। पुनर्वास के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रकिया पूरी की जा रही है।

प्रतीकात्मक

अस्सी फीसद जमीन पर मिल चुका है कब्जा

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला चरण 1334 हेक्टेयर जमीन पर होगा। 1,239 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण व शेष पुनर्ग्रहण से ली जा रही है। अस्सी फीसद जमीन पर अधिग्रहण कार्य पूरा हो चुका है। यह जमीन यमुना प्राधिकरण के कब्जे में आ चुकी है। शेष 20 फीसद जमीन पर कब्जा लेने के लिए किसानों को नोटिस जारी किया गया है। मुआवजा न उठाने पर धनराशि अधिकरण में जमा कराने के बाद प्रशासन जमीन पर कब्जा लेने की कार्यवाही करेगा।

लेखाजोखा

ग्लोबल संकेत और घरेलू चिंताएं भी रहीं गिरावट की वजह, सेंसेक्स और निफ्टी साप्ताहिक बढ़त दर्ज करने में रहे सफल

जीडीपी आंकड़ों के इंतजार में सुस्ताए घरेलू शेयर बाजार

मुंबई, प्रेट्र : पिछले कुछ सत्रों से रिकॉर्ड स्तर पर बंद हो रहे प्रमुख घरेलू शेयर बाजार शुक्रवार को प्रॉफिट बुकिंग के शिकार हुए। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के जीडीपी विकास दर आंकड़ों के इंतजार में निवेशकों में थोड़ी सुस्ती देखी गई। वहीं, हांगकांग को लेकर अमेरिका-चीन में तनाव ने भी निवेशकों को बैकफुट पर रखा। दिन के कारोबार में बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 336.36 अंक यानी 0.82 परसेंट लुढ़ककर 40,793.81 पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला निफ्टी 95.10 अंक टूटकर 12,056.05 पर स्थिर हुआ। हालांकि साप्ताहिक आधार पर सेंसेक्स 434.40 अंक की बढ़त दर्ज करने में सफल रहा। वहीं निफ्टी भी 141.65 अंक सुधार के साथ बंद हुआ।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च प्रमुख विनोद नायर के मुताबिक हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र पर यूस-चीन के बीच हांगकांग मुद्दे पर तनातनी का नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसके अलावा जीडीपी आंकड़ों के कम रहने की आशंका के चलते भी प्रॉफिट बुकिंग को बल मिला।

सेंसेक्स पैक में सप्ताह के आखिरी कारोबारी सत्र के दौरान यस बैंक के शेयरों में सबसे ज्यादा 2.50 परसेंट की गिरावट आई। एचयूएल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एसबीआइ, टाटा मोटर्स और वेदांता के शेयरों में भी 2.37 परसेंट तक की गिरावट देखी गई। दूसरी ओर एयरटेल, एचडीएफसी बैंक और एनटीपीसी के शेयर हरे निशान पर बंद हुए। बीएसई में एनर्जी, मेटल, ऑटो, ऑयल एंड गैस और कैपिटल गुड्स कंपनियों के शेयरों में 1.46 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई। वहीं टेलीकॉम, रियल्टी, यूटिलिटीज और पावर सेक्टर के शेयर 2.54 परसेंट उछाल के साथ बंद हुए। एशिया के अन्य बाजारों में हांगकांग, टोक्यो, और सियोल के बाजार लाल निशान पर बंद हुए। हालांकि यूरोप के शेयर बाजार अपने शुरुआती कारोबार के दौरान बढ़त दर्ज करने में सफल रहे।

प्रतीकात्मक

एनएसई के कमोडिटी सेग्मेंट को सीबीडीटी से मिली मान्यता

नई दिल्ली, प्रेट्र : अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के कमोडिटी डेरिवेटिव्स सेग्मेंट को एसोसिएशन की मान्यता मिल गई है। सीबीडीटी द्वारा मिली मान्यता से इस सेग्मेंट के ट्रेडर्स को टैक्स लाभ मिलेंगे। एनएसई द्वारा जारी एक वक्तव्य में कहा गया है कि उसने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) में इसके लिए आवेदन किया था। सीबीडीटी ने सभी जरूरी शर्तों की जांच के बाद एक्सचेंज के इस सेग्मेंट को एसोसिएशन की मान्यता दे दी है।

इन शेयरों में रही गहमागहमी

आरकॉम : कर्ज संकट से जूझ रही इस कंपनी के लिए भारती एयरटेल द्वारा 9,500 करोड़ की बोली जमा करने की खबरों के बीच इसके शेयरों में तेज उछाल देखा गया। दिन के कारोबार में बीएसई में कंपनी के शेयर 3.85 परसेंट उछलकर 81 पैसे प्रति शेयर पर बंद हुए। वहीं एनएसई में आरकॉम के शेयरों में 5.26 परसेंट की तेजी देखी गई। यहां कंपनी के शेयर एक रुपया प्रति शेयर के भाव पर बिके।

आइसीआइसीआइ सिक्युरिटीज : शुक्रवार को कंपनी के शेयरों में पांच परसेंट तक का उछाल देखा गया। कंपनी ने शेयर बाजारों को बताया कि सेबी के साथ चल रहे स्टॉक ब्रोकिंग नियमों के उल्लंघन के मामले को 28 लाख रुपये का जुर्माना देकर निपटा लिया गया है। इस खबर के कारण बीएसई में कंपनी के शेयर 5.17 परसेंट उछलकर 347.05 रुपये पर बंद हुए। वहीं एनएसीई में यह 4.61 परसेंट की तेजी के साथ 345.10 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर बिके।

फ्यूचर ग्रुप : दिन के कारोबार में ग्रुप के शेयरों में 20 परसेंट तक की तेजी देखी गई। बीएसई में फ्यूचर इंटरप्राइजेज के शेयर 19.86 परसेंट उछाल के साथ 26.55 रुपये के भाव पर बंद हुए। इससे पहले कंपनी ने बताया था कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) ने अमेजन को फ्यूचर ग्रुप में 49 परसेंट हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति दे दी है।

अडानी गैस : टोटल ग्रुप द्वारा कंपनी में 37.4 परसेंट की हिस्सेदारी खरीदने को मंजूरी मिलने के बाद अडानी गैस के शेयरों में आठ परसेंट तक की तेजी आई। बीएसई में कंपनी के शेयर 7.89 की तेजी के साथ 161.30 रुपये पर बंद हुए। वहीं एनएसई में यह 7.52 परसेंट उछलकर 160.70 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बंद हुए।

दिवालिया प्रक्रिया में गई डीएचएफएल

मुंबई, प्रेट्र : आरबीआइ ने संकट से जूझ रही हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी डीएचएफएल का मामला रिजॉल्यूशन प्रक्रिया के लिए एनसीएलटी के पास भेज दिया है। दीवान हाउसिंग फाइनेंस फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) इस रिजॉल्यूशन के लिए एनसीएलटी जाने वाली पहली एनबीएफसी है। पिछले सप्ताह आरबीआइ ने खराब कॉरपोरेट गर्वनेंस और डिफॉल्ट के चलते इसके बोर्ड को भंग कर एक प्रशासक की नियुक्ति की थी। आरबीआइ ने कहा है कि जब तक एसीएलटी इसके रिजॉल्यूशन पर विचार करती है, तब तक इसे कर्ज चुकाने पर अंतरिम छूट दी गई है। इसी महीने की 15 तारीख को सरकार ने इस मामले को आरबीआइ को सौंप दिया था। इसके बाद 20 तारीख को आरबीआइ ने इसके बोर्ड को भंग करके इंडियन ओवरसीज बैंक के पूर्व प्रमुख आर. सुब्रमण्यकुमार को इसका प्रशासक नियुक्त कर दिया था। सुब्रमण्यकुमार की मदद के लिए 22 तारीख को एक कमेटी का गठन किया गया था। यह कमेटी कंपनी की रिजॉल्यूशन प्रक्रिया में सुब्रमण्यकुमार की मदद करेगी।

4 साल पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए आतंकी हमले के मामले में कुल 20 आरोपितों पर मुकदमा चलाया जाएगा। 15 नवंबर, 2015 को नेशनल स्टेडियम समेत कई जगहों पर आइएस के दस आतंकियों ने गोलीबारी कर 130 लोगों की जान ले ली थी।

न्यूज गैलरी

हिंसा की चपेट में इराक 45 लोगों की मौत

नसीरिया : इराक में सरकार के खिलाफ पिछले दो महीने से जारी प्रदर्शनों ने हिंसा का रूप ले लिया है। राजधानी बगदाद और देश के दक्षिणी क्षेत्र में गुरुवार को उग्र प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 45 लोगों की मौत हो गई। अकेले नसीरिया में 25 लोग मारे गए। शिया समुदाय के पवित्र शहर नजफ में भी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में दस प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। सुरक्षा बलों ने यह कार्रवाई प्रदर्शनकारियों द्वारा बुधवार देर रात नजफ स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास को फूंक देने के बाद की। बढ़ती हिंसा से चिंतित इराक में शिया समुदाय के शीर्ष धर्मगुरु आयतुल्लाह अली अल-सिस्तानी ने मुल्क का नेतृत्व बदलने की सलाह दी है। (एएफपी)

धुएं से भरे सिडनी में जलवायु परिवर्तन पर प्रदर्शन

सिडनी : जलवायु परिवर्तन के पर्यावरण पर दुष्प्रभावों को लेकर वैश्विक प्रदर्शनों की शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से शुरुआत की गई। देश के दक्षिणपूर्वी हिस्से के जंगलों में लगी आग के कारण धुएं से भरे सिडनी में पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने स्कूली बच्चों के साथ मिलकर धरना-प्रदर्शन किया। मुख्य प्रदर्शन सिडनी स्थित ऑस्ट्रेलिया की सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी के मुख्यालय पर किया गया। प्रदर्शनकारी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में धमाकेदार भाषण देने वाली 16 साल की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग की अपील पर जुटे थे। (एएफपी)

ट्रंप प्रशासन और तालिबान के बीच शांति वार्ता फिर बहाल

सुलह के आसार ▶ अचानक अफगानिस्तान पहुंचे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया एलान

आतंकी संगठन ने कहा वार्ता के बारे में कुछ कहने की जल्दबाजी नहीं

वाशिंगटन, प्रेट्र : अफगानिस्तान के पहले और आकस्मिक दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलान किया कि उनके प्रशासन ने तालिबान के साथ शांति वार्ता बहाल कर दी है। ट्रंप ने गत सितंबर में इस आतंकी संगठन के साथ वार्ता अचानक रद कर दी थी। तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने इस पर कहा, अमेरिका के साथ सीधी वार्ता बहाल होने के बारे में कुछ कहना अभी जल्दबाजी है। हमारा संगठन इस पर बाद में प्रतिक्रिया देगा।

ट्रंप गुरुवार को काबुल के बाहरी इलाके में स्थित बगराम एयरबेस पर पहुंचे और वहां तैनात अमेरिकी सैनिकों से बातचीत की। यह अफगानिस्तान में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। बगराम में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा, 'वे (तालिबान) समझौता करना चाहते हैं और हम उनके साथ बैठक कर रहे हैं। वे पहले संघर्ष विराम नहीं चाहते थे, लेकिन अब वे ऐसा करना चाहते हैं। मुझे यकीन है कि इस पर इसी दिशा में काम होगा।' अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा, 'हम समझौता होने या पूरी तरह जीत होने तक यहां रहने जा रहे हैं।' इससे पहले ट्रंप ने बगराम में ही अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और अमेरिकी सैनिकों को संबोधित किया। उन्होंने सैनिकों से कहा, 'अफगानिस्तान का युद्ध के मैदान में फैसला नहीं होगा। इसका राजनीतिक समाधान निकालने की जरूरत है।'

इस तरह पटरी पर आई वार्ता : तालिबान ने हाल में अमेरिका के केविन किंग और ऑस्ट्रेलिया के टिमोथी वीक्स को रिहा किया था। ये दोनों काबुल स्थित अमेरिकी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उन्हें अगस्त, 2016 में अगवा कर लिया गया था। इस रिहाई के बाद शांति वार्ता दोबारा पटरी पर आई।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक अफगानिस्तान पहुंचकर सभी को चौंका दिया। उन्होंने काबुल के बाहरी इलाके में बगराम एयर बेस में अमेरिकी सैनिकों को संबोधित किया। इस मौके पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी भी मौजूद रहे। रायटर

अफगानिस्तान में 13 हजार अमेरिकी सैनिक

अफगानिस्तान में इस समय करीब 13 हजार अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ट्रंप ने पुष्टि की है कि वह इस संख्या को 8,600 के स्तर पर लाए जाने की उम्मीद करते हैं। उन्होंने हालांकि इसके लिए कोई समय सीमा नहीं बताई।

अचानक रद कर दी थी वार्ता

ट्रंप ने गत आठ सितंबर को तालिबान के साथ शांति वार्ता अचानक रद कर दी थी। अफगानिस्तान में तालिबान के हमले में एक अमेरिकी सैनिक की मौत के बाद उन्होंने यह कदम उठाया था। वार्ता ऐसे समय पर रद हुई थी, जब अमेरिका और तालिबान शांति समझौते के बेहद करीब दिख रहे थे।

जलवायु परिवर्तन पर बहस से जॉनसन ने किया किनारा

- टीवी चैनल ने उनके स्थान पर कंजरवेटिव पार्टी के लोगो वाली बर्फ की कलाकृति रखी
- ब्रेक्जिट पार्टी के नेता निगेल फराज ने भी इस बहस में नहीं लिया हिस्सा

लंदन, एएनआइ : ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गुरुवार को यहां जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर टीवी पर हो रही चुनावी बहस से खुद को अलग कर लिया। इस पर टीवी चैनल ने उनके स्थान पर कंजरवेटिव पार्टी के लोगो वाली बर्फ की कलाकृति रखकर बहस पूरी की। जॉनसन के अलावा ब्रेक्जिट पार्टी के नेता निगेल फराज ने भी इसमें हिस्सा नहीं लिया। उनके स्थान पर भी पार्टी के प्रतीक के साथ बर्फ की कलाकृति रखी गई। यूरोपीय संसद में जलवायु आपातकाल घोषित करने के मुद्दे पर हुए मतदान के कुछ घंटों बाद ही यह बहस आयोजित की गई थी। ब्रिटेन में 12 दिसंबर को आम चुनाव होने वाले हैं।

सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी ने ब्रिटेन के प्रसारण नियामक ऑफकॉम में शिकायत दर्ज कराई है कि पार्टी ने प्रधानमंत्री जॉनसन के स्थान पर एक अन्य नेता माइकल गोव को चर्चा में शामिल करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन चैनल 4 ने यह प्रस्ताव खारिज कर दिया। पार्टी ने आरोप लगाया है कि चैनल का फैसला बताता है कि वह कंजरवेटिव पार्टी को टीवी बहस में प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहता। इस बहस में विपक्षी लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन, लिबरल डेमोक्रेट जो स्विनसन और अन्य पार्टियों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। इसमें उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनी पार्टी की योजनाओं को जनता के सामने रखा।

नेताओं के स्थान पर बर्फ की कलाकृति रखने के बारे में चैनल 4 ने कहा कि यह धरती के आपातकाल का प्रतिनिधित्व करता है। जॉनसन की पूर्ववर्ती टेरीजा मे ने भी 2017 के चुनाव से पहले टीवी की किसी बहस में हिस्सा नहीं लिया था।

चुनाव अभियान के दौरान एक कॉलेज में सभा को संबोधित करने पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। रायटर

बीमार नवाज शरीफ ने लंदन में कराया पीईटी और सीटी स्कैन

लंदन, प्रेट्र : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की ब्रिटेन के एक अस्पताल में पीईटी (पॉजिट्रोन एमिशन टोमोग्राफी) और सीटी स्कैन समेत कई जांच की गई हैं। ये जांचें उनके प्लेटलेट्स कम होने के कारणों का ठीक-ठीक पता लगाने के लिए की गई हैं। बता दें कि लाहौर हाई कोर्ट से चार हफ्ते के लिए विदेश जाने की अनुमति मिलने के बाद 69 वर्षीय शरीफ को गत 19 नवंबर को एयर एंबुलेंस से लंदन लाया गया था। जहां उनकी तबीयत में स्थिर बनी हुई है।

शरीफ के निजी डॉक्टर अदनान खान ने एक ट्वीट में कहा, 'पूर्व प्रधानमंत्री का लंदन ब्रिज अस्पताल में पीईटी/सीटी एफडीजी स्कैन कराया गया है।' उन्होंने बताया कि यह गंभीर थ्रोंबोसाइटोपेनिया का पता लगाने के लिए की जाने वाली प्रमुख जांचों में से एक है। थ्रोंबोसाइटोपेनिया ऐसी स्थिति है, जिसमें खून में प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। प्लेटलेट्स रंगहीन रक्त कोशिकाएं होती हैं जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करती हैं। पीईटी स्कैन से डॉक्टरों को शरीर के त्रि-आयामी स्कैन के जरिये बीमारियों का पता करने में मदद मिलती है।

पाकिस्तान सरकार से गुलाम कश्मीर में हिंसा रोकने की मांग

- यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी की ओर से आयोजित सम्मेलन में पारित किया गया प्रस्ताव

इस्लामाबाद, एएनआइ : गुलाम कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान सरकार की करतूत के खिलाफ मुल्क के भीतर से ही आवाज उठने लगी है। राजधानी इस्लामाबाद में हुए एक सम्मेलन में सियासी कार्यकर्ताओं ने सरकार से गुलाम कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान में कट्टरपंथ, हिंसा और असहिष्णुता को बढ़ावा दिए जाने पर रोक लगाने की अपील की है।

यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी (यूकेपीएनपी) की ओर से गुरुवार को आयोजित सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें कहा गया है, 'यह सम्मेलन पाकिस्तान की सरकार से उन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने का आग्रह करता है, जो गुलाम कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान में कट्टरपंथ, हिंसा और असहिष्णुता को बढ़ावा देती हैं। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय असहिष्णुता और घृणा का शिकार ना होने पाएं। हम पाकिस्तानी अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि वे कानून का सम्मान करें और गिलगिट बाल्टिस्तान में गैर कश्मीरियों को बसाना बंद कर दें।'

इमरान खान। फाइल

कब्जे वाले इलाके से दूर रहे सरकार : इस प्रस्ताव में पाकिस्तान सरकार से यह आग्रह भी किया गया है कि वह हड़पे हुए गिलगिट बाल्टिस्तान और गुलाम कश्मीर से दूर रहे क्योंकि इससे हालात बिगड़ सकते हैं। सरकार से इन क्षेत्रों को पूरी आजादी देने की मांग की गई है जिससे वहां के निर्वाचित सदस्यों को स्थानीय लोगों की सामाजिक, आर्थिक और सियासी समस्याओं का समाधान करने में मदद मिल सकेगी।

पाक सुप्रीम कोर्ट के जजों को बताया जा रहा सीआइए का एजेंट

- चीफ जस्टिस खोसा बोले-बाजवा मामले में सोशल मीडिया में जजों के खिलाफ हो रहा दुष्प्रचार
- सेवा विस्तार मामले में पाक मीडिया ने सरकार की निंदा की

इस्लामाबाद, आइएएनएस : पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के सेवा विस्तार की सुनवाई के दौरान पाक के मुख्य न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा का कहना है कि सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार के जरिये जजों की छवि को धूमिल किया जा रहा है। उन्हें सीआइए और भारत की विदेशी खुफिया एजेंसियों का एजेंट करार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सेवा विस्तार पर फैसला सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों को सीआइए एजेंट करार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जजों को निशाना बनाने में लोग इस हद तक आगे बढ़ गए कि जजों पर भारत के लिए भी काम करने का आरोप लगाया गया।

पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जब सुनवाई के दौरान जस्टिस खोसा ने इस दुष्प्रचार के बारे में पूछा तो कहा गया कि यह पांचवीं पीढ़ी का युद्ध है। जब पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश खोसा ने पूछा कि पांचवीं पीढ़ी का युद्ध क्या है, तो जवाब में पाकिस्तान के अटर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी का नियंत्रण नहीं है। हमारे आपसी विवाद से बहुत हद तक भारत को फायदा हुआ है। क्या हमें सवाल करने का अधिकार नहीं है।

जबकि पाकिस्तान के प्रमुख अखबारों ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख के सेवा विस्तार से संबंधित संवेदनशील मामले से 'मूर्खतापूर्ण' तरीके निपटने के लिए इमरान खान सरकार की निंदा की और कहा कि लोगों का उनके शासन पर भरोसा 'सबसे अधिक घटा' है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने जनरल कमर जावेद बाजवा को अगले छह महीने के लिए सेना प्रमुख के तौर पर बने रहने की अनुमति दे दी। बाजवा फिलहाल छुट्टी पर हैं। अदालत ने देश की सेना के बारे में सरकार से सख्त सवाल किए।

'डॉन' अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा कि तीन दिन चले जबरदस्त नाटक के बाद शासन व्यवस्था को यह हल मिला और संभावित गतिरोध टल गया। 'द न्यूज इंटरनेशनल' ने अपने संपादकीय में लिखा, 'यह सरकार की सरासर नाकामी है और उसने जो गलती की है, जैसे मूल अधिसूचना पर इतनी जल्दबाजी में कार्रवाई करना और सेना अधिनियम के प्रावधानों या सैन्य नियमों से अनजान प्रतीत होना, यह सब भरोसा जीतने में मदद नहीं करेगा।' 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' ने अपने संपादकीय में लिखा, 'खुशकिस्मती से हम संकट से बाहर हैं, कम से कम फिलहाल तो।' बता दें कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने जनरल कमर जावेद बाजवा के कार्यकाल को छह माह के विस्तार को मंजूरी दी थी।

कमर जावेद बाजवा। फाइल

इस्तीफा देने वाला मंत्री फिर इमरान कैबिनेट में

इस्लामाबाद, प्रेट्र : दो दिन पहले कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले फरोग नसीम को शुक्रवार को दोबारा इमरान खान मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने नसीम को शपथ दिलाई। सेना अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा को सेवा विस्तार देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने के लिए उन्होंने दो दिन पहले कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।

नसीम को मिले नए विभाग के बारे में विरोधाभासी खबरें हैं। डॉन न्यूज के मुताबिक उन्हें मिले मंत्रालय की अभी तक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन एक्सप्रेस ट्रिब्यून और जियो न्यूज ने कहा कि उन्हें दोबारा कानून मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने गत 19 अगस्त को अधिसूचना जारी कर बाजवा का कार्यकाल बढ़ा दिया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं में अनियमितताओं का हवाला देते हुए उस पर मंगलवार को रोक लगा दी थी। नसीम ने उसी दिन कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देकर इस हाईप्रोफाइल मामले में सरकार का प्रतिनिधित्व करने का निर्णय लिया था। प्रधानमंत्री के विशेष सहायक शहजाद अकबर के अनुसार, नसीम ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया था क्योंकि कानून मंत्री रहते हुए वह मुकदमा नहीं लड़ सकते थे।

जलवायु परिवर्तन को लेकर प्रदर्शन...

जलवायु परिवर्तन को लेकर वैश्विक अभियान 'फ्राइडे फॉर फ्यूचर' के अंतर्गत लोगों ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन में स्प्री नदी में उतरकर अनूठा प्रदर्शन किया। लोगों की मांग थी कि जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए सरकार ठोस उपाय करे। स्वीडन की जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग की पहल पर विश्वव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। रायटर

हांगकांग में पुलिस ने विश्वविद्यालयों की 12 दिन से चल रही घेराबंदी खत्म की

- लोकतंत्र समर्थकों ने नए सिरे से रैलियों और हड़ताल का आह्वान किया
- स्वायत्त प्रांत में फिर हिंसा भड़कने की आशंका, प्रशासन हुआ सतर्क

हांगकांग, एजेंसियां : हांगकांग पुलिस ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय की घेराबंदी खत्म कर दी। विवि के भीतर मौजूद सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने के लिए बीते 12 दिन से पुलिस ने परिसर को घेर रखा था। लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि आने वाले दिनों में वे नए सिरे से रैलियां निकालेंगे और हड़ताल करेंगे। पिछले हफ्ते स्थानीय चुनाव में लोकतंत्र समर्थक दलों को मिली भारी जीत के बावजूद हांगकांग की नेता कैरी लैम और बीजिंग ने और अधिक राजनीतिक रियायत देने से इन्कार कर दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरने का नए सिरे से एलान किया है।

पुलिस ने परिसर में छिपाकर रखे गए गैसोलिन के करीब 4,000 बम वहां से हटाए। प्रदर्शनकारी ये बम छोड़ गए थे। प्रदर्शनकारियों की परिसर और नजदीक की सड़कों पर लगभग दो हफ्ते पहले दंगा अधिकारियों के साथ झड़प हुई थी। विवादास्पद विधेयक के विरोध में बीते छह महीने में हांगकांग पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में गतिरोध सबसे अधिक नाटकीय घटनाक्रम था। गुरुवार को करीब 100 अधिकारी पॉलिटेक्निक परिसर में सुबूतों को एकत्र करने और खतरनाक चीजों को हटाने के लिए दाखिल हुए थे। पुलिस ने दो दिन में 3,989 गैसोलिन बम, 1,339 विस्फोटक वस्तुएं, 601 बोतल हानिकारक तरल पदार्थ और 573 हथियार बरामद किए। कोई प्रदर्शनकारी नहीं मिला। पुलिस के आने से पहले तक गिरफ्तारी से बचने के लिए लगभग 20 लोग वहां छिपे हुए थे। विवि के एक अधिकारी ने कहा कि परिसर को जो नुकसान पहुंचा है उसकी मरम्मत के लिए पांच से छह महीनों का वक्त लगेगा।

शुक्रवार को एक बार फिर सैकड़ों ने लोगों ने लोकतंत्र समर्थक नारे लगाते हुए पूरे हांगकांग में रैलियां निकालीं। हालांकि पुलिस की चेतावनी के बाद प्रदर्शनकारी तितर-बितर हो गए। कुछ रैलियों में लोग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पोस्टर लिए थे। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा हांगकांग बिल पर हस्ताक्षर करने के बाद गुरुवार रात को रैली का आयोजन किया गया था। इसमें प्रदर्शनकारियों ने अन्य देशों से भी अमेरिका की तरह समर्थन में आने को कहा था।

बीते दिनों पुलिस ने हांगकांग पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में घुसकर प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया था। एपी

सिंगापुर ने एफबी को दिया सरकार विरोधी पोस्ट ठीक करने का आदेश

सिंगापुर, एएफपी : सिंगापुर सरकार ने शुक्रवार को एक न्यूज साइट पर लिखे लेख को ठीक करने का फेसबुक को आदेश दिया। इस लेख में सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में चुनाव धांधली करने का आरोप लगाया गया है। फेक न्यूज के खिलाफ बने कानून पर चिंता व्यक्त करने वाली दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी ने सरकार के इस अनुरोध पर कोई टिप्पणी नहीं की है और बिना किसी बदलाव के लेख अब भी साइट पर है।

सिंगापुर सरकार ने गुरुवार को सरकार विरोधी वेबसाइट चलाने वाले द स्टेट्स टाइम्स रिव्यू के कर्ताधर्ता एलेक्स टैन से चुनावों पर 23 नवंबर के बाद की गई पोस्ट को ठीक करने का आदेश दिया था। लेकिन विदेश में रहने वाले टैन ने इसे मानने से इन्कार करते हुए कहा था कि वह आस्ट्रेलियाई नागरिक हैं और विदेशी सरकार का आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। इसके बाद कानून के तहत फेक न्यूज पर नजर रखने के लिए गठित समिति ने कहा कि अब उसने फेसबुक को लेख में सुधार के आदेश दिए हैं। यह कानून मंत्रियों को यह अधिकार देता है कि वह फेक न्यूज पर सोशल मीडिया साइट को चेतावनी जारी करने के साथ ही किसी विशेष परिस्थिति में पोस्ट या उसमें शामिल तथ्यों को हटाने का भी आदेश दे सकते हैं।

उत्तर कोरिया ने हासिल की तेजी से रॉकेट दागने की क्षमता, परीक्षण से किम संतुष्ट

सियोल, रायटर : परमाणु मसले पर अमेरिका के साथ वार्ता में आए गतिरोध के बीच उत्तर कोरिया ने तेजी से रॉकेट दागने की क्षमता हासिल कर ली है। उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने तेजी से रॉकेट दागने में सक्षम एक बड़े मल्टीपल रॉकेट लांचर के परीक्षण पर संतुष्टि जताई है। किम की निगरानी में इस रॉकेट लांचर का गुरुवार को परीक्षण किया गया था।

दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टॉफ (जेसीएस) ने बताया कि उत्तर कोरिया की ओर से गुरुवार को कम दूरी के दो रॉकेट समुद्र में दागे गए थे। उसके नए सुपर-लार्ज मल्टीपल रॉकेट लांचर का यह चौथा परीक्षण था। विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर कोरिया ने गत अगस्त में केएन-25 रॉकेट लांचर से पर्दा उठाने के बाद कई परीक्षण किए हैं। इससे यह जाहिर होता है कि वह अपने मोबाइल लांच व्हीकल के जरिये तेजी से मल्टीपल रॉकेट दागने में सक्षम हो रहा है। यह क्षमता हासिल होने से उत्तर कोरिया अपने पड़ोसी दक्षिण कोरिया या अमेरिका की ओर से होने वाले किसी हमले की स्थिति में तेजी से जवाबी कार्रवाई कर सकेगा।

30 सेंकेंड में दो रॉकेट दागने में सक्षम : जेसीएस के अनुसार, सुपर-लार्ज मल्टीपल रॉकेट लांचर का गत अगस्त से परीक्षण चल रहा है। उस समय यह 19 मिनट में दो मिसाइलें दाग पाता था। लेकिन अब इसी काम को महज 30 सेकेंड के अंदर अंजाम देने की क्षमता हासिल हो गई है। उत्तर कोरिया ने अपने ताजा परीक्षण के जरिये अमेरिका को यह याद दिलाया है कि वह परमाणु वार्ता में आए गतिरोध को दूर करने के लिए लचीलापन दिखाए।

उत्तर कोरिया ने सुपर-लार्ज मल्टीपल रॉकेट लांचर का चौथा परीक्षण किया। एपी

सिंगापुर और भारत की वायुसेना ने किया संयुक्त अभ्यास

सिंगापुर, प्रेट्र : भारत के साथ संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण के दौरान सिंगापुर की वायुसेना ने भारतीय वायु सेना के छह सुखोई लड़ाकू विमानों के साथ अपने छह अत्याधुनिक एफ-16 लड़ाकू विमानों को तैनात किया है।

भारतीय वायु सेना और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर एयर फोर्स (आरएसएएफ) के सैनिक बंगाल के कलाईकुंडा वायु सैनिक अड्डे पर 31 अक्टूबर से 12 दिसंबर तक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण (जेएमटी) में हिस्सा ले रहे हैं। सिंगापुर के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जेएमटी के 10वें संस्करण के मौके पर अभ्यास का दायरा बढ़ाते हुए इसमें पहली बार भारतीय नौसेना के साथ वायु-समुद्र प्रशिक्षण को भी जोड़ा गया है। एक बयान में कहा गया है कि आरएसएएफ ने भारतीय वायुसेना के छह एसयू-30एमकेआई लड़ाकू विमानों के साथ प्रशिक्षण के लिए अपने छह एफ- 16सी/डी लड़ाकू विमानों को तैनात किया है। जेएमटी दोनों वायु सेनाओं के सदस्यों को अपने संचालन कौशल और प्रशिक्षण को बढ़ाने का मौका देता है।

राष्ट्रपति चुनाव में कथित धांधली के खिलाफ काबुल में प्रदर्शन, जमकर हुई नारेबाजी

काबुल, आइएएनएस : अफगानिस्तान में राष्ट्रपति उम्मीदवार अब्दुल्ला अब्दुल्ला के हजारों समर्थकों ने शुक्रवार को राजधानी काबुल में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति अशरफ गनी और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यह प्रदर्शन दो महीने पहले हुए चुनाव के प्रारंभिक नतीजे घोषित करने में हो रही देरी और राष्ट्रपति के पक्ष में की गई कथित चुनावी धांधली के विरोध में किया गया था।

राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ गठबंधन सरकार में शामिल अब्दुल्ला अब्दुल्ला की चुनावी टीम के प्रवक्ता ने कहा, हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग नियमों के मुताबिक काम करे और अपने अवैध फैसलों को वापस ले। हमारी प्रमुख आपत्ति तीन लाख अवैध मतों की गिनती के खिलाफ है। इसे अमान्य किया जाना चाहिए। 28 सितंबर को हुए चुनाव का परिणाम 19 अक्टूबर को घोषित किया जाना था। लेकिन तकनीकी दिक्कतों का हवाला देते हुए इसे 14 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। चुनाव आयोग के अनुसार 27 लाख वोटों में से करीब 19 लाख वोट बायोमीट्रिक रूप से सत्यापित थे। इन सत्यापित मतों में से 86 हजार को इसलिए रद कर दिया गया क्योंकि आयोग द्वारा निर्धारित कसौटी पर यह खरे नहीं उतरे थे। अब्दुल्ला के समर्थकों ने वोटों की दोबारा गिनती का बहिष्कार किया है। उन्होंने 34 में से सात प्रांतों में चुनाव अधिकारियों को इस प्रक्रिया को पूरा करने से रोक दिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से यह तय किया जाना था कि दावेदारों में से किसे पहले दौर में बहुमत मिला है।

काबुल में शुक्रवार को अब्दुल्ला अब्दुल्ला के समर्थकों ने प्रदर्शन किया। एपी

मैनचेस्टर सिटी के साथ मुंबई सिटी एफसी की साझेदारी युवाओं के लिए अच्छा मौका है।
– अमरिंदर सिंह, भारतीय गोलकीपर

स्टोक्स, एशर-स्मिथ को मिला एसजेए अवॉर्ड

लंदन, आइएएनएस : विश्व कप जीतने वाली इंग्लिश क्रिकेट टीम के हीरो बेन स्टोक्स और वर्ल्ड चैंपियन स्प्रिंटर दिना एशर-स्मिथ को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन (एसजेए) ब्रिटिश स्पोर्ट्स अवार्डर्स में क्रमश: स्पोर्ट्समैन एवं स्पोर्ट्सवूमेन ऑफ द इअर पुरस्कार से नवाजा गया। इस साल दोहा में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तीन स्वर्ण जीतकर इतिहास रचने वाली एशर को लगातार दूसरी बार यह पुरस्कार मिला है।

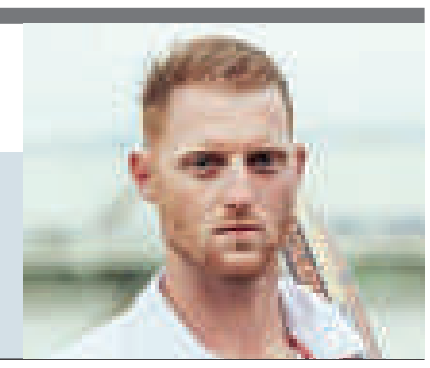

डेविस कप में भारत का पाकिस्तान के खिलाफ शानदार आगाज

रामकुमार और सुमित नागल ने आसान जीत के साथ भारत को दिलाई 2-0 की बढ़त

नूर सुल्तान, प्रेट्र: तमाम खींच-तान और आयोजन स्थलों के विवादों को पीछे छोड़ते शुक्रवार से पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हुए डेविस कप के पहले ही दिन भारतीय टेनिस खिलाड़ियों ने अपनी धमक दिखाई। आलम ये रहा कि पहले दिन रामकुमार रामनाथन और सुमित नागल ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कही टिकने नहीं दिया और भारत को 2-0 से बढ़त दिलाई।

महज दो गेम जीत पाया पाक: दोनों सिंगल्स मुकाबले एकतरफा रहे। दोनों भारतीय सितारों ने पाकिस्तान को केवल दो गेम जीतने दिए। रामकुमार ने पहले मैच में 17 वर्षीय मुहम्मद शोएब को महज 42 मिनट तक चले मुकाबले में 6-0, 6-0 से शिकस्त दी। शोएब केवल दूसरे सेट के छठे गेम में थोड़ी चुनौती पेश कर पाए। वह बहुत मुश्किल से रामकुमार को दो ड्यूस अंकों तक खींचा। इसके बाद नागल ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए डेविस कप में अपनी पहली जीत दर्ज की। उन्होंने दूसरे सिंगल्स में हुफैजा मुहम्मद रहमान को 64 मिनट तक चले आसान मुकाबले में 6-0, 6-2 से हराकर भारत को 2-0 की बढ़त दिलाई।

पाक को खली सीनियर खिलाड़ियों की कमी: इस दौरान पाकिस्तान को अपने शीर्ष खिलाड़ियों की कमी खली जो इस मुकाबले को तटस्थ स्थान आयोजित कराए जाने के फैसले के विरोध में हट गए थे। पहले मैच में जहां पाकिस्तान ने पूरी तरह से घुटने टेक दिए तो वहीं दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान के युवा खिलाड़ी हुफैजा ने नागल का जितना संभव हो सका लंबी रैलियों में उलझाने की कोशिश की। दूसरे सेट के दूसरे गेम में दो बार उन्होंने नागल को ड्यूस अंकों तक खींचा और तीसरो गेम जीतकर पहली बार पाकिस्तान के नाम पर एक गेम लिखा। हालांकि नागल को जीत के लिए ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा और उन्होंने आठवें गेम में मैच अपने नाम किया।

अब पेस की बारी: अनुभवी लिएंडर पेस और जीवन नेदुचेझियन अब शनिवार को डबल्स मुकाबले में हुफैजा और शोएब से भिड़ेंगे जहां भारत की निगाहें इस मुकाबले वहीं खत्म करने पर होंगी। भारत अभी तक पाकिस्तान से छह मुकाबलों में कभी हारा नहीं है और इसके कायम रहने की पूरी संभावना है। शनिवार को जीत से पेस डेविस कप इतिहास में सर्वाधिक डबल्स मैच जीतने के अपने विश्व रिकॉर्ड को आगे बढ़ाएंगे। वह अभी 43 जीत के साथ शीर्ष पर हैं। इस मुकाबले का विजेता विश्व कप क्वालीफायर्स में क्रोएशिया से भिड़ेगा जो कि अगले साल छह और सात मार्च को खेला जाएगा।

डेविस कप के पहले दिन पाकिस्तान पर 2-0 की बढ़त हासिल करने के बाद उत्साहित भारतीय टेनिस टीम • ट्विटर

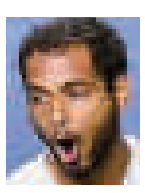

हर अंक पर मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। हम पहले दिन 2-0 की बढ़त हासिल करके खुश हैं। अब उम्मीद है कि शनिवार को जीवन और लिएंडर पेस पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बमबारी करेंगे और भारत की आसान जीत सुनिश्चित करेंगे।
रामकुमार रामनाथन, भारतीय टेनिस खिलाड़ी

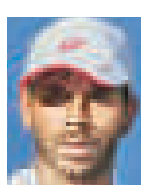

मैंने अच्छी शुरुआत की और मजबूती के साथ इसे समाप्त किया। मैं और राम हारना नहीं चाहते थे। हमारे विरोधी हमसे जूनियर थे लेकिन उन्होंने अच्छा खेल दिखाया और जो कर सकते थे, उन्होंने किए। शनिवार को भी यही स्कोर लाइन रहने की उम्मीद है।
सुमित नागल, भारतीय टेनिस खिलाड़ी

यह भारत के लिए शानदार दिन था। राम ने हमें अच्छी शुरुआत दिलाई। उन्होंने बेहद कम समय में मुकाबले को अपने नाम किया। दूसरा मुकाबला आसान दिख रहा था लेकिन वह थोड़ा मुश्किल था।
रोहित राजपाल, भारत के गैर खिलाड़ी कप्तान

पाक के खिलाफ बनाए एक विकेट पर 302 रन, डेविड-मार्नस के बीच 294 रन की साझेदारी

डे-नाइट टेस्ट में वार्नर-लाबुशाने के शतक

एडिलेड, एएफपी: डेविड वार्नर और मार्नस लाबुशाने के शतकों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने यहां पाकिस्तान के खिलाफ डे-नाइट टेस्ट के पहले दिन शुक्रवार को अपना दबदबा कायम किया। ये दोनों दूसरे विकेट के लिए 294 रन की अटूट साझेदारी निभा चुके हैं। उनकी इस साझेदारी के चलते बारिश की वजह से जब दिन का खेल रोका गया तो ऑस्ट्रेलिया ने एक विकेट पर 302 रन बना लिए थे। वार्नर 228 गेंदों पर 19 चौकों की मदद से 166 रन और लाबुशाने 205 गेंदों पर 17 चौकों की मदद से 126 रन बनाकर नाबाद हैं।

वार्नर और लाबुशाने ने ब्रिसबेन में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट में क्रमशः 154 और 185 रन की पारियां खेली थीं। ऑस्ट्रेलिया में लगातार 13 टेस्ट हार चुकी पाकिस्तानी टीम को दो टेस्ट मैचों की इस सीरीज को बराबर करने के लिए इस टेस्ट को जीतना होगा, लेकिन उसके लिए यह बेहद मुश्किल चुनौती नजर आ रहा है।

साल दर साल पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया में विकेट लेना चुनौती बनता जा रहा है और गुलाबी गेंद से भी उसके गेंदबाजों को संघर्ष करना पड़ा। अनुभवी तेज गेंदबाज मुहम्मद अब्बास को 16 साल के तेज गेंदबाज नसीम शाह की जगह पाकिस्तानी टीम में शामिल किया गया। अब्बास ने पिछले महीने अक्टूबर में यूएई में दो टेस्ट में 17 विकेट झटके थे। साथ ही 19 साल के दायें हाथ के तेज गेंदबाज मुहम्मद मूसा को टेस्ट पदार्पण का मौका मिला। लेकिन, पहले टेस्ट की तरह ही कोई भी गेंदबाज वार्नर और लाबुशाने को मुश्किल में डालने में नाकाम रहा। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान के लिए उस समय एक उम्मीद की किरण नजर आई जब जो बर्न्स सिर्फ चार रन बनाकर चलते बने। बर्न्स का विकेट तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने झटका। इसके बाद वार्नर और लाबुशाने ने चायकाल तक स्कोर को एक विकेट पर 70 रन तक पहुंचाया। लगातार हो रही हल्की बारिश की वजह से खिलाड़ियों को निर्धारित समय से दो घंटे ज्यादा तक ड्रेसिंग रूम में रहने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन, जब वे दोबारा मैदान पर लौटे तो वार्नर ने जल्द ही अपना अर्धशतक पूरा किया। वार्नर ने अपनी फॉर्म को बरकरार रखा और लेग स्पिनर यासिर शाह पर एक रन के साथ अपना 23वां शतक पूरा किया। इस साल इंग्लैंड में एशेज सीरीज में 10 पारियों में सिर्फ 95 रन बनाने वाले पूर्व ऑस्ट्रेलियाई उप कप्तान वार्नर के लिए यह सीरीज बेहद शानदार साबित हुई है। दूसरी ओर, लाबुशाने ने मूसा पर चौका जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। दक्षिण अफ्रीका में जन्मे 25 साल के लाबुशाने ने एशेज के बाद एक बार फिर शानदार फॉर्म दिखाई और शाह की गेंद पर दो रन लेकर शतक पूरा किया।

लाथम के शतक से न्यूजीलैंड मजबूत

हैमिल्टन, एएफपी: टॉम लाथम के 11वें टेस्ट शतक (नाबाद 101) और रोस टेलर (53) के साथ उनकी शतकीय साझेदारी की बदौलत न्यूजीलैंड ने यहां इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन शुक्रवार को मजबूत शुरुआत की। हालांकि, दिन का खेल चायकाल के बाद सिर्फ तीन गेंद फेंके जाने के बाद ही बारिश की वजह से रोकना पड़ा। उस समय न्यूजीलैंड का स्कोर तीन विकेट पर 173 रन था। लाथम ने 164 गेंदों का सामना किया और 15 चौके जड़े।

बायें हाथ के बल्लेबाज लाथम का 66 रन के निजी स्कोर पर बेन स्टोक्स ने कैच गिराया। इंग्लैंड को उन्हें आउट करने का मौका गंवाने और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिल पाने का अफसोस था। टेलर को लाथम के साथ शतकीय साझेदारी के दौरान संदिग्ध निर्णय का फायदा मिला। टेलर को जीवनदान मिलना भी इंग्लैंड को महंगा पड़ा। स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद की गेंद उनके पैड में लगी और अंपायर ने आउट दे दिया। लाथम से बात करने के बाद टेलर ने रिव्यू लिया और अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा।

कीवी बल्लेबाज टॉम लाथम, एपी

पहले गेंदबाजी के अनुकूल विकेट को देखते हुए क्रिस वोक्स को इंग्लैंड की टीम में शामिल किया गया था, जिससे टीम पांच तेज गेंदबाजों के साथ उतर सके। वोक्स ने न्यूजीलैंड की पारी में गिरे तीन विकेटों में से दो हासिल किए। साथ ही इंग्लैंड बेन स्टोक्स को अपने गेंदबाजी हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सका। इतना ही नहीं, स्टोक्स को दो ओवर गेंदबाजी करने के बाद बायें घुटने में दर्द महसूस हुआ। अब रात को उनके घुटने का निरीक्षण करने के बाद ही तय हो सकेगा कि वह इस पारी में आगे गेंदबाजी कर पाएंगे या नहीं।

हालांकि, न्यूजीलैंड की शुरुआत खराब रही और जीत रावल (05) के बाद कप्तान केन विलियमसन (04) भी सस्ते में पवेलियन लौट गए। लेकिन, 39 रन पर दो विकेट गंवाने के बाद लाथम और टेलर ने तीसरे विकेट के लिए 116 रन जोड़े।

दूसरा टेस्ट
- कीवी टीम ने बनाए तीन विकेट पर 173 रन
- इंग्लैंड की ओर से वोक्स ने झटके दो विकेट

11 वां टेस्ट शतक जड़ा लाथम ने। टेस्ट में न्यूजीलैंड के लिए उनसे ज्यादा शतक सिर्फ ब्रेंडन मैकुलम (12), जॉन राइट (12), मार्टिन क्रो (17), रोस टेलर (18) और केन विलियमसन (20) ने जड़े हैं

05 शतक जड़ चुके हैं टॉम लाथम अब अपनी पिछली 10 टेस्ट पारियों में

23 वां शतक जड़ा डेविड वार्नर ने 81वें टेस्ट में। यह पाकिस्तान के खिलाफ उनका पांचवां टेस्ट शतक है

05 डे-नाइट टेस्ट मैचों में यह पहला मौका है जब वार्नर ने 50 रन का आंकड़ा छुआ

02 शतक जड़ चुके हैं अब मार्नस लाबुशाने 11 टेस्ट मैचों में। उनके दोनों शतक पाकिस्तान के खिलाफ बने हैं

294 रन की अटूट साझेदारी निभा चुके हैं वार्नर व लाबुशाने। यह डे-नाइट टेस्ट में किसी टीम व किसी विकेट की सबसे बड़ी साझेदारी है

अब पैर की नो बॉल पर रहेगी तीसरी नजर

तैयारी
- आइपीएल में नो बॉल जांचने के लिए इस्तेमाल होगा रन आउट कैमरा
- पिछले सत्र में अंपायरों ने छोड़ी थीं पैर की कई नो बॉल

नई दिल्ली, आइएएनएस: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) इस बात को लेकर काफी प्रयास कर रहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) के अगले सत्र में मैदानी अंपायरों को पैर की नो बॉल को पकड़ने में तकनीक की मदद मिले। यह प्रयास भारत और बांग्लादेश के बीच कोलकाता में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में लागू किया गया था, लेकिन बोर्ड इसे अब आगे भी जारी रखने के बारे में विचार कर रहा है।

बोर्ड रन आउट कैमरा का इस्तेमाल नो बॉल को पकड़ने के लिए भी कर रहा है ताकि अंपायर गेंदबाज की कमी को पकड़ सकें। आइपीएल के बीते संस्करण में इस बात को लेकर काफी बवाल हुआ था क्योंकि कई मैचों में अंपायर गेंदबाज के पैर की नो बॉल को पकड़ नहीं पाए थे। सिर्फ आइपीएल में ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिसबेन में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भी यह विवाद रहा था क्योंकि दूसरे दिन के दो सत्र में 21 नो बॉल पकड़ में नहीं आ सकी थीं। बीसीसीआइ के संयुक्त सचिव जयेश जॉर्ज ने कहा कि यह नए तरीकों को लागू करने की बात है और नए अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि तकनीक का पूरा इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने कहा कि हां, यह काम अभी प्रगति पर है। आइपीएल हमेशा प्रयोग के लिए रहा है। हमारी कोशिश है कि आइपीएल का हर सत्र नई तकनीक को लेकर आए और खेल को आगे ले जाने में मदद करे। अहम बात यह है कि जब तकनीक इस तरह के मुद्दे सुलझाने में मदद कर सकती है तो फिर खिलाड़ी क्यों भुगते?

संयुक्त सचिव ने कहा कि अतीत में हमने देखा है कि पैर की नो बॉल एक विवादित मुद्दा रहा है। मेरा यह मानना है कि तकनीक पैर की नो बॉल को पकड़ने के लिए उपयोग में ली जा सकती है। इसके लिए बड़े पैमाने पर जांच की जरूरत है और हम विंडीज सीरीज में भी यह जारी रखेंगे। उनसे जब पूछा गया कि क्या विंडीज सीरीज को लेकर जो डाटा मिलेगा क्या उस पर आइपीएल की गर्विनंग काउंसिल और बोर्ड के अधिकारी चर्चा करेंगे? इस पर जवाब मिला कि जब पूरा डाटा आएगा तो हम साथियों के साथ इस पर चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ने को लेकर विचार करेंगे। तीसरे अंपायर द्वारा जो कैमरे रन आउट की जांच करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं वही कैमरे नो बॉल की जांच के लिए उपयोग में लिए जाएंगे। यह कैमरा एक सेकंड में 300 फ्रेम को कैद करते हैं। इन कैमरा को ऑपरेटर अपनी इच्छा के मुताबिक जूम कर सकता है।

रोहित की ब्रांड वैल्यू में जबरदस्त उछाल

नई दिल्ली, प्रेट्र : लाजवाब फॉर्म में चल रहे सीमित ओवर क्रिकेट में भारतीय टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा के ब्रांड वैल्यू में जबरदस्त उछाल आया है। इस साल इंग्लैंड में खेले गए विश्व कप में हिटमैन रोहित ने रिकॉर्ड पांच शतक जड़े थे। इसके बाद उन्होंने टेस्ट में ओपनिंग करते हुए तीन शतक लगाए और कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। इस करिश्माई प्रदर्शन के बाद वह कारपोरेट जगत का चहेता बन गए हैं। 32 वर्षीय रोहित के मैनेजमेंट टीम के सूत्रों की माने तो ब्रांड रोहित खूब चमक रहा है।

रोहित शर्मा

श्रीकांत हारे, सौरभ सेमीफाइनल में

खेल संवाददाता, लखनऊ

▸ सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में हारे किदांबी, कोरिया के सोन वान हो ने दी शिकस्त

गैर वरीय सौरभ वर्मा और क्वालीफायर रितुपर्णा दास ने क्वार्टर फाइनल में शानदार जीत के साथ सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में मेजबानों की उम्मीद को कायम रखते हुए सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। हालांकि, भारत के स्टार शटलर और खिताब के प्रबल दावेदार किदांबी श्रीकांत के अभियान को कोरियाई खिलाड़ी सोन वान ने क्वार्टर फाइनल में हराकर खत्म कर दिया। दूसरी ओर, ओलंपिक चैंपियन कैरोलिना मारिन अपनी लय बरकरार रखते हुए अंतिम चार में जगह बनाने में कामयाब रहीं।

बीबीडी यूपी बैडमिंटन अकादमी में हो रही इस चैंपियनशिप में शुक्रवार को विश्व रैंकिंग में 36वें नंबर के भारतीय खिलाड़ी सौरभ वर्मा ने 40 मिनट चले क्वार्टर फाइनल में 41वें नंबर के थाई खिलाड़ी को 21-19, 21-16 से मात दी। सौरभ ने थाइलैंड के कुनवालत वितिदसर्न को अपने मजबूत डिफेंस और जोरदार स्मैश के सामने टिकने नहीं दिया। वहीं, युवा ऋतुपर्णा दास ने हमवतन श्रुति मुंडाडा को रोमांचक क्वार्टर फाइनल में 24-26, 21-10 और 21-19 से मात देकर महिला सिंगल्स के अंतिम चार में जगह सुनिश्चित की। रितुपर्णा अब सेमीफाइनल में थाइलैंड की फिटायापोर्ण चाइवान से भिड़ेंगी।

महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में कुहू गर्ग और अनुष्का पारिख की जोड़ी को हांगकांग की एनजी विंग युंग व येइंग एनजी तिंग ने 21-15, 21-9 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। जबकि इसी वर्ग के एक अन्य क्वार्टर फाइनल में सिमरन सिंघी और रितिका ठाकेर की भारतीय जोड़ी की चुनौती हार के साथ बाहर हो गई।

श्रीकांत पर भारी पड़े सोन वान: पुरुष सिंगल्स के हाईवोल्टेज क्वार्टर फाइनल में सातवीं वरीय कोरिया के सोन वान हो ने किदांबी श्रीकांत को चौंकाते हुए 21-18, 21-19 से हराकर अंतिम चार में जगह पक्की की। इस महत्वपूर्ण मुकाबले के पहले गेम में एक समय श्रीकांत और सोन वान 14-14 अंकों के साथ बराबरी पर थें, लेकिन इसके बाद वान ने लगातार तीन अंक जुटाकर श्रीकांत को बैकफुट पर कर दिया पहला गेम अपने नाम करते हुए भारतीय खिलाड़ी पर दबाव बना लिया।

कोलकाता में हो सकता है ईस्ट बंगाल-युनाइटेड मुकाबला

जागरण संवाददाता, कोलकाता

फुटबॉल डायरी

अगर सब कुछ योजनानुसार हुआ तो अगले साल कोलकाता में ईस्ट बंगाल और मैनचेस्टर युनाइटेड का मैच देखने को मिल सकता है। कोलकाता दौरे पर आए मैनचेस्टर युनाइटेड के चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के खेल मंत्री अरूप विश्वास से राज्य सचिवालय नवान्न में मुलाकात की। इसमें युनाइटेड के फुटबॉल निदेशक एलन जॉन डॉसन, क्रिस्टोफर लॉरेन्स कॉमन, क्लब के अधिकारी फिलिप मैल्कम स्मिथ और मैथ्यू चार्ल्स जोंस शामिल रहे।

वहीं इस दौरान प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने साल्टलेक स्टेडियम का दौरा किया, जहां मैदान, ड्रेसिंग रूम समेत अन्य सुरक्षात्मक व्यवस्था का निरीक्षण किया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक युनाइटेड प्रतिनिधिमंडल ने स्टेडियम में सुविधाओं पर संतोष व्यक्त करने के साथ ही कोलकाता के खेल संस्कृति की भी सराहना की। इतना ही नहीं उन्होंने स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था पर भी कोई आपत्ति नहीं की है। अगर होता है तो यह मैच ईस्ट बंगाल के शताब्दी समारोह का एक हिस्सा होगा और इसे युनाइटेड के प्री-सीजन एशिया टूर में भी शामिल किया जाएगा। साथ ही बताया गया कि जुलाई 2020 के अंतिम सप्ताह में इस मैच के होने की संभावना है।

नए साल से पहले नहीं खेल पाएंगे फैबिनो : लंदन : लिवरपूल के फैबिनो टखने की चोट की वजह से एक महीने से ज्यादा समय के लिए मैदान से बाहर रहेंगे। फैबिनो को चैंपियंस लीग में नापोली के खिलाफ चोट लगी थी।

रजत को मिली अध्यक्ष पद छोड़ने की अनुमति

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

हम अरुण जेटली के सपने को पूरा करेंगे। हम दिल्ली के क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे।
– दिनेश शर्मा, पूर्व संयुक्त सचिव, डीडीसीए

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के लोकपाल न्यायाधीश (सेवानिवृत) बदर दुर्रेज अहमद ने शुक्रवार को डीडीसीए अध्यक्ष पद से रजत शर्मा का इस्तीफा मंजूर कर लिया। इससे पहले लोकपाल ने उनके इस्तीफे को रोक दिया था। डीडीसीए 25 से 27 दिसंबर के बीच अपनी वार्षिक आम सभा (एजीएम) बुलाएगा और उसमें ही अध्यक्ष पद सहित अन्य पदों के लिए होने वाले चुनाव पर निर्णय लिया जाएगा। तब तक उपाध्यक्ष राकेश बंसल, अध्यक्ष पद का कार्य भी देखेंगे। वहीं सचिव विनोद तिहारा एक दिसंबर को मुंबई में होने वाली बीसीसीआइ की एजीएम में डीडीसीए के प्रतिनिधि होंगे।

शर्मा ने 16 नवंबर को खींचतान और दबाव का आरोप लगाते हुए डीडीसीए से इस्तीफा दिया था। इसके एक दिन बाद 17 नवंबर को अहमद ने उनके इस्तीफे को रोक दिया थ, लेकिन रजत के दोबारा इस्तीफा देने के बाद लोकपाल ने उसे मंजूर कर लिया है। शर्मा ने कहा कि मैंने लोकपाल को शुक्रवार सुबह लिखा और कहा कि वह मुझे सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दें। उन्होंने अपने पत्र में अहमद को लिखा कि वह एक राज्य की अस्त-व्यस्त संगठन को आगे नही चला सकते हैं। इस पत्र में उन्होंने लिखा कि मैंने 16 नवंबर को भी इस्तीफा दिया था। हालांकि लोकपाल के आदेश के बाद मैं अपने पद पर बना रहा। हालांकि डीडीसीए में स्थिति पूरी तरह से अस्त-व्यस्त है। ऐसे में मैं अपने पद पर बने नहीं रह सकता हूं।

शर्मा का 20 माह का कार्यकाल काफी मुश्किलों भरा रहा था। इस बीच उनके संयुक्त सचिव विनोद तिहारा के साथ खराब संबंध भी जगजाहिर रहे थे। तिहारा, शर्मा ग्रुप से ही डीडीसीए चुनाव जीते थे, लेकिन एक ही सप्ताह के भीतर उनके संबंध शर्मा के साथ खराब हो गए। शर्मा ने आरोप लगाया था कि तिहारा डीडीसीए में नियुक्तियों पर नियंत्रण कर रहे हैं।

इसके बाद तिहारा को एक्जीक्यूटिव कमेटी ने बर्खास्त कर दिया था। तिहारा ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। शर्मा ने अहमद को लिखा कि मैं उन लोगों के साथ काम नहीं कर सकता हूं जो लोकपाल या हाई कोर्ट का सम्मान नहीं करते हैं। शर्मा के 16 नवंबर को इस्तीफा देने के बाद सीईओ रवि चोपड़ा ने भी इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा क्रिकेट सलाहकार समिति के दो सदस्य सुनील वाल्सन और यशपाल शर्मा ने भी इस्तीफा दे दिया था। एक दिन बाद अहमद ने आदेश दिया था कि शर्मा को अपने पद पर बने रहना होगा और साथ ही उन्होंने तिहारा की बहाली भी रोक दी थी। अहमद ने कहा कि यह साफ है कि रजत ने डीडीसीए अध्यक्ष पद पर नहीं बने रहने की इच्छा जताई है।

भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज टीम से रसेल और ब्रावो आउट

भारतीय दौरा
- वेस्टइंडीज बोर्ड ने भारत दौरे के लिए घोषित की वनडे और टी-20 टीम
- पोलार्ड संभालेंगे कमान, छह दिसंबर को पहला टी-20 मुकाबला

एंटीगुआ, प्रेट्र : भारत दौरे के लिए वेस्टइंडीज बोर्ड ने शुक्रवार को वनडे और टी-20 टीम की घोषणा की। उनकी टीम में आंद्रे रसेल और ड्वेन ब्रावो जैसे बड़े नाम शामिल नहीं हैं। हालांकि कप्तान के तौर पर कीरोन पोलार्ड को बरकरार रखा गया है। भारत दौरे पर विंडीज टीम को तीन वनडे और तीन टी-20 मैच की सीरीज खेलनी है।

24 वर्षीय युवा विकेटकीपर बल्लेबाज निकोलस पूरन टी-20 टीम के उप कप्तान होंगे, जबकि शाई होप वनडे में उप कप्तान की भूमिका निभाएंगे। अबू धाबी में जारी टी-10 लीग में छह मैच खेलने वाले दिग्गज ऑलराउंडर रसेल फिट होने के बावजूद टीम में जगह नहीं बना सके हैं। दूसरी ओर हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करने वाले पूर्व कप्तान ब्रावो को भी टीम में जगह नहीं दी गई है। विंडीज के दिग्गज ओपनिंग बल्लेबाज क्रिस गेल को भी टीम में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि उन्होंने ब्रेक लेने की बात कहते हुए अपना नाम वापस ले लिया था। बता दें कि हाल में विंडीज टीम ने भारत में खेली गई अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में तो जीत दर्ज की थी, लेकिन टी-20 में उसे हार का सामना करना पड़ा था।

चयनकर्ताओं ने उन खिलाड़ियों पर भरोसा दिखाया जो लखनऊ में खेले थे। बायें हाथ के स्पिन ऑलराउंडर फाबियन एलेन घुटने की चोट से उबरने के बाद टीम में जगह बनाने में सफल रहे। वह इस महीने में अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में नहीं खेल सके थे। दिनेश रामदीन हैमस्ट्रिंग के कारण सीरीज के कुछ हिस्से में नहीं खेल पाए थे। उन्होंने फिटनेस हासिल कर टीम में जगह बना ली। मौजूदा आइसीसी विश्व टी-20 चैंपियन वेस्टइंडीज तीन मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज से दौरे की शुरुआत करेगी जो छह दिसंबर से हैदराबाद में शुरू होगी। इसके बाद दूसरा टी-20 आठ दिसंबर को तिरुवनंतपुरम में जबकि तीसरा मैच मुंबई में 11 दिसंबर को खेला जाएगा। दोनों टीमें फिर तीन वनडे खेलेंगी, जो 15 दिसंबर को चेन्नई में, 18 दिसंबर को विशाखापत्तनम में और 22 दिसंबर को कटक में खेला जाएगा। कोच फिल सिमंस ने कहा कि हमें प्रत्येक प्रारूप में तीन मैच खेलने हैं इसलिए हम प्रत्येक टीम को भारत के खिलाफ खेलने का मौका देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान का निरादर नहीं करना चाहते, लेकिन भारत का सामना करना सबसे ज्यादा मुश्किल है, विशेषकर वनडे में।

वनडे टीम : कीरोन पोलार्ड (कप्तान), सुनील अंब्रीश, शाई होप, खारी पियरे, रोस्टन चेज, अल्जारी जोसेफ, शेल्डन कॉटरेल, ब्रैंडन किंग, निकोलस पूरन, शिमरोन हेटमायर, एविन लुइस, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, कीमो पॉल, हेडन वॉल्श जूनियर।

टी-20 टीम : कीरोन पोलार्ड (कप्तान), फाबियन एलेन, ब्रैंडन किंग, दिनेश रामदीन, शेल्डन कॉटरेल, एविन लुईस, शेरफेन रदरफोर्ड, शिमरोन हेटमायर, खारी पियरे, लेंडिल सिमंस, जेसन होल्डर, हेडन वॉल्श जूनियर, कीमो पॉल, निकोलस पूरन, केसरिक विलियम्स।

आंद्रे रसेल। फाइल फोटो, एपी

अधिक पदकों के लिए नए तरीकों व ऊर्जा से काम करना होगा रिजिजू

साक्षात्कार

2016 रियो ओलंपिक में जब भारत को सिर्फ दो पदक मिले थे तो उसके बाद से देश में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने पूरे देश में एक अभियान सा चलाया था। इसके बाद उम्मीद जगी थी कि भारत 2020 टोक्यो ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन करने में सफल होंगे। अब यह तो वक्त ही बताएगा कि हमें टोक्यो में कितनी सफलता मिलती है, लेकिन मौजूदा केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू का मानना है कि पदकों की संख्या बढ़ाने के लिए नए तरीकों व ऊर्जा के साथ काम रना होगा। **किरन रिजिजू** से **यशपाल वर्मा** ने खास बातचीत की। पेश हैं प्रमुख अंश :-

● भारतीय खेलों के लिए आपका विजन क्या है?

-भविष्य की योजनाओं में खेल अहम हिस्सा है। ओलंपिक में मिलने वाले पदकों की गिनती संतोषजनक नहीं है और इसके लिए नए तरीकों व ऊर्जा के साथ काम करना होगा। नई सोच के साथ खिलाड़ियों को स्कूल स्तर पर सुविधाएं देने का प्रयास है, जिससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा व आर्थिक मदद मिलेगी।

● पिछली योजनाओं से खेलो इंडिया कैसे अलग है?

-हिंदुस्तान में स्कूल व यूनिवर्सिटी गेम्स अलग-अलग होते हैं। इस खेलों को देश में चार भागों में बांटा गया है और प्रत्येक खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। वर्ष 2020 में 21 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के खिलाड़ियों के लिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ओडिशा में आयोजित करवाए जाएंगे। इसके अलावा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स गुवाहटी में 10 जनवरी 2020 को होंगे। इस संबंध में दो दिन बाद खेलों का लोगो जारी करने जा रहे हैं। साथ ही, खेलो इंडिया अंडर-17 स्कूल गेम्स और भारत के पारम्परिक खेलों के मुकाबले करवाए जाएंगे।

● फिट इंडिया के तहत मंत्रालय क्या कदम उठा रहा है?

-प्रत्येक नागरिक को फिट इंडिया अभियान के साथ जुड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 29 अगस्त को खेल दिवस के दिन फिट इंडिया की शुरुआत की गई। भारत के फिट स्कूल, संस्थाएं, शहर, गांव को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। पंचायत मंत्रालय से बात करके प्रत्येक गांव-गांव में खेल व फिटनेस के लिए मुहिम चलाई जाएगी।

● ओलंपिक को लेकर भारत की कितनी तैयारी है?

-अभी हमारे खिलाड़ी टोक्यो-2020 की तैयार कर रहे हैं और 2024 व 2028 ओलंपिक के लिए हमने देश के लिए अधिक से अधिक पदक जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए स्कूली स्तर पर बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित करना होगा। विदेशों में बच्चों को स्कूल स्तर के खेलों के लिए प्रेरित किया जाता है तभी भविष्य में खेलों में बेहतर परिणाम सामने आते हैं। मंत्रालय की ओर से स्कूल स्तर पर पूरे देश में खेलों में सुधार किया जाएगा और इसके लिए खेल संघ को भी टास्क दिया गया है।

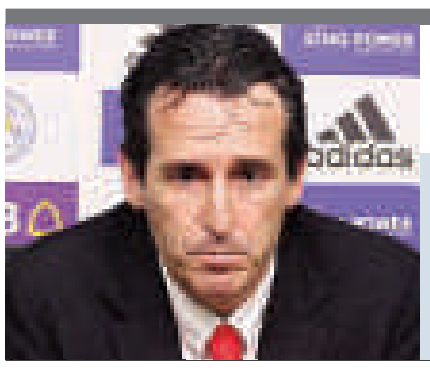

मैंने अपने करियर में काफी अच्छे मुकाबले खेले हैं, लेकिन अब मेरा संन्यास लेने का समय आ गया है।
– एलेक्स ब्लैकवेल, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर

अर्सेनल ने कोच इमेरी को किया बर्खास्त

लंदन, एएफपी : इंग्लिश फुटबॉल क्लब अर्सेनल ने अपने कोच उनेई इमेरी को बर्खास्त कर दिया है। यह फैसला क्लब की यूरोपा लीग में इनत्राच्ट फ्रंकफर्ट के हाथों मिली हार के बाद लिया है। क्लब ने एक बयान में कहा कि हम आज इस बात का एलान करते हैं कि हमने अपनी टीम के मुख्य कोच उनेई इमेरी और उनकी कोचिंग टीम से अलग होने का फैसला किया है। क्लब ने कहा कि यह फैसला इसलिए लिया गया।

न्यूज गैलरी

नॉकआउट दौर में पहुंचे साथियान

चेंगडु (चीन) : भारत के साथियान गुणनसेकरन ने यहां जारी अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ (आइटीटीएफ) पुरुष विश्व कप के नॉकआउट दौर में जगह बना ली है। इस टूर्नामेंट में भारत की इकलौती चुनौती साथियान ने शुक्रवार को ग्रुप-डी में दोनों मैच जीत नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। साथियान ने फ्रांस के सिमोन गौजी को 4-3 से मात देकर फ्रांसिसी खिलाड़ी पर अपनी पहली जीत हासिल की। दूसरे मैच में साथियान का सामना डेनमार्क के जोनाथन ग्रोथ से था। इस मैच में भारतीय खिलाड़ी ने 4-2 से जीत हासिल की। (प्रेट्र)

हिरासत में ही रहेंगे गौतम, काजी, सय्यम

बेंगलुरु : कर्नाटक प्रीमियर लीग (केपीएल) में आरोपी खिलाड़ी सीएम गौतम और अब्रार काजी के अलावा सट्टेबाज को पुलिस हिरासत में ही रखा जाएगा, जबकि अन्य आरोपियों को जमानत दे दी गई है। केंद्रीय अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त कुलदीप जैन ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी। बेंगलुरू ब्लास्टर्स की टीम के सदस्य काजी और गौतम को सात नवंबर को भारतीय अपराध संहिता (आइपीसी) की धारा 420 के तहत पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। हरियाणा के रहने वाले सट्टेबाज सय्यम को 11 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। जिन आरोपियों को जमानत मिली है उनमें बेंगलुरु ब्लास्टर्स के निशांत सिंह और विश्वनाथन, उनके गेंदबाजी कोच वीनू प्रसाद और बलारी टस्कर्स के भुवनेश के नाम शामिल हैं। (आइएएनएस)

कैलिस ने रखी आधी दाढ़ी और मूंछ

नई दिल्ली : दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी जैक कैलिस इन दिनों अजीबोगरीब स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। कैलिस ने अपनी आधी दाढ़ी और आधी मूंछ शेव करा ली है। कैलिस ने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर साझा की है, जिसमें वह आधी दाढ़ी और आधी मूंछ में दिखाई दे रहे हैं। उनकी इस तस्वीर ने उनके प्रशंसकों को चौंका दिया है। कैलिस ने हालांकि अपनी इस स्थिति को साफ कर दिया है। कैलिस ने इंस्टाग्राम पर लिखा है कि वह अगले कुछ दिनों तक इसी रूप में नजर आएंगे क्योंकि उन्होंने सेव द राइनो चैलेंज स्वीकार किया है। कैलिस के मुताबिक उनके देश में गैंडा की संख्या तेजी से घट रही है और इन्हें बचाने के लिए एक अभियान चलाया गया है, जिसके तहत जो इस चैलेंज को स्वीकार करेगा और इस अभियान का साथ देगा। (प्रेट्र)

40 की उम्र में भारत के लिए खेलने को तैयार अली

भारतीय फुटबॉलर अनवर अली। जागरण

फुटबॉल ▶ भारत के लिए 33 मुकाबले खेल चुके हैं अनवर

आइ-लीग 2019-20 में पंजाब एफसी की ओर से उतरेंगे

विकास पांडेय, नई दिल्ली

एक समय था जब अनवर अली का नाम भारतीय फुटबॉल टीम के अच्छे डिफेंडर में शुमार किया जाता था, लेकिन पिछले सात साल से यह नाम केवल लीग में चर्चा का विषय बनकर रह गया है। अनवर कभी आइ-लीग तो कभी इंडियन सुपर लीग (आइएसएल) में खेलकर भारतीय टीम में वापसी की राह तलाश रहे हैं।

2008 में भारत के लिए पदार्पण करने वाले अनवर 33 मुकाबलों में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हालांकि, 2012 से वह टीम से बाहर हैं और अब उनकी उम्र भी 35 पार कर चुकी है, लेकिन अनवर को अभी भी उम्मीद है कि उन्हें मौका मिलेगा तो वह भारत की ओर से अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अनवर ने कहा कि देश के लिए खेलने की उम्मीद कभी खत्म नहीं होगी। मैं 40 का भी हो जाऊंगा तब भी मैं यह उम्मीद बनाए रखूंगा। देश के लिए खेलना किसी भी खिलाड़ी के लिए सम्मान की बात है और मैं हमेशा देश के लिए अपना 100 फीसद देने के लिए तैयार हूं।

दर्जनों भारतीय क्लबों के साथ खेल चुके अनवर इस बार आइ-लीग में पंजाब का प्रतिनिधित्व करेंगे। पंजाब की टीम 2017-18 में चैंपियन बनी थी, लेकिन पिछले सत्र में उसे नौवें स्थान से संतोष करना पड़ा था। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआइएफएफ) ने आइ-लीग की जगह आइएसएल को अपनी प्रमुख लीग बनाने का फैसला किया है, जिसे एएफसी से भी सहमति मिल गई है। ऐसे में आइ-लीग के खिलाड़ियों के भविष्य पर प्रश्न खड़ा हो गया है। हालांकि, अनवर ने कहा, हर चीज के अपने नफा एवं नुकसान हैं। जब से आइएसएल और आइ-लीग दोनों टूर्नामेंट भारत में आयोजित हो रहे हैं तब से ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को अपनी पहचान बनाने का मौका मिल रहा है। जहां तक आइ लीग की बात है तो इस लीग का एक अपना इतिहास है। मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट डिविजन और सेकेंड डिविजन नाम देने से कुछ खास फर्क पड़ेगा।

पंजाब में जन्मे अनवर पिछले सत्र में आइएसएल में मुंबई सिटी की ओर से खेल रहे थे। लगातार क्लब बदलने और आइ-लीग में वापसी के सवाल पर अनवर ने कहा कि जब मैं पहली बार जेसीटी छोड़कर डेंपो में गया था तब कोई भी पंजाब के खिलाड़ियों को मोहन बागान, डेंपो, ईस्ट बंगाल और महिंद्रा जैसे बड़े क्लबों से जाकर खेलने में डर लगता था। उनको लगता था कि इन क्लबों के लिए खेलना मुश्किल होता होगा। डेंपो में जाने से पहले ही मैंने तय किया था कि मैं कभी लंबे समय तक नहीं रहूंगा क्योंकि मैं कहीं फंसकर नहीं रहना चाहता हूं।

मैं अपने खेल में सुधार करने के लिए भारत आया हूं : डिका

अनवर अली की तरह असेर पियरिक डिपेंडा डिका भी पंजाब की ओर से पहली बार आइ-लीग में उतरेंगे। कैमरून मूल के डिका के पास भी मोहन बागान जैसे नामी क्लब के साथ खेलने का अनुभव है। डिका इस नई चुनौती के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मैं पंजाब का प्रतिनिधित्व करने के लिए रोमांचित हूं। हर देश में फुटबॉल खेलने की एक अलग शैली होती है। मैं अपने खेल में सुधार करने के लिए भारत आया हूं।

आज से आइ-लीग का आगाज

नई दिल्ली, जेएनएन : आइ-लीग के 13वें संस्करण के पहले मुकाबले में आइजॉल एफसी और मोहन बागान के बीच आइजॉल के राजीव गांधी स्टेडियम में शनिवार को भिड़ंत होगी। 11 टीमों की इस लीग में शनिवार को दिन के दूसरे मुकाबले में गोकुलम केरल और नेरोका एफसी की टीमें भी आमने-सामने होंगी। 2019-20 के सत्र में कुल 110 मैच खेले जाएंगे। मणिपुर के ट्रॉउ एफसी को पहली बार लीग में शामिल किया गया है। इस क्लब ने पिछले सत्र में सेकेंड डिविजन लीग जीता था। इस बार विजेता टीम को एक करोड़ रुपये और उप विजेता टीम को 60 लाख रुपये दिए जाएंगे।

बीसीबी के अधिकारी को बांग्लादेश से बाहर जाने से रोका

ढाका, एएफपी : बांग्लादेश के भ्रष्टाचार रोधी आयोग ने शीर्ष क्रिकेट अधिकारी को देश से बाहर जाने से रोक दिया है, क्योंकि उसने खेल की राष्ट्रीय संस्था में जांच तेज कर दी है। प्रवक्ता ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। महबूबुल अनम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दो सीनियर निदेशकों में से एक हैं जो संदेह के घेरे में हैं।

आयोग के प्रवक्ता प्रणब कुमार भट्टाचार्जी ने कहा कि अनम के खिलाफ अवैध रूप से धन इकट्ठा करने के लिए जांच चल रही है। संबंधित प्राधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह सुनिश्चित करें कि वह देश छोड़कर नहीं जाएं। आयोग ने आव्रजन पुलिस को पत्र लिखा है कि निविदाओं और नियुक्तियों में छेड़छाड़ करने, क्रिकेट बोर्ड प्रायोजकों के चयन में अपने पद का गलत इस्तेमाल करने के लिए अनम जांच के घेरे में हैं। इसके अनुसार, 'पता चला है कि यह व्यक्ति अपने परिवार के साथ देश से भागने की कोशिश कर रहा है। उचित जांच के लिए यह जरूरी है कि उसे विदेश जाने से रोका जाए।'

हालांकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के पूर्व महासचिव और उपाध्यक्ष अनम ने किसी भी तरह के गलत काम से इन्कार किया है। उन्होंने कहा कि मैं बीसीबी की किसी भी टेंडर प्रक्रिया या प्रायोजन में शामिल नहीं हूं। इस तरह के आरोप सच नहीं हैं। इससे पहले बांग्लादेश क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर शाकिब अल हसन भी मैच फिक्सिंग में फंसने के कारण दो वर्ष का प्रतिबंध झेल रहे हैं।

कबड्डी टूर्नामेंट में पाकिस्तान को नहीं मिली भारत की ओर से एनओसी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

- पंजाब सरकार श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाशोत्सव पर करा रही आयोजन
- पाकिस्तान को एनओसी दिलाने में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर कर रहे प्रयास

पंजाब सरकार की ओर से अंतरराष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट एक दिसंबर से करवाया जा रहा है। इसमें पाकिस्तान की टीम को भी हिस्सा लेना है, लेकिन भारत सरकार ने उसे अब तक एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) जारी नहीं किया है। पंजाब के खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने कहा कि प्रदेश सरकार पाक को एनओसी दिलवाने के लिए प्रयास कर रही है क्योंकि भारत-पाक मैच का सबसे ज्यादा रोमांच होता है और लोग सबसे ज्यादा इसे देखना चाहते हैं।

पंजाब सरकार श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में यह आयोजन करवा रही है। सोढ़ी ने कहा कि टूर्नामेंट में भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, केन्या, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका व अमेरिका की टीमें हिस्सा ले रही हैं। पाकिस्तान की टीम को एनओसी दिलवाने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि भारत-पाकिस्तान के बीच मैच हो और दोनों देशों के खेल प्रेमी इसका लुत्फ उठा सकें। खेल मंत्री ने बताया कि प्रतियोगिता के मैच सात शहरों में होंगे। प्रतियोगिता का शुभारंभ गुरु नानक स्टेडियम सुल्तानपुर लोधी (कपूरथला) में होगा। इस दिन चार मैच होंगे। तीन दिसंबर को गुरु नानक स्टेडियम अमृतसर में दो मैच खेले जाएंगे। चार दिसंबर को गुरु रामदास स्पोर्ट्स स्टेडियम फिरोजपुर में दो मैच, पांच दिसंबर को आउटडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम बठिंडा में दो मैच, छह दिसंबर को पोलो ग्राउंड पटियाला में दो मैच होंगे। सेमीफाइनल आठ दिसंबर को चरण गंगा स्टेडियम आनंदपुर साहिब (रूपनगर) में होंगे। फाइनल मैच दस दिसंबर को शहीद भगत सिंह स्टेडियम, डेरा बाबा नानक (गुरदासपुर) में होगा। यहीं पर तीसरे स्थान के लिए भी मैच का आयोजन होगा। पाक टीम भाग ले पाता है या नहीं यह देखना होगा।

एकमात्र टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज की टीम ने अफगानिस्तान को नौ विकेट से दी शिकस्त

खेल संवाददाता, लखनऊ

- टेस्ट मुकाबला जीत कैरेबियाई टीम ने सीरीज पर किया कब्जा
- मैच में दस विकेट लेने वाले कॉर्नवॉल बने मैन ऑफ द मैच

वेस्टइंडीज ने अपने ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत यहां खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच की तीसरे दिन के शुरुआत्री में ही अफगानिस्तान को नौ विकेट से रौंदकर सीरीज पर कब्जा जमा लिया। कैरेबियाई टीम की जीत रहकीम कॉर्नवॉल की शानदार गेंदबाजी के साथ शमराह ब्रुक्स की बल्लेबाजी का भी अहम भूमिका रही।

इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में पहली पारी में 90 रन से पिछड़े अफगानिस्तान ने तीसरे दिन शुक्रवार को सात विकेट पर 109 रन के आगे खेलना शुरू किया और उसके बाकी तीन विकेट महज 7.1 ओवर में 11 रन और जोड़कर कुल 120 के स्कोर पर आउट हो गए। हालांकि ये तीनों विकेट कैरेबियाई कप्तान और तेज गेंदबाज जेसन होल्डर के खाते में गए। सिर्फ 31 रनों के लक्ष्य को वेस्टइंडीज ने 6.2 ओवर में एक विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। क्रैग ब्रेथवेट आठ रन बनाकर आमिर हमजा की गेंद पर आउट हो गए। पहली पारी में अर्धशतक जड़ने वाले जॉन कैंपबेल 19 और शाई होप छह रन बनाकर नाबाद रहे। वेस्टइंडीज की तरफ से भारत की किसी भी पिच पर एक मैच में सबसे ज्यादा 10 विकेट लेने वाले ऑफ स्पिनर रहकीम कॉर्नवॉल को 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया।

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए अच्छी शुरुआत के बावजूद अफगानिस्तान की टीम पहली पारी में सिर्फ 187 रनों पर सिमट गई। मेजबानों की लचर बल्लेबाजी का सिलसिला दूसरी पारी में भी जारी रहा। उनकी खराब बल्लेबाजी का ही नतीजा रहा कि, दूसरे ही दिन दूसरी पारी में अच्छी शुरुआत के बावजूद उसके सात विकेट महज 107 पर गिर गए थे। वहीं, अफगानिस्तान के पहली पारी के 187 रनों के जवाब में कैरेबियाई टीम के शमराह ब्रुक्स ने धैर्य का परिचय देते हुए शानदार शतक जड़ा जिसकी बदौलत मेहमान टीम 277 रन बनाकर 90 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल करने में सफल रहीं।

विविध

डीएम का चपरासी बन होटल में रह रहा संदिग्ध नेपाली, पूछताछ

जागरण संवाददाता, बरेली

कैंट क्षेत्र में संदिग्ध हालत में घूमते नेपाली युवक को आर्मी इंटेलीजेंस ने हिरासत में लिया, जिससे चौंकाने वाली सामग्री बरामद हुई। पांच दिन पहले पकड़ा गया वह युवक न सुन सकता है और न बोल सकता है, लेकिन उसके पास से मिला सामान उसके जासूस होने की ओर इशारा कर रहा। पुलिस ने उसके कमरे से भारत के नक्शे बरामद किए, जिन पर उप्र के अयोध्या, कानपुर व बरेली समेत कई जिलों को इंगित करते हुए निशान लगाए गए हैं। इसके अलावा नेपाल व भारत की कंपनियों के 16 सिम कार्ड, दो पेन ड्राइव, दो आधार कार्ड, कई मेल आइडी भी बरामद की हैं, जिनकी जांच की जा रही है। वह जिस होटल में रह रहा था वहां के मालिक को उसने खुद को बरेली के जिलाधिकारी कार्यालय में चपरासी के पद पर कार्यरत और लखनऊ सचिवालय से अटैच होना बताया था। होटल मालिक उसके झांसे में था। नेपाली युवक होटल मालिक के मोबाइल से ही नेपाल में वीडियो कॉल कर इशारों में बात करता था।

नेपाल में 65 लाख, अलग अलग बैंकों के दस खाते : अब तक हुई जांच में नेपाली युवक के पास से दो आधार कार्ड मिले हैं। एक में उसने खुद के लखनऊ तोपखाना कैंट क्षेत्र निवासी गंगा बहादुर विश्वकर्मा व दूसरे में बिहार के जिला पूर्णिया, थाना वभनी के गांव निखरैल निवासी मुहम्मद मंसूर का पुत्र मुहम्मद मंजर बताया है। उसके पास से अलग अलग बैंकों की दस पासबुक बरामद हुई हैं, जिनके खाते उसने इन्हीं दोनों नाम से खुलवा रखे हैं। इसके अलावा उसके पास 65 लाख रुपये नेपाल में होने की जानकारी भी इंटेलीजेंस को मिली है। इसके चलते ही उसके खातों की भी जांच कराई जा रही है।

आर्मी इंटेलीजेंस ने नेपाली युवक को कैंट क्षेत्र से पकड़ा है। इसक चलते आशंका है कि उसने पेन ड्राइव में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज छिपा रखे होंगे। जिसे उसने लॉक कर रखा है। पेन ड्राइव के लॉक तुड़वाने और उसकी जानकारी के लिए फॉरेंसिक लैब को भेजा गया है। इंटेलीजेंस की जांच युवक को जासूस समझ कर ही की जा रही है।

कैंट थाने में बैठा युवक अपना नाम गंगा बहादुर विश्वकर्मा बता रहा है। लिखकर बताया कि 2015 में नेपाल में आए भूकंप के बाद से वह भारत में है। बताया कि बरेली से पहले, पीलीभीत, मुरादाबाद, बिहार और लखनऊ में रहा है। लखनऊ के एक होटल में मोमोज बनाने का काम करता था। उसे कैंट थाने में रखा गया है, पुलिस टीमें भी उससे पूछताछ कर रही हैं। वहीं डीएम कार्यालय ने ऐसे किसी युवक के चपरासी होने की बात से इन्कार किया।

कई चरण में टीमें उससे पूछताछ कर चुकी हैं। अभी तक प्रमाणित साक्ष्य नहीं मिल सके हैं। बरामद सामान को जांच के लिए भेजा गया है।
राजेश पांडेय, डीआइजी

आइएमए की मुख्यधारा में शामिल हुए 58 कैडेट

जागरण संवाददाता, देहरादून

देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में शुक्रवार को आयोजित ग्रेजुएशन सेरेमनी में कैडेट धीरज गुणवंत को गोल्ड, राहुल वर्मा को सिल्वर और संदीप शेखावत को ब्रांज मेडल दिया गया। जागरण

- आर्मी कैडेट कॉलेज की 114वीं ग्रेजुएशन सेरेमनी में दी गई जेएनयू की डिग्री
- डिग्री प्राप्त करने वाले 58 कैडेट में 21 विज्ञान और 37 कला वर्ग के

भारतीय सैन्य अकादमी (आइएमए) स्थित आर्मी कैडेट कॉलेज (एसीसी) की 114वीं ग्रेजुएशन सेरेमनी में 58 कैडेट को जेएनयू की डिग्री प्रदान की गई। एसीसी में तीन साल के कड़े प्रशिक्षण और पढ़ाई के बाद ये कैडेट अब आइएमए की मुख्यधारा से जुड़ गए हैं। एक साल के प्रशिक्षण के बाद वह सेना में बतौर अधिकारी शामिल हो जाएंगे।

सिपाही के रूप में फौज में भर्ती हुए देश के 58 युवाओं ने शुक्रवार को तरक्की की उड़ान भरी। वर्षों से सेना में अफसर बनने का सपना संजोए ये कैडेट आखिरकार अपनी लगन और मेहनत के बूते मुकाम तक पहुंच गए हैं। अब आइएमए में एक वर्ष प्रशिक्षण लेकर अगले साल वह पीओपी में अंतिम पग भरेंगे। खेत्रपाल सभागार में आइएमए कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल एसके झा ने इन कैडेट को जेएनयू (जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी) से स्नातक की उपाधि और अवार्ड दिए। डिग्री पाने वालों में 21 कैडेट विज्ञान और 37 कला वर्ग के हैं। कमांडेंट ने अफसर बनने की राह पर अग्रसर इन कैडेट को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने सभी कैडेट को याद दिलाया कि एसीसी ने देश को बड़ी संख्या में ऐसे अफसर दिए हैं, जिन्होंने अपनी क्षमता के बूते कई पदक जीते। अभिभावकों को बधाई देते हुए कहा कि उनके अथक प्रयास और परिश्रम की बदौलत आज यह दिन आया है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट को बधाई देते कहा कि वह अपने प्रदर्शन में निरंतरता बनाए रखें।

इससे पहले एसीसी के प्रधानाचार्य डॉ. नवीन कुमार ने कॉलेज की प्रगति रिपोर्ट पेश की। उन्होंने कहा कि आज उन्नत प्रौद्योगिकी व तकनीकी विकास के साथ चुनौतियां भी बढ़ी हैं। ऐसे में स्कॉलर वॉरियर बनकर खुद को इस बदलाव के अनुरूप ढालने का प्रयास करें। एसीसी विंग के कमांडर ब्रिगेडियर वीएम चौधरी ने भी सभी कैडेट को बधाई दी।

इनको मिला पुरस्कार

चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेडल	
मेडल	कैडेट
गोल्ड मेडल	धीरज गुणवंत, काशीपुर उत्तराखंड
सिल्वर मेडल	राहुल वर्मा, रायबरेली, उप्र
ब्रांज मेडल	संदीप सिंह शेखावत जयपुर, राजस्थान
कमांडेंट बैनर	कारगिल कंपनी
सर्विस सब्जेक्ट्स	धीरज गुणवंत, उत्तराखंड
ह्यूमेनिटीज स्ट्रीम	नदीम अहमद, जम्मू-कश्मीर
साइंस स्ट्रीम	धीरज गुणवंत, उत्तराखंड

'मेडिक्लेम पॉलिसी से हुआ इलाज तो भी मोटर एक्सीडेंट मामलों में वाहन बीमा कंपनी करें भुगतान'

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

- हाई कोर्ट ने कहा-अपने वेतन से ली गई थी मेडिक्लेम पॉलिसी, इसका वाहन एक्सीडेंट से लेना-देना नहीं

दुर्घटना की स्थिति में होने वाले इलाज के लिए भले ही मेडिक्लेम पॉलिसी से भुगतान हुआ है, लेकिन मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा तय राशि का वाहन बीमा कंपनी को भुगतान करना ही होगा। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने यह अहम आदेश बीमा कंपनी की याचिका को खारिज करते हुए जारी किए हैं।

वाहन बीमा कंपनी रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ के आदेश को चुनौती दी है। कंपनी ने बताया कि मीनाक्षी अपने पति के साथ दोपहिया वाहन से 2014 में सेक्टर 47 से सेक्टर 35 आ रहीं थीं। इसी बीच एक वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी जिसके कारण दोनों गिर गए और उन्हें गंभीर चोटें आईं। इनके कारण मीनाक्षी 25 फीसद दिव्यांग हो गईं। इसके लिए ट्रिब्यूनल ने उन्हें मुआवजे के रूप में 15,19,857 रुपये भुगतान करने के आदेश दिए थे।

कंपनी ने पहली दलील यह दी थी कि एक्सीडेंट के बाद उसका वेतन घट गया था और ऐसे में घटे हुए वेतन के अनुसार ही उसकी आय के नुकसान की गणना की जानी चाहिए। हाई कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए मुआवजा राशि को सही करार दिया। इसके बाद कंपनी ने कहा कि पीड़ित को मेडिकल खर्च के तौर पर करीब 98 लाख रुपये भुगतान करने के ट्रिब्यूनल ने जो आदेश दिए हैं वह दोषपूर्ण हैं। कंपनी ने दलील दी कि पीड़िता का मेडिकल इंश्योरेंस था और इसी के तहत उस बीमा कंपनी ने खर्च की राशि का भुगतान कर दिया। एक ही इलाज के दो अलग-अलग जगह से पैसे नहीं लिए जा सकते इसलिए वाहन बीमा कंपनी को इस राशि के भुगतान से छूट दी जाए।

पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट। फाइल

हाई कोर्ट ने कंपनी की दलील को खारिज करते हुए कहा कि मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत भले ही उसका भुगतान किया गया हो लेकिन उस पॉलिसी से एक्सीडेंट का कोई लेना-देना नहीं है। ऐसे में एक्सीडेंट की स्थिति में मेडिक्लेम का कानूनी प्रावधान ऊपर है और बीमा कंपनी को इसका भुगतान करना ही होगा।

मंडी में अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे का रास्ता साफ

राज्य ब्यूरो, शिमला

- भूमि अधिग्रहण व निर्माण कार्य का पूरा खर्च केंद्र उठाएगा, तीन हजार बीघा जमीन का अधिग्रहण होगा

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के बल्ह में अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा बनाने का रास्ता साफ हो गया है। प्रस्तावित हवाईअड्डे के लिए तीन हजार बीघा भूमि का अधिग्रहण होगा। केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण और हवाईअड्डा निर्माण का पूरा खर्च उठाने की हामी भर दी है। यह हवाईअड्डा दो चरण में बनेगा। जैसे हवाईअड्डा ऑपरेशनल होगा, उसमें केंद्र और राज्य की 51:49 फीसद की हिस्सेदारी होगी। अगले सप्ताह केंद्रीय टीम हवाईअड्डे के प्रस्तावित स्थल का दौरा करने के लिए पहुंच सकती है।

अधिकांश जमीन किसानों की : बल्ह घाटी में प्रस्तावित हवाईअड्डे के लिए तीन हजार बीघा जमीन का अधिग्रहण होगा। अधिग्रहण होने वाली अधिकांश जमीन किसानों की निजी भूमि है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के हवाईअड्डे के लिए हाल ही में सर्वेक्षण हुआ था। इस परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की टीमें सर्वेक्षण कर चुकी हैं। सर्वेक्षण के बाद टीम ने रिपोर्ट नागरिक उड्डयन मंत्रालय को सौंपी थी।

केंद्र सरकार ही मंडी हवाई अड्डे के निर्माण का सारा खर्च उठाएगी। इसके लिए केंद्र ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। हवाई अड्डा ऑप्रेशनल होने के बाद इसमें 51:49 फीसद की हिस्सेदारी केंद्र और हिमाचल की रहेगी। जल्द ही इसके लिए सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी जाएंगी। उम्मीद है अगले वित्त वर्ष में हवाई अड्डे का काम शुरू हो।
– डॉ. श्रीकांत बाल्दी, मुख्य सचिव

जयराम का ड्रीम प्रोजेक्ट : मंडी में अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ड्रीम प्रोजेक्ट है। वह काफी समय से इस मसले को केंद्र सरकार के समक्ष उठा रहे हैं। यह प्रदेश का सबसे बड़ा हवाईअड्डा होगा। प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से भी इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शिमला और धर्मशाला की दूरी इस हवाई अड्डे से लगभग समान है। प्रदेश में इस समय तीन हवाईअड्डे हैं। शिमला का एयरपोर्ट काफी ऊंचाई पर स्थित है। गगल का हवाईअड्डा सबसे उपयुक्त है। भुंतर हवाईअड्डा नदी किनारे होने से इसकी पट्टी की पर्याप्त लंबाई पूरी नहीं करता है।

ओडिशाके बड़गांव में मानवता शर्मसार

जागरण संवाददाता,बड़गांव (सुंदरगढ़)

- 18 साल पहले की थी दूसरी बिरादरी की युवती से शादी, बिरादरी के लोगों ने अंतिम संस्कार में शामिल होने से किया मना

सुंदरगढ़ जिले के बड़गांव ब्लॉक अंर्तगत सहाजबहाल गांव में शुक्रवार को मानवता उस समय शर्मसार हुई जब एक युवक की बिरादरी के लोगों ने अंतिम संस्कार करने और उसमें शामिल होने से इन्कार कर दिया। डेलकी खड़िया बिरादरी के युवक ने दूसरी बिरादरी की युवती से शादी की थी। इसका प्रायश्चित नहीं करने से बिरादरी के लोग नाराज थे। इस पर दूसरी बिरादरी के कुछ साथियों ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार किया।

जानकारी के अनुसार सहाजबहाल गांव के सरोज प्रधान की गुरुवार की रात तीन बजे अचानक तबीयत खराब होने के बाद मौत हो गई। ऐसे में उसकी बिरादरी के लोगों ने दूसरी बिरादरी की लड़की से शादी करने और उसका प्रायश्चित नहीं करने के कारण उसका अंतिम संस्कार करने से साफ मना कर दिया। साथ ही उस बिरादरी का कोई सदस्य भी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। सरोज का अपराध बस इतना था कि उसने 18 साल पहले पास के गांव दशरापाड़ा की किसान बिरादरी की लड़की से शादी की थी। कहा जाता है नवजात एवं शव की कोई जाति नहीं होती है लेकिन सहाजबहाल गांव में डेलकी खड़िया बिरादरी का इससे कोई सरोकार नहीं। तभी तो उन्होंने सरोज के अंतिम संस्कार में शामिल होने से इन्कार कर दिया। इसके बाद गांव के उसके साथी गणेश जयपुरिया, सरोज साहू, चिन्मय शा, ए बेहरा व गगन सेठ आदि ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार किया।

मौसम विशेष

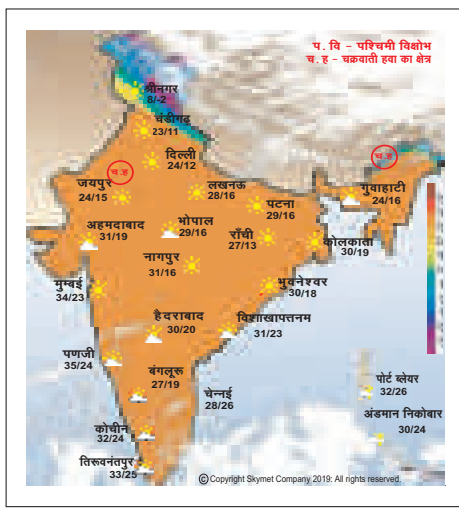

जम्मू-कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में मौसम शुष्क व ठंडा बना रहेगा। सुबह के तापमान में गिरावट तथा दिन के तापमान में हल्की वृद्धि हो सकती है। राजस्थान, हरियाणा व पंजाब में सुबह के समय कुहासा या कोहरा छाया रहेगा। दिल्ली में प्रदूषण स्तर सामान्य बना रहेगा तथा मौसम शुष्क रहेगा।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	34/22/व	अहमदाबाद	31/16/आंबा
कोलकाता	30/19/सा	बड़ोदा	32/17/सा
चेन्नई	29/24/व	नागपुर	31/17/व
हैदराबाद	30/19/आंबा	इन्दौर	28/19/व
बंगलूरू	26/19/सा	राँची	29/18/आंबा
त्रिवेन्द्रम	31/25/व	पटना	29/18/व
गुवाहाटी	24/16/सा	जमशेदपुर	31/20/आंबा
गंगटोक	06/-5/व	पुणे	31/22/आंबा

पहली बार दो अंतरराष्ट्रीय टीमों के बीच फुटबॉल मैच खेला गया

1872 में आज ही पहली बार दो अंतरराष्ट्रीय टीमों स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच ग्लासगो में फुटबॉल मैच खेला गया था। इस मैच को देखने के लिए करीब चार हजार लोग पहुंचे थे। उस समय इस मैच की एंट्री फीस पांच रुपये थी।

सर्वाधिक बिकने वाला संगीत एल्बम रिलीज हुआ

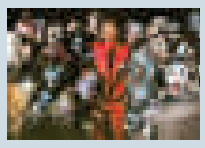

1982 में आज ही पॉप संगीत के बादशाह माइकल जैक्सन का चर्चित संगीत एल्बम थ्रिलर रिलीज हुआ था। यह अबतक का सर्वाधिक बिकने वाला एल्बम है। इस एल्बम की दुनिया भर में 6.6 करोड़ से ज्यादा कॉपी बिकीं। इसने पॉप संगीत के बादशाह माइकल जैक्सन को खूब प्रसिद्धि दिलाई थी।

जगदीश चंद्र बसु ने बताया था कि पौधों में भी बसती है जान

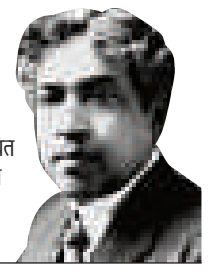

महान विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बसु का जन्म 1858 में आज ही ढाका (अब बांग्लादेश) में हुआ था। उन्होंने रेडियो और माइक्रो वेव ऑपटिक्स के कई सिद्धांतों की नींव रखी। 1895 में इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव के वायरलेस ट्रांसमिशन का डेमो दिया। जिसमें उन्होंने तरंगों की मदद से थोड़ी दूर पर रखी घंटी को बजाया था। उन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक डिवाइस की खोज की थी, जिसकी मदद से यह साबित किया था कि पौधों में भी जान बसती है। 1904 में अमेरिकन पेटेंट हासिल करने वाले वह पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। 23 नवंबर, 1937 को उनका देहांत हो गया।

इधर-उधर की

चाय का तलबी है यह घोड़ा

लंदन,एजेंसी : आदमी, आम हो या खास। उसके दिन की शुरुआत चाय की चुस्कियों से ही होती है। लेकिन एक घोड़ा भी ऐसा है, जो चाय का इतना आदी है कि यदि एक कप चाय न मिले तो वह काम की शुरुआत ही नहीं करता। इंग्लैंड के मर्सीसाइड शहर की पुलिस में भर्ती इस घोड़े की उम्र करीब 20 साल है। जो पिछले 15 साल से पुलिस विभाग में कार्य कर रहा है। इसे रोज सुबह अस्तबल में ही एक कप चाय का इंतजार रहता है। इस घोड़े का नाम जैक है। जैक की चाय को बिना मलाई के दूध में बनाया जाता है। जिसमें दो चम्मच शक्कर भी होती है। सामान्य से बड़े कप में आने वाली चाय यदि इसे न मिले तो यह काम नहीं करता। मर्सीसाइड पुलिस ने जैक का चाय पीते वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है, जिसे अबतक दो लाख लोग देख चुके हैं और बहुत सारे लोगों ने इस पर कमेंट भी किया है।

अमेजन की आग से पिघल रहे ग्लेशियर

चिंताजनक ▶ दो हजार किलोमीटर दूर स्थित एंडीज पर्वतमाला के ग्लेशियर पर पड़ रहा असर

बायोमास के एयरोसोल्स से फीकी हो सकती है एंडियन ग्लेशियर की चमक

वाशिंगटन, प्रेट्र : ब्राजील में अमेजन के जंगलों में लगी आग का असर दो हजार किलोमीटर दूर स्थित ग्लेशियरों पर भी पड़ रहा है। एक नए अध्ययन में दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला में भी इसका प्रभाव देखा गया है। शोधकर्ताओं के मुताबिक इसके कारण यहां ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगे हैं।

साइंटिफिक रिपोर्ट्स नामक जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में पाया गया कि जंगलों में आगजनी से बायोमास जलने से बने एयरोसोल्स (ब्लैक कार्बन) को हवा अपने साथ एंडियन ग्लेशियरों तक ले जा रही है। शोधकर्ताओं ने कहा, 'ये एयरोसोल्स बर्फ पर जमा होते हैं और ग्लेशियरों के पिघलने की दर बढ़ा देते हैं। बर्फ की चादर पर ब्लैक कार्बन के कण गिरने से ग्लेशियरों चमक भी फीकी हो जाती है। इसे अल्बिडो रिड्यूशन कहा जाता है।'

ब्राजील के रियो डी जेनेरियो स्टेट यूनिवर्सिटी के न्यूटन डी मैगलस नेटो और उनके सहयोगियों ने बोलिवियाई जोंगो ग्लेशियर पर अमेजन बेसिन के बायोमास के संभावित प्रभाव का एक मॉडल तैयार किया। इसके लिए उन्होंने वर्ष 2000 से 2016 तक आग लगने की घटनाओं, धुएं, वर्षा और ग्लेशियर के पिघलने की गति का अध्ययन कर जुटाए गए आंकड़ों का इस्तेमाल किया।

ग्लेशियरों के लगातार पिघलने से भविष्य में बढ़ेगा समुद्र का जल स्तर। फाइल

इस दौरान शोधकर्ताओं ने साल 2007 और 2010 के आंकड़ों का खास ध्यान रखा क्योंकि इस बीच अमेजन के बेसिन में आगजनी की सर्वाधिक घटनाएं हुई थीं। शोधकर्ताओं ने ब्लैक कार्बन के कारण 'स्नो एल्बिडो रिड्यूशन' की भी जांच की। इससे पहले तक बर्फ की चमक फीकी होने का कारण धूल के कणों को माना जाता था। उनके मॉडल से पता चला कि अकेले ब्लैक कार्बन और धूल के कारण सालाना ग्लेशियर के पिघलने की दर में तीन-चार फीसदी की बढ़ोतरी की संभावना है और यदि इन दोनों कारकों का असर एकसाथ होता है तो बर्फ पिघलने की दर छह फीसद तक बढ़ जाती है।

शोधकर्ताओं ने कहा, 'धूल की मात्रा अधिक होने पर ग्लेशियर सालाना 11 से 13 फीसद तक पिघल सकते हैं और ब्लैक कार्बन के कणों के कारण बर्फ पिघलने की दर 12 से 14 फीसद की बढ़ोतरी हो सकती है।' उन्होंने कहा कि अध्ययन के परिणाम बताते हैं बर्फ में धूल के कणों की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि अमेजन के जंगलों से कितनी मात्रा में बायोमास के एयरोसोल्स हवा की मदद से यहां तक पहुंचे हैं।

प्रभावित होंगे ग्लेशियर: शोधकर्ताओं ने कहा कि बढ़ती खाद्य पदार्थों की मांग के परिणामस्वरूप ब्राजील में वनों की कटाई का और विस्तार हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप ब्लैक कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि हो सकती है जो एंडियन ग्लेशियरों को प्रभावित कर सकती है।

खनिज से भी संबंधित हो सकती हैं पुरानी संरचनाएं

स्पेक्ट्रम

- ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के शोधकर्ता ने किया दावा
- कहा- अध्ययन से मंगल पर जीवन के संकेतों को तय करने में मिलेगी मदद

लंदन, प्रेट्र : आमतौर पर पुरानी संरचनाओं को जीवाश्मों से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा मान लिया जाता है कि ये संरचनाएं किन्हीं जीवों से संबंधित होंगी। कई बार उनके डीएनए का विश्लेषण कर वैज्ञानिक यह अनुमान भी लगाते हैं कि जीवाश्म किस जीव का हो सकता है और जब उसकी मौत हुई होगी तो वह कितने वर्ष का रहा होगा आदि। पर अब एक नए अध्ययन में इन जीवाश्मों के बारे में नया दावा किया गया है। इसमें कहा गया है कि पुरानी संरचनाएं जीवाश्मों के बजाय खनिज से भी संबंधित हो सकती हैं। शोधकर्ताओं का दावा है कि इस अध्ययन से भविष्य में मंगल मिशन के दौरान वहां जीवन के संकेतों को निर्धारित करने में मिलेगी।

प्रोसीडिंग्स ऑफ रायल सोसायटी बी नामक जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि सूक्ष्म जीवों के अवशेषों से बने तंतु लौह-खनिज से युक्त हो सकते हैं। ये तंतु केमिकल गार्डनिंग नामक प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के शोधकर्ता और इस अध्ययन लेखक सीन मैकमोहन के अनुसार, पहले के शोधों में ऐसी संरचनाओं को पृथ्वी का सबसे पुराना जीवाश्म बताया गया था। उन्होंने कहा कि लेकिन इस तरह की सूक्ष्म संरचनाओं को स्वतंत्र साक्ष्यों के अभाव में जीवाश्म ही नहीं मान लेना चाहिए। मैकमोहन ने कहा, वर्तमान अध्ययन से भविष्य में लाल ग्रह पर जीवन के संभावित संकेतों को निर्धारित करने में मदद मिल सकती है।

इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने प्रयोगशाला में छोटी खनिज संरचनाओं का निर्माण किया। ये संरचनाएं ठीक वैसी ही थी जैसी मंगल ग्रह की चट्टानों पर लौह-समृद्ध संरचनाएं मिलती हैं। मैकमोहन ने बताया कि उन्होंने रसायन युक्त सिलिकेट या कार्बोनेट युक्त क्षारीय तरल पदार्थों के साथ लौह-समृद्ध कणों को मिलाकर संरचनाएं बनाईं। इसके लिए केमिकल गार्डनिंग प्रक्रिया को अपनाया गया।

उन्होंने कहा कि इस तरह की रासायनिक प्रतिक्रियाओं का सैकड़ों वर्षों से अध्ययन किया गया है, लेकिन अब तक चट्टानों के भीतर लौहे की समृद्ध संरचनाओं का विस्तार से अध्ययन नहीं किया गया था। मैकमोहन ने कहा कि वास्तविकता में इन जीवाश्मों को दोबारा अध्ययन करने की जरूरत है क्योंकि इनमें गैर-जैविक खनिज जमा होने की संभावना अधिक है।

शोध अनुसंधान

घर बैठे हो सकेगी प्रोस्टेट कैंसर की जांच

प्रोस्टेट कैंसर की जांच के लिए अब कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। शोधकर्ताओं ने एक ऐसी आसान विधि विकसित की है, जिसके जरिये घर बैठे ही मूत्र के नमूनों से इस बीमारी की जांच हो सकेगी। शोधकर्ताओं के अनुसार, पीयूआर टेस्ट (प्रोस्टेट यूरिन रिस्क) को घर में ही मूत्र नमूनों पर आजमाया जा सकता है। प्रोस्टेट कैंसर का अनुमान लगाने के लिए यह पहला अहम कदम होता है। इससे इस बीमारी के बायोमार्कर के स्तर की पहचान हो सकती है। इंग्लैंड के नॉर्विच मेडिकल स्कूल के प्रमुख शोधकर्ता डॉ जेर्मी क्लार्क ने कहा, 'पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर सबसे आम रोग है। आमतौर पर यह बीमारी धीरे-धीरे बढ़ती है। प्रोस्टेट कैंसर के लिए सामान्य रूप से रक्त जांच, डिजिटल रेक्टल एक्जामिनेशन (डीआरई), एमआरआइ या बायोप्सी से गुजरना पड़ता है। लेकिन पीयूआर महज मूत्र नमूनों से इस रोग के खतरे को भांप सकता है।' -एएनआइ

एआइ की मदद से ब्रेन इंजरी का हो सकेगा इलाज

भारतवंशी समेत शोधकर्ताओं के एक दल ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) आधारित एक ऐसी विधि ईजाद की है, जिससे डॉक्टरों को गंभीर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी (टीबीआइ) के इलाज में मदद मिल सकेगी। साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, इस विधि के जरिये 85 फीसद तक यह सटीक अनुमान लगाया जा सकता है कि रोगी को बचाने के लिए डॉक्टरों के पास कितने दिन का समय है। फिनलैंड की हेलसिंकी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता राहुल राज ने कहा, 'इस तरह का डायनेमिक प्रोग्नोस्टिक मॉडल कभी पेश नहीं किया गया। इसके लिए हालांकि अभी कुछ इंतजार करना होगा। कुछ समय बाद हम चिकित्सा क्षेत्र में इसे आजमा सकेंगे।' बढ़ती दुर्घटनाओं के कारण टीबीआइ मौत के प्रमुख कारण के तौर पर उभर रहा है। मस्तिष्क पर चोट लगने के कारण होने वाली इस समस्या का उपचार आइसीयू में होता है, लेकिन हर तीन में एक रोगी की मौत हो जाती है। -आइएएनएस

वैज्ञानिकों ने लैब में तैयार किया कार्बन डाइऑक्साइड खाने वाला बैक्टीरिया

- इजरायल के विजमान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज के शोधार्थियों का दावा
- वातावरण से ग्रीनहाउस गैसों के स्तर को कम करने की खुल सकती है राह

यरुशलम, प्रेट्र : शोधकर्ताओं ने लैब में एक नया बैक्टीरिया तैयार किया है। यह बैक्टीरिया ऊर्जा के लिए कांप्लेक्स आर्गेनिक कंपाउंड की जगह कार्बन डाइऑक्साइड को पचाने में सक्षम है। इसके विकास से आने वाले समय में ऐसे प्रोजेक्ट की राह खुल सकती है, जिसमें बैक्टीरिया के उपयोग से पर्यावरण के लिए खतरनाक ग्रीनहाउस गैसों के स्तर को कम किया जा सकता है।

इजरायल के विजमान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज के शोधकर्ताओं के अनुसार, धरती पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों की दो श्रेणियां हैं। एक ऑटोट्रोफ्स है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉयोमास में तब्दील करता है। जबकि दूसरा हेटेरोट्रोफ्स आर्गेनिक कंपाउंड का सेवन करता है। जर्नल सेल में प्रकाशित अध्ययन में उस प्रक्रिया की व्याख्या की गई है, जिसके जरिये शोधकर्ताओं ने एशेरिकिया कोली (ई कोली) नामक बैक्टीरिया को कार्बन डाइऑक्साइड पचाने वाला बना दिया। उन्होंने बताया कि बॉयोमास में ऑटोट्रोफ्स ऑर्गनिज्म का वर्चस्व होता है। इसकी ज्यादातर खाद्य पदार्थों और ईंधन की उत्पत्ति में अहम भूमिका होती है। बॉयोमास कार्बनिक पदार्थ होता है, जो वनस्पतियों और पशुओं से प्राप्त होता है। शोधकर्ताओं ने कहा कि सिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स बनाना चुनौतीपूर्ण था। उन्होंने लैब में तैयार ई कोली के मेटाबोलिज्म में बदलाव कर ऑटोट्रोफ्स तैयार किया। हालांकि ऑटोट्रोफ्स के पैमाने पर खरा उतरने के लिए ई कोली के मेटाबोलिज्म में किया गया बदलाव पर्याप्त नहीं पाया गया। इसके लिए अभी और शोध करने की जरूरत बताई गई है।

यह अध्ययन सेल नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ है। प्रतीकात्मक

विजमान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज के शोधकर्ता और इस अध्ययन के प्रमुख लेखक शमुअल ग्लीजर ने कहा, 'एक बुनियादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम यह देखना चाहते थे कि क्या बैक्टीरिया के आहार में परिवर्तन करने से उनके बायोमास का संश्लेषण संभव है।' उन्होंने कहा कि अध्ययन के दौरान हमें उत्साहजनक परिणाम देखने को मिले। भविष्य में इस बैक्टीरिया में अन्य जरूरी बदलाव कर वायुमंडल से ग्रीन हाउस गैसों को कम करने में मदद मिल सकती है।

घंटों बाधित रहे फेसबुक व इंस्टाग्राम, यूजर ने ट्विटर पर किया ट्रोल

सैन फ्रांसिस्को, एएफपी : फेसबुक और इसके सहयोगी एप गुरुवार को घंटों बाधित रहे। इससे नाराज यूजर ने समस्या को ट्विटर पर ट्रोल कर दिया। हालांकि, सोशल मीडिया कंपनी ने दावा किया है कि कुछ एप में आई बाधा दूर कर ली गई है। कंपनी के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, 'गुरुवार सुबह फेसबुक परिवार के एप के इस्तेमाल में यूजर को परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। अब इस समस्या को दूर कर लिया गया है।' फेसबुक ने दावा किया कि उसके चार केंद्रीय सर्वरों में से एक में तकनीकी बाधा आ गई थी। इसके कारण लोगों को घंटों परेशानियों का सामना करना पड़ा।

उधर, फेसबुक परिवार के इंस्टाग्राम समेत अन्य एप की तकनीकी बाधा को यूजर ने ट्विटर पर ट्रोल कर दिया। लोगों ने तरह-तरह की टिप्पणियां कीं। इंटरनेट की निगरानी करने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर के मुताबिक फेसबुक परिवार में परेशानी की शुरुआत सुबह करीब 8:45 बजे बजे हुई थी। इससे दुनिया भर के कई हिस्सों के उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा।

कार्यक्षमता बढ़ाने के साथ बेहतर अवसर भी देती है तकनीक

बेंगलुरु, आइएएनएस : स्मार्ट तकनीक कार्यस्थलों में अब काफी बदलाव ला चुकी है। पिछले कुछ दशकों में इसकी मदद से कार्यकौशल में भी विविधता देखने को मिली है। समय के साथ-साथ यह लोगों का जीवन भी सहज बना रही है। हाल ही में हुए एक नए अध्ययन में यह दावा किया गया है कि 82 फीसद भारतीय मानते हैं कि तकनीक से कार्यक्षमता में सुधार होने के साथ ऑफिस का माहौल में भी पहले के मुकाबले काफी बदल गया है। साथ ही यह अच्छी नौकरी के साथ-साथ बेहतर अवसर भी उपलब्ध कराता है।

लेनेवो के इस सर्वे में अमेरिका, मैक्सिको, ब्राजील, चीन, भारत, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली के लगभग 15 हजार लोगों को शामिल किया गया था। इसमें दुनियाभर के लोगों ने कार्यस्थल पर तकनीक के माध्यम से कार्यक्षमता के बारे में अपनी राय दी।

लेनेवो पीसीएसडी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल अग्रवाल ने कहा, नए दौर के कर्मचारियों की मांगों और कार्यस्थल को बेहतर बनाने के लिहाज से तकनीक में सुधार बेहद जरूरी है। अध्ययन में बताया गया है कि 73 फीसद भारतीयों का मानना है कि तकनीक कुशल लोगों को अच्छी नौकरी का अवसर देने के साथ-साथ करियर को बेहतर बनाने में मदद करती है। दुनियाभर में 56 फीसद लोगों का मानना है कि तकनीक करियर को अगले स्तर तक ले जाने में मददगार है।

संगीतमय विरोध

कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में सरकार विरोध प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय के छात्रों ने म्यूजिक के जरिये अनूठे ढंग से विरोध जताया। पिछले कई सप्ताह से देश की सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन चल रहा है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के हजारों छात्रों ने वायलिन बजाया और एक से बढ़कर एक मधुर धुन बजाई। शांतिप्रिय विरोध के इस तरीके को लोगों ने भी काफी पसंद किया। एएफपी

अमेरिका में थैंक्सगिविंग परेड का जश्न मनाया

न्यूयॉर्क सहित अमेरिका के विभिन्न शहरों में मैसी थैंक्सगिविंग दिवस का जश्न मनाया और भव्य परेड निकाली गई। इस परेड में लाखों लोग शरीक हुए और कई करोड़ों ने टीवी पर इसका लाइव प्रसारण देखा। अच्छी फसल होने की खुशी में यह दिवस मनाया जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति रहे अब्राहम लिंकन ने पहली बार 1863 में सरकारी तौर पर थैंक्सगिविंग डे मनाने की घोषणा की थी। हालांकि उन्होंने यह घोषणा संयुक्त सेना की गेटिस बर्ग में जीत के उपलक्ष्य में की थी। यह दिवस कनाडा, फिलीपीस, नीदरलैंड में भी मनाया जाता है। रायटर

स्क्रीन शॉट

'राम लखन' जैसी नहीं होगी 'बागी 3' : रितेश देशमुख

'कभी खुशी कभी गम', 'ब्रदर्स' जैसी फिल्में पिछले कुछ वर्षों में रिलीज हुई हैं जो भाइयों के रिश्ते पर बनी हैं। एक वक्त ऐसा भी रहा है, जब 'रामलखन', 'करण अर्जुन', 'परिंदा', 'दीवार' जैसी ज्यादातर फिल्में भाइयों के संबंधों पर ही बनती थीं और हिट भी होती थीं। लेकिन अब इस रिश्ते को पर्दे पर दर्शाने वाली फिल्में कम हो गई हैं। 'कबीर सिंह' में भाइयों की एक झलक नजर आई थी। लेकिन अब भाइयों के रिश्ते पर एक पूरी फिल्म लेकर आ रहे हैं निर्देशक फरहाद सामजी। 'बागी 3' की कहानी दो भाइयों की होगी। 'बागी' फ्रेंचाइजी की इस तीसरी फिल्म की शूटिंग आधी खत्म की जा चुकी है। फिल्म में रितेश देशमुख और इस फ्रेंचाइजी का चेहरा रह चुके टाइगर श्रॉफ भाइयों के किरदार में होंगे। रितेश टाइगर के बड़े भाई का किरदार निभाएंगे। खबरों की मानें तो रितेश फिल्म में पुलिस अफसर बने हैं। मराठी फिल्म 'माउली' के बाद यह दूसरी बार होगा, जब रितेश पुलिस अफसर का रोल निभाएंगे। खबरें आ रही थीं कि यह फिल्म वर्ष 1989 में रिलीज हुई जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर अभिनीत फिल्म 'राम लखन' जैसी होगी। रितेश बताते हैं कि फरहाद समाजी ने कहा था कि 'राम लखन' जैसा रोल है। लेकिन मेरा मानना है कि 'राम लखन' फिल्म से बहुत अलग होगी 'बागी 3' की कहानी। रितेश कहते हैं, 'मैं 'राम लखन' फिल्म की तुलना 'बागी 3' के साथ नहीं कर सकता हूं। 'राम लखन', 'करण अर्जुन' जैसी फिल्में दो भाइयों की कहानी पर आधारित थी। जब भी दो भाइयों पर फिल्में बनती हैं, तो जज्बा वही होता है, जो इन फिल्मों में रहा है। उसी जज्बे और प्यार को लेकर हम 'बागी 3' भी बना रहे हैं। फिल्म में भाइयों का रिश्ता तो होगा, लेकिन जो 'बागी' का जॉनर हमेशा से रहा है, वह भी इस फिल्म में रहेगा।' इस वर्ष रितेश देशमुख की तीन फिल्में रिलीज हुई थीं।

डबल रोल में होंगी तापसी पन्नू

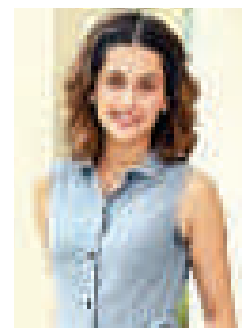

तापसी पन्नू के सितारे इन दिनों बुलंदियों पर हैं। इस वर्ष उनकी चार फिल्में 'बदला', 'गेम ओवर', 'मिशन मंगल', 'सांड की आंख' रिलीज हुई हैं। उनकी आगामी फिल्मों में 'रश्मि रॉकेट', 'वुमनिया' और 'थप्पड़' जैसी महिला केंद्रित फिल्में शामिल हैं। हाल ही में खबर आई थी कि तापसी को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज की बायोग्राफी भी ऑफर हुई है। इन खबरों के बीच अब जो दूसरी खबर सामने आ रही है, वह यह है कि संजय लीला भंसाली अब तापसी पन्नू के साथ फिल्म बनाने की तैयारी में हैं। सूत्रों के मुताबिक, संजय लीला भंसाली प्रोडक्शन की फिल्म 'सिया जिया' तापसी को ऑफर की गई है। इस फिल्म में तापसी डबल रोल में होंगी। फिल्म में उनका किरदार 'चालबाज' की श्रीदेवी या 'सीता गीता' की हेमा मालिनी के किरदार की जैसा होगा, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। फिल्म की सहनिर्माता शबीना खान होंगी। 'सिया जिया' फिल्म का निर्देशन कौन करेगा, यह भी अभी तय नहीं किया गया है।

हिंदी फिल्मों में कदम रखेंगे 'अर्जुन रेड्डी' फेम अभिनेता विजय देवराकोंडा

'कबीर सिंह' इस वर्ष की सुपरहिट फिल्मों में शामिल है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 278 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। 'कबीर सिंह' तेलुगु फिल्म 'अर्जुन रेड्डी' की रीमेक थी। शाहिद ने जो किरदार 'कबीर सिंह' में निभाया था, वह किरदार 'अर्जुन रेड्डी' में अभिनेता विजय देवराकोंडा ने निभाया था। इन दिनों दक्षिण भारतीय और हिंदी फिल्मों के बीच की रेखा धूमिल होती जा रही है। अब दोनों ही इंडस्ट्री के दरवाजे एक-दूसरे के लिए पूरी तरह से खुल गए हैं। अब विजय देवराकोंडा भी हिंदी फिल्मों में आने की तैयारी में हैं। विजय ने बताया कि वह हिंदी फिल्मों में डेब्यू करने के लिए मन बना चुके हैं। अपने पसंदीदा जॉनर की बात करते हुए उन्होंने बताया कि वह लव और एक्शन ड्रामा वाली फिल्मों में काम करना चाहते हैं। 'कबीर सिंह' और 'अर्जुन रेड्डी' दोनों ही फिल्में अपने विषय की वजह से काफी सुर्खियों में रही थीं। जुनूनी प्रेमी का प्यार जताने का तरीका कई लोगों को अच्छा नहीं लगा था, जिसके बाद ट्विटर पर लोगों के बीच फिल्म को लेकर काफी बहस भी हुई थी।

'हंगामा 2' से जुड़ीं शिल्पा, पहली बार करेंगी कॉमेडी रोल

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी पिछले 13 सालों से बड़े पर्दे से दूर हैं, लेकिन अब वह फिल्म 'निकम्मा' के साथ एक बार फिर बॉलीवुड में वापसी कर रही हैं। इसके साथ ही शिल्पा के पास दूसरी फिल्मों के ऑफर भी आने भी शुरू हो गए हैं। 'निकम्मा' की शूटिंग के साथ ही शिल्पा ने फिल्म 'हंगामा 2' के लिए भी हां कह दी है। इस फिल्म से वह प्रियदर्शन के साथ पहली बार जुड़ रही हैं। इस कॉमेडी फिल्म में परेश रावल व मीजान जाफरी होंगे और दक्षिण की अभिनेत्री प्रणीता सुभाष भी होंगी। फिल्म की शूटिंग जनवरी में शुरू होने की उम्मीद है। एक सूत्र के अनुसार, 'फिल्म भले ही 'हंगामा' के सीक्वल के रूप में आ रही है, लेकिन इसकी अलग स्टोरीलाइन होगी। फिल्म में शिल्पा एक ग्लैमरस करियर-ओरिएंटेड महिला का किरदार निभाएंगी, जो एक मजेदार गलतफहमी का केंद्र बन जाती हैं।' प्रियदर्शन ने बताया कि 'हंगामा 2' की शूटिंग 6 जनवरी से शुरू होगी। प्रियदर्शन कहते हैं, 'मैं इस रोल के लिए ऐसी एक्ट्रेस चाहता था, जो फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर चुकी हो। शिल्पा परेश रावल के अपोजिट दिखेंगी।

अध्ययन

स्टैफिलोकॉकस ऑरियस बैक्टीरिया में वैज्ञानिकों ने खोजा प्रोटीन, विशेष अणुओं की मदद से हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने में है कारगर

एंटीबायोटिक दवाओं के विकास में उपयोगी होगा प्रोटीन

नई दिल्ली, आइएसडब्ल्यू : दवाओं के प्रति बैक्टीरिया में बढ़ती प्रतिरोधक क्षमता को देखते हुए नई दवाओं का विकास चिकित्सा क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों में से एक है। नई एंटीबायोटिक दवाओं का निर्माण आमतौर पर पादप अर्क और फफूंद जैसे प्राकृतिक उत्पादों या फिर केमिकल लाइब्रेरी में संग्रहित रसायनों की श्रृंखला पर आधारित होता है। लेकिन, एंटीबायोटिक दवाओं की खोज से जुड़े शोध कार्यों में ऐसी प्रक्रियाओं का महत्व कई बार बढ़ जाता है, जिन पर अपेक्षाकृत रूप से कम खोजबीन की गई हो। इसलिए नए एंटीबायोटिक एजेंट के रूप में 'क्विनोन एपोक्साइड' का विकास महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

भारतीय वैज्ञानिकों ने स्टैफिलोकॉकस ऑरियस नामक बैक्टीरिया के एंटीबायोटिक दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधी क्षमता रखने वाले रूपों में ऐसे प्रोटीन की पहचान की है, जिसे आणविक स्तर पर लक्ष्य बनाकर इस बैक्टीरिया को नष्ट किया जा सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस खोज के आधार पर नई एंटीबायोटिक दवाएं विकसित करने में मदद मिल सकती है।

शोधकर्ताओं ने इस अध्ययन के दौरान एक अणु भी विकसित किया है जो बैक्टीरिया में पहचाने गए मार-आर प्रोटीन को लक्ष्य बनाकर उस बैक्टीरिया को नष्ट कर सकता है। यह अणु इंडोल आधारित क्विनोन एपोक्साइड है, जो सक्रिय जीवाणुरोधी एजेंट की तरह काम करता है। क्विनोन एपोक्साइड बैक्टीरिया की कोशिकाओं को भेदकर और उसमें मार-आर प्रोटीन की कार्यप्रणाली को बाधित करके उसे मार देता है।

सीएसआइआर-केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (सीडीआरआइ), लखनऊ और भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आइआइएसईआर), पुणे के वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया यह अध्ययन शोध पत्रिका जर्नल ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री में प्रकाशित किया गया है।

अध्ययन में शामिल आइआइएसईआर, पुणे के शोधकर्ता डॉ. हरिनाथ चक्रपाणि ने बताया कि स्टैफिलोकॉकस ऑरियस बैक्टीरिया में पहचाने गए इस प्रोटीन को बैक्टीरिया-रोधी एजेंट्स के जरिये लक्ष्य बनाया जा सकता है, जिससे कई गंभीर संक्रमणों से लड़ने में मदद मिल सकती है। इसे अत्यधिक दवा प्रतिरोधी वीआरएसए बैक्टीरिया के खिलाफ प्रभावी पाया गया है।

क्या है स्टैफिलोकॉकस ऑरियस : स्टैफिलोकॉकस ऑरियस संक्रमण पैदा करने वाला बैक्टीरिया है, जो दवाओं के लिए आसानी से प्रतिरोधी के रूप में उभर सकता है और उपचार के विकल्पों को सीमित कर सकता है। इसमें पाया जाने वाला मार-आर प्रोटीन इस बैक्टीरिया की वृद्धि और उसके जीवित रहने के लिए एक जरूरी तत्व है। लेकिन, बैक्टीरिया में इस प्रोटीन की कार्यप्रणाली बाधित होने पर वह जीवित नहीं रह पाता है। इस अध्ययन में आइआइएसईआर, पुणे में इंडोल आधारित क्विनोन एपोक्साइड यौगिकों का संश्लेषण किया गया है। जबकि, सीएसआइआर-सीडीआरआइ, में संक्रमण पैदा करने वाले विभिन्न बैक्टीरिया पर इन यौगिकों का परीक्षण किया गया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि स्टैफिलोकॉकस ऑरियस बैक्टीरिया को मारने के लिए मार-आर परिवार के प्रोटीन को लक्ष्य बनाया जाना कारगर हो सकता है, सिर्फ इस बात का पता लगाने के लिए शोध में सैकड़ों संभावित प्रोटीन लक्ष्यों का परीक्षण किया गया है।

सहजीवी बैक्टीरिया : शोधकर्ताओं का कहना है कि स्टैफिलोकॉकस ऑरियस मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला एक सहजीवी बैक्टीरिया है। यह बैक्टीरिया प्रायः त्वचा और शरीर के भीतर श्लेष्मा झिल्लियों में पाया जाता है। पर, रक्त प्रवाह या फिर भीतरी ऊतकों में यह बैक्टीरिया प्रवेश कर जाए तो निमोनिया, हृदय वॉल्व और हड्डियों जैसे गंभीर संक्रमण हो सकते हैं।